VIDYA UNIVERSITY PRESS

TOUCH n PASS

सर्वश्रेष्ठ परीक्षा पथ-प्रदर्शक

B.A.
द्वितीय वर्ष
(डिप्लोमा कोर्स)
सेमेस्टर-IV

भूगोल

आर्थिक भूगोल

SYLLABUS

UNIT-I

Meaning, Concepts and Approaches of Economic Geography : Spatial organization economic activities.

UNIT-II

Resource : Meaning, concept, classification and distribution.

UNIT-III

Spatio-Economic organization of, Forestry, fishing and mining activities.

UNIT-IV

Agricultural typologies, agricultural land use model (J.H. Van Thunen).

UNIT-V

Types of Industries : Factors of location of Industries; Iron and steel Industry, cotton textiles and sugar, Theory of Industrial location (Alfred Weber).

UNIT-VI

World Transportation : Sea routes and major transcontinental railways.

UNIT-VII

WTO and International Trade : Patterns and trends.

UNIT-VIII

Effect of globalization on developing countries.

TOUCH n PASS

VIDYA®
UNIVERSITY PRESS

पंजीकृत कार्यालय
विद्या एम्पायर, बागपत रोड,
मेरठ, उत्तर प्रदेश (NCR) 250 002
www.vidyauniversitypress.com

© प्रकाशक

लेखन एवं सम्पादन
शोध एवं अनुसन्धान प्रकोष्ठ

मुद्रक
विद्या यूनिवर्सिटी प्रेस

TOUCH 'n' PASS

विषय-सूची

UNIT-I : आर्थिक भूगोल का अर्थ, अवधारणाएँ एवं उपागम ...3
UNIT-II : संसाधन : अर्थ, अवधारणा, वर्गीकरण एवं विपणन ...18
UNIT-III : वानिकी, मत्स्यपालन एवं खनन गतिविधियों की स्थैतिक-आर्थिक संरचना ...31
UNIT-IV : कृषि का प्रारूप वर्गीकरण ...43
UNIT-V : उद्योगों के प्रकार ...58
UNIT-VI : विश्व परिवहन ...74
UNIT-VII : डब्ल्यू०टी०ओ० तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार ...110
UNIT-VIII : विकासशील देशों पर वैश्वीकरण का प्रभाव ...131

UNIT-I

आर्थिक भूगोल का अर्थ, अवधारणाएँ एवं उपागम
Meaning, Concepts and Approaches of Economic Geography

खण्ड-अ अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. आर्थिक भूगोल को परिभाषित कीजिए।
Define Economic Geography.

उत्तर संसार के विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादन पर पड़ने वाले प्रत्यक्ष प्रभाव के वैज्ञानिक अन्वेषण को आर्थिक भूगोल कहते हैं।

प्र.2. संस्थागत उपागम के कोई तीन दोष लिखिए।
Write any three demerits of Institutional Approach.

उत्तर संस्थागत उपागम के तीन दोष निम्नलिखित हैं—

1. आर्थिक भूगोल में मानव के व्यावहारात्मक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है अत: मानव पर प्रयोग करना कठिन है।
2. इस पद्धति में सीमित निरीक्षण के आधार पर ही निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अत: उनकी सत्यता सन्देहास्पद रहती है।
3. यह पद्धति सर्व साधारण के लिए उपयोगी नहीं हैं।

प्र.3. आर्थिक भूगोल का प्राणीशास्त्र से सम्बन्ध बताइए।
State the relation between Economic Geography and Biology.

उत्तर प्राणीशास्त्र में विभिन्न जीव-जन्तु, पक्षी तथा मानव का विश्लेषणात्मक अध्ययन होता है इनकी संरचना एवं स्वभाव आदि से आर्थिक क्रियायें प्रभावित होती हैं। आर्थिक क्रियाओं तथा आर्थिक लाभ परिपेक्ष में आर्थिक भूगोल इनका अध्ययन करता है।

प्र.4. संस्थागत उपागम की दो विशेषताएँ लिखिए।
Write any two characteristics of Institutional Approach.

उत्तर संस्थागत उपागम की निम्नांकित विशेषतायें हैं—

1. इस उपागम द्वारा निष्कर्ष उपस्थित दशाओं के ध्यानपूर्वक मूल्यांकन के आधार पर प्राप्त किये जाते हैं।
2. इस उपागम में प्राकृतिक व सांस्कृतिक दशाओं के विशिष्ट व सामान्य गुणों पर जोर दिया जाता है।

प्र.5. आर्थिक भूगोल में स्थानिक प्रारूप को परिभाषित कीजिए।
Define spatial pattern in Economic Geography.

उत्तर भूगोल में स्थानिक स्वरूप का विवेचन सभी शाखाओं में प्रचलित है। लाँश द्वारा विकास का क्षेत्रीय प्रारूप मॉडल के लिए केन्द्रीय स्थल सिद्धांत तथा आर्थिक भूदृश्य न केवल वर्तमान तक चर्चा में है अपितु इसको विकसित किया गया है अर्थव्यवस्था का भौगोलिक स्वरूप के अन्तर्गत अर्थव्यवस्था का सामान्य मॉडल तथा अर्थव्यवस्था का स्थानिक मॉडल भी इसी दिशा को इंगित करता है।

प्र.6. आर्थिक भूगोल में सतत विकास को लिखिए।
Write Sustainable Development in Economic Geography.

उत्तर विकास ऐसा होना चाहिए जिससे पर्यावरण संतुलन बना रहे। दूसरे शब्दों में, विनाशरहित विकास औद्योगिकीकरण, प्रौद्योगिकी विकास, परिवहन तंत्र का विकास, कृषि में कीटनाशकों का प्रयोग संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन आदि विकास द्वारा पर्यावरण न केवल प्रदूषित होता है अपितु पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित होता जा रहा है यह मानव अस्तित्व के लिए भी खतरा है।

TOUCH n' PASS

प्र.7. विकास की नवीन् अवधारणाएँ संक्षेप में बताइए।
Briefly explain the new concepts of development.

उत्तर आर्थिक विकास किसी भी देश अथवा प्रदेश की प्राथमिकता होती है यद्यपि आर्थिक विकास का सामान्य रूप में आर्थिक भूगोल में अध्ययन किया जाता रहा है इसे निम्न प्रकार द्वारा भी समझ सकते हैं—

(अ) सतत् विकास की अवधारणा
(ब) आर्थिक विकास और जीवन की गुणवत्ता
(स) समग्र विकास।

प्र.8. आर्थिक भूगोल का इतिहास बताइए।
State the history of Economic Geography.

उत्तर इतिहास मानव के विकास, उनकी क्रियाओं, घटनाओं आदि का समुचित ब्यौरा प्रस्तुत करता है। इसी क्रम में आर्थिक इतिहास का विवरण होता है देश/राज्य अथवा प्रदेश में किस प्रकार आर्थिक विकास का घटनाक्रम अर्थात् उत्थान पतन हुआ, यह इतिहास से ज्ञात होता है। इसका प्रमुख उदाहरण उपनिवेशों की स्थापना एवं क्रमिक समाप्त होना है इनके समाप्त होने में शोषणकारी नीतियों का प्रमुख योग रहा है। दूसरा उदाहरण सोवियत संघ का विघटन है एक समय का शक्तिशाली देश आज कई देशों में विभक्त है। जिसका मुख्य कारण आर्थिक रहा है। वहीं आर्थिक भूगोल उन भौगोलिक कारणों का विश्लेषण करता है जिसके कारण विकास में बाधा हुई है। इसी आधार पर भावी विकास की योजना का निर्धारण होता है। अत: यह दोनों क्षेत्र सामन्जस्य रखते हैं।

खण्ड-ब लघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. आर्थिक भूगोल में सैद्धान्तिक व संस्थागत उपागम में समानता बताइए।
State the similarity between Theoretical and Institutional Approach in Economic Geography.

उत्तर

सैद्धान्तिक व संस्थागत उपागम में समानता
(Similarity between Theoretical and Institutional Approach)

1. **वर्णन**—किसी भी विषय को समझने के लिये या उसके विचारों को अभिव्यक्त करने लिये वर्णन या स्पष्टीकरण आवश्यक है। यह विषय से, वस्तु से या विधि से सम्बन्धित होता है और कभी-कभी तीनों से ही सम्बन्धित हो सकता है इसके आधार पर वाद में सम्बन्धित कार्य को आगे बढ़ाया जा सकता है। अत: यह प्राथमिक दशा है।
2. **मापदण्ड**—साधारण वर्णन बहुत कम शुद्ध होता है। अत: अधिक शुद्धता के लिये संख्या, सांख्यिकी व गणित की विधियों से व्यक्त किया जा सकता है। जनगणना के आँकड़े इसका सर्वोत्तम उदाहरण कहा जा सकता है। अत: विभिन्न मापदण्डों (मात्रात्मक स्वरूप) को अपनाना आजकल महत्त्वपूर्ण हो गया है इस दृष्टि से कम्प्यूटरों का उपयोग होने के कारण यह प्रक्रिया अधिक जटिल होने लग गई है।
3. **वर्गीकरण**—वर्गीकरण, वर्णन व मापदण्ड के बाद की स्थिति है, जिससे विषय को अधिक स्पष्ट समझने का प्रयास किया जाता है। यह शोध के विषय के अनुसार हो सकता है। विश्व में प्राकृतिक व मानवीय तत्त्वों का वितरण बड़ा ही स्पष्ट है। अत: उन्हें किसी उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत करके समझा जा सकता है क्योंकि अर्थ तंत्र का प्रतिरूप क्षेत्र को प्रभावित करता है व क्षेत्र, अर्थ तन्त्र के प्रतिरूप को प्रभावित करता है अत: यह वर्गीकरण दोनों ही उपागमों की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं।
4. **वास्तविक व सापेक्षिक स्थिति**—दोनों ही उपागमों में महत्त्वपूर्ण हैं। दोनों ही उपागम वर्तमान में आर्थिक गतिविधियों की स्थिति व उनका कार्य समझने के लिए ऊर्जा को महत्त्व देते हैं। इसका महत्त्व भावी सम्भावनाओं व नियोजन करने की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि ऊर्जा का उपयोग निरन्तर बढ़ता जा रहा है।

TOUCH n PASS

प्र.2. संस्थागत व सैद्धान्तिक उपागम में अन्तर बताइए।
State the difference between Institutional and Theoretical Approach.

उत्तर

संस्थागत व सैद्धान्तिक उपागम में अन्तर
(Difference between Institutional and Theoretical Approach)

दोनों उपागमों में महत्त्वपूर्ण अन्तर विधि का है जहाँ आगमन उपागम तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ता है वहाँ सैद्धांतिक उपागम कल्पना व तर्क के सहारे आगे बढ़ता है। मोटे रूप में दोनों अलग-अलग विधियाँ हैं लेकिन अधिक गहराई से देखा जाये तो दोनों ही थोड़ी बहुत एक-दूसरे की पूरक व निर्भरता लिये हुये है। मान लीजिये कि आगमन उपागम में हम किसी निष्कर्ष पर पहुँचना चाहते हैं। तो विभिन्न प्रकार के उपलब्ध आँकड़ों की सहायता लेते हैं, लेकिन किस प्रकार के आँकड़ों का चयन एवं उपयोग किया जाये इसके लिये कल्पना का सहारा लेना पड़ेगा जबकि दूसरी ओर निगमन पद्धति अपनाते हैं तो अनुमानित सिद्धांतों की जाँच के लिये हमें वास्तविक जगत के तथ्यों को प्राप्त करना पड़ेगा। अत: दोनों को अलग-अलग मानना गलत है। मार्शल के अनुसार, वैज्ञानिक अध्ययन के लिये दोनों की उसी प्रकार आवश्यकता है जिस प्रकार चलने के लिए दायें व बायें पैर की आवश्यकता होती है। कौन-सा वैज्ञानिक अध्ययन निगमनात्मक अधिक है और कौन-सा आगमनात्मक। यह कहना कठिन है।

प्र.3. संस्थागत उपागम किन बातों पर आधारित है? संक्षेप में उल्लेख कीजिए।
On what is the Institutional Approach based? Mention in brief.

उत्तर

संस्थागत उपागम के आधार
(Bases of Institutional Approach)

संस्थागत उपागम निम्नांकित बातों पर आधारित हैं—

1. मानव द्वारा लिये गये निर्णय (भूतकाल व वर्तमानकाल में लिए गए) प्राकृतिक व सांस्कृतिक वातावरण से सम्बन्धित होते हैं या उनसे प्रभावित होते हैं।
2. सर्वव्यापी एवं विशिष्ट, दोनों ही प्रकार की विशेषताओं के विकास में प्राकृतिक व सांस्कृतिक वातावरण को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ज्ञान होना आवश्यक है, ताकि विकास से सम्बन्ध जोड़ा जा सके।
3. आर्थिक गतिविधियों के भूत, वर्तमान व भविष्य के स्वरूप व स्थिति से सम्बन्धित उद्देश्यात्मक दशा की ओर आने में वास्तविक की बजाय सापेक्षिक दृष्टि से तथा नियमों के बजाय प्रवृत्तियों की दृष्टि से देखना चाहिए क्योंकि ये गतिविधियाँ मानव द्वारा सम्पादित होती है और मनुष्य मशीन के कल पुर्जे की तरह नहीं है कि उसको नियम के आधार पर ढाला जा सके या वह नियमानुसार चलता रहे।
4. मानव और प्रकृति द्वारा निर्मित वातावरण समय की दृष्टि से चक्रीय है अर्थात् वातावरण में परिवर्तन एक प्रक्रिया है जो पृथ्वी पर बार-बार घटित होती रहती है। अत: उसका स्थानिक प्रतिरूप नापा जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है और कभी-कभी पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है कि अमुक घटना के बाद अमुक घटना होगी।
5. कुछ घटनायें पूर्णत: विशिष्ट होती है क्योंकि वे किसी संस्कृति, समाज व्यक्ति या प्राकृतिक वातावरण के किसी भी अंग से मेल नहीं खाती है। ये किसी क्रमिक प्रक्रिया के रूप में न होकर अलग प्रकार की ही होती है अत: उनका घटित होना स्थानिक रूप से विशेष प्रकार का ही होता है। इसलिए न तो उन्हें आसानी से नापा जा सकता है न ही वर्गीकृत किया जा सकता है और न ही मॉडल की सहायता से आंका जा सकता है।
6. आर्थिक भूगोल में समय व लागत विभिन्न प्रकार के संचरणों में महत्त्वपूर्ण है लेकिन ये ही हमेशा नियन्त्रक तत्त्व नहीं होते हैं क्योंकि समय व लागत तत्त्वों का मानवीय मूल्य भिन्न-भिन्न समय में, अलग-अलग स्थान पर, विभिन्न व्यक्तियों के लिये, पृथक-पृथक संस्कृति के अनुसार अलग-अलग होता है। एक ही प्रकार की दशाओं में भी अलग-अलग निर्णय कर्त्ता अलग-अलग प्रकार से व्यवहार करते हैं।

प्र.4. सैद्धान्तिक उपागम की विशेषताएँ बताइए।
State the Characteristics of Theoretical Approach.

उत्तर

सैद्धान्तिक उपागम की विशेषताएँ
(Characteristics of Theoretical Approach)

सैद्धान्तिक उपागम की अग्रांकित विशेषताएँ हैं—

TOUCH 'n PASS

1. वास्तविक जगत में बहुत जटिलतायें पायी जाती हैं। इसका अध्ययन इस उपागम के द्वारा सरलीकृत परिस्थिति में मानकर करते हैं, फिर वास्तविकता की ओर बढ़ते हैं अर्थात् काल्पनिक दशा से वास्तविकता की ओर आते हैं।
2. गणित व तर्क का उपयोग होने से इससे प्राप्त निष्कर्ष सुनिश्चित होते हैं। यदि पर्याप्त सावधानी से काम लिया जाये, तो निगमन उपागम अतुल्य है। मनुष्य की बुद्धि के लिए यह खोज का सबसे शक्तिशाली यंत्र है।
3. सर्वसाधारण के लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि अधिकांश मनुष्य किसी ऐसी प्रणाली जिसमें निरीक्षण, प्रयोग शारीरिक श्रम की आवश्यकता हो, उसे अपनाने में कतराते हैं। इस विधि में घर पर बैठे-बैठे कुछ स्वयं सिद्ध निष्कर्षों व मोटे-मोटे अनुभवों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं।
4. यह प्रणाली अनुमान लगाने व सम्भावनायें व्यक्त के लिए भी उपयुक्त है।
5. यह प्रणाली कम खर्चीली है।
6. इस प्रणाली में तर्क द्वारा नियम स्थापित किये जाते हैं। अत: ये नियम निश्चित, विश्वसनीय व त्रुटिहीन होते हैं।
7. इसमें तर्क का आधार होने से पक्षपात का भय नहीं रहता है।
8. यह आगमन विधि के सहायक के रूप में भी काम आती है।

दोष— 1. यह वास्तविकता से अलग हटकर काल्पनिक मान्यताओं पर निर्भर है। अत: जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वे तर्कसंगत तो होते हैं लेकिन व्यावहारिक जगत में सत्य होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है।

2. सामान्यत: सत्य की वास्तविकता को जाँचना सम्भव नहीं होता है क्योंकि इस विधि में यह पता लगाना कठिन होता है कि जिस सत्य के आधार पर हम बढ़ रहे हैं वह स्वयं कहाँ तक विश्वसनीय है?

प्र.5. आर्थिक भूगोल एवं अर्थशास्त्र में सम्बन्ध स्पष्ट कीजिए।
Clarify the relation between Economic Geography and Economics.

उत्तर

आर्थिक भूगोल एवं अर्थशास्त्र
(Economic Geography and Economics)

आर्थिक भूगोल तथा अर्थशास्त्र में घनिष्ट सम्बन्ध है क्योंकि मूलरूप से दोनों ही विषय आर्थिक क्रियाओं और अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित हैं। आर्थिक क्रियायें अर्थात् कृषि, पशुपालन, खनन, उद्योग, ऊर्जा, परिवहन, विपणन एवं व्यापार का अध्ययन अर्थशास्त्र एवं भूगोल का आधार है यद्यपि दोनों के अध्ययन दृष्टिकोण में अंतर है जहाँ अर्थशास्त्र वित्तीय को महत्त्व देता है वहीं आर्थिक भूगोल भौगोलिक पर्यावरण एवं उसके प्रभाव को। अर्थव्यवस्था का अध्ययन आर्थिक भूगोल में उसके स्थानिक स्वरूप को महत्त्व दिया जाता है अर्थशास्त्र को सैद्धांतिक कहा जाता है और आर्थिक भूगोल को अनुभाविक इसका कारण अर्थशास्त्र में उत्पादन प्रक्रिया, बाजार प्रक्रिया, मुद्रा विनिमय आदि को सैद्धांतिक पत्र का अध्ययन होता है।

उत्पादन कौन करता है, कहाँ करता है कैसे होता है यह आर्थिक भूगोल का विषय है वर्तमान में राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय विकास में अर्थशास्त्र महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है बल्कि आर्थिक, भूगोल इसकी पृष्ठभूमि तैयार करता है ये दोनों विषय एक दूसरे के पूरक हैं केन्द्रीय स्पल सिद्धांत, वॉन टपूनेन का कृषि स्थिति सिद्धांत, स्मिथ का औद्योगिक उपस्थिति सिद्धांत तथा गुरुत्व मॉडल सिद्धांत दोनों विषयों में सम्मिलित है।

खण्ड-स विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. आर्थिक भूगोल के उपागम को समझाते हुए संस्थागत उपागम का वर्णन कीजिए।
Explaining the approach of Economic Geography describe Institutional Approach.

उत्तर

आर्थिक भूगोल के उपागम
(Approaches to Economic Geography)

एक समय आर्थिक भूगोल को वाणिज्य-भूगोल के रूप में ही पहचाना जाता था लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ही आर्थिक-भूगोल का इतना अधिक विकास हुआ कि आज यह एक स्वतन्त्र विषय के रूप में ही नहीं उभरा है बल्कि इसकी कई स्वतन्त्र शाखाएँ भी विकसित हो गई हैं; जैसे—विपणन भूगोल, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, परिवहन भूगोल आदि। आज आर्थिक भूगोल के मूल रूप की अपेक्षा इसकी शाखाओं का स्वरूप अधिक स्पष्ट हो गया है।

TOUCH n PASS

आर्थिक भूगोल अपने विकास की प्रारम्भिक दशा में भी कोई विशिष्ट अध्ययन का विधि तन्त्र विकसित नहीं कर पाया। प्रारम्भ में कई प्रकार के अध्ययन के उपागम अपनाये जाते रहे। चिशोम का वाणिज्य भूगोल जो 1889 में प्रकाशित हुआ उसमें तीन प्रकार के उपागमों को अपनाया गया है—

1. **तथ्यात्मक उपागम**—इसमें वस्तुओं के उत्पादन, वितरण व विनिमय अर्थात् उत्पादन, वितरण व विनिमय से सम्बन्धित सामान्य तथ्यों का वर्णन किया गया।
2. **वस्तुनिष्ठ उपागम**—इसमें अलग-अलग वस्तु के आधार पर अध्ययन किया गया।
3. **प्रादेशिक उपागम**—इसके अनुसार अलग-अलग राष्ट्रों में उत्पादन व व्यापार का अध्ययन किया गया।

आने वाले वर्षों में अधिकांश लेखकों द्वारा प्रादेशिक व वस्तुनिष्ठ उपागम का मिश्रित स्वरूप अपनाया गया, लेकिन प्रथम विधि को अब तक उपेक्षित रखा गया जिसका आधार इसके भौगोलिक होने में संदेह के कारण था। लेकिन अन्तिम दशा में यह अपने आप ही स्वीकृत रूप में न आकर स्थानिक-विश्लेषण से सम्बन्धित सिद्धांतों के सामान्य विकास के अंग के रूप में आया। आज का यह नवीन उपागम अलग-अलग प्रदेशों या अलग-अलग वस्तुओं में सम्बन्धित न होकर, सामान्य सिद्धांत बनाने का है जिसमें विभिन्न तथ्यों को अलग-अलग नहीं मानकर बल्कि उनको तथ्य मानकर अध्ययन किया जाता है। इन तथ्यों से सम्बन्धित सामान्यीकरण (Generalisation) या तो मौखिक रूप से या सांख्यिकी के रूप में आते हैं जिसके आधार पर वास्तविक जगत की विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के वितरण एवं संचार के बारे में कहा जा सकता है।

जैसाकि पहले बताया जा चुका है कि आर्थिक भूगोल एक विज्ञान है इसी के नाते इसके अपने नियम है। आर्थिक भूगोल की विभिन्न समस्याओं एवं विषय-वस्तु का अध्ययन करने के कई उपागम है जिसमें प्रादेशिक उपागम, वस्तुनिष्ठ उपागम, ऐतिहासिक आगमन उपागम व सैद्धांतिक निगमन उपागम महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं। अत: हम यहाँ इन दोनों ही अंतिम उपागमों का विस्तृत अध्ययन करेंगे।

संस्थागत उपागम
(Institutional Approach)

इस उपागम को संस्थागत या अनुभवाश्रित या तथ्य प्रणाली या ऐतिहासिक उपागम भी कहते हैं। इस विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर आते हैं। इसमें व्यक्तिगत निरीक्षणों एवं प्रयोगों की सहायता से सर्वव्यापी या सामान्य नियम बना लेते हैं; जैसे—लोहा, चाँदी, सोना, सीसा आदि पानी में डालने पर डूब जाते हैं। हम जानते हैं कि ये सब धातुएँ हैं। अत: हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सभी धातुएँ पानी में डालने पर डूब जाती हैं। यह नियम अनुभव के आधार पर बनाया है। इसी प्रकार मान लीजिये कि बाजार में किसी वस्तु का मूल्य गिर जाने पर काफी संख्या में ग्राहकों को उस वस्तु को खरीदते देखते हैं, तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मूल्य गिर जाने पर वस्तु की माँग बढ़ जाती है। यह भी निरीक्षण पर आधारित है। इस प्रकार इस उपागम में हम अनेक तथ्यों को एकत्रित करते हैं और फिर उन तथ्यों के निरीक्षण, अनुभव या प्रयोगों के आधार पर एक सामान्य निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। अत: आगमन प्रणाली वास्तविकता के निकट होती है। इसलिए इसे वास्तविक प्रणाली भी कहते हैं।

इस उपागम के अनुसार यह माना जाता है कि मानव अलग-अलग है। प्रत्येक अलग इकाई की तरह कार्य करता है। आर्थिक भूगोल में आर्थिक गतिविधियों को स्थिति का स्वरूप विभिन्न व्यक्तियों द्वारा लिये गये निर्णयों का परिणाम है, लेकिन ये व्यक्ति विभिन्न तत्त्वों के प्रभाव से मुक्त नहीं है। व्यक्तियों पर कई तरह के प्रभाव पड़ते हैं जिसके कारण वह इस प्रकार से व्यवहार करता है कि उसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। इस उपागम के अनुसार मानव व्यवहार की कुछ प्रवृत्तियों को कुछ सीमा तक मानव समुदाय के व्यवहार से ज्ञात किया जा सकता है; जैसे—मूल्य गिरने पर मानव अधिक वस्तु खरीदता है। व्यक्ति विशेष का व्यवहार इतना सरल नहीं है जो जाना जा सके क्योंकि इसमें कई बातें उसके व्यवहार को प्रभावित करती है जिनमें उस व्यक्ति की आय, रुचि, आवश्यकता आदि महत्त्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार मानव की औसत आयु, जीवन बीमा की सारणियों से ज्ञात की जा सकती है। इन प्रवृत्तियों का अधिकतम उपयोग तभी किया जा सकता है जबकि इनमें अधिक व्यक्ति सम्मिलित होते हैं जैसे-जैसे इनकी संख्या घटती जाती है इनकी उपयोगिता भी घटती जाती है; जैसे—एक व्यक्ति की आयु का अनुमान लगाने में यह विधि पूर्णत: अनुपयोगी है, एक व्यक्ति की आयु का अनुमान, उसके स्वास्थ्य, उसके पूर्वजों की आयु, उसके भोजन, उसकी रुचि आदि कई बातों की पृष्ठभूमि में देखने पर ही लगाया जा सकता है।

इस उपागम के अनुसार मानव-व्यवहार पर कई संस्थाओं का भी प्रभाव पड़ता है। व्यावसायिक संगठन, सरकार, आर्थिक संस्थायें, सामाजिक संगठन, आदि कई तरह की संस्थायें मानव के विचारों को प्रभावित करती है और उसके व्यवहार को भी

प्रभावित करती है क्योंकि मानव कई आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़ा है उनके पूर्वज भी इनसे सम्बन्धित रहे हैं। अत: मानव व्यवहार इनसे प्रभावित हुये बिना नहीं रह सकता है। इसके कारण इसे संस्थागत उपागम भी कहते हैं। सामान्यत: हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के उद्योगों व्यापारिक संगठनों, खेतों आदि आर्थिक गतिविधियों में निर्णयकर्त्ताओं की संख्या कम होती है फिर भी वे स्वतन्त्र रूप से निर्णय नहीं ले पाते हैं बल्कि परम्पराओं, राजनैतिक, आर्थिक संस्थाओं, आस-पास के व्यक्तियों व समुदायों में प्रभावित होते रहते हैं। अत: एक व्यक्ति विशेष के द्वारा लिया गया निर्णय स्वतन्त्र नहीं होता है उस पर प्राकृतिक व सांस्कृतिक दशाओं का प्रभाव पड़ता है। अत: इस उपागम के अनुसार किसी भी क्षेत्र में उपस्थित कोई भी आर्थिक गतिविधि का अध्ययन केवल वर्तमान के सन्दर्भ में करना असंगत है क्योंकि वह आर्थिक गतिविधि वर्तमान के साथ-साथ भूतकाल में बदलती हुई प्राकृतिक व सांस्कृतिक परिस्थितियों में लिए गए निर्णयों पर आधारित होती है। अत: विभिन्न जटिलताओं को समझने के लिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक है।

आर्थिक भूगोल में इस उपागम के अनुसार आर्थिक गतिविधियों की स्थिति का प्रतिरूप कई व्यक्तियों द्वारा लिए गए निर्णयों का परिणाम है। अत: इनका अध्ययन मानव व्यवहार से सम्बन्धित है जो स्वयं भी कई प्राकृतिक व सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होता है। जिसका अध्ययन करने के बाद भावी प्रवृत्तियों का अनुमान लगाया जा सकता है। इस उपागम के अनुसार नियमों की अपेक्षा सामान्य निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं तथा निश्चित भविष्यवाणी तो नहीं की जा सकती है लेकिन भावी प्रवृत्तियों की ओर संकेत किया जा सकता है।

इसके निष्कर्ष मुख्यत: ध्यान पूर्वक लिए गए अकेले निर्णय पर होते हैं जिसको पहले एक व्यक्ति व्यक्त करता है तब उसका सभा, सम्मेलनों में समालोचनात्मक अध्ययन होता है। इस प्रकार इस विधि के निष्कर्ष चकित करने वाले नहीं होते हैं बल्कि ध्यानपूर्वक किये गये विचारों से युक्त होते हैं।

प्र.2. आर्थिक भूगोल के सैद्धान्तिक निगमन उपागम का वर्णन कीजिए।

Describe the Theoretical Deductive Approach of Economic Geography.

उत्तर

सैद्धान्तिक निगमन उपागम
(Theoretical Deductive Approach)

इस उपागम में हम सामान्य सत्य के आधार पर विशिष्ट सत्य की जानकारी करते हैं। इस प्रणाली में मानसिक विश्लेषण द्वारा सामान्य से विशिष्ट की ओर आते हैं। अत: यह तर्क पर आधारित है। कभी-कभी सामान्य सत्य स्वत: सिद्ध होते हैं अत: उनके आधार पर नए नियमों की खोज की जाती है। मनुष्य मरणशील है यह एक सामान्य सत्य है। देवेन्द्र भी एक मनुष्य है इस प्रकार तर्क द्वारा हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि देवेन्द्र भी मरणशील है।

प्रारम्भ में जबकि सांख्यिकी का विकास नहीं हुआ था तब इसी उपागम का अधिक उपयोग होता था। यह उपागम कुछ मान्यताओं और कल्पनाओं के आधार पर तर्क का उपयोग कर निष्कर्ष निकालने में सहायक है। इन मान्यताओं की प्रकृति को पूरी तरह समझ लेने के बाद यह बात स्वीकार कर ली जाती है कि वे विवाद से परे है। रोबिन्स के अनुसार "इनकी सत्यता को स्थापित करने के लिए हमें कोई नियंत्रित प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है ये हमारे दैनिक अनुभव के इतने अभिन्न अंग होते हैं कि उन्हें व्यक्त करते ही पता लग जाता है कि वे सही हैं।"

यह उपागम वैज्ञानिक-विधियों से मिलता-जुलता है इसके अध्ययन का आधार निम्न प्रकार है—

1. निरीक्षण करना, 2. वर्गीकरण करना, 3. स्पष्टीकरण करना, 4. सम्भावनायें व्यक्त करना ।

1. **निरीक्षण करना**—यह कार्य ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा अनुभव करके किया जाता है। यह अनुभव क्षेत्र में जाकर, पुस्तकालयों में उपलब्ध सामग्री जनगणना प्रतिवेदन, मानचित्र व अन्य प्रकाशित सामग्री की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं जो गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। लेकिन इसमें मात्रात्मक (आँकड़े) अधिक महत्त्वपूर्ण होते हैं।
2. **वर्गीकरण करना**—वर्गीकरण का अर्थ है कि जो सूचनायें प्राप्त की गई हैं उन्हें विभाजित किया जाये। लेकिन उनका वर्गीकरण हमारे उद्देश्य से सम्बन्धित होना चाहिये। वर्गीकरण साधारण भी हो सकता है और अधिक गहन भी। लेकिन यह इतना गहन एवं स्पष्ट अवश्य होना चाहिये जिससे कि हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो सके।
3. **स्पष्टीकरण करना**—वैज्ञानिक विधि में यही कार्य सबसे कठिन व महत्त्वपूर्ण होता है। प्राप्त सूचनाओं का स्पष्टीकरण तर्कसंगत होना चाहिये। इसके लिए दृढ़ तर्कसंगत आधार हो लेकिन यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि किसी प्रश्न का कोई एक ही स्पष्टीकरण नहीं होता है। स्पष्टीकरण तभी पूर्ण कहा जा सकता है जबकि स्पष्टीकरण जिस व्यक्ति को दिया

जाता है वह कोई और प्रश्न न करें व संतुष्ट हो जाये। लेकिन स्पष्टीकरण अलग-अलग स्तर के व्यक्तियों के लिए अलग-अलग हो सकता है; जैसे—बच्चे का मस्तिष्क अविकसित होता है अत: उसे किसी प्रश्न का स्पष्टीकरण साधारण शब्दों में व छोटे रूप में दिया जाता है। जबकि युवा और वृद्ध व्यक्ति के सामने स्पष्टीकरण अलग स्तर का होता है।

आर्थिक भूगोल में स्थानीयकरण से सम्बन्धित समस्यायें आती हैं। अत: स्थानीयकरण को स्पष्ट करने के लिए स्थानीयकरण के कारकों का उपयोग करना चाहिये जो कि स्थानिक भिन्नता वाले होते हैं। इसके लिये स्थानिक समानतायें जो सर्वत्र फैली होती है उनको एकत्रित करना बेकार है क्योंकि वे इस प्रकार के स्पष्टीकरण में कोई सहायता नहीं करती हैं।

4. **सम्भावनायें व्यक्त करना**—सम्भावनायें दो प्रकार की हो सकती हैं—
   1. हम निश्चयपूर्वक यह कह सके कि भविष्य में क्या होगा।
   2. भविष्य में होने वाली सम्भावनायें व्यक्त करना।

   लेकिन हम जानते हैं कि क्षेत्रीय सिद्धांतों में मानव व्यवहार महत्त्वपूर्ण है

   अत: हम केवल सम्भावनायें ही व्यक्त कर सकते हैं न कि निश्चयपूर्वक भविष्य वाणी। विभिन्न चरों का चुनाव करने के लिये हमें आवश्यक एवं पर्याप्त दशाओं का ध्यान रखना चाहिये क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि कोई घटना आवश्यक दशायें होने पर पूरी ही घटित होगी लेकिन यह निश्चित है कि उन दशाओं के पर्याप्त न होने पर वह घटना घटित नहीं होगी या दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि पर्याप्त दशायें उपलब्ध हो तो घटना घटित होगी, उदाहरण के लिए, 'अ' के दाढी है इसलिए वह पुरुष है क्योंकि सभी पुरुष दाढ़ी वाले होते हैं। लेकिन यह सत्य नहीं है क्योंकि कुछ औरतों के भी दाढ़ी होती है। अत: 'अ' के लिये एक पुरुष होने के लिए दाढ़ी का होना आवश्यक दशा है लेकिन मात्र मुँह पर बाल बढ़ाने से ही पुरुष नहीं हो जाता, अत: दाढ़ी पर्याप्त दशा नहीं है।

   इसी प्रकार वर्षा के लिये बादलों का होना आवश्यक है लेकिन बादलों के होने से ही वर्षा नहीं हो जाती है। वर्षा के लिये इन बादलों का किसी प्रकार ठण्डा होना भी आवश्यक है तभी वर्षा होगी। अत: वर्षा के लिए बादल अपर्याप्त दशा है। वर्षा बादलों के ठण्डे होने पर ही होगी। अत: बादलों का होना व उनका ठण्डा होना वर्षा के लिए पर्याप्त दशायें हैं।

किसी भी सिद्धान्त के तीन भाग होते हैं—

1. **परिकल्पना** (Hypothesis) से तात्पर्य किसी घटना को स्पष्ट करने के लिये प्रारम्भिक रूप में की गई कल्पना से है जब हम किसी भौगोलिक तथ्य को वैज्ञानिक विधि से तर्कसंगत स्पष्टीकरण द्वारा प्रारम्भिक अनुमान लगाते हैं, इसे परिकल्पना कहते हैं।
2. **मान्यतायें** (Assumptions) ये तर्कसंगत कथन होते हैं या सम्भावित सत्य की दशायें, जिन पर सिद्धांत निर्भर करता है जिससे परिकल्पना को वास्तविक जगत की असंख्य जटिलताओं से हटाकर अधिक स्पष्टता से देखा जा सकता है।
3. **सिद्धांत के निष्कर्ष** (Postulates) जो कि सिद्धांत के अन्तिम निष्कर्ष होते हैं लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि वैज्ञानिक परीक्षण करते समय हमारी मान्यतायें कमजोर से कमजोर व कम से कम हो जिन पर कि सिद्धांत आधारित हैं।

तर्कसंगत कारण अनुमानित होते हैं। अत: परिणाम भी अनुमानित निकलते हैं। जिन्हें बाद में वास्तविक जगत की घटनाओं से परखा जा सकता है। सभी वैज्ञानिक अन्वेषण कुछ सीमा तक अनुमानित परिकल्पनाओं से शुरु होते हैं। सिद्धांतों को समझने के लिए मॉडल्स का उपयोग किया जाता है। यह शब्दों में, गणितीय चिन्हों, रेखाचित्रों, भौतिक या ठोस रूप में हो सकते हैं, कुछ सरल होते हैं कुछ जटिल। अत: वे सिद्धान्त को व्यक्त करने वाले प्रतिरूप होते हैं। मॉडल्स वास्तविक जगत से भी कुछ सम्बन्ध अवश्य रखते हैं, यद्यपि ये वर्तमान वास्तविक जगत से बहुत कम सम्बन्धित होते हैं। लेकिन इन्हें इसके कारण अस्वीकार नहीं करना चाहिये।

संक्षेप में, सैद्धान्तिक उपागम बारीकी से निरीक्षण व उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकरण करता है। यहाँ पर वह वैज्ञानिक विधि अपनाता है और उसका वैज्ञानिक स्पष्टीकरण देने के लिये कुछ मान्यतायें (कल्पनायें) लेता है जो कि वास्तविक जगत की वास्तविकताओं को हटाकर ली जाती है। अत: यह मुख्यत: मान्यताओं या अनुमानों पर निर्भर करता है। इसके अनुसार सम्पूर्ण संसार एक बड़ा मानव व प्रकृति का तन्त्र है जिसमें कई उपतन्त्र फैले हैं। अत: इस मानव व प्रकृति के तन्त्र की जटिलताओं को, व उसमें उत्पन्न स्थानिक प्रतिरूपों को उपतन्त्रों के सम्बन्धों और उनके विश्लेषण से समझना आवश्यक है।

TOUCH 'n PASS

प्र.3. आर्थिक भूगोल का अर्थ व विभिन्न परिभाषाओं का वर्णन कीजिए।
Describe the meaning and different definitions of Economic Geography.

उत्तर

आर्थिक भूगोल का अर्थ
(Meaning of Economic Geography)

भूगोल मानव पर्यावरण सम्बन्धों को स्थानिक एवं क्षेत्रीय संदर्भ में वर्णित करता है। वास्तव में, प्रत्येक क्षेत्र में मानवीय क्रियाओं का विकास इन्हीं अन्तर सम्बन्धों का प्रति फलन है। जो समय एवं स्थान के साथ तथा तकनीकी एवं वैज्ञानिक प्रगति के साथ परिवर्तित होता रहता है। मानव की प्राथमिक आवश्यकता भोजन, वस्त्र और आवास है और उसे पूर्ण करने के लिये निरंतर विकास करता रहता है व जीवन की गुणवत्ता में परिवर्तन करता रहता है।

विविध आर्थिक क्रियाओं के विकास हेतु यह प्रकृति से संघर्ष एवं समायोजन करता है। इसी के प्रतिफल रूप में भौगोलिक परिस्थितियों में जीवन का विकास या दूसरे शब्दों में आर्थिक विकास में भिन्नता है जहाँ एक ओर सम्मुनत् प्रदेश है तो दूसरी ओर प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियों के कारण नितान्त अविकसित क्षेत्र है। इस सम्पूर्ण विविधता का अध्ययन ही भूगोल का विषय क्षेत्र है।

भूगोल का प्रारम्भिक स्वरूप वर्णनात्मक था जिसके अंतर्गत सम्पूर्ण प्राकृतिक व मानवीय क्रियाओं एवं प्रक्रमों का क्षेत्रीय व विश्व व्यापी वर्णन मानचित्रीय स्थिति के संदर्भ में किया जाता रहा है किन्तु शीघ्र ही इसकी दो शाखाओं में विभाजन हो गया।

1. प्राकृतिक भूगोल या भौतिक भूगोल (Physical Geography)
2. मानव भूगोल (Human Geography)

मानव भूगोल के अंतर्गत सम्पूर्ण मानवीय क्रियाओं को भौगोलिक परिवेश में वर्णन किया जाता है जिसमें आर्थिक क्रियायें भी शामिल है। ज्ञान के विस्तार एवं भौगोलिक अध्ययन में विशिष्टीकरण के प्रारम्भ से भूगोलवेत्ताओं ने यह अनुभव किया कि मानव भूगोल में यद्यपि आर्थिक तथ्यों एवं क्रियाओं का वर्णन एवं विश्लेषण किया जाता है किन्तु यह सीमित होता है, यह शोधपरक न होकर कम उपयोगी है। इस कारण आर्थिक भूगोल की एक वृहद् शाखा का विकास हुआ। इसकी अनेक विशिष्ट उप-शाखाओं का निर्माण हुआ।

जैसे—कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, संसाधन भूगोल, परिवहन भूगोल, विपणन भूगोल।

अत: स्पष्ट है कि आर्थिक भूगोल, भूगोल की अविभाजित शाखा है जो अपने काल में सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाओं को समेटे हुये है। आर्थिक भूगोल की उपयोगिता अत्यधिक है क्योंकि यह मात्र ज्ञान का स्रोत नहीं अपितु आर्थिक विकास एवं नियोजन का पथ प्रदर्शक है।

परिभाषाएँ (Definitions)

आर्थिक भूगोल का सूत्रपात 18वीं सदी के उत्तरार्द्ध से हुआ था तथा इसका प्रारम्भिक स्वरूप वाणिज्य भूगोल (Commercial geography) के रूप में हुआ। सर्वप्रथम 1882 में जर्मन विद्वान गोत्य (Gatz) ने आर्थिक भूगोल शब्दावली का प्रयोग कर आर्थिक भूगोल को परिभाषित किया।

"संसार के विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादन पर पड़ने वाले प्रत्यक्ष प्रभाव के वैज्ञानिक अन्वेषण को आर्थिक भूगोल कहते हैं"। इस प्रकार आर्थिक भूगोल एक स्वतंत्र शाखा के रूप में विकसित होता हुआ वर्तमान में एक वटवृक्ष का रूप ले चुका है। इसकी विभिन्न भूगोलवेत्ताओं द्वारा निम्न परिभाषाएँ दी गई हैं—

1. **मर्फी के अनुसार**, "आर्थिक भूगोल का सम्बन्ध स्थान-स्थान की उन समानताओं और विविधताओं से है,"
   मर्फी ने उन भौगोलिक परिस्थितियों की ओर इंगित किया है जिनसे जीवन अर्थात् आर्थिक क्रियाकलाप विकसित होते हैं। यह सर्वविदित है कि विश्व में कहीं कृषि की प्रधानता तो कहीं पशुपालन है, एक ओर खनिज खनन है तो दूसरी ओर औद्योगिक विकास। आज भी विश्व के कतिपय भागों में आर्थिक विकास अवरूद्ध है: जैसे—विषुवत्त रेखीय प्रदेश, टुण्ड्रा प्रदेश, उच्च पर्वतीय प्रदेश, अण्टार्कटिका आदि, क्योंकि यहाँ भौगोलिक परिस्थितियाँ मानव विकास एवं आर्थिक विकास के प्रतिकूल है। विश्व के विभिन्न भागों में धरातल, भूगर्भ बनावट, जलवायु प्राकृतिक वनस्पति, मृदा आदि में जहाँ एक ओर समानता है उनमें विविधता भी पर्याप्त है। इसी कारण विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में मानवीय व्यवसाय अथवा जीवन भिन्न है। आर्थिक भूगोल इन्हीं भिन्नता समानताओं का तार्किक विश्लेषण का भविष्य के विकास का मार्ग प्रदर्शित करता है।

TOUCH 'n' PASS

2. **आर०एन० ब्राउन के अनुसार**, "आर्थिक भूगोल, भूगोल शास्त्र का वह भाग है जो मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं पर उसकी जैविक एवं अजैविक पर्यावरण के प्रभावों का अध्ययन करता है।"
परिभाषा से स्पष्ट है कि पर्यावरण मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं को नियन्त्रित करता है। पर्यावरण के जैविक तत्त्व; जैसे—वनस्पति, जीव जन्तु तथा अजैविक तत्त्व; जैसे—उच्चावच, जलवायु, भूगर्भिक बनावट, मृदा आदि सामूहिक रूप से आर्थिक क्रियाओं को विकसित करने में सक्रिय भूमिका निभाती है। इसी कारण नदियों के मैदानी भाग; जैसे—गंगा, सिंधु, इरावदी, नील आदि में कृषि का विकास हुआ। न्यूजीलैण्ड तथा डेनमार्क जैसे देशों की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का योगदान है। पर्यावरण के प्रतिकूल होने पर अमेजन बेसिन, सहारा का मरुस्थल, साइबेरिया, ग्रीनलैण्ड, अंटार्कटिका आदि में वर्तमान वैज्ञानिक तकनीकी विकास के उपरांत भी आर्थिक विकास नहीं हो पाया है। आर्थिक भूगोल विकास के कारकों एवं उसके बाधक कारकों का सम्पूर्ण विश्लेषण विश्व व्यापी परिवेश में करता है।
3. **शाह के अनुसार**, "आर्थिक भूगोल विश्व के मानव जीवन के विकास के परिचायक के रूप में प्राथमिक संसाधनों और औद्योगिक वस्तुओं के संदर्भ में जीवनयापन की समस्याओं से सम्बन्धित है।"
शाह ने विश्व में मानव जीवन के विकास के परिचायक के रूप में प्राथमिक संसाधनों जिनमें प्राकृतिक जैविक एवं आर्थिक संसाधन सम्मिलित हैं, को माना है। इसी संदर्भ में, उन्होंने उद्योग एवं औद्योगिक उत्पादों को विशेष रूप से रेखांकित किया है। सामूहिक रूप से संसाधन एवं उद्योग आर्थिक प्रगति एवं जीवन की गुणवत्ता से नियंत्रक एवं निर्धारक है तथा आर्थिक भूगोल इनका पूर्ण, विवरण के साथ उस समस्याओं को भी इंगित करता है।
4. **वाई०जी० साँराकिन के अनुसार**, "आर्थिक भूगोल समाज के विकास के साथ विकसित हुए क्षेत्रीय व्यवस्थाओं को वर्णित करता है इन वास्तविक क्षेत्रीय गतिविधियों में भी सम्बन्धित है जो साथ की उत्पादन एवं सामाजिक क्रियाओं से जुड़ी हुई है।"
5. **सी०एफ० जोन्स के अनुसार**, "मनुष्य के उत्पादक उद्यमों एवं उनकी उपजों के वितरण से उसकी परिस्थिति के प्राकृतिक तत्त्वों का आर्थिक दशाओं के सम्बन्ध का अध्ययन आर्थिक भूगोल है।"
6. **बैंगस्टन तथा रोयन के अनुसार**, "आर्थिक भूगोल विश्व के विभिन्न भागों के मूलभूत साधनों एवं प्रधान उत्पादक क्रियाओं की विशेषताओं का अनुसंधान करता है और वह मूलभूत साधनों के उपयोग पर प्राकृतिक परिस्थितियों की विभिन्नताओं के प्रभावों का मूल्यांकन करता है।"
7. **अलेक्जेण्डर तथा गिन्सन के अनुसार**, "मानव की उत्पादक, विनिमय एवं उपभोक्ता से सम्बन्धित क्रियाओं का पृथ्वी तल पर क्षेत्रीय वितरण का अध्ययन आर्थिक भूगोल है।"

ये सभी परिभाषायें आर्थिक भूगोल के सम्पूर्ण परिवेश को समाहित करती है। आर्थिक क्रियाओं में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण क्रिया उत्पादन है जिसमें कृषि उत्पादन, खनिज औद्योगिक उत्पादन आदि सभी सम्मिलित होते हैं। उत्पादन के पश्चात् उत्पादित वस्तु को उपभोक्ता तक पहुँचाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है, परिवहन वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ तक विनिमय होता है। यह क्रिया स्थानीय, क्षेत्रीय विपणन केन्द्र जहाँ व्यापारिक गतिविधियाँ सम्पन्न होती है ये क्रियायें प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न हो सकती है। अत: आर्थिक भूगोल सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाओं को भौगोलिक पर्यावरण के सामन्जस्य के साथ प्रस्तुत करता है। कुछ अन्य परिभाषायें भी निम्न प्रकार है जिसमें आर्थिक भूगोल का विश्लेषण किया गया है—

लॉयड और डिकन के अनुसार, "अर्थव्यवस्था के स्थानिक आयाम से सम्बन्धित व्यावहारिक विज्ञान के रूप में आर्थिक भूगोल ऐसे सामान्य नियमों एवं सिद्धांतों की रचना से सम्बन्धित है जो अर्थव्यवस्था के परिचालन की व्याख्या करती है।"

होडर और ली ने अपनी पुस्तक Economic Geography में आर्थिक भूगोल की मूल प्रकृति को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि "आर्थिक भूगोल सामान्यत: अर्थव्यवस्था के क्रियान्वयन से भिन्न तत्त्वों से सम्बन्धित रहा है। इन तत्त्वों के व्यवहार एवं अर्न्तसम्बन्ध के प्रचलित वितरण के प्रभाव से सम्बन्धित है।"

भूगोल के ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार, "आर्थिक भूगोल संसाधनों वस्तुओं और सेवाओं के परिवहन एवं उपयोग तथा उनके भूदृश्य पर प्रभाव के स्थानिक वितरण का विश्लेषण करता है।"

प्र.4. आर्थिक भूगोल की अभिनय प्रवृत्तियों का विस्तार से विवरण दीजिए।
Give a detailed description of recent trends in Economic Geography.

उत्तर

आर्थिक भूगोल की अभिनय प्रवृत्तियाँ
(Recent Trends in Economic Geography)

भूगोल की प्रकृति, विषय क्षेत्र, अध्ययन विधि आदि अत्यधिक परिवर्तनशील नहीं है क्योंकि आर्थिक भूगोल मानव की सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाओं का भौगोलिक परिवेश में अध्ययन करता है। सामान्य वर्णन एवं विश्लेषण के साथ आज आर्थिक भूगोल में आर्थिक विकास के विभिन्न आयामों, व्यावहारिक समस्याओं एवं आर्थिक नियोजन का न केवल अध्ययन किया जाता है अपितु विकास की सम्भावनाओं का भी पता लगाया जाता है। आर्थिक भूगोल की नवीन प्रवृत्तियाँ निम्न प्रकार हैं—

1. **अन्तर विषयी प्रकृत्ति का विकास** (Development of Interdisciplinary Nature)—भूगोल में अन्तर विषयी प्रकृति सदैव से ही रही है किन्तु आर्थिक भूगोल में विगत चार या पाँच दशकों से इस प्रवृत्ति का अधिक विकास हुआ है। इससे सामाजिक एवं प्राकृतिक विज्ञानों का समावेश ही रहा है। आर्थिक भूगोल में सर्वाधिक अर्थशास्त्र के नवीन तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है। उत्पादन, विनिमय तथा उपभोग से सम्बन्धित सिद्धांत जो अर्थशास्त्र में अध्ययन किये जाते थे, आज आर्थिक भूगोल में प्रमुखता से लिये जाते हैं। इसी प्रकार प्राकृतिक तथ्यों का अध्ययन करते समय वनस्पति विज्ञान, जैव विज्ञान व पर्यावरण विज्ञान, जलवायु विज्ञान आदि की सहायता ली जाती है। आर्थिक भूगोल की प्रकृति में इस परिवर्तन के कारण इसका स्वरूप व्यावहारिक बहुत हो गया है।
2. **विशिष्टीकरण** (Specialisation)—आर्थिक भूगोल में वर्तमान में अत्यधिक विशिष्टीकरण हो गया है जो इसके विकास व निरन्तर विकसित होने की प्रवृत्ति का परिचायक है। आर्थिक भूगोल की विभिन्न शाखायें, कृषि भूगोल, संसाधन भूगोल, परिवहन भूगोल, विपणन भूगोल, व्यापारिक भूगोल, पर्यटन भूगोल आदि विकसित हुये हैं जो इसमें हो रहे विशिष्टीकरण का परिचायक है। इस विकास से आर्थिक भूगोल का क्षेत्र न केवल व्यापक हुआ है अपितु बहुत उपयोगी हो गया है। आर्थिक भूगोल विशिष्टीकरण के कारण एक गतिशील विषय बन गया है। इस प्रकार आर्थिक भूगोल, भूगोल की सर्वाधिक विकसित शाखा बन गया है।
3. **अर्थव्यवस्था के पर्यावरणीय सम्बन्धों का अध्ययन** (Study of Environment Relation of the Economy)—प्रत्येक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का निर्धारण वहाँ का पर्यावरण करता है और वह पारिस्थितिकी का अंग होता है। आर्थिक भूगोल पर्यावरणीय भूगोल का (तत्त्वों का) आर्थिक क्रियाओं पर प्रभाव तथा इसके विपरीत आर्थिक क्रियाओं का पर्यावरण पर प्रभाव का अध्ययन कर विकास की नई दिशा का मार्ग प्रशस्त करता है।
4. **स्थानिक (क्षेत्रीय) प्रारूप** (Spatial Pattern)—भूगोल में स्थानिक स्वरूप विवेचन सभी शाखाओं में प्रचलित है। लाँश द्वारा विकास का क्षेत्रीय प्रारूप मॉडल के लिए केन्द्रीय स्थल सिद्धांत तथा आर्थिक भूदृश्य न केवल वर्तमान तक चर्चा में है अपितु इसको विकसित किया गया है। अर्थव्यवस्था का भौगोलिक स्वरूप के अन्तर्गत अर्थव्यवस्था का सामान्य मॉडल तथा अर्थव्यवस्था का स्थानिक मॉडल भी इसी दिशा को इंगित करता है।
5. **बाजारोन्मुखी अर्थतंत्र का अध्ययन एवं विपणन भूगोल का विकास** (Study of Market-oriented Economy and Development of Distribution Geography)—आधुनिक अर्थतन्त्र का एक प्रमुख पहलू है इसका बाजारोन्मुखी होना। बाजार अथवा विपणन केन्द्र वे स्थल होते हैं, जहाँ उत्पादक एवं उपभोक्ताओं का मिलन होता है तथा विपणन के माध्यम से वस्तुओं का क्रय-विक्रय होता है।
   बाजार केन्द्र एवं व्यापारिक तथा विपणन केन्द्रों के आर्थिक भूगोल में महत्त्वपूर्ण होने के कारण ही विपणन भूगोल का विकास हुआ। वर्तमान में विपणन भूगोल आर्थिक भूगोल की तरह शाखा है अनेक भूगोलवेत्ताओं; जैसे— बी०जे०एल० बेरी, आर०एच०टी० स्मिथ, बी०डब्ल्यू० होडर, बी०जे० ग्रार्नियर, आर०एल० डेविस पीटरस्कॉट भारत के पी०के० श्रीवास्तव, एच०एम०, बी०जी० तानस्कर आदि ने इसको विकसित किया।
   विपणन भूगोल ने आर्थिक भूगोल में अनेक नवीन् तथ्यों का समावेश किया है तथा इसकी अभिनय प्रवृत्तियों को नवीन् दिशा दी है।
6. **कृषि विकास के भौगोलिक अध्ययन में नवीन् पक्ष** (New Aspects in Geographical Study of Agricultural Development)—आर्थिक भूगोल में कृषि का महत्त्वपूर्ण पक्ष है। कृषि उपजों का उत्पादन, वितरण प्रकार के अतिरिक्त विगत् दशकों में कृषि से सम्बन्धित अनेक नवीन् विषयों को आर्थिक भूगोल में सम्मिलित किया गया

है; जैसे—शस्य संयोजन, फसलीय सघनता एवं उत्पादकता, कीटनाशकों का कृषि पर प्रभाव, कृषि प्रदेशों को निर्धारण आदि जे. कोस्ट्रोविकी द्वारा प्रस्तुत "Agricultural Typology" ने कृषि प्रकारों के अध्ययन को नवीन् दिशा दी है।

7. **परिवहन भूगोल में नवीन प्रवृति** (New Trends in Gransport Geography)—परिवहन भूगोल का आर्थिक भूगोल की शाखा के रूप में विकास हुआ है, साथ ही इसने आर्थिक भूगोल को नवीनता भी प्रदान की है। परिवहन प्रवेश्यता, संयोजकता, आवागमन प्रारूप, परिवहन लागत परिवहन नियोजन आदि के माध्यम से परिवहन के विशिष्ट पक्षों को स्पष्ट किया जाता है।
8. **उद्योगों की उपस्थिति एवं स्थानीयकरण का अध्ययन** (Study of Industrial Location and Their Localisation)—औद्योगिक भूगोल के विकास के साथ उद्योगों से सम्बन्धित नवीन पत्र पर जोर दिया गया। अल्फेड बेवर, टार्ड फवंडर का बाजार क्षेत्र सिद्धांत, मेलबिन ग्रीनहर का अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धांत, फलेटर का बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत, हूबर का न्यूनतम लागत का सिद्धांत, वाल्टर इकाई का स्थानीयकरण का सिद्धांत आदि ने आर्थिक भूगोल में उद्योगों के अध्ययन को नवीन दिशा प्रदान की।
9. **सांख्यिकी विधियों का प्रयोग** (Application of Statistical Techniques)—आर्थिक भूगोल में 1980 के दशक के बाद से ही सांख्यिकीय विधियों का प्रचलन तीव्रता से होने लगा है। विलियन गेरीसन, बेन बेरी, विलियन वानिट्ज के साथ अमेरिकी, ब्रिटिश एवं स्वीडिश भूगोलवेत्ताओं ने इसकी पृष्ठभूमि तैयार की विनियम बुंगे ने गणितीय भूगोल का स्वरूप प्रदान किया है।
10. **विकास की नवीन अवधारणायें** (New Concepts of Development)—आर्थिक विकास किसी भी देश अथवा प्रदेश की प्राथमिकता होती है। यद्यपि आर्थिक विकास का सामान्य रूप में आर्थिक भूगोल में अध्ययन किया जाता रहा है। इसे निम्न प्रकार द्वारा भी समझ सकते हैं—

    (अ) सतत् विकास की अवधारणा, (ब) आर्थिक विकास और जीवन की गुणवत्ता, (स) समग्र विकास।

    (अ) **सतत् विकास** (Sustainable Development)—विकास ऐसा होना चाहिए जिससे पर्यावरण संतुलन बना रहे। दूसरे शब्दों में, विनाशरहित विकास औद्योगिकीरण, प्रौद्योगिक विकास, परिवहन तंत्र का विकास, कृषि में कीटनाशकों का प्रयोग संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन आदि विकास द्वारा पर्यावरण न केवल प्रदूषित होता है अपितु पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित होता जा रहा है, यह मानव अस्तित्व के लिए भी खतरा है।

    (ब) **आर्थिक विकास और जीवन की गुणवत्ता** (Economic Development and Quality of Life)—विकास का उद्देश्य मानव के जीवन को सुख-सुविधायें प्रदान करना है जिससे उसका जीवन सुखी हो सके। उपभोक्ता वादी संस्कृति से संसाधनों का दोहन हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और उसका प्रतिकूल प्रभाव न केवल मानव अपितु सम्पूर्ण मानव जाति पर पड़ रहा है। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए आर्थिक भूगोल में विकास के साथ जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने पर बल दिया जाता रहा है।

    (स) **समग्र विकास** (Holistic Development)—आर्थिक विकास की वर्तमान अवधारणा में समग्र विकास होना चाहिए। कभी-कभी किसी एक क्षेत्र का विकास एक तरफा हो जाता है। विकास में कृषि, खनिज, उद्योग, परिवहन, विपणन व्यापार के साथ नगरीय एवं ग्रामीण विकास होना आवश्यक है। आर्थिक भूगोल में समग्र विकास के तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है।

अन्य प्रवृत्तियाँ (Other Trends)—आर्थिक भूगोल में नवीन क्षेत्र निम्न हैं—

1. निर्णय लेने की प्रक्रिया के अन्तर्गत, प्रकृति, प्रक्रिया परिभाषित करने वाले तथ्यों तथा विधि का अध्ययन।
2. उत्पादन लागत के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करना।
3. गुरुत्व मॉडल के प्रयोग से औद्योगिक उपस्थिति का विश्लेषण करना।
4. व्यवहारात्मक दृष्टिकोण का अध्ययन।
5. दूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना तंत्र।
6. सम्पूर्ण तथ्यात्मक एवं सैद्धांतिक विश्लेषण करना।

TOUCH 'n PASS

प्र.5. आर्थिक भूगोल में अर्थव्यवस्था की स्थानिक संरचना का वर्णन कीजिए।
Describe the Spatial Structure of the Economy in Economic Geography.

उत्तर

अर्थव्यवस्था की स्थानिक संरचना
(Spatial Structure of the Economy)

आर्थिक भूगोल में स्थानिक पक्ष का विशेष महत्त्व है। इसकी प्रमुख समस्या सीमांकन की है क्योंकि उत्पत्ति वस्तु स्थानीय क्षेत्रीय राष्ट्रीय भाषा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में जाती है। सम्पन्न देश अन्य देशों के संसाधनों को लेने में समर्थ है। विश्व अर्थव्यवस्था एकरूपता युक्त बंद हो सकती है, किंतु अर्थव्यवस्था विभिन्न स्थानिक इकाइयों में विभक्त होती है तथा उनमें अंतर सम्बन्ध होता है। स्थानिक संरचना के दो पक्ष कार्यात्मक एवं एकांगी होते हैं। स्थानिक अर्थव्यवस्था के केन्द्र वृहद नगर एवं केन्द्रीय क्षेत्र होते हैं। एक क्षेत्र के प्रत्येक भाषा में आर्थिक क्रियाओं का समग्र विकास होता है तो उनमें अंतर क्रिया न्यूनतम होती है। किन्तु यदि एक क्षेत्र में उद्योग एक पशुपालन तो एक में खनिजों का विकास हुआ है। जब कुछ उनमें समन्वय एवं पूरकता नहीं होगी। अर्थव्यवस्था विकसित नहीं होगी। यदि पूर्ण विशिष्टीकरण नहीं होता तो क्षेत्रीय सम्बन्धों के साथ प्रत्येक का एक क्षेत्र विकसित हो जाता है।

अर्थव्यवस्था की स्थानिक संरचना

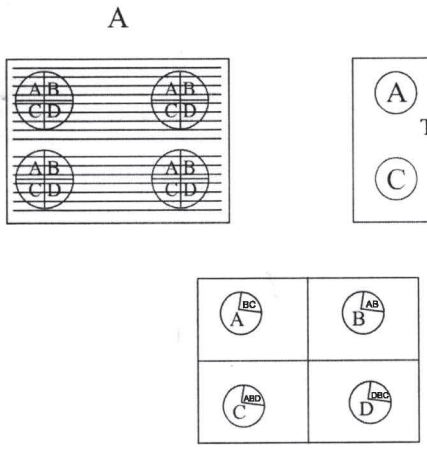

अर्थव्यवस्था की स्थानिक संरचना एवं स्थितिगत विशिष्टता

(अ) इसे बंद अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है इसके अंतर्गत प्रत्येक नगर प्रदेश अपनी-अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है, अर्थव्यवस्था के चार प्रमुख खण्ड को A, B, C तथा D द्वारा अंकित किया गया है। वस्तुओं और सेवाओं का आपसी विनिमय होता है जो उनके क्षेत्रीय प्रभाव क्षेत्र में सीमित है। एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश में आदान प्रदान नहीं है तथा प्रत्येक दिशा अलग अर्थव्यवस्था युक्त है।

(ब) दूसरा आरेख खुली अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करता है। यह एक-दूसरे के पूरक हैं तथा सम्पूर्ण प्रदेश उनका पृष्ठप्रदेश है जिसमें आपस में कोई अवरोध नहीं है। इस व्यवस्था से आर्थिक विशेषीकरण अधिक लाभप्रद होता है।

(स) यह आरेख मिश्रित अर्थव्यवस्था को दर्शाता है इसके अंतर्गत विशिष्टता का विकास हुआ है इसलिये ये एक-दूसरे के पूरक है। इनके माध्यम से विश्व के देशों की अर्थव्यवस्था का भी **विश्लेषण** किया जा सकता है।

आर्थिक क्रियाएँ (Economic Activities)

आदिकाल से ही मानव अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य क्रियायें करता रहता है जो अन्य आवश्यकतायें; जैसे—खाना पीना, सामाजिक व्यवस्थायें पूर्ण करता है। मानव प्रारम्भ से ही अपने को ऊँचा उठाने का प्रयास करता आ रहा है अर्थात् विकास की ओर अग्रसर है। इसी प्रकार मानव ने कई प्रकार के उद्यमों का विकास किया और विकास के साथ-साथ क्रियाओं का विस्तार करता गया।

आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन आर्थिक भूगोल का प्रमुख पक्ष है। आर्थिक क्रियायें भी अनेक प्रकार की होती हैं। आर्थिक भूगोल में आर्थिक क्रियाओं को महत्त्व दिया जाता है।

आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण (Classification of Economies Activities)—आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण निम्न प्रकार हैं—

प्राथमिक आर्थिक क्रियायें—इन क्रियाओं के अंतर्गत मनुष्य की प्रारम्भिक क्रियाओं को रखा जाता है; जैसे—कृषि करना, पशु पालन, आखेट करना, मत्स्य पालन। आदिकाल से ही मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये इन सभी क्रियाओं को पूर्ण करता चला आ रहा है।

द्वितीयक आर्थिक क्रियायें—इसके अंतर्गत उत्पादन जैसी क्रियायें हैं जो प्राकृतिक संसाधनों में परिवर्तन कर उपयोग की जाती हैं। इसके अंतर्गत खनन उद्योग, व्यापारिक, कृषि, पशु-चारण आदि शामिल हैं।

तृतीयक आर्थिक क्रियायें—वे क्रियायें प्राथमिक व द्वितीयक क्रियाओं से भिन्न हैं। इसमें परिवहन, व्यापार, बैंकिंग, संचार के साधन कारखाने, लेखाकार, प्रबन्धक आदि तृतीयक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं।

चतुर्थ वर्ग की आर्थिक क्रियायें—शिक्षक, चिकित्सक, वकील, इंजीनियर आदि के कार्य इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं।

पंचम वर्ग की आर्थिक क्रियायें—यह क्रियायें अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा उत्पन्न होती है जो सलाह के द्वारा की जाती है। कानून व प्राविधिक, वैज्ञानिक, शोध-प्रबंध सम्बन्धी होती है।

क्रियायें (Activities)

अर्थव्यवस्था में कच्चे माल को कारखाने तक तथा उत्पादित माल को उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के लिये सभी क्रियाओं को सम्पन्न कराया जाता है। एलेक्जेंडर और गिल्सन ने अपनी पुस्तक Economic (Geography) 1975 में आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण आरेख द्वारा प्रस्तुत किया—

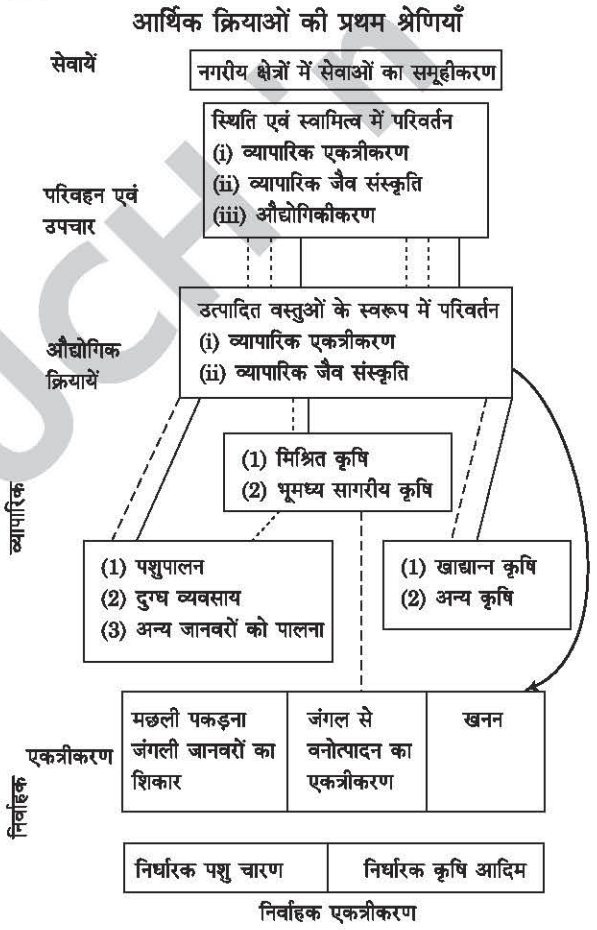

TOUCH 'n PASS

मानव की प्रमुख आर्थिक क्रियाओं को विकास के रूप में वर्णित किया गया है। ये तथ्य सामान्य परिकल्पना द्वारा वर्णित किये गये हैं।

1. क्षेत्र में निम्न स्तरीय व्यापारिक विकास होने पर कृषि, मछली पालन एवं वनोत्पादन से अधिक अनुपात में लोग लगे होते हैं।
2. व्यापारीकरण के स्तर में वृद्धि के अनुपात में उपर्युक्त तीनों क्रियायें कम होने लगती हैं तथा व्यापार एवं परिवहन में क्रियाओं में वृद्धि होती है।
3. जैसे-जैसे व्यापारिक स्तर में और अधिक वृद्धि होकर तृतीय स्तर पर पहुँच जाती हैं तो औद्योगिक विकास अधिक होता जाता है।
4. अधिक व्यापारिक विकास और तीव्र गति से सेवाओं का विस्तार होता जाता है जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का उच्चतर विकास होता जाता है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्र.1. आर्थिक भूगोल को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया?
(क) मर्फी (ख) गोत्य (ग) लॉयड (घ) डिकन

उत्तर (ख) गोत्य

प्र.2. "मनुष्य के उत्पादक उद्यमों एवं उनकी उपजों के वितरण से उसकी परिस्थिति के प्राकृतिक तत्त्वों का आर्थिक दशाओं के सम्बन्ध का अध्ययन आर्थिक भूगोल है"। यह कथन किसका है?
(क) मर्फी (ख) लॉयड (ग) सी०एस० जोन्स (घ) रोयन

उत्तर (ग) सी०एस० जोन्स

प्र.3. प्रत्येक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का निर्धारण करता है-
(क) वहाँ का क्षेत्रफल (ख) वहाँ की जनसंख्या (ग) वहाँ का पर्यावरण (घ) वहाँ का तापमान

उत्तर (ग) वहाँ का पर्यावरण

प्र.4. निम्नलिखित में कौन आर्थिक भूगोल के उपागम नहीं है?
(क) तथ्यात्मक उपागम (ख) वस्तुनिष्ठ उपागम (ग) प्रादेशिक उपागम (घ) इनमें से कोई नहीं

उत्तर (घ) इनमें से कोई नहीं

प्र.5. वर्गीकरण का अर्थ है सूचनाओं को-
(क) संकलित करना (ख) विभाजित करना (ग) फैलाना (घ) इनमें से कोई नहीं

उत्तर (ख) विभाजित करना

प्र.6. सैद्धान्तिक निगमन उपागम के अध्ययन का आधार निम्न में से नहीं है-
(क) निरीक्षण करना (ख) वर्गीकरण करना (ग) स्पष्टीकरण करना (घ) मूल्यांकन करना

उत्तर (घ) मूल्यांकन करना

प्र.7. आर्थिक भूगोल में सिद्धान्तों को समझने के लिए किसका उपयोग किया जाता है?
(क) मॉडल्स (ख) कल्पनाएँ (ग) वर्गीकरण (घ) इनमें से कोई नहीं

उत्तर (क) मॉडल्स

प्र.8. "आर्थिक भूगोल विश्व के मानव जीवन के विकास के परिचायक के रूप में प्राथमिक संसाधनों और औद्योगिक वस्तुओं के संदर्भ में जीवनयापन की समस्याओं से सम्बन्धित है।" कथन किसका है?
(क) वाई०जी० साँराकिन (ख) बैंगस्टन (ग) शाह (घ) रोयन

उत्तर (ग) शाह

प्र.9. पुस्तक Economic Geography किसके द्वारा लिखी गई?
(क) होडर और ली (ख) बैंगस्टन और रोयन (ग) सी०एफ० जोन्स (घ) इनमें से कोई नहीं

उत्तर (क) होडर और ली

TOUCH 'n PASS

प्र.10. आर्थिक क्रियाओं में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण क्रिया है–
(क) परिवहन (ख) विनिमय (ग) उत्पादन (घ) विपणन
उत्तर (ग) उत्पादन

प्र.11. आर्थिक भूगोल सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाओं को ..... के सामन्जस्य के साथ प्रस्तुत करता है।
(क) सन्तुलन (ख) आवश्यकता (ग) भौगोलिक पर्यावरण (घ) माँग
उत्तर (ग) भौगोलिक पर्यावरण

प्र.12. ''अर्थव्यवस्था के स्थानिक आयाम से सम्बन्धित व्यावहारिक विज्ञान के रूप में आर्थिक भूगोल ऐसे सामान्य नियमों एवं सिद्धान्तों की रचना से सम्बन्धित है जो अर्थव्यवस्था के परिचालन की व्याख्या करती है।'' यह कथन किसके द्वारा दिया गया?
(क) लॉयड (ख) डिकन (ग) दोनों (क) एवं (ख) (घ) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (ग) दोनों (क) एवं (ख)

प्र.13. ऐसा विकास जिसमें पर्यावरण संतुलन बना रहता है, होता है–
(क) समग्र विकास (ख) सतत् विकास (ग) दोनों (क) एवं (ख) (घ) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (ख) सतत् विकास

प्र.14. स्थानिक संरचना के कितने पक्ष होते हैं?
(क) दो (ख) तीन (ग) चार (घ) पाँच
उत्तर (क) दो

प्र.15. निम्न में से कौन-सी क्रिया मनुष्य की प्रारम्भिक क्रियाओं में सम्मिलित नहीं है?
(क) पशु पालन (ख) मत्स्य पालन (ग) खनन उद्योग (घ) आखेट करना
उत्तर (ग) खनन उद्योग

प्र.16. निम्न में से कौन द्वितीयक वर्ग की आर्थिक क्रिया नहीं है?
(क) कृषि (ख) पशु-चारण (ग) खनन उद्योग (घ) मत्स्य पालन
उत्तर (घ) मत्स्य पालन

प्र.17. निम्न में से कौन-सी सैद्धान्तिक व संस्थागत उपागमों में समानता है?
(क) वर्णन (ख) मापदण्ड (ग) वर्गीकरण (घ) ये सभी
उत्तर (घ) ये सभी

प्र.18. सैद्धान्तिक उपागम की विशेषता है–
(क) कम खर्चीली (ख) आगमन विधि की सहायक
(ग) अनुमान लगाने में उपयुक्त (घ) ये सभी
उत्तर (घ) ये सभी

प्र.19. चिशोम का वाणिज्य भूगोल कब प्रकाशित हुआ था?
(क) 1880 (ख) 1885 (ग) 1889 (घ) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (ग) 1889

प्र.20. ''मानव की उत्पादक, विनिमय से सम्बन्धित क्रियाओं का पृथ्वी तल पर क्षेत्रीय वितरण का अध्ययन आर्थिक भूगोल है।'' यह कथन किसका है?
(क) रोयन (ख) बैंगस्टन (ग) अलेक्जेण्डर व गिन्सन (घ) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (ग) अलेक्जेण्डर व गिन्सन

TOUCH n' PASS

UNIT-II

संसाधन : अर्थ, अवधारणा, वर्गीकरण एवं विपणन

Resource : Meaning, Concept, Classification and Distribution

खण्ड-अ अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. जिमरमैन के अनुसार आर्थिक भूगोल के संसाधन को परिभाषित कीजिए।

Define Resources of Economic Geography by Zimmermann.

उत्तर जिमरमैन के अनुसार, "संसाधन कोई वस्तु या पदार्थ नहीं है, बल्कि वह प्रकार्य है जिसे कोई वस्तु या पदार्थ मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकता है।"

प्र.2. खनिज संसाधन से आप क्या समझते हैं?

What do you understand by mineral resources?

उत्तर वर्तमान औद्योगिक युग में खनिज पदार्थ किसी देश की सम्पन्नता तथा आर्थिक विकास की आधारशिला हैं। खनिजों के अन्तर्गत वे सब पदार्थ सम्मिलित हैं जो खनन क्रिया से प्राप्त होते हैं। वैज्ञानिक रूप से खनिज अजैविक पदार्थ हैं जिनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। अधिकांश खनिज दो तत्त्वों से निर्मित होते हैं। (हीरा तथा कार्बन इसका अपवाद है)। खनिजों को दो वर्गों में रखा जाता है—1. धातुएँ तथा अधातुएँ। **धात्विक** खनिजों के चार प्रकार (लौहांस, लौह मिश्र, अलौहांस तथा बहुमूल्य) होते हैं। **अधात्विक** खनिजों में—1. खनिज ईंधन, 2. खनिज उर्वरक, 3. रत्न जवाहरात तथा 4. भू-द्रव्य (Earth material) सम्मिलित हैं।

प्र.3. ऊर्जा संसाधन के महत्त्व पर प्रकाश डालिए।

Throw light on the importance of Energy Resources.

उत्तर शक्ति के साधन को ऊर्जा संसाधन भी कहा जाता है। ऊर्जा आधुनिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। ये आर्थिक क्रियाओं के लिए अनिवार्य हो गई है। किसी भी देश के औद्योगिक, कृषि, यातायात के विकास के लिए ऊर्जा अर्थात् शक्ति के साधनों की आवश्यकता होती है। शक्ति के साधनों को ही आधुनिक युग में आधार माना जाता है। यह आर्थिक विकास का सूचक होता है। अत: जिन संसाधनों का प्रयोग करके हम मशीनों को चलाते हैं, यातायात के साधनों को गति प्रदान करते हैं, कृषि को यांत्रिक बनाते हैं, घरेलू कार्यों में उपयोग करते हैं, उन्हें ऊर्जा संसाधन कहा जाता है। इसके अभाव में आर्थिक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है।

प्र.4. वन को 'अनुपम संसाधन' क्यों कहा गया है?

Why is forest called Matchless Resource?

उत्तर वन राष्ट्रीय सम्पत्ति है। एक महत्त्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन है। इससे तापमान में कमी और वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। जिससे जलवायु अनुकूल बनी रहती है। वनों से भूमि कटाव कम होता है और नदियों में जल प्रवाह सामान्य बना रहता है। पशु पक्षियों के लिए आवास, चारा और प्राकृतिक वातावरण प्राप्त होता है। वनों से ईंधन, इमारती लकड़ियों के अतिरिक्त उद्योगों के लिए कच्चा माल की प्राप्ति होती है। वन से हमें फल-फूल, कंद-मूल तथा औषधियों की प्राप्ति होती है। जीवन में वनों से अनेकों प्रकार के लाभ उठाते हैं। इसलिए वन को 'अनुपम संसाधन' कहा गया है।

TOUCH 'n' PASS

प्र.5. मानव किन गुणों के कारण सभी प्राकृतिक संसाधनों के मूल्य में परिवर्तन लाता है?
Due to which qualities human beings changes in the value of all Natural Resources?

उत्तर मनुष्य अपनी बुद्धि, प्रतिभा, क्षमता, तकनीकी ज्ञान और कार्य-कुशलता जैसे गुणों का प्रयोग करके प्राकृतिक संसाधनों के मूल्य में परिवर्तन लाता है। मानव अपने साहस, संघर्षशीलता, ज्ञान और सूझबूझ का प्रयोग कर संसाधनों के मूल्यों में परिवर्तन लाता है; जैसे—छोटानागपुर के खनिज भंडार का युगों तक कोई महत्त्व था। उसका कोई मूल्य न था परन्तु जब खनिजों का महत्त्व समझ में आया। उसकी उपयोगिता समझ में आयी, उसे निकालना आरम्भ किया गया और उपयोग में लाया गया तो वही खनिज सम्पदा मूल्यवान हो गई। इसी प्रकार नदियाँ तभी संसाधन बन पायी जब उनका उपयोग सिंचाई में, जल विद्युत उत्पादन में मत्स्य पालन के लिए एवं यातायात के लिए किया जाने लगा। भूगोलवेत्ता ने कहा है, "संसाधन हुआ नहीं करते, बना करते हैं।"

प्र.6. मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है?
Why are resources necessary for human?

उत्तर प्रकृति प्रदत्त वस्तुएँ हवा, पानी, वन, वन्यजीव, भूमि, मिट्टी, खनिज सम्पदा एवं शक्ति के साधन या स्वयं मनुष्य द्वारा निर्मित संसाधन के बिना मनुष्य की जरूरतें पूरी नहीं हो सकती हैं तथा सुख सुविधा नहीं मिल सकती है। मनुष्य का आर्थिक विकास संसाधनों की उपलब्धि पर ही निर्भर करता है। संसाधनों का महत्त्व इस बात से लगता है कि इनकी प्राप्ति के लिए मनुष्य कठिन से कठिन परिश्रम करता है, साहसिक यात्राएँ करता है, फिर अपनी बुद्धि, प्रतिभा, क्षमता, तकनीकी ज्ञान और कुशलताओं का प्रयोग करके उनके उपयोग की योजना बनाता है, उन्हें उपयोग में लाकर अपना आर्थिक विकास करता है।

प्र.7. खनिज कितने प्रकार के होते हैं? सोदाहरण परिचय दीजिए।
How many types of minerals are there? Give examples.

उत्तर सामान्यत: खनिजों को दो वर्गों में बाँटा जाता है—

1. **धात्विक खनिज**—ऐसे खनिजों में धातु मौजूद रहते हैं। ये धातु किसी-न-किसी धातु के साथ मिले होते हैं; जैसे—लौह अयस्क, ताँबा, निकेल आदि। धातु की उपस्थिति के आधार पर धात्विक खनिज को भी दो उप-भागों में बाँटा जाता है। (क) लौहयुक्त धातु-मैंगनीज, क्रोमाइट, (ख) अलौहयुक्त धातु-सोना, चाँदी, तांबा।
2. **अधात्विक खनिज**—ऐसे खनिजों में धातुएँ नहीं होती हैं। कोयला और पेट्रोलियम जैसे खनिज ईंधन अधात्विक खनिज है।

प्र.8. ऊर्जा संकट दूर करने के लिए ऊर्जा के किन स्रोतों को विकास करने की आवश्यकता है? इसके लिए कौन-से प्रयास किये जा रहे हैं?
Which sources need to be developed to do away with energy crisis? What efforts are being undertaken for the same?

उत्तर भारत में परम्परागत ऊर्जा के साधन सीमित हैं और दिनों दिन विद्युत की माँग कृषि, उद्योग परिवहन तथा दैनिक जीवन में बढ़ती जा रही है। अत: विद्युत का उत्पादन बढ़ाना आवश्यक हो गया है। इसके लिए ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोतों को विकसित करने की आवश्यकता है। इसके लिए आयोग बनाये गये और परम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग स्थापित किए गए हैं। इस दिशा में अन्य ऊर्जा की खोज की जा रही है। इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा तथा अपशिष्ट पदार्थ से उत्पन्न ऊर्जा को विकसित करने पर बल दिया जा रहा है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर गैस प्लांट स्थापित कर ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है। आजकल शहरों में भी सड़कों पर रोशनी के लिए बायोगैस का प्रयोग किया जा रहा है।

खण्ड-ब लघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. आर्थिक भूगोल के संसाधनों को परिभाषित कीजिए।
Define the Resources of Economic Geography.

उत्तर

संसाधन (Resources)

संसाधन वे तत्त्व या स्रोत हैं जो मानवीय उद्देश्यों तथा आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम होते हैं। किसी वस्तु को तभी संसाधन माना जाता है जब वह मनुष्य की किसी आवश्यकता की पूर्ति करता हो या करने में समर्थ हो। कोई भी वस्तु या तत्त्व स्वयं

में संसाधन नहीं है, बल्कि मनुष्य के लिये उसकी उपयोगिता उसे संसाधन बना देती है। किसी वस्तु या स्रोत की उपयोगिता देशकाल की परिस्थिति के अनुसार मनुष्य की भौतिक बौद्धिक तथा सांस्कृतिक क्षमता पर निर्भर करती है क्योंकि उसके अनुसार ही मनुष्य किसी उपलब्ध वस्तु या स्रोत का उपयोग करता है। अत: प्राविधिक विकास के साथ-साथ संसाधनों की मात्रा में वृद्धि की प्रवृत्ति पायी जाती है।

सामान्यत: संसाधन का अभिप्राय केवल मूर्त या गोचर पदार्थों से लगाया जाता है किन्तु अनेक अमूर्त (abstract) तत्त्व जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं संसाधन की श्रेणी में आते हैं। मूर्त (दिखाई देने वाले) तत्त्वों में भूमि, जल, वन, मिट्टी, खनिज, कृषित उपजें, औद्योगिक उत्पादन, कारखाने, भवन, सड़कें आदि प्रमुख हैं। अमूर्त तत्त्वों में मनुष्य का स्वास्थ्य, शिक्षा, वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान, कार्यकुशलता, सामाजिक संगठन, आर्थिक प्रगति, राजनीतिक स्थिरता, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एवं संगठन प्रमुख संसाधन है। कोई भी पदार्थ मानव-उपयोगिता के कारण ही संसाधन बन पाता है, वही दूसरी ओर मनुष्य स्वयं भी एक संसाधन है जो अपने ज्ञान तथा कार्यकुशलता से अनेक संसाधनों का निर्माण करता है; जैसे—खेत-खलिहान, बाग, कारखाने, भवन, सड़कें, रेलमार्ग, विधि सेवाएँ आदि मानव निर्मित (सांस्कृतिक) संसाधन हैं। निर्माण प्रकिया के अनुसार संसाधन दो प्रकार के हो सकते हैं—प्राकृतिक एवं मानवीय (सांस्कृतिक)।

जिमरमैन के अनुसार, "संसाधन कोई वस्तु या पदार्थ नहीं है, बल्कि वह प्रकार्य (Function) है जिसे कोई वस्तु या पदार्थ मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कर सकता है।"

जेलिन्स्की ने भी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के गुण को ही संसाधन की प्रमुख विशेषता माना है जो मनुष्य के ज्ञान के साथ-साथ बढ़ता जाता है। उनके अनुसार, "संसाधन वे तत्त्व या गुण होते हैं जो मानव आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं और जो अपनी आर्थिक तथा सांस्कृतिक उपलब्धियों तथा अपनी संसाधन दोहन की क्षमता के अनुसार लोगों के उद्देश्यों, प्रतिमाओं तथा प्रयत्नों के साथ-साथ बढ़ते जाते हैं।"

प्र.2. संसाधनों के वर्गीकरण तथा प्रबंध का उल्लेख कीजिए।

Explain the Classification and Management of Resources.

उत्तर

संसाधनों का वर्गीकरण
(Classification of Resources)

संसाधनों का वर्गीकरण तत्त्वों, संसाधनों की उपलब्धता, उपयोगिता, नव्यकरणीयता आदि आधारों पर किया जा सकता है।

पर्यावरणीय तत्त्व संसाधन के मौलिक आधार हैं जिनके अनुसार संसाधन दो प्रकार के होते हैं—

1. **अजैविक संसाधन** (abiotic resources)—इन्हें भौतिक संसाधन भी कहते हैं। भूमि, पर्वत, पठार, मैदान, घाटी, नदी, झील, सागर, महासागर, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, शैल, खनिज, मिट्टी आदि इसी वर्ग में आते हैं।
2. **जैविक संसाधन** (biotic resources)—वनस्पति, जीव-जन्तु, सूक्ष्म जीव एवं मनुष्य इस वर्ग में सम्मिलित हैं।

उत्पत्ति एवं **विकास** के आधार पर संसाधनों के दो वृहत वर्ग हैं—1. प्राकृतिक संसाधन एवं 2. मानव संसाधन। मनुष्य जो समस्त संसाधनों का उत्पादक तथा उपभोक्ता है, स्वयं भी एक प्रमुख संसाधन है। वास्तव में, मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है जो किसी तत्त्व को उपयोगिता प्रदान करता है। किसी भी देश-काल की कुल जनसंख्या, जनसंख्या का घनत्व, जीवनस्तर, जीवन-शैली, मानवीय आवश्यकताएँ, कार्यकुशलता, वैज्ञानिक एवं प्राविधिक ज्ञान, पूँजी की उपलब्धता, संसाधनों का स्वामित्व, सरकारी नीति, सरकार की स्थिरता, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध आदि विविध मानवीय कारक हैं जो संसाधन की मात्रा, मूल्यांकन, शोषण की विधि आदि को निर्धारित या प्रभावित करते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण संसाधन आधार होता है किन्तु उसकी संसाधनता, मनुष्य के ज्ञान तथा उपयोगिता में निहित होती है। नव्यकरणीयता (renewability) के अनुसार संसाधन दो प्रकार के होते हैं—1. परिवर्द्धनीय तथा 2. पुन: प्रयोजनीय।

1. **परिवर्द्धनीय संसाधन**—वे हैं जिनके गुणों में वृद्धि की जा सकती है या जिन्हें दीर्घकाल तक उपयोग में लाया जा सकता है। वन, भूमि, जल, मिट्टी, वन्यजीव मछली आदि इसी प्रकार के संसाधन हैं।
2. **पुन: प्रयोजनीय संसाधन**—वे हैं जिनके रूप में परिवर्तन द्वारा उन्हें बार-बार प्रयोग में लाया जा सकता है; जैसे—विभिन्न प्रकार के धात्विक खनिज।

TOUCH 'n PASS

संसाधन प्रबन्ध (Resource Management)

संसाधन प्रबन्ध का तात्पर्य किसी संसाधन के कुशल नियंत्रण तथा व्यवस्थापक से है जो वर्तमान खनिज–आर्थिक आवश्यकताओं, उपलब्ध तकनीकी ज्ञान, भावी उपयोगिता एवं आवश्यकता, पर्यावरण संरक्षण आदि को ध्यान में रखकर संचालित होता है। संसाधन का अनुकूलतम उपयोग करना तथा अनावश्यक क्षति रोकना इसका उद्देश्य है। संसाधन प्रबन्धन के तीन प्रमुख पक्ष हैं—1. संसाधनों का सर्वेक्षण, 2. संसाधनों का मूल्यांकन, 3. संसाधनों का उपयोग एवं संरक्षण।

संसाधन संरक्षण (Resource Conservation)

संसाधन संरक्षण संसाधन प्रबन्धन का ही एक पक्ष (अंग) है। इसका अर्थ किसी देश–काल में विद्यमान प्राकृतिक संसाधन आधार तथा जनसंख्या के मध्य सन्तुलन स्थापित करना है जिससे वर्तमान सामाजिक–आर्थिक प्रगति के लिये विमान संसाधनों का उचित तथा सर्वोत्तम उपयोग करने के साथ ही भविष्य में भी उनकी सतत आपूर्ति बनी रहे। इसके लिए उनका दुरुपयोग अपशिष्टीकरण तथा अनावश्यक शोषण न्यूनतम हो। दूसरे शब्दों में, संसाधन संरक्षण का अर्थ संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग (Optimum use) से है। संसाधन संरक्षण का अर्थ संसाधन के अप्रयोग (non use) से कदापि नहीं है और न ही उनके संचित करने से है। वास्तव में, संरक्षण का मूलाधार मितव्ययिता है, जिसमें अंधाधुन्ध उपयोग तथा अवांछित दुरुपयोग को कम किया जाये तथा उनका विवेकपूर्ण (rational) उपयोग है। यह संसाधनों को टिकाऊ या संपोषणीय (sustainable) बनाने की उत्तम विधि है।

प्र.3. संसाधनों के विकास में 'सतत् विकास' की अवधारणा की व्याख्या करें।
Explain the concept of Sustainable Development in the development of Resources.

उत्तर संसाधन मनुष्य की जीविका का आधार है। जीवन की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए संसाधनों के सतत् विकास की अवधारणा आवश्यक है। संसाधन को प्रकृति का उपहार मानकर मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग करना शुरू किया, जिसके कारण पर्यावरणीय समस्याएँ भी उत्पन्न हो गयी है।

शक्ति सम्पन्न लोगों ने अपने स्वार्थ में संसाधनों को विवेकहीन दोहन किया जिससे विश्व पारिस्थितिकी में घोर संकट पैदा हो गया। भूमंडलीय तापन, ओजोन परत में क्षय, पर्यावरण–प्रदूषण, अम्लीय वर्षा, ऋतु परिवर्तन जैसे संकट पैदा होते जा रहे हैं। अगर ये परिस्थिति बनी रही तो संसार के सभी मानव का जीवन संकट में पड़ जायेगा।

इन परिस्थितियों से बचने के लिए संसाधनों का नियोजित उपयोग जरूरी है। इससे पर्यावरण को बिना क्षति पहुँचाए भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है। ऐसी सोच ही सतत् विकास कही जाती है। इससे वर्तमान विकास के साथ भावी पीढ़ी की आवश्यकताएँ भी पूरी होगी और भविष्य भी सुरक्षित रह सकेगा।

प्र.4. स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध स्वरूपों का वर्णन कीजिए।
Describe the different forms of Resource on the basis of Ownership.

उत्तर

स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विभिन्न स्वरूप
(Different forms of Resources on the Basis of Ownership)

स्वामित्व के आधार पर संसाधन के चार प्रकार होते हैं—

(i) **व्यक्तिगत संसाधन**—ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होते हैं जिसके बदले में वह व्यक्ति सरकार को लगान भी चुकाते हैं; जैसे—खेती की जमीन, घर, बाग–बगीचा, तालाब आदि ऐसे संसाधन हैं जिस पर व्यक्ति निजी स्वामित्व रखता है।

(ii) **सामुदायिक संसाधन**—ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के अधीन होते हैं जिसका लाभ विशेष समुदाय के लोगों के लिए सुलभ होता है; जैसे—चरागाह, श्मशान घाट, मंदिर, मस्जिद, सामुदायिक भवन, तालाब आदि।

(iii) **राष्ट्रीय संसाधन**—कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय हैं। सरकार को यह वैधानिक अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकती है। सरकार को अधिग्रहित संसाधन का मुआवजा देना पड़ता है।

(iv) **अंतर्राष्ट्रीय संसाधन**—ऐसे संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। तट रेखा से 200 किमी की दूरी को छोड़कर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता है। ऐसे संसाधनों का उपयोग सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से किसी राष्ट्र, द्वारा किया जा सकता है।

TOUCH 'n' PASS

प्र.5. ''संसाधन हुआ नहीं करते, बना करते हैं'' इस कथन की व्याख्या कीजिए।
Explain the statement, "Resources do not happen, they are made."

उत्तर

संसाधन हुआ नहीं करते, बना करते हैं
(Resources do not Happen, They are Made)

संसार में अनेको प्राकृतिक पदार्थ बिखरे पड़े हैं जब तक उनका उपयोग नहीं किया जाता है वे संसाधन नहीं बन पाते। मनुष्य उन्हें पता लगाता है। फिर अपनी बुद्धि, विवेक, क्षमता, तकनीक और कुशलता का प्रयोग कर अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, आर्थिक विकास के लिए उनके उपयोग की योजना बनाता है और उपयोग में लाकर वह उन्हें संसाधन बनाता है। मनुष्य के आर्थिक विकास के लिए संसाधन अति आवश्यक होता है। नदियाँ तभी संसाधन बन पाती हैं जब मानव उनका उपयोग सिंचाई में, जल विद्युत उत्पादन में, मत्स्य पालन में एवं जलीय यातायात के रूप में और अनेक आर्थिक कार्यों में करता है। सदियों से शोक का कारण बनने वाली नदी, विनाशकारी बाढ़ लाने वाली नदी, हजारों हजार की संख्या में जान माल को क्षति पहुँचाने वाली नदी पर योजना बनाकर बाँध बनाया गया, नहरें निकाली गयी, सिंचाई का काम लिया, विद्युत उत्पादन किए गये जिससे सिंचाई और उद्योग के विकास में मदद मिलने लगी तो वहीं शोक पैदा करने वाली नदी प्राकृतिक संसाधन बन गई, खुशहाली का कारण बनी। इसीलिए एक भूगोलवेत्ता जिम्मरमैन ने ठीक ही कहा है कि संसाधन हुआ नहीं करते, बना करते हैं।

प्र.6. संसाधनों के संरक्षण से क्या तात्पर्य है? यह संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है?
What is the meant by conservation of Resources? How can it be done?

उत्तर

संसाधनों का संरक्षण
(Conservation of Resources)

मानव प्राकृतिक संसाधनों का सृष्टिकर्त्ता नहीं है इसलिए मानव प्राकृतिक संसाधन को पूँजी समझकर उपयोग करें। इसका तात्पर्य यह है कि संसाधनों के उपयोग में कम-से-कम दुरुपयोग हो, उनकी कम-से-कम बर्बादी हो। मिट्टी जैसी संपदा की उर्वरता बनी रहे, उसे निम्नीकरण या कटाव से बचाया जाये। वन सम्पदा के अत्यधिक उपयोग में लाए जाने पर पुनः स्थापन पर बल देना उनका संरक्षण कहलाता है। अतः संरक्षण से तात्पर्य है संसाधनों का अधिकाधिक समय तक अधिक लोगों के लिए आवश्यकता की पूर्ति हेतु उपयोग हो।

संसार की आबादी का बड़ा भाग कृषि पर आश्रित है और कृषि कार्य के लिए मानव भूमि और मिट्टी का उपयोग करता है। इन संसाधनों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यदि इनमें कोई कमी है तो उसे पूरा कर उपयुक्त बनाया जाए। यदि वह बर्बाद हो रही है तो किस तरह उसका संरक्षण किया जाए। इसके लिए भूमि का उपयोग इस प्रकार होना चाहिए कि मिट्टी के प्रकार के अनुसार फसलें उगानी चाहिए ताकि भूमि की उत्पादकता बनी रहे और मिट्टी की गुणवत्ता नष्ट न हो।

इस प्रकार जल संरक्षण, वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण, खनिज संपदा संरक्षण के लिए भी योजनाबद्ध और विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए तो उनसे अधिक से अधिक समय तक लाभ उठाया जा सकता है तथा वे मानव जगत के लिए संरक्षित रह सकते हैं। संसाधनों का योजनाबद्ध, समुचित और विवेकपूर्ण उपयोग ही उनका संरक्षण है। संरक्षण का तात्पर्य कदापि यह नहीं कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग न कर उनकी रक्षा की जाए उनके खर्च की आवश्यकता के बावजूद उन्हें बचाकर भविष्य के लिए रखा जाए।

प्र.7. शक्ति संसाधनों के संरक्षण हेतु कौन-कौन से उपाय किये जा सकते हैं?
Which measures can be undertaken for the conservation of Energy Resources?

उत्तर

शक्ति संसाधनों के संरक्षण हेतु उपाय
(Measures Undertaken for Conservation of Resources)

शक्ति संसाधन के संरक्षण के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं—

1. **ऊर्जा के उपयोग में मितव्ययिता**—ऊर्जा का उचित एवं आदर्शतम उपयोग होने से ऊर्जा का दुरुपयोग नहीं होता है।
2. **ऊर्जा के नवीन क्षेत्रों की खोज**—ऊर्जा संकट का समाधान नवीन ऊर्जा स्रोतों में निहित होते हैं। इसके लिए सुदूर संवेदी प्रणाली का भी प्रयोग हो रहा है।
3. **ऊर्जा के नवीन वैकल्पिक साधनों का उपयोग**—जो संसाधन समाप्त होने वाले हैं जिनकी पुनरावृत्ति सम्भव नहीं है, उस संसाधन को संरक्षित करना चाहिए। बदले में ऐसे स्रोत जो न समाप्त होने वाले हैं, ऐसे वैकल्पिक साधनों का प्रयोग

TOUCH 'n PASS

किया जाए; जैसे—जल विद्युत, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि। ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत भी कहे जाते हैं।

4. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग**—ऊर्जा संकट एक वैश्विक समस्या है। जिसे विश्व के देशों को आपसी मतभेद भुलाकर सहयोग एवं समाधान करना चाहिए। आज UNO, OPEC, WTO, G8 जैसे देश इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। ऊर्जा का उपयोग हम अपनी जरूरत के हिसाब से करके एवं बेवजह उसका उपयोग न करके शक्ति के संसाधनों को संरक्षण कर सकते हैं।

प्र.8. संसाधन के नियोजन से आप क्या समझते हैं? इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालिए।

What do you understand by Resource Planning? Throw light on its need.

उत्तर

संसाधन के नियोजन और इसकी आवश्यकता
(Resource Planning and Its Need)

संसार में संसाधनों का वितरण असमान रूप से फैला हुआ है। किसी क्षेत्र में यह आवश्यकता से अधिक तो किसी क्षेत्र में आवश्यकता से कम मात्रा में पाई जाती है। भारत में तो यह क्षेत्रीय विविधता और भी अधिक है। अत: पूरे देश के विकास के लिए संसाधनों का नियोजन आवश्यक है। मानव की अपने भौतिकवादी जीवन की आवश्यकताएँ बढ़ती जा रही हैं और उनकी आपूर्ति में संसाधनों का अत्यधिक शोषण करता जा रहा है जिससे अनेकों संसाधन समाप्ति के कगार पर हैं और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है। यदि संतुलन नष्ट हुआ तो मानव का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए संसाधन नियोजन की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है।

प्र.9. भारत के आर्थिक विकास में जल संसाधन का योगदान बताइए।

Mention the contribution of Water Resources in the Economic Development of India.

उत्तर

भारत के आर्थिक विकास में जल संसाधन का योगदान
(Contribution of Water Resources in the Economic Development of India)

भारत के आर्थिक विकास में जल संसाधन का योगदान महत्त्वपूर्ण माना जाता है। घरेलू उपयोग से लेकर उद्योग-धंधे तथा कृषि कार्य एवं यातायात, जल विद्युत उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। उद्योग धंधे; जैसे—लोहा-इस्पात उद्योग, रसायन उद्योग, कपड़ा उद्योग आदि में जल की अधिक आवश्यकता होती है। जल का सबसे अधिक उपयोग कृषि कार्य में सिंचाई के रूप में किया जाता है। समय पर पर्याप्त मात्रा में सिंचाई फसल के उत्पादकता को बढ़ाता है। इसके लिए धरातलीय और भूमिगत दोनों सिंचाई का सहारा लिया जाता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति की सफलता मूलत: सिचांई पर ही आधारित है। जल का उपयोग आंतरिक जल मार्ग; जैसे—नदी, नहर, झील के रूप में भी किया जाता है। इस तरह जल एक महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय संसाधन है जिसका उपयोग हर क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत के आर्थिक विकास में जल संसाधन का अत्यधिक योगदान है।

खण्ड-स विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. संसाधनों में आर्थिक क्रियाओं की व्याख्या कीजिए।

Explain the Economic Activities in Resources.

उत्तर

आर्थिक क्रियाएँ
(Economic Activities)

वस्तुओं के उत्पादन, उपभोग तथा विनिमय से सम्बन्धित सभी क्रियाएँ आर्थिक क्रियाएँ कहलाती हैं। उत्पादन से अभिप्राय खाद्यान्न, पशु उत्पाद, मत्स्य, वनोत्पाद तथा औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन से है।

आर्थिक क्रियाओं को चार वर्गों में बाँटा जाता है—प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थक (व्यवसाय)।

TOUCH 'n PASS

प्राथमिक क्रियाओं के अन्तर्गत आखेट, वस्तु संग्रह, खनन, मत्स्यन तथा कृषि सम्मिलित हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से ग्रहण किये जाते हैं। इन कार्यों में संलग्न व्यक्तियों को 'Red collar workers' कहा जाता है।

द्वितीयक क्रियाएँ वर्तमान वस्तुओं के रूपान्तरण द्वारा उन्हें अधिक मूल्यवान बनाने से सम्बन्धित हैं। इनमें विनिर्माणी उद्योग सम्मिलित हैं। इनमें संलग्न व्यक्तियों को 'Blue collar workers' कहा जाता है।

तृतीयक क्रियाएँ सेवाएँ प्रदान करने से सम्बन्धित हैं। इनमें अनेक प्रकार की व्यक्तिगत एवं व्यापारिक क्रियाएँ सम्मिलित हैं। इनके क्रियाओं में संलग्न व्यक्तियों को 'Pink collar workers' कहा जाता है।

चतुर्थक क्रियाएँ व्यावसायिक एवं प्रशासनिक सेवाओं से सम्बन्धित होती हैं। इनमें संलग्न व्यक्तियों को 'White collar workers' कहा जाता है।

एक अन्य विशिष्ट वर्ग की आर्थिक क्रियाएँ पंचम क्रियाएँ कहलाती हैं, जिनमें सरकारी तथा निजी क्षेत्र के शीर्ष प्रबन्धन अधिकारी एक्जीक्यूटिव, शोधकर्त्ता, कानून, वित्तीय तथा व्यावसायिक सलाहकार आदि सम्मिलित हैं। इसमें संलग्न व्यक्तियों को 'Gold Collor Workers' कहा जाता है।

1. **प्राथमिक क्रियाएँ** (Primary Activities)—**भोजन संग्रह तथा आखेट मानव** के प्राचीनतम व्यवसाय हैं। इन क्रियाओं में आदिम तथा पिछड़ी जनजातियाँ संलग्न होती हैं। उष्ण कटिबन्ध में आज भी अनेक समुदाय अपनी जीविका के लिये इन क्रियाओं पर निर्भर हैं। जीविका निर्वाहक मत्स्योत्पादन भी इसी वर्ग में सम्मिलित है। भोजन संग्रह अमेजन बेसिन, पूर्वी द्वीप समूह तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के आन्तरिक भागों में आज भी प्रचलित है। मलाया के संभाग भोजन संग्रहकर्त्ताओं का उत्तम उदाहरण है।

आदिम आखेट (Primitive Hunting) एक प्राचीन व्यवसाय है जो पहले एक व्यापक क्रिया थी, परन्तु अब सीमित हो गयी है। यह आर्कटिक प्रदेश, आस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका तथा दक्षिणी अमेरिका के अन्तरिक क्षेत्रों में अब भी प्रचलित है। कालाहारी के बुशमैन तथा उत्तरी अमेरिका के एस्किमो इसके उत्तम उदाहरण है।

चलवासी पशुचारण (Nomadic Herding) पशुओं के पालतूकरण पर आधारित है। ये पशुचारक प्राकृतिक चारागाहों की तलाश में घुमक्कड़ी जीवन बिताते हैं। दक्षिणी पश्चिमी तथा मध्य एशिया के अर्द्ध मरुस्थलों में तथा उत्तरी अफ्रीका के शुष्क भागों में यह आर्थिक क्रिया प्रचलित है। उत्तरी यूरेशिया से अलास्का तथा विस्तृत क्षेत्र भी घुमक्कड़ी पशुचारण का गौण क्षेत्र है। चलवासी पशुचारण का एक विशेष प्रकार **मौसमी प्रवास** (transhumance) कहलाता है जिसमें पशुचारक शीतकाल तथा ग्रीष्मकाल में घाटियों तथा पर्वतों के बीच ऋतु क्रम से पशुओं सहित प्रवास करते हैं। मध्य एशिया में खिरगीज, इसके सर्वोत्तम उदाहरण हैं। एण्डीज, पूर्वी अफ्रीका, सूडान तथा भारत में हिमालय क्षेत्र में ही यह प्रचलित है। हिमाचल प्रदेश के गद्दी, जम्मू, कश्मीर के गुज्जर तथा बकरवाल भी मौसमी प्रवास अपनाते हैं।

पशुपालन (Livestock Ranching) अधिक उन्नत आर्थिक क्रिया है जो घास प्रदेशों में प्रचलित है। पशुपालक (रैंचर्स) स्थायी आवासों में रहते हैं। सवाना के लानौज, कैम्पोज उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी, मध्य एशिया के स्टेपी, अर्जेन्टिना तथा उरुग्वे के पम्पा, दक्षिणी अफ्रीका के वेल्ड तथा आस्ट्रेलिया के डाउन्स पशुपालन के प्रमुख क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में स्थायी चारागाहों में पशु पाले/चराये जाते हैं।

मत्स्यन एवं वानिकी (Fishing and Forestry) भी प्राथमिक क्रियाएँ हैं। मत्स्यन दो स्तरों पर प्रचलित हैं—जीविका निर्वाह (Subsistence) तथा वाणिज्यिक, विश्व के प्राय: सभी तटवर्ती क्षेत्रों में जीविका निर्वाहक मत्स्यन प्रचलित है। वाणिज्यिक मत्स्यन के प्रमुख क्षेत्र-उत्तरी पश्चिमी प्रशान्त, उत्तरी पूर्वी अटलांटिक, दक्षिणी पश्चिमी प्रशान्त, पश्चिमी मध्यवर्ती प्रशान्त, उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक है। मत्स्यन का एक विशिष्ट स्वरूप जलीय कृषि (Aquaculture) है, जिसके अन्तर्गत स्वच्छ तथा खारे जल में मछलियाँ पाली जाती हैं। मोती वाली मछलियों की प्राप्ति (Pearl Fishery) के प्रमुख क्षेत्र आस्ट्रेलिया का उत्तरी तट, श्रीलंका, फारस की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी आदि हैं। मोती उत्पादन (Pearl Culture) में जापान तथा चीन अग्रणी है।

निर्वाहक स्तर पर वानिकी (Fishery as Subsistence) एक ह्रासमान व्यवसाय है। यद्यपि वाणिज्यिक स्तर पर यह महत्त्वपूर्ण है। वनों से अनेक प्रकार की गौण उपजें भी प्राप्त की जाती हैं। जिनमें गोंद, राल, गिरियाँ, चमड़ा कमाने के पदार्थ आदि सम्मिलित हैं। वाणिज्यिक वानिकी के अन्तर्गत कोमल तथा कठोर लकड़ियाँ वनों से प्राप्त की जाती हैं जिनका उपयोग उद्योगों (मुख्यत: कागज एवं लुगदी) में किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, स्वीडन, जर्मनी, फिनलैण्ड, जापान, रूस आदि देश प्रमुख उत्पादक हैं।

TOUCH 'n' PASS

प्र.2. खनिजों की विशेषताएँ एवं प्रमुख खनिज संसाधनों का वर्णन कीजिए।
Describe the Characteristics of Minerals and Major Mineral Resources.

उत्तर

खनिजों की विशेषताएँ
(Characteristics of Minerals)

खनिजों की विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं—

1. खनिज निक्षेप छिटपुट, छोटे क्षेत्रों में बिखरे होते हैं।
2. ये अधिकांशत: भूगर्भ में स्थित हैं। अत: इनके सर्वेक्षण तथा दोहन में बड़ी मात्रा में पूँजी, श्रम, संयंत्र तथा प्राविधिकी प्रयुक्त होती है।
3. खनिजों के भण्डार निश्चित तथा अनव्यकरणीय हैं। कुछ खनिजों (सोना, चाँदी, लोहा) का पुनर्चक्रण (recycling) संभव है, किन्तु ये सभी क्षयशील हैं।
4. अधिकांश धातुएँ टिकाऊ होती हैं, इन्हें पिण्डों या निर्मित वस्तुओं के रूप में सुरक्षित रखा जा सकता है।
5. निरन्तर शोषण के कारण खदानें गहरी तथा खर्चीली होती जाती है।
6. खनिज-उत्पादन उपयोग, बाजार (माँग) के अनुसार घटता-बढ़ता रहता है।
7. अधिक सम्पन्न खनिजों का उत्पादन शीघ्रता से किया जाता है।
8. कम मूल्यवान खनिजों के दोहन का विचार नहीं किया जाता है।
9. खनिज उपभोग की आवश्यकता तथा इच्छा मानव समाज (लोगों के जीवन स्तर, प्राविधिक ज्ञान-स्तर, आर्थिक विकास स्तर तथा सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक संगठन) पर निर्भर करती है।

प्रमुख खनिज संसाधन (Major Mineral Resources)

प्रमुख खनिज संसाधन निम्न प्रकार हैं—

1. **लौह अयस्क**—मुख्यत: निम्न प्रकार के होते हैं—हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, साइडराइट तथा आयरन पायराइट्स।
   प्रमुख उत्पादक क्षेत्र—यूक्रेन (क्रिवोई रोग), रूस (मैग्नी टोगोर्स्क, बुजनेत्स्क), ब्राजील (मिनास गिरास), चीन (मंचूरिया, शान्तुंग, शैन्सी प्रान्त), संयुक्त राज्य (सुपीरियर झील या मेसाबीरेन्ज, अलाबामा राज्य), ऑस्ट्रेलिया, (पिलबरा), स्वीडन (किरूना, गैलीवेयर), दक्षिण अफ्रीका (पोस्टमासबर्ग, ट्रांसवाल), भारत (झारखण्ड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक)।
   प्रमुख उत्पादक देश—चीन, ब्राजील, आस्ट्रेलिया, भारत, रूस ।
2. **मैंगनीज**—
   प्रमुख अयस्क—पाइरोल्युसाइट, साइलोमेलीन, ब्रोनाइट।
   प्रमुख उत्पादक क्षेत्र—यूक्रेन (निकोपोल, चियातुरा), ब्राजील (मिनास, जेरास, अमापा), गैबोन, दक्षिण अफ्रीका (पोस्टमासबर्ग, किम्बरले)।
3. **क्रोमियम**—
   प्रमुख अयस्क—क्रोमाइट।
   प्रमुख उत्पादक क्षेत्र—दक्षिण अफ्रीका (रूस्तनबर्ग), कजाखिस्तान (क्रोमताऊ, कोमोरोको), भारत (झारखण्ड, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र), फिलीपीन्स (उत्तरीलुजों द्वीप पर जम्बालेज क्षेत्र), जिम्बावे (सेल्युके)।
4. **निकिल**—
   प्रमुख अयस्क—पेन्टलनड्यूट।
   प्रमुख उत्पादक क्षेत्र—रूस (दक्षिणी यूराल, कोला प्रायद्वीप, पेचोरा)। आस्ट्रेलिया, कनाडा (सडबरी, उत्तरी मैनीटोबा), न्यू कैलेडोनिया, इण्डोनेशिया।
5. **टंगस्टन**—
   प्रमुख अयस्क—शीलाइट, वोल्फ्रमाइट।
   प्रमुख उत्पादक क्षेत्र—चीन (नानकिंग पर्वत, हुनान, किंयांग्सी), रूस (पूर्वी साइबेरिया), दक्षिण कोरिया।

TOUCH 'n PASS

6. **एन्टीमनी—**
प्रमुख अयस्क—स्टिबनाइट।
प्रमुख उत्पादन क्षेत्र—चीन (हुनान, क्वांग्सी), दक्षिण अफ्रीका (ट्रांसवाल), रूस (राजोलिंस्क), ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, बोलीविया, आस्ट्रेलिया।
7. **ताँबा—**
प्रमुख अयस्क—चेल्को पाइराइट, चेल्कोसाइट, बोनाइट, क्यूप्राइट, मैचुलाइट, एजुराइट।
प्रमुख उत्पादक क्षेत्र—चिली (चुकि कामाता, एल नेनिएन्ते, एल साल्वेडोर, ला-एफ्रिकाना), पेरू (सेरों डि पास्का, मोरोकोचा, कैसेपाल्का, टोक्वेपाला), संयुक्त राज्य अमेरिका (एरिजोना, ऊटाह, मोन्टाना, नेवादा, न्यू मैक्सिकों), कनाडा (सडबरी ओन्टारियो, क्यूबेक, मैनीटोबा, सस्केचवान), जाम्बिया, दक्षिण अफ्रीका कटंगा-जायरे, इण्डोनेशिया, चीन (युन्नान, जेचवान, तांगशान)।
8. **बॉक्साइट (एल्युमिनियम)**
गौण अयस्क—क्रायोलाइट (केवल ग्रीनलैण्ड में)
प्रमुख उत्पादक क्षेत्र—आस्ट्रेलिया (वाइपा, उत्तर पूर्वी न्यूसाउथवेल्स तथा पर्थ के निकट), भारत (मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश) ब्राजील, चीन (हुनान, क्वीचाऊ सिचुआन), गिनी, घाना सियरालिओन, जमैका, इण्डोनेशिया, रूस, सूरीनाम, वेनेजुएला, कजाखिस्तान।
9. **जस्ता—**
प्रमुख अयस्क—स्फेरेलाइट
प्रमुख उत्पादक देश—चीन, पेरू, आस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा ।
10. **सीसा—**
प्रमुख अयस्क—गेलेना (सेरुसाइट, एंग्लेसाइट अन्य)।
प्रमुख उत्पादक देश—चीन, आस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, पेरू, मैक्सिको ।
11. **टिन—**
प्रमुख अयस्क—कैरसेराइट (टिन स्टोन)
प्रमुख उत्पादक क्षेत्र—चीन (नानकिंग पर्वत, युन्नान, क्वांग्सी, कियांग्सी, हुनान) इण्डोनेशिया (बंका, बिलिटन, सिंगकेप), मलेशिया (किन्ता सेंलंगेर, पेनांग द्वीप, क्वालालंपुर, पेराक, सुनोई लेम्बिग), बोलीविया (पोटोसी), पेरू (सान एन्टोनियो डिपोलो)।
12. **सोना—**
प्रमुख उत्पादक क्षेत्र—चीन (युन्नान, मंचूरिया, सिनलिंग शान), संयुक्त राज्य अमेरिका (अलास्का, कैलिफोर्निया, कोलोरेडो, नेवादा, दक्षिण डाकोटा), आस्ट्रेलिया (कालागूर्ली, कूलगार्डी, बेन्डिंगो, बेलारेट, माउन्ट मोर्गन), रूस (याकुत्स्क, अल्दान, इण्डिगिरिका एवं कोलिका नदियों की घाटियाँ), दक्षिण अफ्रीका (ट्रांसवाल में विटवाटर्सरेन्ड), ओडेनडाल्सरस्ट-ओरेन्ज फ्री स्टेट) पेरू, इण्डोनेशिया।
13. **चाँदी—**
प्रमुख अयस्क—अर्जेन्टाइट।
प्रमुख उत्पादक क्षेत्र—मैक्सिको (पेचूका, चिहुआहुआ, जकाटकास, अलेपोटोस, फ्रेसमिलो, सान्टा इयुलालिआ), पेरू (सेरो डिपास्को, हुआनकाओ, अयाकुचो), चीन, आस्ट्रेलिया (ब्रोकेन हिल, माउन्ट ईसा, लेक जार्ज), चिली (चुकिकामाता, एलतेनिएन्ते, पोट्रेरिलो), बोलीविया (पोटोसी)।
14. **अभ्रक—**
प्रमुख प्रकार—मस्कोबाइट (श्वेत), फ्लोगोपाइट (पीला), बायोटाइट (काला)।
प्रमुख उत्पादक क्षेत्र—भारत (शीट अभ्रक)-गया मुंगेर, हजारीबाग, सिंहभूम, मानभूम कोडरमा (झारखण्ड), रूस, फिनलैण्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका, कोरिया रिप०, फ्रांस, कनाडा।

TOUCH 'n' PASS

प्र.3. ऊर्जा के संसाधनों का विस्तार से वर्णन कीजिए।
Describe the Energy Resources in detail.

उत्तर

ऊर्जा के संसाधन
(Energy Resources)

परम्परागत स्त्रोत (Traditional Sources)—कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जीवाश्म ईंधन हैं।

1. **कोयला—**
किस्में—एन्थ्रेसाइट, विटुमिनस, लिग्नाइट, पीट ।
प्रमुख उत्पादक क्षेत्र—संयुक्त राज्य अमेरिका (अप्लेशियन, रॉकी पर्वत, प्रशान्त तटीय), चीन (शैन्सी, शान्सी, सिन्क्याँग, सिचुमान, हुपे, चुन्नान, क्वीचाऊ), भारत (दामोदर घाटी-झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़-उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश), आस्ट्रेलिया (न्यूसाउथवेल्स, इप्सविच, क्वीन्स लैण्ड), रूस (डोनेत्स्क, कुजनेत्स्क, यूराल, मास्को-तुला, पेचोरा बेसिन, पूर्वी साइबेरिया), दक्षिण अफ्रीका (ट्रांसवाल, नेटाल)।
2. **पेट्रोलियम**—प्रमुख उत्पादक क्षेत्र-रूस (वोल्गा-यूराल, सखालीन द्वीप, पेचोरा बेसिन, पश्चिमी साइबेरिया), सऊदी अरब (दाहरन, दम्मान, अबकैफ, कातिफ), संयुक्त राज्य अमेरिका (अप्लेशियन, टेक्सास, गल्फ तट, कैलिफोर्निया, ईरान (मस्जिद-ए-सुलेमान, लाली, नफ्त सेफिद, गच सारन, आगाजारी, करमन-शाही), कुवैत (बुर्धान, मीना-अल-अहमदी, वाफ्रा, मागवा साबरिया, मिंगिश), इराक (किरबुक, नफ्त-खानेह, बुटमाह, जुबैर, रूमाइला), संयुक्त अरब अमीरात (आबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान), चीन (कारामाई, सिन्कयांग, ताचिंग, हेलुंग कियांग, कान्सू, किंघई, सिचुआन, शांतुंग, हैनान), मैक्सिको (टेम्पिको, वेराक्रुज, टबास्को), वेनेजुएला (मैराकाइबो, ओरीनोको, अपुरे-बेसिन)।
प्रमुख तेल शोधन शालाएँ—पारागुआना (वेनेजुएला), उलसान (द० कोरिया), रिलायन्स-जामनगर (भारत), बेटाउन (संयुक्त राज्य अमेरिका), रासतनुस (सऊदी अरब), होवेन्सा (वर्जिन द्वीप), मीना-अल-अहमदी (कुवैत), टेक्सॉससिटी, (संयुक्त राज्य अमेरिका), पुलाऊ बुकोन (सिंगापुर), अबादान (ईरान), माइलियाओं (ताइवान), सिटगो लेक चार्ल्स (लॉस एंजिलीस संयुक्त राज्य अमेरिका), शैल पर्निस (नीदरलैण्ड्स), रॉटरडम (नीदरलैण्ड्स), सऊदी अरामको-यान्बू, अंगार्स्क (रूस), ओमस्क (रूस), नोवो उफा (रूस)।
प्रमुख तेल शोधक देश—(महत्त्व क्रम से) संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान, इटली, कनाडा, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, मैक्सिको, स्पेन, नीदरलैण्ड्स, ब्राजील, सऊदी अरब, सिंगापुर।
ऊर्जा संकट (Energy Crisis)—मध्य-पूर्व में पेट्रोलियम की खोज होने पर उद्योग एवं परिवहन क्षेत्र में इसके उत्पादन तथा उपभोग में अभूतपूर्व तेजी आयी जिसने इन दोनों (उद्योग एवं परिवहन) क्षेत्रों में क्रान्ति उत्पन्न कर दी। ऊर्जा के रूप में कोयले का महत्त्व क्रमश: घटने लगा। किन्तु ऊर्जा के लिये तेल (पेट्रोलियम) पर निरन्तर निर्भरता के कारण अनेक देश विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं के लिये सुभेद्य (vulnerable) हो गये। किन्तु तब भी किसी ने आने वाले खतरे की आशंका नहीं की थी। 1973 में तेल निर्यातक देशों (Opec) द्वारा तेल पर प्रतिबन्ध लगा दिये जिसने सम्पूर्ण विश्व को हिलाकर रख दिया। रातों-रात सस्ते पेट्रोलियम की प्रचुर आपूर्ति का भ्रम मिट गया। इस वैश्विक ऊर्जा संकट से चिन्तित औद्योगिक देशों ने ऊर्जा के संरक्षण तथा नये स्रोतों सम्बन्धी नीतियों पर कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि से सभी देश चिन्तित थे। 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान भी ऊर्जा संकट पैदा हुआ। इसलिए विश्व के सभी देशों ने अपने ऊर्जा-उपभोग में कटौती करना प्रारम्भ कर दिया। वस्तुत: इन घटनाओं ने ऊर्जा के क्षेत्र में 'संरक्षण क्रान्ति' (Conservation Revolution) पैदा कर दी। ऊर्जा का सरंक्षण ही नहीं, जीवाश्म ईंधनों द्वारा होने वाले पर्यावरणीय प्रभावों की चिन्ता भी सभी देशों के लिये प्राथमिकता बन गयी।
3. **प्राकृतिक गैस**—प्राकृतिक गैस प्राय: पेट्रोलियम क्षेत्रों में मिलती है।
प्रमुख उत्पादक क्षेत्र—क्रमश: रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ईरान, नार्वे, अल्जीरिया, यूनाइटेड किंगडम, चीन, इण्डोनेशिया, तुर्कमेनिस्तान, सऊदी अरब, मलेशिया, नीदरलैण्ड्स आदि हैं।
4. **परमाणु विद्युत ऊर्जा—**
यूरेनियम इसका प्रमुख स्रोत है, कनाडा, आस्ट्रेलिया, कजाखिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, रूस, नाइजर, उज्बेकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूक्रेन, चीन, चेक रिप०, भारत, ब्राजील, पाकिस्तान (अवरोही क्रम में), प्रमुख उत्पादक हैं।

थोरियम—(मोनाजाइट अयस्क से प्राप्त) भारत के केरल राज्य ब्राजील के पूर्वी तट पर, संयुक्त राज्य के फ्लोरिडा तट एवं इदाहो राज्य प्रमुख उत्पादक हैं। परमाणु विद्युत ऊर्जा को 'भविष्य की ऊर्जा' कहा जाता है।

परमाणु ऊर्जा उत्पादक देश—संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जापान, रूस, उत्तरी कोरिया, जर्मनी, कनाडा, यूक्रेन, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, चीन, स्पेन, बेल्जियम, स्विटजरलैण्ड, चेक रिपब्लिकन आदि (अवरोही क्रम में)।

5. **जल विद्युत**—इसके उत्पादन के लिये निरन्तर प्रवाही जल, प्रपात प्राविधिकी माँग के क्षेत्र प्रमुख कारक हैं। यद्यपि अफ्रीका पर विश्व की 41% से अधिक सम्भाव्य (Potential) जल विद्युत ऊर्जा विद्यमान है। किन्तु यहाँ 1% से भी कम ऊर्जा विकसित की गयी है। इसके विपरीत एशिया (23%) उत्तरी अमेरिका (13%) यूरोप (10.5%) तथा दक्षिण अमेरिका (8.5%) में कोष्ठकानुसार जल विद्युत का विभव मिलता है।

प्रमुख जल विद्युत उत्पादक देश—क्रमशः (अवरोही क्रम में) चीन, ब्राजील, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, नार्वे, भारत, जापान, वेनेजुएला, स्वीडन, फ्रांस, कोलम्बिया, इटली, आस्ट्रिया, स्विटजरलैण्ड, तुर्की आदि हैं।

विश्व की प्रमुख बाँध परियोजनाएँ
(Main Dam Projects of the World)

संयुक्त राज्य अमेरिका—टैनेसी घाटी एवं बहुउद्देशीय परियोजना (टैनेसी नदी) ग्राण्ड कूली तथा बोनविले (कोलम्बिया नदी), हूवर तथा ग्लेन केनयन बाँध (कोलोरेडो नदी), सान जोआक्विन बाँध (कैलिफोर्निया), फोर्ट पैक, गैरिसन, ओआहै, बिग बियर, फोर्ट रैण्डल, गेविन्स पोर्ट (मिसौरी नदी), कूलिज तथा रूजवेल्ट बाँध (कोलोरेडो की सहायकों पर)।

रूस—वोल्खोव, बोल्गा, सिमल्यांस्का, मिंगचौर, ग्युमुक्ष, गोर्की, कामा, ब्रात्स्क, पावलोव्सक (उफा नदी), कौनास, नोवोसिबिर्स्क (ओव नदी), इर्कुट्स्क (अंगारा नदी) उस्त-कोमेनो गोर्स्क (इर्तिश नदी)।

चीन—फैंगमैन (संगारी नदी), सानमेन बाँध (ह्वांगहो), लिउकिया कुआंगतिंग (मुंगतिंग नदी), शिल्सेतान (सिचुआन), शांगथू (ल्यूची), सिनान बाँध, आनह्वेई बाँध, सिकियांग बाँध, थ्री-गॉर्जेस बाँध ।

भारत—कोयना नदी पर कोयना बाँध, कावेरी नदी पर शिवसमुद्रम, पायकारा, मैटूर पापानासम, पेरियार, कुण्डा, मेयार, पल्लीवासल, सेंगुलम, इदुक्की, सबरिगिरि, तुंगभद्रा, नागार्जुन सागर, श्री शैलम, सितेरू, मचकुण्ड, हीराकुण्ड, दामोदर नदी घाटी परियोजना, कोसी, चम्बल, भाखड़ा नाँगल बाँध, टिहरी बाँध।

अन्य प्रमुख बाँध—अफ्रीका में जैम्बेजी नदी पर करीबा बाँध, मिस्र में असवान बाँध, घाना में वोल्टा नदी पर अकोसोम्बो बाँध, सूडान में नील नदी पर सेनार बाँध, युगाण्डा में ओवेन प्रपात, दक्षिण अमेरिका में ब्राजील पराना नदी पर इताइपु बाँध।

वैकल्पिक (गैर परम्परागत) ऊर्जा (Alternative or Non-conventional Energy)

1. **सौर ऊर्जा**—संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया के मोजाक मरुस्थल में सोलर बम।
2. **पवन ऊर्जा**—कैलिफोर्निया (संयुक्त राज्य अमेरिका) में एटलामोन्ट पास में विश्व का विशालतम पवन फार्म है। चीन, डेनमार्क, नीदरलैण्ड्स भारत में भी पवन ऊर्जा विकसित है।
3. **भूतापीय ऊर्जा**—आइसलैण्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका (इदाहो राज्य में बोइस में), भारत (लद्दाख में युगा घाटी सम्भाव्य), इटली में (टस्कनी डिस्ट्रिक्ट), न्यूजीलैण्ड (बराक) मैक्सिको, फिलीपीन्स, जापान, इण्डोनेशिया तथा डेनमार्क।
4. **ज्वारीय ऊर्जा**—फ्रांस (लारैन्स) कनाडा (नोवास्कोशिया में फण्डी की खाड़ी क्षेत्र में अनापोलिस, शेपोडी, कैब्सकुक, एम्हर्स्ट आदि), नार्वे (क्वालसुण्ड), इंग्लैण्ड (डेवन तट), संयुक्त राज्य अमेरिका (सेन फ्रांसिस्को की खाड़ी में गोल्डन ग्रेट तथा न्यूयॉर्क सिटी में ईस्ट रिवर पर), उत्तरी आयरलैण्ड (स्ट्रैंग फोर्ड लो), रूस (बेरेन्ट्स सागर में किसलय गुबा), दक्षिण कोरिया (जिन्दो उल्दोलमोक)।
5. **लहर ऊर्जा**—पुर्तगाल (एगुकाडूप लहर पार्क) विश्व का प्रथम व्यावसायिक लहर फार्म है। इसके पूर्व फ्रांस में बोर्डो के निकट रोयाँ में प्लान्ट लगाया गया। स्कॉटलैण्ड, कार्नवाल (इंग्लैण्ड) तथा पश्चिमी आस्ट्रेलिया में अन्य छोटे प्लान्ट लगाये गये हैं।
6. **बायोमास ऊर्जा**—लकड़ी, अपशिष्ट पदार्थों, एल्कोहोल आदि से लघु स्तर पर जैवकार ऊर्जा बनायी जाती है। ब्राजील में इकानोल से, संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का से, चीन में बायोगैस से, भारत में गोबर गैस, चावल के भूसे, गन्ने की खोई तथा नगरीय कचरे से ऊर्जा प्लान्ट लगाये गये हैं।

TOUCH 'n' PASS

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्र.1. वन संपदा का एक उदाहरण है–
(क) मिट्टी (ख) लकड़ी (ग) ताँबा (घ) एल्युमिनियम
उत्तर (ख) लकड़ी

प्र.2. धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है?
(क) प्राकृतिक संसाधन (ख) भौतिक संसाधन (ग) औद्योगिक संसाधन (घ) सामाजिक संसाधन
उत्तर (क) प्राकृतिक संसाधन

प्र.3. निम्नलिखित में से कौन-सा मानव निर्मित संसाधन है?
(क) उष्णकटिबंधीय (ख) झरने का जल
(ग) पहाड़ (घ) कैंसर उपचार की औषधि
उत्तर (घ) कैंसर उपचार की औषधि

प्र.4. भारत का कौन-सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है?
(क) केरल (ख) तमिलनाडु (ग) झारखंड (घ) कर्नाटक
उत्तर (घ) कर्नाटक

प्र.5. भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया गया है?
(क) विनिर्माण (ख) विद्युत (ग) निर्माण (घ) खनन एवं उत्खनन
उत्तर (घ) खनन एवं उत्खनन

प्र.6. देश में किस राज्य में खनिज के सर्वाधिक भंडार है?
(क) बिहार (ख) उत्तर प्रदेश (ग) झारखंड (घ) पंजाब
उत्तर (ग) झारखंड

प्र.7. जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है–
(क) नाभिकीय संलयन (ख) चन्द्रमा (ग) सूर्य (घ) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (घ) इनमें से कोई नहीं

प्र.8. निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है?
(क) लकड़ी (ख) गोबर गैस (ग) नाभिकीय ऊर्जा (घ) कोयला
उत्तर (ग) नाभिकीय ऊर्जा

प्र.9. संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग करना है उन्हें नवीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है?
(क) संसाधन (ख) सतत पोषण (ग) संसाधन विलक्षण (घ) संसाधन निरूपण
उत्तर (क) संसाधन

प्र.10. प्रौद्योगिकी भी एक निर्मित संसाधन है–
(क) स्थानिक (ख) व्यापक (ग) मानव (घ) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (ग) मानव

प्र.11. विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है?
(क) तीन (ख) दो (ग) चार (घ) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (ख) दो

प्र.12. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन पेटेन्ट को सही तरीके से परिभाषित करता है?
(क) किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार (ख) किसी कलात्मक पूँजी पर एकमात्र अधिकार
(ग) किसी व्यावसायिक बौद्धिक पूँजी पर एकमात्र अधिकार (घ) उपरोक्त सभी
उत्तर (क) किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार

प्र.13. भारत में निम्नलिखित इस्पात-संयंत्र में से कौन-सा विश्व स्तरीय स्टेनलेस स्टील का प्रमुख उत्पादक है?
(क) बोकारो (ख) दुर्गापुर (ग) सलेम (घ) विशाखापत्तनम
उत्तर (ग) सलेम

TOUCH 'n PASS

प्र.14. उड़ीसा में लौह अयस्क कहाँ स्थित हैं?
(क) मयूरभंज जिला (ख) केन्दुझर जिला
(ग) (क) और (ख) दोनों (घ) कोरापुट जिला
उत्तर (ग) (क) और (ख) दोनों

प्र.15. अनुपम संसाधन किसे कहा गया है?
(क) नदीयों को (ख) खनिजों को (ग) वन को (घ) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (ग) वन को

प्र.16. खनिजों को कितने वर्गों में बाँटा गया है?
(क) दो (ख) तीन (ग) चार (घ) पाँच
उत्तर (क) दो

प्र.17. निम्न में से कौन अधात्विक खनिज है?
(क) मैंगनीज (ख) क्रोमाइट (ग) चाँदी (घ) कोयला
उत्तर (घ) कोयला

प्र.18. स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं?
(क) तीन (ख) चार (ग) छः (घ) आठ
उत्तर (ख) चार

प्र.19. ''संसाधन हुआ नहीं करते, बना करते हैं।'' यह कथन है–
(क) जिम्मरमैन (ख) गिन्सन (ग) अलेक्जेण्डर (घ) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (क) जिम्मरमैन

प्र.20. आर्थिक क्रियाओं को कितने वर्गों में बाँटा गया है?
(क) तीन (ख) चार (ग) पाँच (घ) दो
उत्तर (ख) चार

प्र.21. एल्युमिनियम का अयस्क है–
(क) स्फेरेलाइट (ख) कैरसेराइट (ग) बॉक्साइट (घ) चेल्को पाइराइट
उत्तर (ग) बॉक्साइट

प्र.22. विश्व का प्रथम व्यावसायिक लहर फार्म है–
(क) एगुकाडूप लहर पार्क (ख) स्ट्रैंग फोर्ड लो (ग) टस्कनी डिस्ट्रिक्ट (घ) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (क) एगुकाडूप लहर पार्क

प्र.23. 'भविष्य की ऊर्जा' किसे कहा जाता है?
(क) विद्युत ऊर्जा को (ख) परमाणु विद्युत ऊर्जा को
(ग) प्राकृतिक गैसों को (घ) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (ख) परमाणु विद्युत ऊर्जा को

प्र.24. चाँदी का प्रमुख अयस्क है–
(क) कैरसेराइट (ख) स्फेरेलाइट (ग) अर्जेन्टाइट (घ) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (ग) अर्जेन्टाइट

प्र.25. टिन का प्रमुख अयस्क है–
(क) कैरसेराइट (ख) अर्जेन्टाइट (ग) क्रयोलाइट (घ) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (क) कैरसेराइट

प्र.26. निम्नलिखित में से कौन कोयले की किस्म नहीं है?
(क) एन्थ्रेसाइट (ख) विटुमिनस (ग) लिग्नाइट (घ) कैरसेराइट
उत्तर (घ) कैरसेराइट

TOUCH 'n' PASS

❑

UNIT-III

वानिकी, मत्स्यपालन एवं खनन गतिविधियों की स्थैतिक-आर्थिक संरचना

Spatio-Economic Organisation of Forestry, Fishing and Mining Activities

खण्ड-अ अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. खनन से आप क्या समझते हैं?

What do you Understand by Mining?

उत्तर खनन पृथ्वी से कच्चे संसाधनों; जैसे—धातु, मिट्टी, रत्न और खनिज निकालने की प्रक्रिया है। एक खनन निगम के भंडार और संसाधन इसकी सबसे मूल्यवान सम्पत्ति है। समकालीन खनन प्रक्रिया में खनन संचालन के सम्भावित लाभ का निर्धारण, अयस्क जमा का पता लगाना और कीमती वस्तुओं को निकालना शामिल है।

द्वितीय क्षेत्र की प्रमुख उत्पादों की एक विस्तृत शृंखला का निर्माण और उत्पादन के लिए कच्चे माल के खनन पर काफी निर्भर करता है।

प्र.2. मत्स्य पालन को परिभाषित कीजिए।

Define Pisciculture.

उत्तर दुनिया में सबसे महत्त्वपूर्ण प्राथमिक उद्योगों में से एक मछली पकड़ना है। इसमें मछली उत्पादों की बिक्री, शिपिंग, विपणन, संरक्षण और प्रसंस्करण जैसे विभिन्न कार्य शामिल हैं। औद्योगिक मछली पालन दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती खाद्य उत्पादन पद्धति है और मछली फार्म वर्तमान में दुनिया के लगभग आधे समुद्री भोजन प्रदान करते हैं।

प्र.3. प्राथमिक क्षेत्र में किस प्रकार के लोग कार्य करते हैं?

What types of people work in Primary Sector?

उत्तर प्राथमिक क्षेत्र के श्रमिकों में किसान, कोयला खनिज और शिकारी शामिल हैं। यह एक सत्य है कि जैसे-जैसे कोई देश विकसित होता है, प्राथमिक उद्योग पर उसकी निर्भरता कम होती जाती है तथा द्वितीयक तृतीयक उद्योगों पर उसकी निर्भरता बढ़ती जाती है।

प्र.4. प्राथमिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत कार्यबल कार्यरत हैं?

What percentage of the work force is employed in the Primary Sector?

उत्तर इथियोपिया, पूर्वी अफ्रीका में, एक विकासशील अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण है, जिसमें प्राथमिक उद्योग 88% रोजगार के लिए जिम्मेदार हैं, तृतीयक उद्योग 10% के लिए जिम्मेदार हैं। द्वितीयक क्षेत्रों में 2% का योगदान है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के औद्योगिक देशों में प्राथमिक उद्योग में रोजगार सिर्फ 3% है। द्वितीयक उद्योग 25% है, तृतीयक उद्योग 70% है और चतुर्थ वर्ग उद्योग 2% है।

प्र.5. पशुचारण क्या है?

What is Herding?

उत्तर आखेट पर निर्भर रहने वाले समूह ने जब ये महसूस किया कि केवल आखेट से जीवन का भरण-पोषण नहीं किया जा सकता है, तब मानव ने पशुपालन व्यवसाय के विषय में सोचा। विभिन्न जलवायुविक दशाओं में रहने वाले लोगों ने उन क्षेत्रों में

TOUCH 'n' PASS

पाए जाने वाले पशुओं का चयन करके पालतू बनाया। भौगोलिक कारकों एवं तकनीकी विकास के आधार पर वर्तमान समय में पशुपालन व्यवसाय निर्वहन अथवा व्यापारिक स्तर पर किया जाता है।

खण्ड-ब लघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. प्राथमिक क्रियाओं में आखेट एवं भोजन संग्रह का उल्लेख कीजिए।
Mention Hunting and Food Gathering among the Primary Activities.

उत्तर

आखेट एवं भोजन संग्रह
(Hunting and Food Gathering)

मानव सभ्यता के आरंभिक युग में आदिमकालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए अपने समीप के वातावरण पर निर्भर रहता था। उसका जीवन-निर्वाह दो कार्यों द्वारा होता था (क) पशुओं का आखेट कर, और (ख) अपने समीप के जंगलों से खाने योग्य जंगली पौधे एवं कंद-मूल आदि को एकत्रित कर।

आदिमकालीन समाज जंगली पशुओं पर निर्भर था। अतिशीत एवं अत्यधिक गर्म प्रदेशों के रहने वाले लोग आखेट द्वारा जीवन-यापन करते थे। तकनीकी विकास के कारण यद्यपि मत्स्य-ग्रहण आधुनिकीकरण से युक्त हो गया है तथापि तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग अब भी मछली पकड़ने पर निर्भर हैं। यह बगैर तकनीकी दशाओं में किया जाता है। इसे अधिकतर आदिमकालीन समाज के लोग करते हैं। ये लोग अपने भोजन, वस्त्र एवं शरण की आवश्यकता की पूर्ति हेतु पशुओं एवं वनस्पति का संग्रह करते हैं। इस कार्य के लिए बहुत कम पूँजी एवं निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसमें भोजन अधिशेष भी नहीं रहता है एवं प्रति व्यक्ति उत्पादकता भी कम होती है।

भोजन संग्रह विश्व के दो भागों में किया जाता है—(i) उच्च अक्षांश के क्षेत्र जिसमें उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया एवं दक्षिणी चिली आते हैं (ii) निम्न अक्षांश के क्षेत्र जिसमें अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, आस्ट्रेलिया एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के आंतरिक प्रदेश आते हैं।

आधुनिक समय में भोजन संग्रह के कार्य का कुछ भागों में व्यापारीकरण भी हो गया है। ये लोग कीमती पौधों की पत्तियों, छाल एवं औषधीय पौधों को सामान्य रूप से संशोधित कर बाजार में बेचने का कार्य भी करते हैं। पौधे के विभिन्न भागों का ये उपयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर छाल का उपयोग कुनैन, चमड़ा तैयार करना एवं कार्क के लिए; पत्तियों का उपयोग, पेय पदार्थ, दवाइयाँ एवं कांतिवर्द्धक वस्तुएँ बनाने के लिए, रेशे को कपड़ा बनाने, दृढ़फल को भोजन एवं तेल के लिए एवं पेड़ के तने का उपयोग रबड़, बलाटा, गोंद व राल बनाने के लिए करते हैं।

विश्व स्तर पर भोजन संग्रहण का अधिक महत्त्व नहीं है। इन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त उत्पाद विश्व बाजार में प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर सकते। कई प्रकार की अच्छी किस्म एवं कम दाम वाली कृत्रिम उत्पादों ने उष्ण कटिबंधीय वन के भोजन संग्रह करने वाले समूहों के उत्पादों का स्थान ले लिया है।

प्र.2. चलवासी पशुचारण को परिभाषित कीजिए।
Define Nomadic Herding.

उत्तर

चलवासी पशुचारण
(Nomadic Herding)

चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन-निर्वाह व्यवसाय रहा है जिसमें पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार एवं यातायात के लिए पशुओं पर ही निर्भर रहता था। वे अपने पालतू पशुओं के साथ पानी एवं चरागाह की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते थे। इन पशुचारक वर्गों के अपने-अपने निश्चित चरागाह क्षेत्र होते थे।

भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के पशु पाले जाते हैं। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में गाय-बैल प्रमुख पशु हैं, जबकि सहारा एवं एशिया के मरुस्थलों में भेड़, बकरी एवं ऊँट पाला जाता है। तिब्बत एवं एंडीज के पर्वतीय भागों में याँक व लामा एवं आर्कटिक और उप उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में रेंडियर पाला जाता है।

चलवासी पशुचारण के तीन प्रमुख क्षेत्र हैं। इसका प्रमुख क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका के एटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया एवं मध्य चीन तक फैला है। दूसरा क्षेत्र यूरोप तथा एशिया के टुंड्रा प्रदेश में है जबकि तीसरा क्षेत्र दक्षिणी गोलार्द्ध में दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका एवं मेडागास्कर द्वीप पर है।

TOUCH 'n PASS

नए चरागाहों की खोज में ये पशुचारक समतल भागों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में लम्बी दूरियाँ तय करते हैं। गर्मियों में मैदानी भाग से पर्वतीय चरागाह की ओर एवं शीत में पर्वतीय भाग से मैदानी चरागाहों की ओर प्रवास करते हैं। इनकी इस गतिविधि को ऋतुप्रवास कहा जाता है। भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी एवं भूटिया लोगों के समूह ग्रीष्मकाल में मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं एवं शीतकाल में पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्र में आ जाते हैं। इसी प्रकार टुंड्रा प्रदेश में ग्रीष्म काल में दक्षिण से उत्तर की ओर एवं शीत में उत्तर से दक्षिण की ओर चलवासी पशुचारकों का पशुओं के साथ प्रवास होता है। चलवासी पशुचारकों की संख्या अब घट रही है एवं इनके द्वारा उपयोग में लाए गए क्षेत्र में भी कमी हो रही है। इसके दो कारण हैं (क) राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण (ख) कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना बनाना।

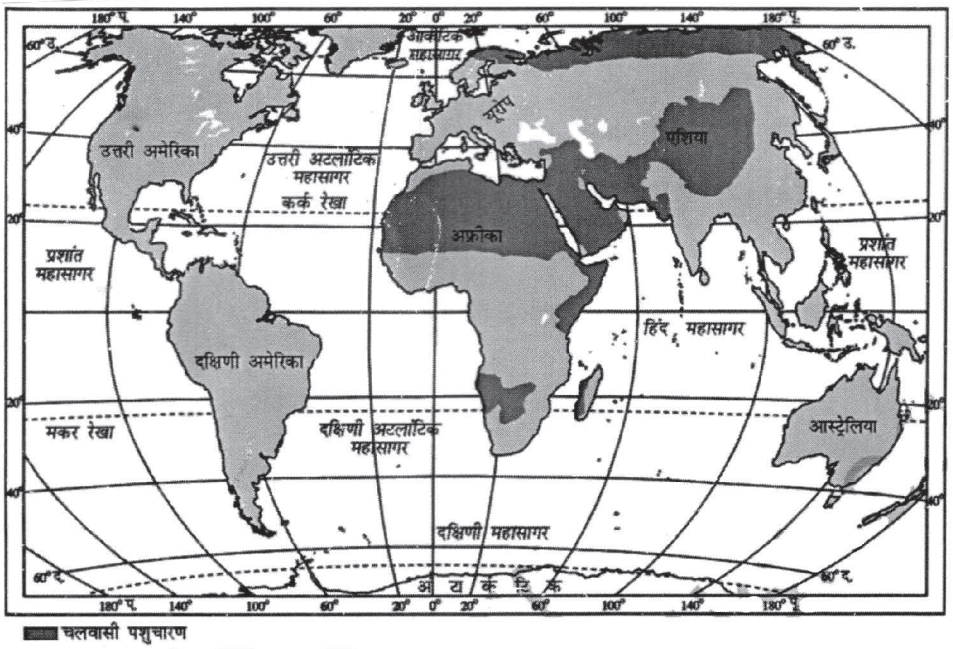

चित्र : चलवासी पशुचारण के क्षेत्र

प्र.3. वाणिज्य पशुधन पालन पर चित्र सहित संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए।

Write a short note on Commercial Animal Husbandry with a diagram.

उत्तर

वाणिज्य पशुधन पालन
(Commercial Animal Husbandry)

चलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्य पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित एवं पूँजी प्रधान है। वाणिज्य पशुधन पालन पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है एवं फार्म भी स्थायी होते हैं। यह फार्म विशाल क्षेत्र पर फैले होते हैं एवं सम्पूर्ण क्षेत्र को छोटी-छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। चराई को नियंत्रित करने के लिए इन्हें बाड़ लगाकर एक-दूसरे से अलग कर दिया जाता है। जब चराई के कारण एक छोटे क्षेत्र की घास समाप्त हो जाती है तब पशुओं को दूसरे छोटे क्षेत्र में ले जाया जाता है। वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं की संख्या भी चरागाह की वहन क्षमता के अनुसार रखी जाती है।

यह एक विशिष्ट गतिविधि है, जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। प्रमुख पशुओं में भेड़, बकरी, गाय-बैल एवं घोड़े हैं। इनसे प्राप्त मांस, खालें एवं ऊन को वैज्ञानिक ढंग से संसाधित एवं डिब्बा बंद कर विश्व के बाजारों में निर्यात कर दिया जाता है। पशुफार्म में पशुधन पालन वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। इसमें मुख्य ध्यान पशुओं के प्रजनन, जननिक सुधार बीमारियों पर नियंत्रण एवं उनके स्वास्थ्य पर दिया जाता है।

विश्व में न्यूजीलैंड, आस्टेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है।

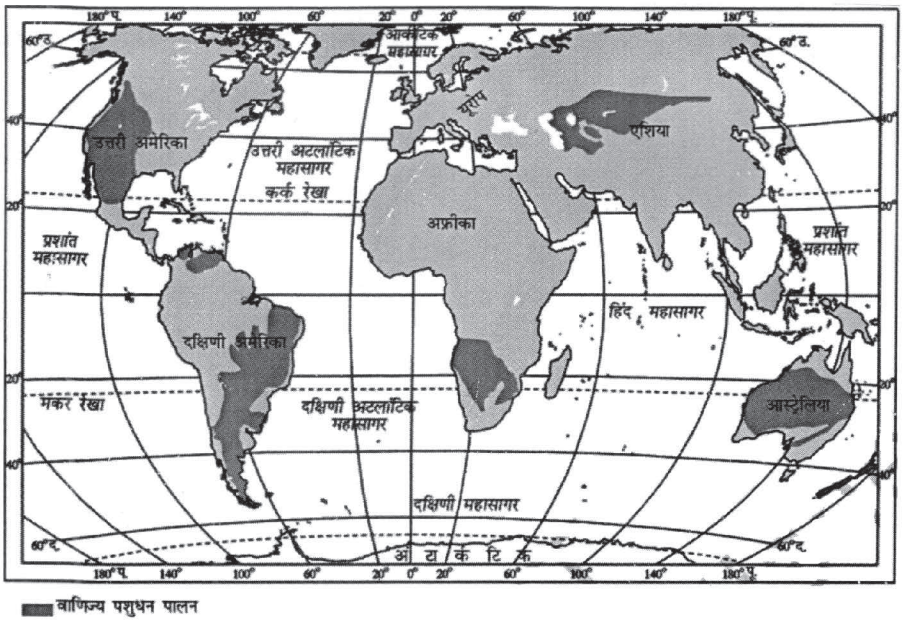

चित्र : वाणिज्य पशुपालन के क्षेत्र

प्र.4. खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक एवं विधियों का उल्लेख कीजिए।
Explain the factors and methods affecting Mining Operations.

उत्तर

खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक एवं विधियाँ
(Factors and Methods Affecting Mining Operations)

मानव विकास के इतिहास में खनिजों की खोज की कई अवस्थाएँ देखी जा सकती हैं; जैसे—ताम्र युग, कांस्य युग एवं लौह युग। प्राचीन काल में खनिजों का उपयोग औजार बनाने, बर्तन बनाने एवं हथियार बनाने तक ही सीमित था। इसका वास्तविक विकास औद्योगिक क्रांति के पश्चात् ही सम्भव हुआ एवं निरन्तर इसका महत्त्व बढ़ता रहा है।

खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक

खनन कार्य की लाभप्रदता दो बातों पर निर्भर करती है—

1. भौतिक कारक जिनमें खनिज निक्षेपों के आकार, श्रेणी एवं उपस्थिति की अवस्था को सम्मिलित करते हैं।
2. आर्थिक कारक जिनमें खनिज की माँग, विद्यमान तकनीकी ज्ञान एवं उसका उपयोग, अवसंरचना के विकास के लिए उपलब्ध पूँजी एवं यातायात व श्रम पर होने वाला व्यय आता है।

खनन की विधियाँ (Methods of Mining)

उपस्थिति की अवस्था एवं अयस्क की प्रकृति के आधार पर खनन के दो प्रकार हैं— धरातलीय एवं भूमिगत खनन। धरातलीय खनन को विवृत खनन भी कहा जाता है। यह खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका है, क्योंकि इस विधि में सुरक्षात्मक पूर्वोपायों एवं उपकरणों पर अतिरिक्त खर्च अपेक्षाकृत न्यूनतम होता है एवं उत्पादन शीघ्र व अधिक होता है।

जब अयस्क धरातल के नीचे गहराई में होता है तब **भूमिगत** अथवा **कूपकी खनन** विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में लंबवत् कूपक गहराई तक स्थित हैं, जहाँ से भूमिगत गैलरियाँ खनिजों तक पहुँचने के लिए फैली हैं। इन मार्गों से होकर खनिजों का निष्कर्षण एवं परिवहन धरातल तक किया जाता है। खदान में कार्य करने वाले श्रमिकों तथा निकाले जाने वाले खनिजों के सुरक्षित और प्रभावी आवागमन हेतु इसमें विशेष प्रकार की लिफ्ट बेधक (बरमा), माल ढोने की गाड़ियाँ तथा वायु संचार प्रणाली की आवश्यकता होती है। खनन का यह तरीका जोखिम भरा है क्योंकि जहरीली गैसें, आग एवं बाढ़ के कारण कई बार दुर्घटनाएँ होने का भय रहता है।

विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश उत्पादन की खनन, प्रसंस्करण एवं शोधन कार्य से पीछे हट रहे हैं क्योंकि इसमें श्रमिक लागत अधिक आने लगी है। जबकि विकासशील देश अपने विशाल श्रमिक शक्ति के बल पर अपने देशवासियों के ऊँचे रहन-सहन को बनाए रखने के लिए खनन कार्य को महत्त्व दे रहे हैं। अफ्रीका के कई देश, दक्षिण अमेरिका के कुछ देश एवं एशिया में आय के साधनों का पचास प्रतिशत तक खनन कार्य से प्राप्त होता है।

खण्ड-स विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. प्राथमिक क्रियाओं में कृषि की विभिन्न मुख्य प्रणालियों का वर्णन कीजिए।
Describe the different main methods of Agriculture in Primary Activities.

उत्तर

कृषि (Agriculture)

विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दशाएँ कृषि कार्य को प्रभावित करती हैं एवं इसी प्रभाव के कारण विभिन्न कृषि प्रणालियाँ देखी जाती हैं। कृषि विभिन्न प्रकार के फसलों का बोया जाना तथा पशुपालन विभिन्न कृषि विधियों पर आधारित होता है। मुख्य प्रणालियाँ निम्नलिखित हैं—

1. निर्वाह कृषि

इस प्रकार की कृषि में कृषि क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय उत्पादों का सम्पूर्ण अथवा लगभग का उपयोग करते हैं। इसको दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

(a) आदिकालीन निर्वाह कृषि

आदिकालीन निर्वाह कृषि अथवा स्थानांतरणशील कृषि का कार्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ आदिम जाति के लोग यह कृषि करते हैं। इसका क्षेत्र अफ्रीका, दक्षिणी एवं मध्य अमेरिका का उष्णकटिबन्धीय भाग एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया है।

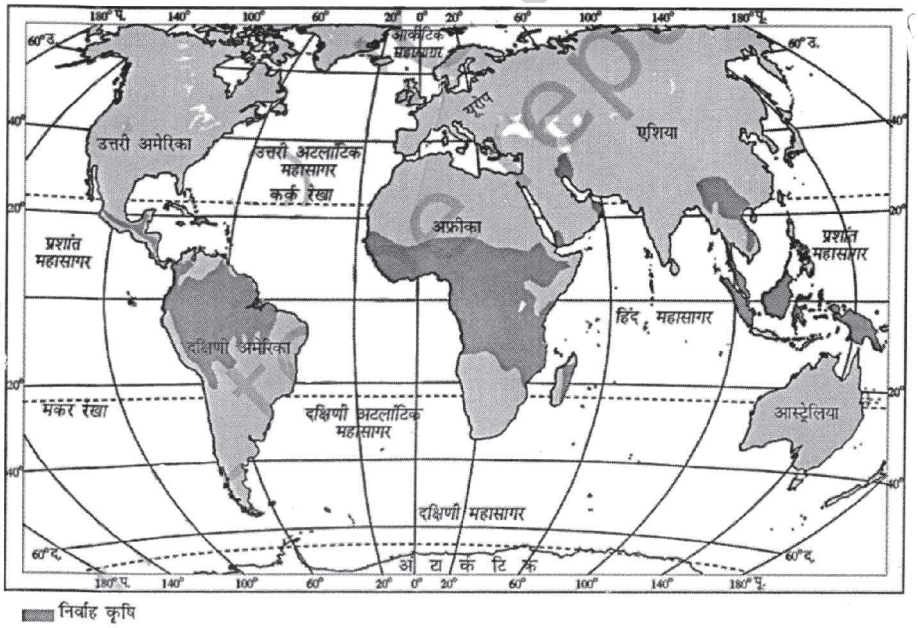

चित्र : आदिकालीन निर्वाह कृषि के क्षेत्र

इन क्षेत्रों की वनस्पति को जला दिया जाता है एवं जली हुई राख की परत उर्वरक का कार्य करती है। इस प्रकार स्थानांतरणशील कृषि कर्तन एवं दहन कृषि भी कहलाती है। इसमें बोए गए खेत बहुत छोटे-छोटे होते हैं एवं खेती भी पुराने औजार; जैसे, लकड़ी, कुदाली एवं फावड़े द्वारा की जाती है। कुछ समय पश्चात् (3 से 5 वर्ष) जब मिट्टी का उपाजाऊपन समाप्त हो जाता है, तब कृषक नए क्षेत्र में वन जलाकर कृषि के लिए भूमि तैयार करता है। कुछ समय पश्चात् कृषक वापस पहले वाले कृषि क्षेत्र पर कृषि

कार्य करने आ जाता है। इस कृषि कार्य में सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस क्षेत्र में भूमि की उर्वरता कम होती जाती है जिससे झूम का चक्र (आग लगाकर कृषि क्षेत्र तैयार करना) छोटा होता जाता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में इसे झूमिंग, मध्य अमेरिका एवं मैक्सिको में मिल्पा एवं मलेशिया व इंडोनेशिया में लादांग कहा जाता है।

(b) गहन निर्वाह कृषि

इस प्रकार की कृषि मानसून एशिया के घने बसे देशों में की जाती है।

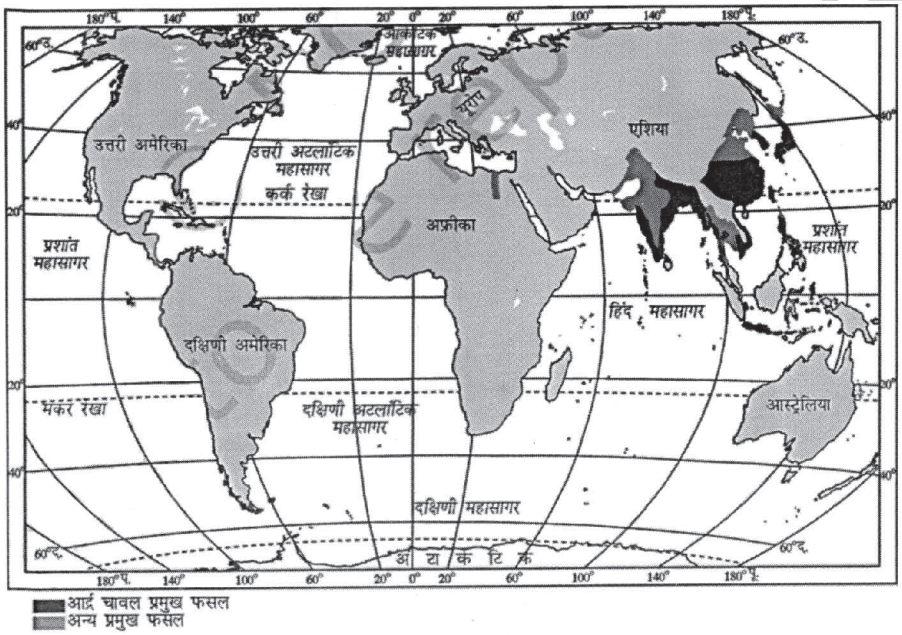

चित्र : गहन निर्वाह कृषि के क्षेत्र

गहन निर्वाह कृषि के दो प्रकार हैं—

(i) **चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि**—इसमें चावल प्रमुख फसल होती है। अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार छोटा होता है एवं कृषि कार्य में कृषक का सम्पूर्ण परिवार लगा रहता है। भूमि का गहन उपयोग होता है एवं यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम का अधिक महत्त्व है। उर्वरता बनाए रखने के लिए पशुओं के गोबर की खाद एवं हरी खाद का उपयोग किया जाता है। इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है, परन्तु प्रति कृषक उत्पादन कम है।

(ii) **चावल रहित गहन निर्वाह कृषि**—मानसून एशिया के अनेक भागों में उच्चावच, जलवायु, मृदा तथा अन्य भौगोलिक कारकों की भिन्नता के कारण धान की फसल उगाना प्राय: सम्भव नहीं है। उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया एवं उत्तरी जापान में गेहूँ, सोयाबीन, जौ एवं सोरपम बोया जाता है। भारत में सिंध-गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग में गेहूँ एवं दक्षिणी व पश्चिमी शुष्क प्रदेश में ज्वार-बाजरा प्रमुख रूप से उगाया जाता है। इस कृषि की अधिकतर विशेषताएँ वो ही है जो चावल प्रधान कृषि की हैं। केवल अंतर यह है कि इसमें सिंचाई की जाती है।

2. रोपण कृषि

यूरोपीय लोगों ने विश्व के अनेक भागों का औपनिवेशीकरण किया तथा कृषि के कुछ अन्य रूपों की शुरुआत की; जैसे—रोपण कृषि, जो वृहद् स्तरीय लाभोन्मुख उत्पादन प्रणाली है। यूरोपीय उपनिवेशों ने अपने अधीन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में चाय, कॉफी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केले एवं अनन्नास की पौध लगाई।

इस कृषि की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें कृषि क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता है। इसमें अधिक पूँजी निवेश, उच्च प्रबंध एवं तकनीकी आधार एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। यह एक फसली कृषि है जिसमें किसी एक फसल के

उत्पादन पर ही सकेंद्रण किया जाता है। श्रमिक सस्ते मिल जाते हैं एवं यातायात विकसित होता है जिसके द्वारा बागान एवं बाजार सुचारू रूप से जुड़े रहते हैं।

फ्रांसवासियों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी एवं कोकोआ की पौध लगाई थी। ब्रिटेनवासियों ने भारत एवं लंका में चाय के बाग, मलेशिया में रबड़ के बाग एवं पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना एवं केले के बाग विकसित किए। स्पेन एवं अमेरिकावासियों ने फिलीपीन्स में नारियल व गन्ने के बागान लगाए। इंडोनेशिया में एक समय गन्ने की कृषि में हॉलैंडवासियों (डचों) का एकाधिकार था। ब्राजील में अभी भी कुछ कॉफी के बागान जिन्हें फेजेंडा कहा जाता है यूरोपवासियों के नियंत्रण में है। वर्तमान में अधिकतर बागानों का स्वामित्व देशों की सरकार अथवा नागरिकों के नियंत्रण में है।

3. विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि

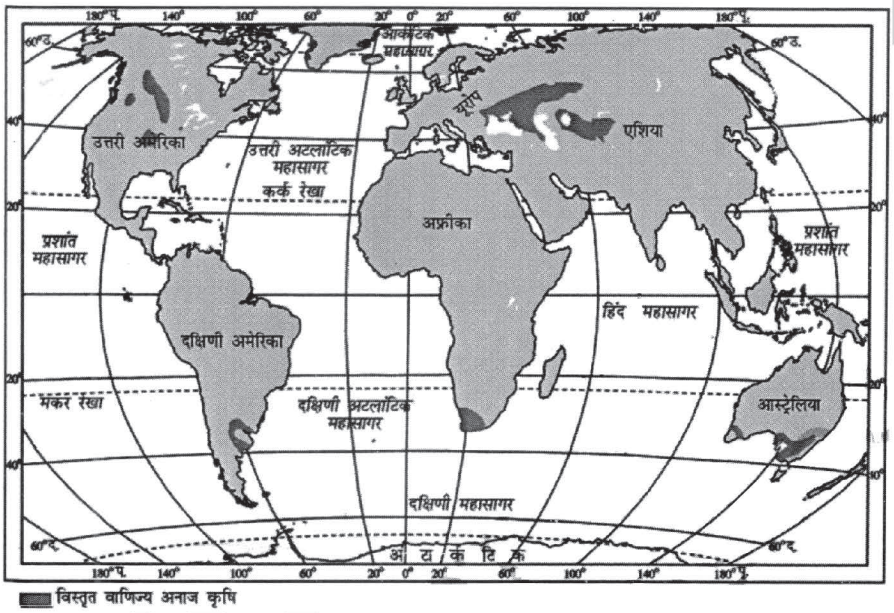

चित्र : विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के क्षेत्र

मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्द्ध शुष्क प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसकी मुख्य फसल गेहूँ है। यद्यपि अन्य फसलें; जैसे—मक्का, जौ, राई एवं जई भी बोई जाती है। इस कृषि में खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है एवं खेत जोतने से फसल काटने तक सभी कार्य यंत्रों द्वारा सम्पन्न किए जाते हैं। इसमें प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है परन्तु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। इसी प्रकार की कृषि का क्षेत्र यूरेशिया के स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका के प्रेयरीज, अर्जेंटीना के पंपास, दक्षिणी अफ्रीका के वेल्डस, आस्ट्रेलिया के डाउंस एवं न्यूजीलैंड के केंटरबरी के मैदान में है।

4. मिश्रित कृषि

इस प्रकार की कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है, उदाहरणस्वरूप उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी-अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरेशिया के कुछ भाग एवं दक्षिणी महाद्वीपों के समशीतोष्ण अक्षांश वाले भागों में इसका विस्तार है।

इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है। इसमें बोई जाने वाली फसलें गेहूँ, जौ, राई, जई, मक्का, चारे की फसल एवं कंद-मूल प्रमुख हैं। चारे की फसलें मिश्रित कृषि के मुख्य घटक हैं। फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को इसमें समान महत्त्व दिया जाता है। फसलों के साथ पशुओं; जैसे— मवेशी, भेड़, सुअर एवं कुक्कुर आय के मुख्य स्रोत हैं। शस्यावर्तन एवं अंत: फसली कृषि मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

विकसित कृषि यंत्र, इमारतों, रासायनिक एवं वनस्पति खाद (हरी खाद) के गहन उपयोग आदि पर अधिक पूँजी व्यय के साथ कृषकों की कुशलता और योग्यता मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषताएँ हैं।

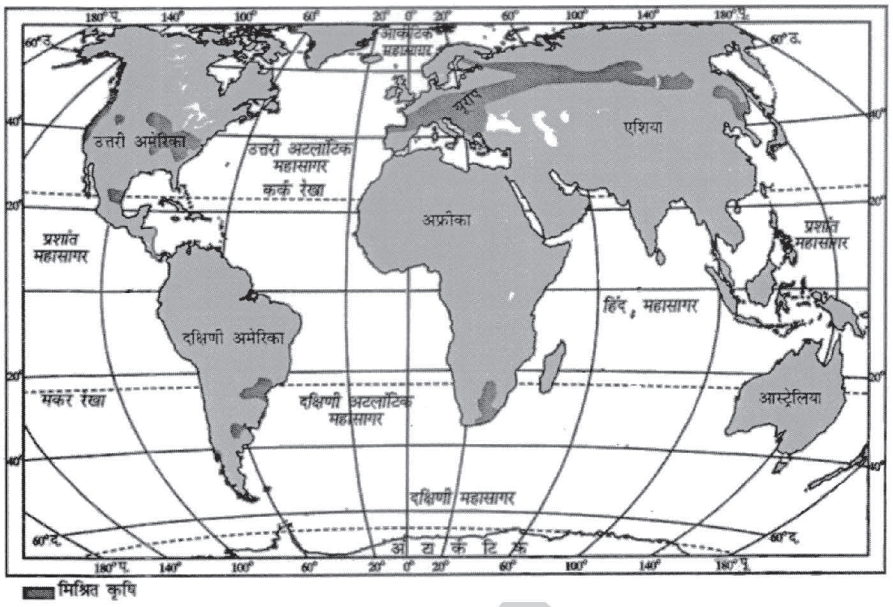

चित्र : मिश्रित कृषि के क्षेत्र

5. डेरी कृषि

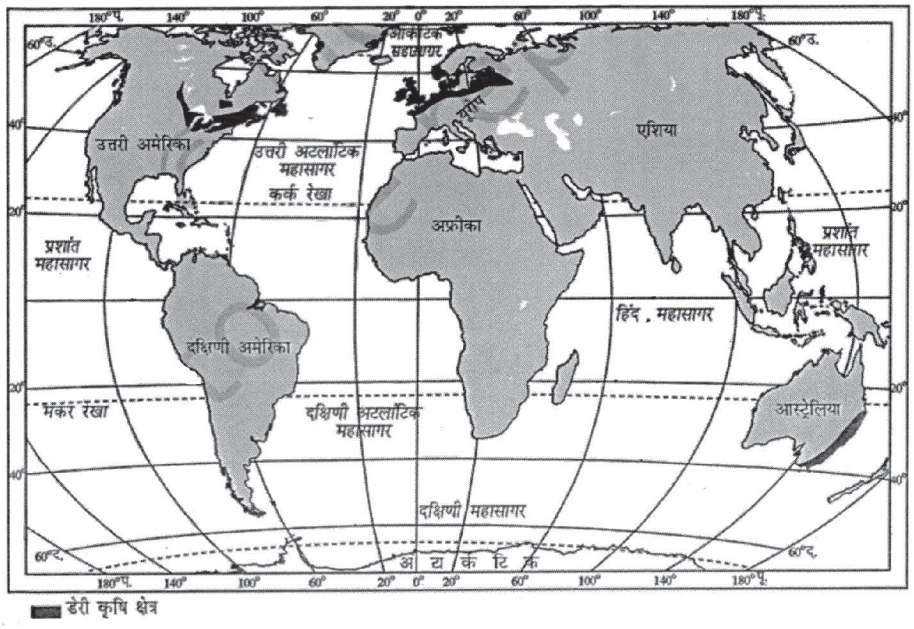

चित्र : डेरी कृषि के क्षेत्र

डेरी व्यवसाय दुधारु पशुओं के पालन-पोषण का सर्वाधिक उन्नत एवं दक्ष प्रकार है। इसमें पूँजी की भी अधिक आवश्यकता होती है। पशुओं के लिए छप्पर, घास संचित करने के भंडार एवं दुग्ध उत्पादन में अधिक यंत्रों के प्रयोग के लिए पूँजी भी अधिक चाहिए। पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन एवं पशु चिकित्सा पर भी अधिक ध्यान दिया जाता है। इसमें गहन श्रम की आवश्यकता होती

है। पशुओं को चराने, दूध निकालने आदि कार्यों के लिए वर्ष भर श्रम की आवश्यकता रहती है क्योंकि फसलों की तरह इनमें कोई अंतराल नहीं होता जिसमें श्रम की आवश्यकता न हो।

डेरी कृषि का कार्य नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र ताजा दूध एवं अन्य डेरी उत्पाद के अच्छे बाजार होते हैं। वर्तमान समय में विकसित यातायात के साधन, प्रशीतकों का उपयोग, पास्तेरीकरण की सुविधा के कारण विभिन्न डेरी उत्पादों को अधिक समय तक रखा जा सकता है।

वाणिज्य डेरी कृषि के तीन प्रमुख क्षेत्र हैं, सबसे बड़ा प्रदेश उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र है। दूसरा कनाडा एवं तीसरा क्षेत्र न्यूजीलैंड, दक्षिणी पूर्वी आस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया है।

6. भूमध्यसागरीय कृषि

भूमध्यसागरीय कृषि अति विशिष्ट प्रकार की कृषि है। इसका विस्तार भूमध्यसागर के समीपवर्ती क्षेत्र जो दक्षिणी यूरोप से उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनीशिया से एटलांटिक तट तक फैला है दक्षिणी कैलीफोर्निया, मध्यवर्ती चिली, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग एवं आस्ट्रेलिया के दक्षिण व दक्षिण पश्चिम भाग में है। खट्टे फलों की आपूर्ति करने में यह क्षेत्र महत्त्वपूर्ण है।

अंगूर की कृषि भूमध्यसागरीय क्षेत्र की विशेषता है। इस क्षेत्र के कई देशों में अच्छे किस्म के अंगूरों से उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा का उत्पादन किया जाता है। निम्न श्रेणी के अंगूरों को सुखाकर मुनक्का एवं किशमिश बनाई जाती हैं। अंजीर एवं जैतून भी यहाँ उत्पन्न होता है। शीत ऋतु में जब यूरोप एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में फलों एवं सब्जियों की माँग होती है तब इसी क्षेत्र से पूर्ति की जाती है।

7. बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि

इस प्रकार की कृषि में अधिक मुद्रा मिलने वाली फसलें; जैसे—सब्जियाँ, फल एवं पुष्प आदि लगाए जाते हैं जिनकी माँग नगरीय क्षेत्रों में होती है। इस कृषि में खेतों का आकार छोटा होता है एवं खेत अच्छे यातायात साधनों के द्वारा नगरीय केन्द्रों जहाँ ऊँची आय वाले उपभोक्ता रहते हैं। इसमें गहन श्रम एवं अधिक पूँजी की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त सिंचाई, उर्वरक, अच्छी किस्म के बीज, कीटनाशी, हरित गृह एवं शीत क्षेत्रों में कृत्रिम ताप का भी इस कृषि में उपयोग होता है।

इस प्रकार की कृषि उत्तरी पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग एवं भूमध्यसागरीय प्रदेश में अधिक विकसित है, जहाँ औद्योगिक क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक है। नीदरलैंड पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है। यहाँ से बागबानी फसल विशेषत: ट्यूलिप (एक प्रकार का फूल) पूरे यूरोप के प्रमुख शहरों में भेजा जाता है। जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियाँ पैदा करता है वहाँ इसको 'ट्रक कृषि' का नाम दिया जाता है। ट्रक फार्म एवं बाजार के मध्य की दूरी, जो एक ट्रक रात भर में तय करता है, उसी आधार पर इसका नाम ट्रक कृषि रखा गया है।

पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों मे उद्यान कृषि के अलावा कारखाना कृषि भी की जाती है। इसमें पशुधन पाला जाता है जिनमें विशेषत: गाय-बैल एवं कुक्कुर होते हैं। इसमें भवन निर्माण, यंत्र खरीदने, प्रकाश एवं ताप की व्यवस्था करने एवं पशु चिकित्सा के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। अच्छी नस्ल का चुनाव और प्रजनन की वैज्ञानिक विधियों कुक्कुर एवं पशुपालन के महत्त्वपूर्ण लक्षण हैं।

कृषि करने वाले संगठन के आधार पर भी कृषि के प्रकारों का वर्गीकरण किया जा सकता है। कृषि संगठन, कृषक का खेतों पर अपना अधिकार एवं उस पर सरकारी नीतियाँ जो कृषि में सहायक होती हैं, से प्रभावित होता है।

8. सहकारी कृषि

जब कृषकों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य सम्पन्न करे उसे सहकारी कृषि कहते हैं। इसमें व्यक्तिगत फार्म अक्षुण्ण रहते हुए सहकारी रूप में कृषि की जाती है।

सहकारी संस्था कृषकों को सभी रूप में सहायता करती है। यह सहायता कृषि उत्पाद में आने वाली सभी चीजों की खरीद करने, कृषि उत्पाद को उचित मूल्य पर बेचने एवं सस्ती दरों पर उचित साधनों को जुटाने के लिए होती है।

सहकारी आंदोलन एक शताब्दी पूर्व प्रारम्भ हुआ था एवं पश्चिमी यूरोप के डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन एवं इटली में यह सफलतापूर्वक चला। सबसे अधिक सफलता इसे डेनमार्क में मिली जहाँ प्रत्येक कृषक इसका सदस्य है।

9. सामूहिक कृषि

इस प्रकार की कृषि का आधारभूत सिद्धान्त यह होता है कि इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सम्पूर्ण समाज एवं सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। कृषि का यह प्रकार पूर्व सोवियत संघ में प्रारम्भ हुआ था जहाँ कृषि की दशा सुधारने एवं उत्पादन में वृद्धि व आत्मनिर्भरता प्राप्ति के लिए सामूहिक कृषि प्रारम्भ की गई। इस प्रकार की सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में **कोलखोज** का नाम दिया गया।

सभी कृषक अपने संसाधन; जैसे—भूमि, पशुधन एवं श्रम को मिलाकर कृषि कार्य करते थे। ये अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि का छोटा-सा भाग अपने अधिकार में भी रखते थे।

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्र.1. उपस्थिति की अवस्था एवं अयस्क की प्रकृति के आधार पर खनन कितने प्रकार के होते हैं?
(क) तीन (ख) दो (ग) एक (घ) चार

उत्तर (ख) दो

प्र.2. किस कृषि में प्रति एकड़ उत्पादन कम तथा प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है?
(क) मिश्रित कृषि (ख) विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि
(ग) रोपण कृषि (घ) डेरी कृषि

उत्तर (ख) विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि

प्र.3. प्राथमिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत कार्यबल कार्यरत हैं?
(क) 88% (ख) 10%
(ग) 2% (घ) इनमें से कोई नहीं

उत्तर (क) 88%

प्र.4. प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल नहीं है?
(क) कृषि (ख) मत्स्य पालन
(ग) अस्पताल (घ) पशु पालन

उत्तर (ग) अस्पताल

प्र.5. निम्नलिखित में से कौन-सी सबसे पुरानी ज्ञात कृषि वानिकी प्रणाली है?
(क) एली क्रॉपिंग (ख) टौंग्या प्रणाली
(ग) गृह उद्यान (घ) झूम कृषि

उत्तर (घ) झूम कृषि

प्र.6. वन नियम, 2022 निम्नलिखित में से किस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रख्यापित किया गया है?
(क) वन संरक्षण अधिनियम, 1980 (ख) वन संरक्षण अधिनियम, 1988
(ग) वन संरक्षण अधिनियम, 1996 (घ) वन अधिकार अधिनियम, 2006

उत्तर (क) वन संरक्षण अधिनियम, 1980

प्र.7. राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के अनुसार न्यूनतम वनावरण क्या है?
(क) एक-आधा (ख) एक-तिहाई
(ग) एक-चौथाई (घ) दो-तिहाई

उत्तर (ख) एक-तिहाई

प्र.8. वनों के तहत भूमि बढ़ाने के लिए उठाए गए चरणों में से कौन-सी गतिविधि विपरीत है?
(क) वनीकरण (ख) स्थानांतरण कृषि
(ग) सामाजिक वानिकी (घ) जल विभाजन विकास

उत्तर (ख) स्थानांतरण कृषि

TOUCH 'n PASS

प्र.9. सामाजिक वानिकी का अर्थ वनों का प्रबंधन और संरक्षण है। निम्नलिखित में से कौन-सा सामाजिक वानिकी का वर्ग नहीं है?

(क) कृषि वानिकी (ख) ग्रामीण वानिकी
(ग) जनजातीय वानिकी (घ) नगरीय वानिकी

उत्तर (ग) जनजातीय वानिकी

प्र.10. ..... का उद्देश्य वन आवरण को बढ़ाना है।

(क) ग्रीन इंडिया के लिए राष्ट्रीय मिशन (ख) स्थानीय निवास पर राष्ट्रीय मिशन
(ग) हरित कौशल विकास कार्यक्रम (घ) इनमें से कोई नहीं

उत्तर (क) ग्रीन इंडिया के लिए राष्ट्रीय मिशन

प्र.11. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है?

(क) वन मृदा अपरदन को रोककर शार्ष मृदा की रक्षा करते हैं।
(ख) जल चक्र को बनाए रखने में वन मदद करते हैं।
(ग) वन पौधे और पशु एक-दूसरे से स्वतंत्र है।
(घ) वन जलवायु और वायु गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं।

उत्तर (ग) वन पौधे और पशु एक-दूसरे से स्वतंत्र है।

प्र.12. भारत के 2011 के वन सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में वन आच्छादन का उच्चतम क्षेत्र है?

(क) फतेहाबाद (ख) पंचकुला
(ग) पानीपत (घ) गुडगाँव

उत्तर (ख) पंचकुला

प्र.13. निम्नलिखित में से कौन-सा वन स्थायी वन का एक प्रकार है?

(क) असुरक्षित (ख) आरक्षित वन
(ग) अवर्गीकृत वन (घ) सामुदायिक वन

उत्तर (ख) आरक्षित वन

प्र.14. निम्नलिखित में से किस वन प्रकार को मानसून वन कहा जाता है?

(क) वर्षा वन (ख) भूमध्यरेखीय वन
(ग) पर्णपाती वन (घ) पर्वतीय वन

उत्तर (ग) पर्णपाती वन

प्र.15. जब किसी एक आवश्यक कारक की तत्काल आपूर्ति संयंत्र की संयुक्त माँग से कम हो जाती है, तो इसे कहते हैं–

(क) एलीलोपैथी (ख) एलीलोस्पोली
(ग) (क) और (ख) (घ) इनमें से कोई नहीं

उत्तर (ख) एलीलोस्पोली

प्र.16. निम्नलिखित में से कौन-सा मछली उपोत्पाद है?

(क) मछली का तेल (ख) मछली की खाद
(ग) मछली का ग्लू (घ) ये सभी

उत्तर (घ) ये सभी

प्र.17. राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो ..... में स्थित है।

(क) बैगलुरु (ख) मुम्बई (ग) प्रयागराज (घ) त्रिवेंद्रम

उत्तर (ग) प्रयागराज

TOUCH 'n' PASS

प्र.18. निम्नलिखित में से कौन एक समुद्री मछली है?
(क) रोहु (ख) कतला (ग) हिल्सा (घ) कॉमन कार्य
उत्तर (ग) हिल्सा

प्र.19. भारत का कौन-सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है?
(क) केरल (ख) तमिलनाडु (ग) झारखंड (घ) कर्नाटक
उत्तर (घ) कर्नाटक

प्र.20. उड़ीसा में लौह अयस्क कहाँ स्थित है?
(क) मयूरभंज जिला (ख) केन्दुझर जिला
(ग) (क) और (ख) दोनों (घ) कोरापुट जिला
उत्तर (ग) (क) और (ख) दोनों

प्र.21. भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है?
(क) आंध्र प्रदेश (ख) गुजरात (ग) झारखंड (घ) उड़ीसा
उत्तर (घ) उड़ीसा

प्र.22. निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य भारत में बॉक्साइट के अधिकतम उत्पादन के लिए जिम्मेदार है?
(क) ओडिशा (ख) राजस्थान (ग) कर्नाटक (घ) पश्चिम बंगाल
उत्तर (क) ओडिशा

प्र.23. निम्नलिखित में से कौन-सा स्थान ताँबे की खान के लिए प्रसिद्ध है?
(क) खेतड़ी (ख) क्योंझर (ग) गया (घ) सतना
उत्तर (क) खेतड़ी

प्र.24. भारत में खनिजों में सबसे समृद्ध पठार ..... है।
(क) छोटा नागपुर (ख) मैसूर का पठान (ग) दक्कन का पठार (घ) मालवा का पठार
उत्तर (क) छोटा नागपुर

प्र.25. इस्पात के निर्माण में निम्नलिखित में से कच्चे माल की सबसे बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है?
(क) कोयला (ख) लौह अयस्क (ग) चूना (घ) पोटाश
उत्तर (क) कोयला

❑

TOUCH 'n PASS

UNIT-IV

कृषि का प्रारूप वर्गीकरण
Agriculture Typologies

खण्ड-अ अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. आर्थिक भूगोल में कृषि को परिभाषित कीजिए।
Define Agriculture in Economic Geography.

उत्तर कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जिसमें फसलोत्पादन तथा पशुपालन सम्मिलित हैं। कृषि के अन्तर्गत भूमि साफ करना, मिट्टी की जुताई से लेकर फसल उगाने, सिंचाई करने, निराई-गुड़ाई फसल काटने आदि तक की विविध क्रियाएँ सम्मिलित होती हैं। कृषि के अनेक प्रकार हैं। विश्व के पिछड़े भागों में आदिम प्रकार की कृषि से लेकर विकसित देशों में आधुनिक तकनीकों तथा वैज्ञानिक विधियों द्वारा उन्नत कृषि की जाती है। कृषि के ऊपर जलवायु, मिट्टी की उर्वरता, तकनीकी तथा आर्थिक विकास आदि का प्रभाव पाया जाता है। कृषि का वर्गीकरण अनेक आधारों पर किया जाता है। **जल की उपलब्धता के आधार पर** कृषि आर्द्र एवं तर, शुष्क तथा सिंचित प्रकार की होती है। **क्षेत्रीय विस्तार के अनुसार** कृषि गहन तथा विस्तृत प्रकार की होती है। **उत्पादन के उद्देश्य** से कृषि निर्वाहक तथा व्यापारिक प्रकार की होती है।

प्र.2. कृषि-सम्बन्धित क्रान्तियों के नाम लिखिए।
Write the names of Agriculture related Revolutions.

उत्तर हरित क्रान्ति (Green Revolution)—कृषि उत्पादन (मुख्यत: गेहूँ, चावल, मक्का)
श्वेत क्रान्ति (White Revolution)—दुग्ध उत्पादन
नीली क्रान्ति (Blue Revolution)—मत्स्योत्पादन
गुलाबी क्रान्ति (Pink Revolution)—झींगा मछली उत्पादन
पीली क्रान्ति (Yellow Revolution)—सूर्यमुखी एवं अन्य तिलहनों का उत्पादन
रजत क्रान्ति (Silver Revolution)—अण्डा उत्पादन
स्वर्ण (सुनहरी) क्रान्ति (Golden Revolution)—फलोत्पादन
इन्द्रधनुषी क्रान्ति (Rainbow Revolution)—नवीन कृषि नीति

प्र.3. खाद्य संकट एवं खाद्य सुरक्षा को परिभाषित कीजिए।
Define Food Crisis and Food Security.

उत्तर खाद्य संकट अकाल से उत्पन्न होता है। अकाल (दुर्भिक्ष) व्यापक भुखमरी को जन्म देते हैं। भुखमरी कुपोषण से वंचितता से उत्पन्न होती है जो पर्याप्त भोजन न मिलने से रोग तथा मृत्यु का कारण भी बन जाती है। अकाल के प्रमुख कारण सूखा (droughts) बाढ़, भूकम्प, युद्ध आदि हैं। अफ्रीका का उपसहारा प्रदेश जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण तीक्ष्ण खाद्यान्न संकट से ग्रस्त हैं। FAO के अनुसार, अफ्रीका के आधे देश खाद्यान्न संकट से ग्रस्त हैं। सोमालिया, इथोपिया, सूडान जैसे देशों में खाद्य संकट अधिक गंभीर है। एशियाई देशों में स्थिति बेहतर है। इन देशों में भोजन संसाधनों की वृद्धि के प्रयास जारी है, जो चुनौतीपूर्ण भी है। खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य किसी देश का अपनी जनसंख्या को लगातार पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराना है। हरित क्रान्ति के कारण एशियाई देशों में खाद्यान्न उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि सम्भव हुई है। अन्य देशों के लिये भोजन आपूर्ति के विस्तार के लिये चार विकल्प सुझाये गये हैं—1. कृषित क्षेत्र में विस्तार, 2. भूमि उत्पादकता में वृद्धि 3. भोजन के नये स्रोतों/संसाधनों का विकास तथा 4. विदेशों द्वारा खाद्यान्नों में सहायता।

TOUCH N PASS

प्र.4. गैर-कृषि गतिविधियाँ क्या हैं?
What are the Non-agricultural Activities?

उत्तर गैर-कृषि गतिविधियों में निर्माण, खनन, उत्खनन, मरम्मत, निर्माण, परिवहन, हस्तशिल्प, लघु-स्तरीय विनिर्माण सामुदायिक सेवा आदि शामिल होते हैं।

प्र.5. भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लक्ष्यों को संक्षेप में लिखिए।
Write the goals of National Food Security in India.

उत्तर 1. पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए चावल, गेहूँ, दालें, मोटे अनाज और व्यावसायिक फसलों की मात्रा में वृद्धि करना, जहाँ वे उगाए जाते हैं, उस क्षेत्र का विस्तार करना और उनकी उत्पादकता में सुधार करना।
2. प्रत्येक खेत में मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता में सुधार करना।
3. कृषि स्तर पर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना।

प्र.6. राष्ट्रीय बागवानी मिशन से आप क्या समझते हैं?
What do you understand by National Horticulture Mission?

उत्तर बागवानी उद्योग को व्यापक तरीके से विकसित करने में मदद करना। इसका तात्पर्य यह है कि रणनीतियाँ बागवानी उद्योग और दुनिया में इसकी स्थिति पर आधारित होंगी। इससे बागवानी उद्योग को व्यापक रूप से विकसित होने से मदद मिलेगी।

खण्ड-ब लघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. कृषि अवस्थिति के आधुनिक सिद्धान्त का उल्लेख कीजिए।
Explain the modern theories of Agricultural Location.

उत्तर

कृषि अवस्थिति के आधुनिक सिद्धान्त
(Modern Theories of Agricultural Location)

कृषि भूमि उपयोग के आधुनिक सिद्धान्त कल्पित मान्यताओं पर आधारित न होकर वास्तविक जगत की भौतिक तथा आर्थिक सीमाओं के अन्तर्गत अनुकूलित दशाओं पर आधारित होते हैं। भिन्न-भौतिक तथा आर्थिक दशाएँ ही फसलोत्पादन की सीमाएँ निर्धारित करती हैं। इस संदर्भ में दो प्रमुख आधुनिक सिद्धान्त निम्नवत् हैं—

1. **भौतिक (प्राकृतिक) सीमाओं तथा अनुकूलतम दशाओं का सिद्धान्त** (Theory of Physical Limits and Optimum Conditions)—प्रत्येक फसल का उत्पादन विशिष्ट भौतिक पर्यावरण (तापमान, आर्द्रता, वर्षा, मिट्टी की उत्पादकता, पोषक तत्त्व आदि) में होता है। ये सभी दशाएँ सर्वत्र नहीं मिलती हैं। अत: किसी क्षेत्र में जैसी भौतिक दशाएँ होती हैं तदनुसार फसलोत्पादन किया जाता है। ऐसी अनुकूलतम दशाओं वाले क्षेत्र स्थिर न होकर प्राविधिक विकास के अनुसार परिवर्तनशील होते हैं। प्राविधिक विकास से भूमि की उत्पादन क्षमता में वृद्धि सम्भव है तथा अन्य लागत तत्त्वों; जैसे—सिंचाई, उर्वरक आदि की स्थितियाँ भी बदलती रहती हैं।
2. **आर्थिक सीमाओं तथा अनुकूलतम दशाओं का सिद्धान्त** (Theory of Economic Limits and Optimum Conditions)—फसलों का उत्पादन विभिन्न आर्थिक दशाओं (भूमि, श्रम, सिंचाई, परिवहन व्यवस्था, बाजार की स्थिति, माँग की मात्रा, बाजार-मूल्य, आर्थिक नीति आदि) से भी निर्धारित होता है। जहाँ प्रति इकाई विक्रय मूल्य तथा उत्पादन लागत का अन्तर शुद्ध लाभ अधिकतम होगा वहीं फसलोत्पादन किया जायेगा।

मैकार्थी एवं **लिण्डवर्ग** (1966) ने सर्वप्रथम अनुकूलतम आर्थिक दशाओं तथा सीमाओं का नियम प्रस्तुत किया था जो **रिकार्डो के आर्थिक लगान सिद्धान्त** पर आधारित है। मैकार्टी ने दुग्ध उत्पादक कृषकों की उत्पादन लागत तथा भूमि के लगान की ही कृषि पेटियों के निर्धारण का आधार बनाया है।

कृषि प्रदेश के प्रकार (Types of Agricultural Regions)—कृषि प्रदेश भूतल पर स्थित एक विस्तृत क्षेत्र होता है जिसमें कृषि दशाओं तथा कृषि कार्य पद्धति सम्बन्धी विशेषताओं में समरूपता पायी जाती है। यह समरूपता तथा सम्बद्धता फसल के प्रकार, उत्पादन विधि, कृषि में प्रयुक्त उपकरण तथा तकनीक, कृषकों की जीवन पद्धति तथा जीवन स्तर आदि के रूप में मिलती है। इन समरूपताओं के आधार पर एक कृषि प्रदेश को अन्य क्षेत्रों से पृथक किया जाता है।

TOUCH 'n' PASS

विश्व स्तर पर कृषि प्रदेशों के सीमांकन के बहुत कम प्रयास किये गये हैं। इनमें अमेरिकी भूगोलवेत्ता **डी. ह्विटलसी** (1936) का कार्य सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने कृषि प्रदेशों के सीमांकन हेतु 5 तत्त्वों को आधार बनाया—1. फसलों एवं पशुओं का साहचर्य, 2. कृषि उत्पादन विधि, 3. कृषि भूमि में पूँजी, श्रम संगठन आदि के विनियोग की मात्रा, 4. कृषि उत्पादों के उपभोग का ढंग तथा 5. कृषि कार्य में प्रयुक्त उपकरण एवं आवासीय दशाएँ।

ह्विटलसी के अनुसार विश्व के वृहत् कृषि प्रदेश निम्नलिखित हैं—1. चलवासी पशुचारण प्रदेश 2. व्यापारिक पशुपालन प्रदेश, 3. स्थानान्तरशील कृषि प्रदेश, 4. प्रारम्भिक स्थायी कृषि प्रदेश, 5. चावल-प्रधान गहन निर्वाहन कृषि प्रदेश, 6. चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि प्रदेश, 7. व्यापारिक बागाती कृषि प्रदेश, 8. भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश, 9. व्यापारिक अन्नोत्पादक कृषि प्रदेश, 10. व्यापारिक पशु एवं फसलोत्पादन कृषि प्रदेश, 11. निर्वाहन फसल एवं पशु उत्पादन प्रदेश 12. व्यापारिक दुग्ध पशुपालन प्रदेश, 13. विशिष्ट बागवानी प्रदेश।

प्र.2. खाद्यान्न फसलों का उल्लेख संक्षेप में कीजिए।
Mention Food Crops in Brief.

उत्तर

खाद्यान्न फसलें
(Food Crops)

खाद्यान्न फसले निम्न प्रकार हैं—

1. **चावल**—चावल मुख्यत: एशिया के मानसूनी प्रदेशों की उपज है, जो सघन आबादी का पोषण करने में समर्थ है। चावल की स्थानीय खपत अधिक होने के कारण इसका विश्व-व्यापार बहुत सीमित है। इसकी प्रति हेक्टेयर उपज मिस्र में सर्वाधिक है। चीन विश्व का वृहत्तम चावल उत्पादक देश (26%) है तथा भारत द्वितीय स्थान (20%) पर है। इण्डोनेशिया का जावा द्वीप भी चावल के उत्पादन के लिये महत्त्वपूर्ण है। थाईलैण्ड विश्व का वृहत्तम चावल निर्यातक देश है। म्यांमार, फिलीपीन्स, अन्य उत्पादक है। अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, मनीला (फिलीपीन्स) में है। चावल की दो प्रमुख किस्में 'इण्डिका' तथा 'जापोनिका' है।
2. **गेहूँ**—फिलीस्तीन को गेहूँ की 'जन्मभूमि' माना जाता है। अनुकूलनशीलता अधिक होने के कारण यह उष्ण कटिबन्ध से लेकर बसन्त कालीन होती है। अधिक आर्द्रता होने पर इसमें 'रेड रॉट' रोज लग जाता है। यूक्रेन के स्टेपी प्रदेश की चरनोजम मिट्टियों तथा अमेरिका के प्रेयरी मैदानों में इसकी अच्छी उपज होती है। अर्जेन्टीना का पम्पा प्रदेश गेहूँ का महत्त्वपूर्ण उत्पादक है। यूरोप में फ्रांस प्रमुख उत्पादक देश है।
3. **मक्का**—संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे 'Corn' कहा जाता है। यह मैक्सिको की मूल उपज है। विश्व में लगभग आधा मक्का उत्पादन अमेरिका में होता है। चीन द्वितीय वृहत्तम उत्पादक है। इससे स्टॉर्च, एल्कोहल, जैव ईंधन (biofuel) भी बनाये जाते हैं। इसे पशुओं को भी खिलाया जाता है।
4. **सई जौ**—यह प्राचीनतम खाद्यान्न है, मिस्र में इसकी खेती के प्रागैतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं। इसका प्रयोग सूप, पोरिज, शिशु-आहार, बियर आदि बनाने में होता है। रूस, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा तथा यूक्रेन इसके प्रमुख उत्पादक देश हैं।

प्र.3. कृषि उत्पादकता से आप क्या समझते हैं?
What do you understand by Agricultural Productivity.

उत्तर

कृषि उत्पादकता
(Agricultural Productivity)

कृषि उत्पादकता का तात्पर्य प्रति इकाई कृषित क्षेत्र या प्रति श्रमिक या प्रति इकाई निविष्टियों पर समस्त उत्पादन की मात्रा से है। इसे उत्पादित वस्तु के मूल्य के रूप में प्रकट किया जा सकता है। सघन कृषि वाले क्षेत्रों में प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक रहता है। कृषि उत्पादकता भौतिक तथा गैर-भौतिक कारकों पर निर्भर करती है। भौतिक कारकों में जलवायु, मिट्टी, स्थलाकृति तथा ढाल एवं गैर-भौतिक कारकों में संस्थागत संरचनात्मक तथा राजनीतिक कारक प्रमुख हैं।

कृषि दक्षता या क्षमता (Agricultural Efficiency or Carrying Capacity)

कृषि दक्षता का सम्बन्ध कृषि उत्पादक के विभव से है। (साथ-साथ लाभ प्रदता भी सम्मिलित है जिसमें कम निवेश से अधिकाधिक लाभ प्राप्त होते हों) कृषि दक्षता से किसी क्षेत्र के कृषि विकास स्तर का ज्ञान प्राप्त होता है तथा कृषि उत्पादन में होने वाले कालिक परिवर्तनों का भी संकेत मिलता है। कृषि उत्पादकता एवं दक्षता में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध होता है।

TOUCH 'n PASS

शस्य गहनता (Ropping intensity)—कृषि या शस्य गहनता से तात्पर्य शुद्ध बोये गये क्षेत्र तथा फसल कृषित क्षेत्र के कुल मध्य अनुपात से है। शस्य गहनता का अभिप्राय एक कृषि वर्ष के दौरान उसी खेत से विभिन्न फसलों के उगाने से है। सूचक कितना होगा, भूमि उपयोग की गहनता उतनी अधिक होगी।

इसका मापन निम्न सूत्र द्वारा किया जाता है— सकल कृषित क्षेत्र/कुल बोया गया क्षेत्र × 100

पौधों का पोषण एवं मृदा उर्वरता—पौधों के विकास के लिये कुल 16 तत्त्व आवश्यक हैं जिनमें से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटैशियम, कैल्सियम तथा मैग्नीशियम वृहत् पोषक तत्त्व हैं तथा लोहा, मैगनीज, जिंक, ताँबा, मौलिब्डेनम, बोरान तथा क्लोरीन लघु पोषक तत्त्व हैं। इनमें से किसी भी तत्त्व की कमी से पौधों का विकास बाधित हो सकता है।

प्र.4. खाद्य (भोजन) एवं पोषण समस्याओं का संक्षेप में उल्लेख कीजिए।
Explain briefly Food and Nutrition Problems.

उत्तर

खाद्य (भोजन) एवं पोषण समस्याएँ
(Food and Nutrition Problems)

भोजन (Food)—भोजन मनुष्य की नितान्त आवश्यकताओं में सर्वोपरि है। लोग प्राय: वही खाते हैं जिसे वे उगाते हैं या पैदा करते हैं या अपने पर्यावरण से प्राप्त करते हैं। भू-जलवायवीय तथा मृदीय दशाओं की भिन्नताएँ फसलोत्पादन तथा पशुओं के पालतूकरण को प्रभावित करती हैं। भू-जलवायवीय दशाओं तथा सामाजिक-सांस्कृतिक पर्यावरण की भिन्नताओं के कारण विश्व भर के लोगों की आहार सम्बन्धी आदतें भिन्न होती हैं। भोजन में अपार विविधताओं के बावजूद विश्व के अधिकांश लोगों के आहार में चाहे वे माँसाहारी हों या शाकाहारी, खाद्यान्नों (गेहूँ, चावल तथा मक्का) की प्रधानता मिलती है। विश्व की जनसंख्या के भोजन का लगभग 60% भाग अन्नों (cereals) से तथा शेष 40% फलीदार तथा जड़दार फसलों, सब्जी, फल, गिरियों, माँस आदि से मिलता है।

पोषण (Nutrition)—मनुष्य को स्वस्थ तथा क्रियाशील रहने के लिये पोषणयुक्त सन्तुलित भोजन की आवश्यकता होती है। कैलोरी को मानव के पोषण का माप माना जाता है। विश्व में भोजन तथा पोषण की उपलब्धता का वितरण अत्यधिक विषम है। वस्तुत: विकसित तथा विकासशील देशों के मध्य भारी पोषणीय अन्तर मिलता है। FAO के अनुसार, विकसित देशों में औसत 3100 कैलोरी/व्यक्ति/दिन तथा विकासशील देशों में मात्र 2200 कैलोरी/व्यक्ति/दिन की तुलना में विकासशील देशों में मात्र 50 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध है। अफ्रीकी, एशियाई तथा लैटिन अमेरिकी देशों में पोषण तथा प्रोटीन के स्तर अतिनिम्न हैं। भोजन अतिरेक (surplus) तथा कमी (defict) के कारण ये विषमताएँ मिलती हैं। आज भी विकासशील देश भूख वंचितता (deprivation) तथा भुखमरी (Starvation) से ग्रस्त हैं। फसलों की क्षति, मौसमी उतार-चढाव, परम्परागत भोजन के वैकल्पिक स्रोतों की अनुपलब्धता, ऊर्जा की अनुपलब्धता एवं सामाजिक-आर्थिक प्रतिबन्ध इस शोचनीय दशा के लिये उत्तरदायी हैं।

प्र.5. वॉन थ्यूनेन सिद्धान्त की आलोचना कीजिए।
Write a criticism of Von Thumen's theory.

उत्तर

वॉन थ्यूनेन सिद्धांत की आलोचनाएँ
(Criticism of Von Thumen's Theory)

1. वॉन थ्यूनेन द्वारा कल्पित मान्यतायें वास्तविक जगत में नहीं पायी जाती। इसी आलोचना से बचने के लिये वॉन थ्यूनेन ने विलग प्रदेश में नौगम्य नदी और उपनगर में कृषि पेटियों के संकेंद्रीय स्वरूप में परिवर्तन को स्वयं स्वीकार कर लिया है।
2. वॉन थ्यूनेन द्वारा जो विलग प्रदेश की कल्पना की गई है। वह वर्तमान समय में कहीं भी मिलना कठिन है।
3. कल्पित मान्यताओं के द्वारा कृषि कार्य, उत्पादन दर, परिवहन सिंचाई आदि नहीं की जा सकती। इसलिये वॉन थ्यूनेन का यह सिद्धांत लागू नहीं होता।
4. वॉन थ्यूनेन का सिद्धांत पूर्णत: कल्पित मान्यताओं पर आधारित है। इसलिये यह कृषि पर खरा नहीं उतरता।

TOUCH 'n PASS

खण्ड-स विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. आर्थिक भूगोल में कृषि के प्रकारों का वर्णन कीजिए।
Describe the types of Agricultural in Economic Geography.

उत्तर

कृषि के प्रकार
(Types of Agriculture)

ह्विटलसी के अनुसार कृषि के प्रकारों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है—

1. **चलवासी पशुचारण**—यह पशुपालन का सरलतम रूप है, जो शुष्क प्रदेशों में प्रचलित है। पशुओं का चयन जलवायु के आधार पर किया जाता है तथा भेड़, बकरियाँ, मवेशी, ऊँट, रेण्डियर आदि पाले जाते हैं। यह क्रिया निर्वाहक स्तर पर होती है। अरब तथा सहारा के मरुस्थल, मध्य एशिया, पूर्वी अफ्रीका, आदि इसके प्रमुख क्षेत्र हैं।
2. **पशुपालन**—चलवासी पशुचारण जैसे पर्यावरण में ही यह वाणिज्यिक क्रिया प्रचलित है। इसमें स्थायी चरागाहों में पशु चराये जाते हैं। पशुपालन कार्य बड़े पैमाने पर होता है। चारे की कमी वाली ऋतु में चारा तथा अन्य फसलें भी उगायी जाती है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका तथा यूरेशिया की घास भूमियों के शुष्क सीमान्त प्रदेशों में यह प्रचलित है। पशुओं को मुख्यत: माँस प्राप्ति तथा अन्य पशु उत्पादों के लिये पाला जाता है।
3. **स्थानान्तरी कृषि**—यह कृषि उष्ण कटिबन्धीय वर्षा वनों की जलवायु में निकृष्ट मिट्टियों में प्रचलित हैं। इसके अन्तर्गत वनों को काटकर तथा जलाकर (slash and burn) खेती की जाती है। पूर्वोत्तर भारत, इण्डोनेशिया तथा दक्षिण एवं पूर्वी एशिया के उष्ण कटिबन्धीय वनों में आज भी यह पिछड़ी कृषि प्रचलित है।
4. **प्राचीन स्थानबद्ध कृषि**—इसमें पिछड़े यन्त्रों उपकरणों द्वारा उर्वरकों का प्रयोग किये बिना निर्वाहक स्तर पर कृषि की जाती है। कुछ बागाती तथा वृक्षदान फसलें भी उगायी जाती है। यह उष्ण कटिबन्ध के कम सघन आबादी क्षेत्रों में प्रचलित हैं।
5. **सघन निर्वाहक चावल प्रधान कृषि**—यह दक्षिण तथा पूर्वी एशिया में सघन आबादी क्षेत्रों में निर्वाहक स्तर पर प्रचलित है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ चावल के स्थान पर अन्य खाद्यान्न उगाये जाते हैं। यह श्रम सघन कृषि है। भारत, चीन, बांग्लादेश, मिस्र तथा दक्षिणी एवं पूर्वी एशिया के नदी डेल्टा क्षेत्रों में यह कृषि प्रचलित है।
6. **चावल-विहीन सघन निर्वाहक कृषि**—कम वर्षा के क्षेत्रों में यह कृषि दक्षिणी एवं पूर्वी एशिया, आन्तरिक एशिया, अफ्रीका, मिस्र आदि में प्रचलित है। गेहूँ तथा बाजरा प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं।
7. **वाणिज्यिक बागानी कृषि**—यह कृषि यूरोपीय उपनिवेशकों द्वारा उष्ण कटिबन्धीय देशों में विकसित की गयी। यह अत्यधिक वाणिज्यिक, यंत्रीकृत तथा पूँजी सघन कृषि हैं। यह प्रमुखत: निर्वाहक कृषि के क्षेत्रों में प्रचलित हैं। चाय, कहवा, गन्ना, रबड़, नारियल, ताड़, केला आदि प्रमुख बागाती फसलें हैं।
8. **भूमध्यसागरीय कृषि**—यह मृदु आर्द्र शीतजलवायु तथा पर्वतीय धरातल वाले क्षेत्रों में प्रचलित हैं। इसके अन्तर्गत फसलों के साथ पशु भी पाले जाते हैं। खाद्यान्नों तथा फलोत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। गेहूँ, फलदार फसलें, केले आदि उगाये जाते हैं।
9. **वाणिज्यिक धान्य कृषि**—मशीनों, उपकरणों तथा उन्नत परिवहन साधनों के आधार पर निर्यातोन्मुख फसलें (गेहूँ मुख्यत:) उगायी जाती हैं। उपार्द्र जलवायु के क्षेत्रों में विस्तृत कृषि की जाती है। इसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम है किन्तु प्रति श्रमिक अधिक होता है। यह कृषि उत्तरी अमेरिका के वृहत् मैदान में बड़े पैमाने पर प्रचलित है, जहाँ जनसंख्या का निम्न घनत्व मिलता है।
10. **वाणिज्यिक मिश्रमि (मवेशी पालन एवं धान्य) कृषि**—यह कृषि मूलत: यूरोप में विकसित की गयीं, अन्यत्र महाद्वीपों (एशिया के अपवाह सहित) पर आर्द्र मध्य अक्षांशों में प्रचलित है। यह बाजारोन्मुखी कृषि है। ब्रिटिश द्वीप एवं न्यूजीलैण्ड इसके प्रमुख उदाहरण हैं। परिवहन साधनों के कारण कृषि में विशेषीकरण होने से यह कृषि अधिक व्यापक हो गयी है।
11. **निर्वाहक शस्य एवं पशु-फार्मिंग**—यह कृषि भी यूरोप में विकसित की गयी। किन्तु यह निर्वाहक स्तर पर की जाती है। यंत्रीकरण, आधुनिक निविष्टियों के प्रयोग से यह कृषि यूरोप में अधिक सघन तथा वाणिज्यिक हो गयी है।

TOUCH 'n PASS

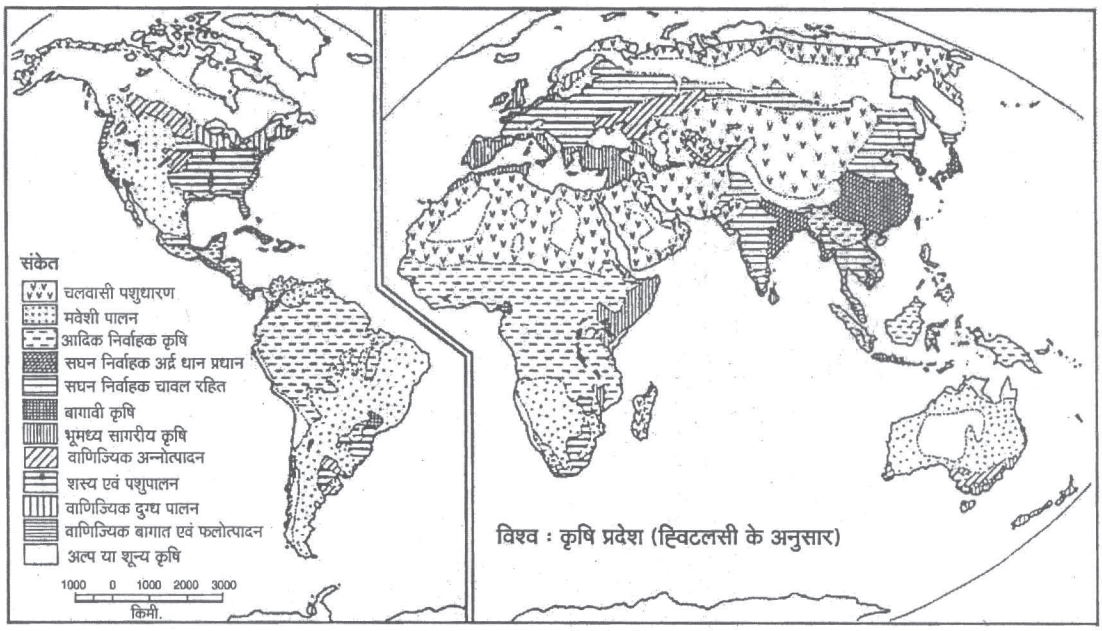

चित्र- : कृषि के प्रकार (हिटिल्सी के अनुसार)

12. **वाणिज्यिक डेयरी कृषि**—इसमें दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों के लिये पशुपालन सम्मिलित हैं। पश्चिमी यूरोप के औद्योगिक तथा नगरीय क्षेत्रों में दूध की अधिक माँग के कारण यह कृषि विकसित की गयी। ब्रिटेन, न्यूजीलैण्ड तथा डेनमार्क इसके प्रमुख क्षेत्र हैं।
13. **विशिष्ट सब्जी एवं फलोत्पादक कृषि**—भूमध्य सागरतटीय यूरोपीय देशों में यह कृषि प्रचलित है। अनुकूल जलवायु स्थानीय बाजार तथा उन्नत परिवहन के साधन इसके विकास के प्रमुख कारक हैं। फ्रांस, कैलिफोर्निया (USA) तथा कुछ अन्य देशों में यह कृषि प्रचलित है।

प्र.2. नकदी फसलों का विस्तार से वर्णन कीजिए।
Describe in details of cash crops.

उत्तर

नकदी फसलें
(Cash Crops)

1. **चाय**—यह लोकप्रिय पेय पदार्थ है जो **'थीं-सिनेसिस'** नामक झाड़ीदार पौधे का वंशज है। इसके मूल स्थान चीन तथा भारत (असम) है। यह उष्ण कटिबन्धीय मानसूनी प्रदेशों का पौधा है। भारत तथा चीन इसके वृहत्तम उत्पादक देश हैं। श्रीलंका, केन्या, तुर्की, इण्डोनेशिया अन्य महत्त्वपूर्ण उत्पादक हैं। यूरोप में इसका प्रचलन अधिक तथा खेती सीमित होने के कारण इसका अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत महत्त्वपूर्ण है। भारत, श्रीलंका, केन्या चाय के प्रमुख निर्यातक देश हैं।
2. **कहवा**—यह आधुनिक विश्व का लोकप्रिय पेय पदार्थ है। यह इथोपिया का मूल पौधा है। इसकी तीन प्रमुख किस्में **'काफिआ अरेबिका' 'काफिआ रोबस्टा'** तथा **'काफिआ लाइबेरिका'** है। विश्व में सर्वाधिक वाणिज्यिक उत्पादन 'अरेबिका' किस्म का होता है। 'रोबास्टा' फफूँदी रोगों की प्रतिरोधी किस्म है जो इण्डोनेशिया में व्यापक रूप से उगती है। लाइबेरिका अफ्रीका में उगती है। इसकी बागाती खेती वियतनाम, ब्राजील, कोलम्बिया, इण्डोनेशिया, मैक्सिको, भारत, आइबरी कोस्ट, ग्वाटेमाला, इथोपिया आदि में होती है। वियतनाम, ब्राजील, कोलम्बिया, आइबरी कोस्ट आदि प्रमुख निर्यातक हैं।

   ब्राजील में साओपॉली को विश्व का कहवा पात्र कहा जाता है। जमैका का **ब्लू माउन्टेन** विश्व में सर्वोत्तम कहवा है। ग्वाटेमाला का अल्टावेरा पाज तथा यमन का मोचा कहवा उत्तम कोटि के है।

3. **कोको**—यह उष्ण कटिबन्धीय वर्षा वनों की प्रारूपिक उपज है। इसका वृक्ष **'कोकोआ थियोब्रोमा'** अमेरिकी उष्ण कटिबन्धीय प्रदेशों की देशज है। इसकी दो प्रमुख किस्में 'कियोलो' तथा **'फोरास्टेरो'** है—क्रियोलो अधिक सुगन्धित किन्तु फोरास्टेरो व्यापक रूप से उगती है। आइवरी कोस्ट, घाना, इण्डोनेशिया तथा नाइजीरिया इसके प्रमुख उत्पादक हैं।
4. **गन्ना**—यह चीनी का प्रमुख स्रोत है तथा उष्णार्द्र जलवायु की फसल है। दक्षिण-पूर्वी एशिया इसका उद्भव क्षेत्र माना जाता है। भारत तथा ब्राजील इसके प्रमुख उत्पादक हैं। कोलम्बिया, चीन, मैक्सिको, थाईलैण्ड, पाकिस्तान, आस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, फिलीपीन्स, इण्डोनेशिया, क्यूबा हवाईद्वीप (USA) अन्य महत्त्वपूर्ण उत्पादक है। मिस्र में इसकी सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उपज होती है।
5. **चुकन्दर**—यह यूरोपीय देशों में चीनी का प्रमुख स्रोत है तथा यूरोप की मूल उपज है। यह शीतोष्ण आर्द्र मृदु जलवायु में सर्वोत्तम उगता है। फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूक्रेन, रूस, तुर्की, पोलैण्ड, इटली, चीन, कनाडा आदि इसके प्रमुख उत्पादक देश हैं।

   चीनी उत्पादन में भारत, ब्राजील, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, थाईलैण्ड, फ्रांस, जर्मनी, क्यूबा, तुर्कमेनिस्तान, दक्षिण अफ्रीका तथा पाकिस्तान क्रमशः उल्लेखनीय देश हैं। विश्व के चीनी व्यापार में 90% अंशदान गन्ने की चीनी का है। चीनी के निर्यातों में ब्राजील, अर्जेन्टीना, आस्ट्रेलिया, क्यूबा, फिलीपीन्स, थाईलैण्ड, दक्षिण अफ्रीका, मॉरीशस तथा पाकिस्तान हैं।
6. **कपास**—भारत को कपास का मूल स्थान माना जाता है। रेशे की लम्बाई के अनुसार यह लम्बी (अमेरिकी, पश्चिमी द्वीप समूह द्वीपीय कपास) मध्यम (मिस्र) तथा लघु (भारतीय) श्रेणी की होती है। उत्तम गुणवत्ता के कारण कपास को 'सफेद सोना' कहा जाता है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, भारत, उज्बेकिस्तान, तुर्की, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, यूनान, तुर्कमेनिस्तान, सीरिया, मिस्र, अर्जेन्टीना आदि देश क्रमशः महत्त्वपूर्ण उत्पादक देश हैं।
7. **प्राकृतिक रबड़**—रबड़ वृक्षों का 'दूध' (latex) है जो मुख्यतः हीविया, ब्राजीलिएन्सिस नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। यह अमेजन बेसिन की मूल उपज है, नेटिव इण्डियन लोग इसे 'कुहूचू' कहते थे। बल्केनाइजेशन प्रक्रिया के आविष्कार ने रबड़ के बड़े पैमाने पर प्रयोग की नींव डाली है। बढ़ती हुई माँग के कारण भारत, श्रीलंका, मलाया तथा इण्डोनेशिया में रबड़ के वृक्ष लगाये गये। सम्प्रति विश्व का अधिकांश प्राकृतिक रबड़ बागानों से प्राप्त होता है। थाईलैण्ड, इण्डोनेशिया, मलेशिया, भारत तथा चीन इसके प्रमुख उत्पादक देश हैं। विश्व में पारा किस्त की रबड़ सर्वोत्तम मानी जाती है।
8. **तम्बाकू**—उत्पादन तथा उपभोग की दृष्टि से तम्बाकू एक सार्वभौमिक फसल है। इसका उपयोग व्यापक रूप से नशे (धूम्रपान) पान, गुटका आदि में किया जाता है तथा अंशतः औषधियाँ एवं कीटनाशी बनाने में इसके डंठल में पोटाश का अंश अधिक होने के कारण इसे खाद के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसकी दो प्रमुख किस्में- 'निकोटिना टोबेक्रम' तथा 'निकोटिना रस्टिका' है। चीन, भारत, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिम्बाब्वे, तुर्की, इण्डोनेशिया आदि देश इसके महत्त्वपूर्ण उत्पादक हैं।

पौधों के उत्पत्ति स्थल

उत्तरी अमेरिका—सूर्यमुखी तथा सोयाबीन।
मध्य अमेरिका—मक्का, टमाटर तथा लाल मिर्च
दक्षिणी अमेरिका—आलू,शकरकन्द, तम्बाकू, मूंगफली, कोको-अन्ननास, रबर, सिनकाना।
उत्तर पूर्वी अफ्रीका—कहवा, जौ, गेहूँ, कपास, तिल।
यूरोप—राई, जंई, चुकन्दर।
चीन—चाय, जौ, सोयाबीन, शफ्तालू, रसदार फल।
दक्षिण पूर्वी एशिया—गन्ना, चावल, केला, रतालू, ब्रेडफ्रूट, गर्म मसाले।
दक्षिण पश्चिम एशिया—गेहूँ, जौ, मिलेट्स, सेब, चेरी, अंगूर, मटर, पोस्त, फ्लैक्स, हैम्प।

कृषि के विशेष प्रकार

विटीकल्चर	अंगूर की खेती
पीसीकल्चर (एक्वा कल्चर)	व्यापारिक स्तर पर मत्स्य कृषि

TOUCH 'n' PASS

सेरीकल्चर	कच्चा रेशम उत्पादन
हॉर्टीकल्चर	व्यापारिक फलोत्पादन
फलोरीकल्चर	व्यापारिक पुष्पकृषि
ओलेरीकल्चर	जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि
मोरीकल्चर	रेशम के कीड़ों के लिये शहतूत की खेती।
आरबोरी कल्चर	विशिष्ट वृक्षों एवं झाड़ियों की खेती, संरक्षण एवं संवर्धन
एपीकल्चर	मौन (मधुमक्खी) पालन।
सिल्वी कल्चर	वन संरक्षण तथा संवर्द्धन
बेणीकल्चर	दक्षिण पूर्वी एशिया में आदिम मानव द्वारा प्रारम्भ की गयी आदिम कृषि
नेमरी कल्चर	सागरीय जीवों का व्यापारिक उत्पादन
वर्मीकल्चर	कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केंचुआ पालन
हॉर्सीकल्चर	व्यापारिक स्तर पर घोड़ों तथा खच्चरों की उन्नत किस्मों को पालना।
ओलिवीकल्चर	जैतून की व्यापारिक वृद्धि
पोमोलॉजी	फल विज्ञान

विश्व में स्थानान्तरी कृषि एवं उनके क्षेत्र

नाम	क्षेत्र
फैंग	विषुवतरेखीय अफ्रीकी देश
मसोले	कागो डेमो० रिप० (जायरे घाटी)
लोगन	पश्चिमी अफ्रीका
टावी	मलागासी
चेतेमिनी	युगाण्डा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे
कैंगिन	फिलीपीन्स
टोंग्या	म्यांमार
लदांग	इण्डोनेशिया
तमराई	थाईलैण्ड
हुआ	जावा/इण्डोनेशिया
मिल्पा	मैक्सिको/मध्य अमेरिका
इचाली	ग्वाडेलूप
मिल्पा	युकाटन, ग्वाटेमाला
कोनूको	वेनेजुएला
रोका	ब्राजील
चेना	श्रीलंका

भारत में स्थानान्तरी कृषि एवं उनके क्षेत्र

नाम	क्षेत्र
झूम	उत्तर पूर्वी भारत
बेवार, दहिया	बुन्देलखण्ड (मध्य प्रदेश)
दिप्पा	बस्तर, छत्तीसगढ़
मातरा	दक्षिण पूर्वी राजस्थान
पोदु	आन्ध्र प्रदेश
कुमारी	केरल में पश्चिमी घाट
विन्गा	ओडिशा
जारा, एरका	दक्षिण भारत

TOUCH 'n' PASS

प्र.3. वॉन थ्यूनेन के मॉडल और इसके स्थानीयकरण का वर्णन कीजिए।
Describe the Von Thunen's Model and its Localisation.

उत्तर कृषि मानव की प्रमुख आवश्यकता है यह ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक महत्त्व रखती है कृषि के अंतर्गत भूमि से सिंचाई, जोत, बीजों का डालना (फसल उगाना) पशु पालन, वृक्षारोपण आदि कार्य सम्मिलित हैं। कृषि के स्थानीकरण (उपस्थिति) का सामान्य अर्थ है— कृषि भूमि उपयोग या ग्रामीण भूमि उपयोग।

कृषि उत्पादन अधिकतर बड़े क्षेत्र में किया जाता है। जबकि उद्योगों को किसी स्थान विशेष पर ही स्थापित किया जा सकता है। अत: कृषि का स्थानीयकरण एवं उद्योग के स्थानीकरण में भिन्नता रहती है। कृषि स्थानीकरण का सिद्धांत मूलत: दो भूखण्डों में केन्द्रित रहता है।

उदाहरण—

(a) भूखण्ड—एक भूखण्ड पर गेहूँ व दूसरे भूखण्ड पर चावल उगाया जा सकता है। इन दोनों की उपज से अच्छी आय प्राप्त हो सकती है।

(b) भूखण्ड—इस भूखण्ड पर भी इसी तरह उपज की जा सकती है और आय प्राप्त की जा सकती है। तीव्रगति से बढ़ती हुई जनसंख्या और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करने की कोशिश की जा सकती है। कृषि भूमि उपयोग के लिये कई सैद्धांतिक उपागमों को अपनाया गया। वॉन थ्यूनेन ने 1826 में सामान्यीकरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया इसके बाद जोनासन, बेकर सहित अनेक विद्वानों ने कृषि उपस्थिति के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और संशोधन भी किया।

वॉन थ्यूनेन का कृषि उपस्थिति सिद्धांत—(1983-1850) (Von Thunen's Agricultural Location Theory) सबसे पहले सन् 1826 में कृषि के स्थानीकरण के सिद्धांत की शुरुआत हुई। वे जर्मनी के मैकलेवर्ग में एक कृषि क्षेत्र के व्यवस्थापक थे जिन्होनें अपने अनुभव काल में भूमि की आर्थिक समीक्षा की। 1826 में ही वॉन थ्यूनेन ने कृषि का स्थानीकरण सिद्धांत दिया।

मान्यतायें—

वॉन थ्यूनेन ने एक अलग प्रकार के प्रदेश की कल्पना की है। जिसके मध्य में एक नगर स्थित होता है और उसके चारों ओर विस्तृत कृषि क्षेत्र स्थित होता है और यह उत्पादन सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिये आत्मनिर्भर होता है। इस प्रकार यहाँ की चीजों का (विलग प्रदेश या अलग प्रदेश) कृषि उत्पादन अन्य बाजारों के लिये नहीं किया जाता।

विलग प्रदेश में प्राकृतिक पर्यावरण; जैसे—भूमि की बनावट, जलवायु आदि ठीक ढंग से बल्कि समान होती है और वह विभिन्न प्रकार की फसलों के उत्पादन के लिये अनुकूल होता है।

केन्द्रीय नगर से दूरी बढ़ने तथा भार में वृद्धि के साथ परिवहन व्यय में भी आनुपातिक वृद्धि होती है।

सम्पूर्ण विलग प्रदेश से केवल एक ही केन्द्रीय नगर होता है। जहाँ नगरीय जनसंख्या निवास करती है। शेष क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है।

सम्पूर्ण विलग प्रदेश में एक ही प्रकार का परिवहन उपलब्ध होता है। वॉन थ्यूनेन मॉडल के अनुसार, " विलग प्रदेश में केन्द्रीय नगर के चारों ओर कृषि भूमि की सकेन्द्रित पेटियाँ पायी जाती है।" जिसका वर्णन निम्न प्रकार है—

1. **प्रथम पेटी में**—नगर से संलग्न और सबसे निकट स्थित होती है। इसमें फल, साग-सब्जियाँ व दुग्ध उत्पादन किया जाता है क्योंकि ये शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थ है। स्थल परिवहन अधिक दूरी तक नहीं हो पाता।
2. **दूसरी पेटी में**—लकड़ी का उत्पादन किया जाता है। लकड़ी भारी होने के कारण इसकी परिवहन लागत अधिक आती है। जिसके कारण इसका उत्पादन बाजार के निकट ही लाभप्रद होता है।
3. **तीसरी पेटी में**—गहन कृषि द्वारा अन्न का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार यह परत रहित गहन कृषि की पेटी होती है।
4. **चौथी पेटी में**—इसमें अन्न की खेती की जाती है। किन्तु इसमें कुछ भूमि को परती भी छोड़ा जाता है।
5. **पाँचवी पेटी में**—परती और चारागाह की अधिकता पायी जाती है। इस प्रकार इस पेटी में त्रिक्षेत्र व्यवस्था पायी जाती है।
6. **छठीं पेटी में**—कृषि उत्पादन की सबसे बाहरी पेटी होती है जिस पर पशुपालन किया जाता है।

दूसरे मॉडल में विलग प्रदेश में एक नौगम्य नदी और मुख्य नगर के अतिरिक्त एक लघु नगर या उपनगर को भी दिखाया गया है। यदि विषम प्रदेश में कोई अन्य उपनगर या लघु नगर स्थित है तो उसके चारों ओर भी संकेन्द्रीय वृतखण्डों में फसलों का उत्पादन हो सकता है।

TOUCH 'n PASS

इस सिद्धान्त के अनुसार, कृषि क्षेत्र में उसी फसल का उत्पादन किया जाता है जिससे अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है इसका परिकलन निम्न प्रकार है—

आर्थिक लाभ (P) = S – (C + T)

जबकि P = कृषक का फसल बेचने से लाभ

S = फसल का विक्रय मूल्य

C = उत्पादन लागत

T = परिवहन लागत

भूमि उपयोग की संकेन्द्रीय पेटियाँ

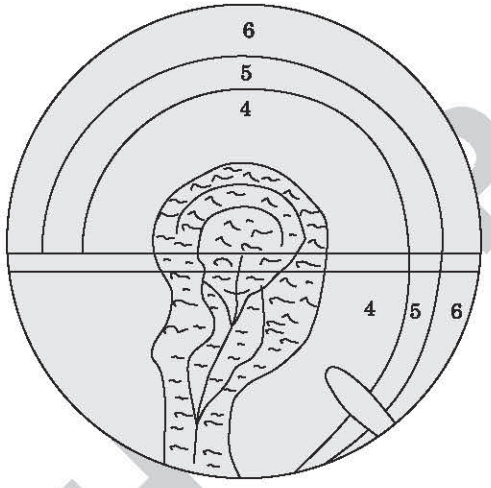

चित्र : नौगम्य नदी और उपनगर द्वारा भूमि उपयोग में परिवर्तन वॉन थ्यूनेन का कृषि उपस्थिति सिद्धांत

वॉन थ्यूनेन के अनुसार—केन्द्रीय नगर को कोई भी वस्तु जितनी दूरी पर उत्पादित होगी बाजार तक लाने में परिवहन व्यय उतना ही अधिक होगा। उदाहरण के लिये, लकड़ी का उत्पादन आधी दूरी तक 50 प्रतिशत का लाभ होता है जो क्रमशः घटते हुये शून्य रह जाता है। उसके पश्चात् अन्य का उत्पादन किया जाता है। भारी वस्तुओं को दूर तक ले जाना, सम्भव नहीं है इसलिये इन्हें निकट ही रखा जाता है। जिन वस्तुओं का उत्पादन कम है वे नगर से अपेक्षाकृत दूर तक उत्पन्न की जा सकती है।

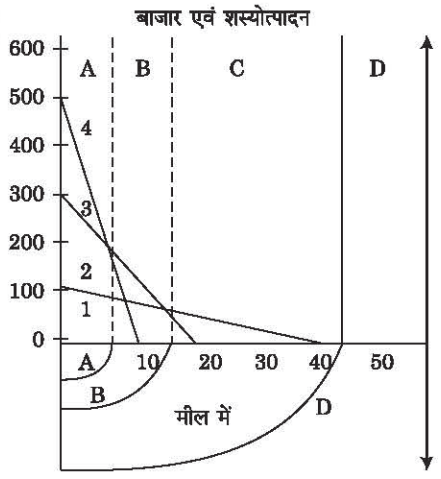

चित्र

कृषि स्थानीयकरण के आधुनिक सिद्धांत
(Modern Theories of Agricultural Location Modification)

कृषि का आधुनिक सिद्धांत कल्पित मान्यताओं पर नहीं, बल्कि वास्तविक जगत में पायी जाने वाली अनुकूलतम दशाओं पर आधारित है। इसके अंतर्गत अनुकूलतम दशाओं में फसलों के उत्पादन क्षेत्रों का सीमांकन किया जाता है। इसके आधुनिक सिद्धांत निम्नलिखित हैं—

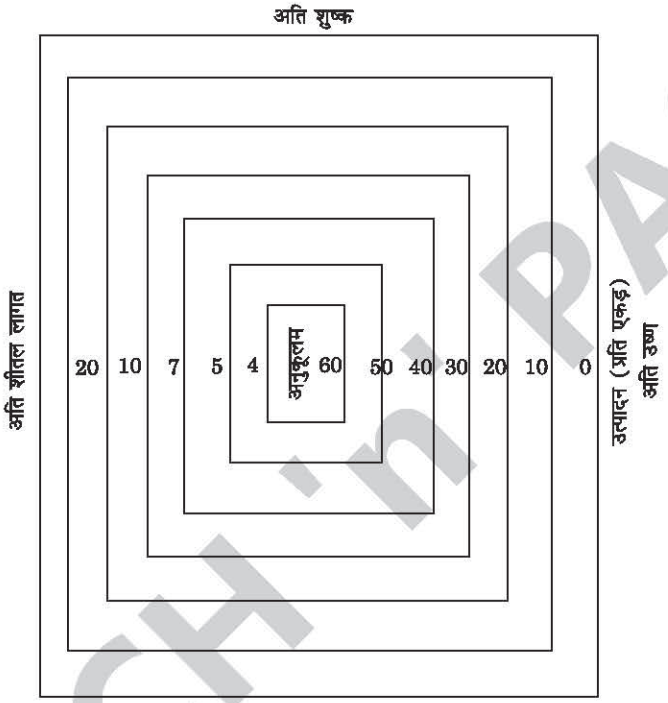

चित्र

1. **प्राकृतिक सीमाओं तथा अनुकूलतम दशाओं का सिद्धान्त** (Theory of Physical and Optimum Conditions)—फसलों का उत्पादन विशिष्ट आर्थिक दशाओं; जैसे—तापमान, जलवायु वर्षा की आवश्यकता होती है। फसलों के उत्पादन के लिए आवश्यक दशायें अनुकूल नहीं पायी जाती। प्रत्येक भूखण्ड का क्षेत्र कैसा है? वहाँ कौन-सी फसल उगाई जायेगी? इस प्रकार प्रत्येक फसल के लिये निर्धारित प्राकृतिक सीमाओं के अंतर्गत अनुकूलतम सीमाओं का सीमांकन किया जाता है। अत: इस क्षेत्र को अनुकूलतम प्राकृतिक दशाओं को स्रोत कहते हैं।
   अनुकूलतम दशाओं वाले क्षेत्र सदैव स्थिर नहीं रहते, बल्कि ये प्राविधिक के आधार पर परिवर्तित होते रहते हैं। उदाहरण— उर्वरकों के प्रयोग, सिंचन सुविधाओं का विस्तार के कारण बेकार पड़ी बंजर भूमि पर गेहूँ, चावल की खेती होने लगी। अत: विभिन्न फसलों के उत्पादन क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं।
2. **आर्थिक सीमाओं तथा अनुकूलतम दशाओं का सिद्धांत** (Theory of economic limits and optimum conditions)—फसलों का उत्पादन आर्थिक दशाओं से भी निर्धारित होता है। आर्थिक दशाओं के अंतर्गत परिवहन व्यवस्था, बाजार की उपस्थिति, माँग की मात्रा, आर्थिक नीति आदि को सम्मिलित किया जाता है जो फसल उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। इस दशा में फसल उत्पादन का विशेष महत्त्व होता है। इन आर्थिक तत्त्वों के परिवर्तनशील होने के कारण इनके आधार पर किसी फसल की आर्थिक सीमा का निर्धारण अधिक कठिन होता है। अनुकूलतम आर्थिक दशाओं का क्षेत्र विशेष महत्त्व रखता है। यदि अनुकूलतम आर्थिक दशा वाले क्षेत्र में कई फसलों का उत्पादन किया जा सकता है तो उसी फसल का उत्पादन किया जायेगा जिससे सबसे अधिक आर्थिक लाभ हो।

TOUCH 'n' PASS

प्र.4. कृषि प्रदेशों की विभिन्न परिभाषाएँ दीजिए।
Give the different definitions of agricultural regions.

उत्तर

कृषि क्षेत्रों की विभिन्न परिभाषाएँ
(Different Definitions of Agricultural Regions)

परिभाषाएँ—ऐसे विस्तृत कृषि प्रदेश होते हैं जिसमें कृषि से सम्बन्धित विशेषताओं की समानता मिलती है, यह समानता निकटवर्ती प्रदेश में भिन्नता रखती है। किसी विशेष कृषि प्रदेश में यह समरूपता, फसलों के प्रकार उत्पादन विधि, कृषि में प्रयुक्त उपकरण एवं प्रविधि तथा कृषकों की जीवन पद्धति एवं स्तर आदि के रूप में हो सकती है। वो भिन्न कृषि प्रदेशों में भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक के कारण भी भिन्नता मिलती है। यही कारक कृषि प्रदेशों के निर्धारण में मूल मानक होते हैं।

इस प्रकार कृषि प्रदेश समरूप या आकृतिक प्रदेश होते हैं जिसमें प्रत्येक लक्षणों की समरूपता मिलती है। कृषि प्रदेश बहु विर्षण प्रदेश होता है। कृषि प्रदेश एक ग्रीक संकल्पना है क्योंकि कृषि तथा प्रदेश दोनों ही समय के साथ परिवर्तनशील है। इस कारण ही विभिन्न भूगोलवैत्ता अपने अनुसार भिन्न-भिन्न मानक अपनाकर कृषि प्रदेशों का निर्धारण करते हैं—

बुचानन के अनुसार, "शस्य शस्य साहचर्य (Crop Combination) पशु पावन साहचर्य आदि मापदण्डों के आधार पर कृषि प्रदेशों का सीमांकन किया जाना चाहिए। अत: परिवर्तनशील स्वरूप में पृथ्वी का कोई भाग जहाँ कृषि का एक विशिष्ट रूप में मिलता है एक कृषि प्रदेश कहलाता है।"

व्हीटलसी के अनुसार, "कृषि प्रदेश ऐसे विस्तृत क्षेत्र होते हैं जहाँ फसलों की किस्मों तथा उनकी उत्पादन विधि में समरूपता मिटाती है। साथ ही कृषि भूमि उपयोग में विशिष्टताजन्य सम्बद्धता मिलती है।"

कृषि प्रदेशों का सीमांकन (Limitation of Agricultural Regional)—कृषि प्रदेशों को निर्धारित करने के लिये फसल, पशु साहचर्य, कृषि की विधियाँ आदि को समाहित किया जाता है, ब्रेकर 1926 ने कृषि प्रदेशों के प्राकृतिक कारकों को आधार माना इसके विपरीत व्हीटलसी 1936 तथा डिफेन ने 1935 ने आर्थिक कारकों को अपेक्षाकृत अधिक महत्त्व दिया।

विश्व के कृषि प्रदेशों को सीमांकन करने में हंटिग्टन, जानसन, बेकर तथा व्हीटलसी के कार्य अधिक महत्त्वपूर्ण रहे हैं।

हंटिगन के अनुसार, प्राकृतिक पर्यावरण कारकों के आधार पर विश्व चार कृषि परिमण्डलों में विभाजित है ये कृषि परिमण्डल निम्न हैं—

प्रथम परिमण्डल में वे क्षेत्र सम्मिलित हैं जो कृषि के लिये सर्वथा अनुपयुक्त हैं। इनमें टुण्ड्रा तथा अन्य हिमाच्छारित क्षेत्र, उच्च पर्वतीय क्षेत्र तथा उष्ण मरूस्थल मुख्य हैं।

द्वितीय वर्ग में कृषि के लिए अनुपलब्ध क्षेत्रों को सम्मिलित किया है जो कृषि के योग्य है लेकिन उपलब्ध नहीं है; जैसे—विषुवत रेखीय वर्षा वन, टैगा वन आदि।

तृतीय वर्ग में कृषि वाले क्षेत्र जिनमें निम्न अक्षांशीय आर्द्र एवं शुष्क प्रदेश, मानसून प्रदेश आदि आते हैं।

चतुर्थ वर्ग में कृषि के लिए अनुकूल दशाओं वाले क्षेत्र जिनमें पश्चिमी यूरोपीय जलवायु तथा अमेरिकी महाद्वीपीय जलवायु मध्य अक्षांशीय, पूर्वी तटीय जलवायु तथा भूमध्य सागरीय जलवायु को सम्मिलित किया जाता है।

जॉनसन के अनुसार, "विश्व को अनुकूल और विषम प्राकृतिक दशाओं के आधार पर पाँच (जीवन, मृत्यु) कृषि प्रदेशों में विभाजित किया जाता है।"

1. उष्ण कटिबन्धीय जीवन प्रदेश
2. उष्ण तथा उपोष्ण कटिबन्धीय मृत्यु प्रदेश या मरुस्थल
3. उपोष्ण कटिबन्धीय प्रदेश या भूमध्य सागरीय प्रदेश
4. शीतोष्ण कटिबन्धीय जीवन प्रदेश
5. ध्रुवीय मृत्यु प्रदेश

कृषि का प्रादेशिक सीमांकन करने के लिये सैद्धांतिक से लेकर आनुभाविक, विवरणात्मक तथा सांख्यिकीय विधियों का उपयोग किया जाता है, ये विधियाँ निम्नलिखित हैं—

1. **आदर्शी विधियाँ**—वॉन थ्यूनेन का 1826 का संकेन्द्रीय वृत खण्ड अग्रणी है इसमें एक समान भौगोलिक दशाओं वाले उर्वर मैदान की कल्पना की गई है। थ्यूनेन के आधार पर 1925 में जानसन ने यूरोपीय कृषि व्यवस्था का निर्धारण किया ई०एम० हूबर ने भी सन् 1948 में आदर्शी सिद्धांत का प्रयोग किया।

TOUCH 'n' PASS

2. **आनुभाविक विधियाँ** (Empircal Techniques)—इस विधि में व्यक्तिगत अनुभवों का उपयोग करके कृषि प्रदेश विरचित किये जाते हैं। इन विधियों का प्रयोग ओ०ई०बेकर (1926-33) जानसन (1923 -26), सी०एफ० जॉन्स (1926-30) जी० टेलर (1930) तथा एस०बी० बाल्केवर्ग (1931-36) द्वारा किया गया। इसमें बेकर अग्रणी है उन्होनें अपने अनुभव के आधार पर आर्थिक कारकों की व्याख्या की है। उनके विचार में कृषि प्रदेश ऐसा होता है जहाँ कृषि सम्बन्धी दशाऐं समान पायी जाती हैं जो जलवायु पर निर्भरता रखती है।
3. **सांख्यिकीय विधियाँ**—अनुभव तथा निरीक्षण पर आधारित विधियों का स्थान सांख्यिकीय विधियों ने लिया है इसका उपयोग सांख्यिकीय सिद्धांतों के द्वारा किया जाता है। इन विधियों में प्रयुक्त कारकों के आधार पर तीन प्रकार के कृषि प्रदेश सीमांकित किये जाते हैं जो निम्न हैं—
   (i) **एक तात्विक विधि**—एक ही तत्त्व को आधार मानकर कृषि प्रदेश का निर्धारण किया जाता है जिसमें फसलों के संकेन्द्रण के अनुसार प्रमुख तथ्य निर्धारित कर लिये जाते हैं; जैसे—अमेरिका में कपास पेटी या मक्का पेटी इसी आधार पर निर्धारित किये गये हैं।
   (ii) **बहुतात्विक विधि**—इस विधि में कृषि प्रादेशीकरण कई मापदण्डों के आधार पर किया जाता है।

(अ) भूमि क्षमता प्रदेश (ब) भू जोत तंत्र
(स) कृषि तंत्र प्रदेश (द) प्रकार्यात्मक प्रदेश

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्र.1. एक ऐसी भूसंपत्ति जहाँ बिक्री के लिए एक नकदी फसल उगायी जाती है। उसे ..... के रूप में जाना जाता है।
(क) किचन गार्डन (ख) बागवानी खेती
(ग) झूम की खेती (घ) उपउत्पादन खेती
उत्तर (ख) बागवानी खेती

प्र.2. उर्वरकों में क्रांति का संबंध किस रंग से है?
(क) गुलाबी (ख) स्वर्ण (ग) काला (घ) धूसर
उत्तर (घ) धूसर

प्र.3. मुगा रेशम भारत के इनमें से किस राज्य से संबंधित है?
(क) अरूणाचल प्रदेश (ख) बिहार (ग) महाराष्ट्र (घ) असम
उत्तर (घ) असम

प्र.4. जिस क्षेत्र में किसान केवल सब्जियों के विशेषज्ञ होते हैं, इस प्रकार की खेती को कहा जाता है–
(क) सहकारी खेती (ख) मिश्रित खेती (ग) ट्रक खेती (घ) सामूहिक खेती
उत्तर (ग) ट्रक खेती

प्र.5. निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य भारत में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है?
(क) मध्य प्रदेश (ख) पश्चिम बंगाल (ग) आंध्र प्रदेश (घ) राजस्थान
उत्तर (ग) आंध्र प्रदेश

प्र.6. किस भारतीय राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली एक बहुत पुरानी प्रथा है?
(क) छत्तीसगढ़ (ख) मेघालय
(ग) तेलंगाना (घ) महाराष्ट्र
उत्तर (ख) मेघालय

प्र.7. निम्नलिखित में से भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव के क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है?
(क) व्यापक निर्वाह खेती (ख) व्यावसायिक खेती
(ग) आदिम निर्वाह खेती (घ) गहन निर्वाह खेती
उत्तर (घ) गहन निर्वाह खेती

TOUCH 'n PASS

प्र.8. वर्ष ..... में, भारत की तत्कालीन प्रधान मंत्री, इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति की शुरूआत करने के लिए 'गेहूँ क्रांति' शीर्षक से विशेष डाक टिकट जारी किए।

(क) 1987 (ख) 1975 (ग) 1950 (घ) 1968

उत्तर (घ) 1968

प्र.9. हरित क्रान्ति सम्बन्धित है–

(क) मछली उत्पादन (ख) कृषि उत्पादन

(ग) दुग्ध उत्पादन (घ) इनमें से कोई नहीं

उत्तर (ख) कृषि उत्पादन

प्र.10. निम्नलिखित में से कौन भारत में फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है?

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (ख) कृषि लागत और मूल्य आयोग

(ग) राजकोषीय विवेक आयोग (घ) कृषि लागत और मूल्य आयोग

उत्तर (ख) कृषि लागत और मूल्य आयोग

प्र.11. स्वर्ण क्रांति किससे सम्बन्धित है?

(क) कीमती खनिज (ख) दलहन (ग) जूट (घ) बागवानी और शहद

उत्तर (घ) बागवानी और शहद

प्र.12. भारत का सर्वाधिक गेहूँ उत्पादक राज्य कौन-सा है?

(क) उत्तर प्रदेश (ख) पंजाब (ग) हरियाणा (घ) मध्य प्रदेश

उत्तर (क) उत्तर प्रदेश

प्र.13. भारत में हरित क्रांति की शुरुआत ..... के दशक में हुई थी।

(क) 1940 (ख) 1990 (ग) 1950 (घ) 1960

उत्तर (घ) 1960

प्र.14. विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है–

(क) स्वामीनाथन (ख) नॉर्मन बोरलॉग

(ग) एम०एस० गौड (घ) इनमें से कोई नहीं

उत्तर (ख) नॉर्मन बोरलॉग

प्र.15. हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई?

(क) 1950 (ख) 1951 (ग) 1956 (घ) 1966

उत्तर (घ) 1966

प्र.16. गुलाबी क्रांति संबंधित है–

(क) झींगा मछली उत्पादन (ख) अण्डा उत्पादन

(ग) सूर्यमुखी एवं अन्य तिलहन (घ) इनमें से कोई नहीं

उत्तर (क) झींगा मछली उत्पादन

प्र.17. सर्वप्रथम अनुकूलतम आर्थिक दशाओं तथा सीमाओं का नियम किसने प्रस्तुत किया?

(क) मैकार्थी (ख) लिण्डवर्ग

(ग) ये दोनों (घ) इनमें से कोई नहीं

उत्तर (ग) ये दोनों

प्र.18. निम्नलिखित में से कौन फसल उत्पादन अनुकूलता के लिए आवश्यक है?

(क) तापमान (ख) आर्द्रता (ग) वर्षा (घ) ये सभी

उत्तर (घ) ये सभी

TOUCH 'n' PASS

प्र.19. विश्व का वृहत्तम चावल उत्पादक देश है–
(क) भारत (ख) चीन (ग) अमेरिका (घ) नेपाल
उत्तर (ख) चीन

प्र.20. गेहूँ की जन्मभूमि कहा जाता है–
(क) भारत (ख) फिलीस्तीन (ग) अमेरिका (घ) मिस्र
उत्तर (ख) फिलीस्तीन

प्र.21. मक्का का वृहत्तम उत्पादक देश है–
(क) चीन (ख) भारत (ग) अमेरिका (घ) रूस
उत्तर (ग) अमेरिका

प्र.22. वॉन थ्यूनेन ने कृषि का स्थानीकरण सिद्धांत किस वर्ष में दिया था?
(क) 1820 (ख) 1824 (ग) 1826 (घ) 1828
उत्तर (ग) 1826

प्र.23. ''कृषि प्रदेश ऐसे विस्तृत क्षेत्र होते हैं जहाँ फसलों की किस्मों तथा उनकी उत्पादन विधि में समरूपता मिलती है। साथ ही कृषि भूमि उपयोग में विशिष्टताजन्य सम्बद्धता मिलती है।'' यह कथन किसका है?
(क) हंटिगन (ख) व्हीटलसी
(ग) बुचानन (घ) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (ख) व्हीटलसी

प्र.24. ''विश्व को अनुकूल और विषम प्राकृतिक दशाओं के आधार पर पाँच कृषि प्रदेशों में विभाजित किया जाता है।'' यह कथन है–
(क) ई०एम० हूलर (ख) जॉनसन
(ग) एस०बी० बाल्केवर्ग (घ) थ्यूनेन
उत्तर (ख) जॉनसन

प्र.25. अण्डा उत्पादन से सम्बन्धित क्रांति है–
(क) रजत क्रांति (ख) स्वर्ण क्रांति
(ग) श्वेत क्रांति (घ) हरित क्रांति
उत्तर (क) रजत क्रांति

TOUCH 'n PASS

UNIT-V

उद्योगों के प्रकार

Types of Industries

खण्ड-अ अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत उद्योग कौन-सा है?

Which is the basic industry for Industrial Development?

उत्तर लोहा और इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। अत: इसे अन्य सभी उद्योगों की जननी भी कह कहते हैं, क्योंकि इसके उत्पादन अन्य सभी वस्तुओं के निर्माण में सहायक होते हैं। इसी उद्योग से किसी देश के औद्योगिक विकास की नींव पड़ती है।

प्र.2. टाटा लोहा और इस्पात कारखाना कब स्थापित किया गया?

When was the Tata Iron and Steel Plant established?

उत्तर टाटा लोहा और इस्पात का कारखाना (TISCO) भारत में निजी क्षेत्र का सबसे पहला बड़ा कारखाना है। जहाँ भारत का 20 प्रतिशत इस्पात बनता है। यह कोयले की अपेक्षा लोहे की खानों के अधिक निकट है। यह कारखाना साकची नामक स्थान पर झारखण्ड में सिंहभूम जिले में स्वर्णरेखा एवं खारकोई नदियों के संगम पर सन् 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था। इन दोनों नदियों की लगभग 5 किलोमीटर चौड़ी घाटी में यह कारखाना स्थित है।

प्र.3. भारी इंजीनियरिंग उद्योग की प्रमुख समस्याएँ लिखिए।

Write the major problems of Heavy Engineering Industry.

उत्तर इन उद्योगों की प्रमुख समस्याएँ निम्नांकित हैं—

(i) नव-विकसित व उन्नत तकनीक का सीमित उपयोग, (ii) विदेशों से आयातित माल से कड़ी प्रतिस्पर्द्धा, (iii) विद्युत एवं ऊर्जा साधनों की निरन्तर कमी, (iv) परिवहन की कठिनाई आदि हैं।

प्र.4. भारत में कांच का सामान बनाने का उद्योग कितने भागों में विभक्त है?

Into how many parts is the Glassware Industry in India Divided?

उत्तर भारत में काँच का सामान बनाने का उद्योग दो भागों में हैं प्रथम प्रकार के कारखाने वे हैं जो कुटीर उद्योगों के रूप में काम करते हैं, और दूसरे प्रकार के वे कारखाने हैं, जो आधुनिक फैक्टरियों के रूप में काम करते हैं।

प्र.5. भारत के कपड़े का निर्यात किन देशों में होता है?

In which countries are the clothes exported from India?

उत्तर भारत से कपड़ों का निर्यात मुख्यत: अरब गणराज्य, सूडान, ब्रिटिश, पूर्वी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सिंगापुर, इथोपिया, इंग्लैण्ड, म्यांमार, मलेशिया, ECM के देश व USA आदि देशों को होता है। इन देशों को मुख्यत: लट्ठा, चादरें, मलमल, वायल, छींट, कोट का कपड़ा, खादी तथा धुला और बिना धुला मोटे कपड़े का अधिक निर्यात होता है।

प्र.6. उत्तर प्रदेश में वस्त्र उद्योग की कितनी मिलें हैं?

How many textile mills are there in Uttar Pradesh?

उत्तर उत्तर प्रदेश में वस्त्र उद्योग की 62 मिलें हैं। इनमें 52 कताई मिलें और 10 मिश्रित मिले हैं। यहाँ 19वीं शताब्दी के अन्त में उद्योग का विकास हुआ है। उत्तर प्रदेश में यद्यपि मुरादाबाद, वाराणसी, बरेली, अलीगढ़, मोदीनगर, हाथरस, सहारनपुर, रामपुर, इटावा आदि स्थानों में सूती कपड़े की मिलें हैं, किन्तु कानपुर इस उद्योग का प्रमुख केन्द्र है जहाँ 10 मिलें हैं। कानपुर को उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहते हैं।

TOUCH 'n' PASS

प्र.7. भारत से जूट का तैयार माल किन-किन देशों में निर्यात किया जाता है?
To which countries are the Finished Jute goods Exported from India?

उत्तर भारत में जूट का तैयार माल संयुक्त राज्य अमेरिका, सुदूरपूर्व अफ्रीकी देशों, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंग्लैण्ड, अर्जेण्टाइना, कनाडा, न्यूजीलैण्ड, रूस, पूर्वी यूरोपीय देशों में तथा मध्य-पूर्व के देशों को भेजा जाता है।

प्र.8. भारत का छठा सार्वजनिक क्षेत्र का एकीकृत इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया?
Where was India's 6th Public Sector Integrated Steel Plant Established?

उत्तर देश का छठा सार्वजनिक क्षेत्र का एकीकृत इस्पात संयंत्र विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया है। यह देश का पहला तटीय इस्पात संयन्त्र है जो राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (RINL) द्वारा संचालित है।

प्र.9. भारत में एलुमिनियम उद्योग का विकास कब हुआ?
When did the Aluminum Industry develop in India?

उत्तर भारत में एलुमिनियम उद्योग का विकास द्वितीय महायुद्ध काल में हुआ। सन् 1937 में आसनसोल के निकट जे०के० नगर में एलुमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया की स्थापना की गयी। इसमें एलुमिनियम ढलाई व चादरें बनाने तक का सम्पूर्ण कार्य एक ही स्थान पर होता है।

प्र.10. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कच्चे इस्पात का उत्पादन कितना था?
What was the production of raw steel under the Eleventh Five Year Plan?

उत्तर ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष (2011-12) में कच्चे इस्पात का उत्पादन 74.29 मिलियन टन रहा।

खण्ड-ब लघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. भारत में लौह-इस्पात उद्योग के विकास पर प्रकाश डालिए।
Describe the development of Iron-Steel Industry in India.

उत्तर

भारत में लौह-इस्पात उद्योग का विकास
(Development of Iron-Steel Industry in India)

भारत में लोहा पिघलाने, ढालने तथा इस्पात तैयार करने का कार्य अत्यन्त प्राचीन काल से किया जा रहा है। दिल्ली का लौह-स्तम्भ जो लगभग 1500 वर्ष पुराना है, इस उद्योग की उस समय की उन्नति का परिचायक है। अगारिया जाति यह कार्य मध्यवर्ती भारत व नागपुर के पठार में करती थी जिन्हें गाड़िया लुहार के नाम से भी सम्बोधित किया जाता है। किन्तु पश्चिमी देशों में आधुनिक ढंग से कारखानों के स्थापित हो जाने के कारण भारतीय कुटीर उद्योग को बड़ा धक्का पहुँचा और भारत निर्यातक से आयातक देश बन गया। 18वीं और 19वीं शताब्दी में दक्षिणी भारत में 1779 और 1830 में अर्काट जिले में दो अंग्रेजों (मोटले फरकूहर तथा जोशिया हीथ) द्वारा इस्पात संयन्त्र लगाने के असफल प्रयत्न किए गए। सन् 1847 में पश्चिम बंगाल में झरिया कोयला-क्षेत्र कुल्टी में बाराकार लौह कम्पनी (Barakar Iron Company) की स्थापना की गयी। सन् 1889 में यह कारखाना बंगाल लौह इस्पात कम्पनी (Bengal Iron and Steel Company) के अधिकार में चला गया।

इसके बाद सन् 1907 में झारखण्ड में सांकची नामक स्थान पर भारत के प्रसिद्ध व्यवसायी जमशेदजी टाटा द्वारा टाटा लोहा-इस्पात कम्पनी (TISCO) की स्थापना की गयी जिसमें ढले लोहे का उत्पादन बार सन् 1911 में तथा इस्पात का उत्पादन सन् 1913 में किया गया। सन् 1908 में एक और कारखाना पश्चिम बंगाल में भारतीय लोहा-इस्पात कम्पनी (Indian Iron and Steel Company) के नाम से आसनसोल के निकट हीरापुर में स्थापित किया गया। सन् 1936 में कुल्टी और हीरापुर के दोनों कारखाने भारतीय लोहा और इस्पात कम्पनी (Indian Iron and Steel Company) के नाम से मिला दिए गए। सन् 1837 में बर्नपुर में स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल (Steel Corporation of Bengal) की स्थापना की गयी और इसे भी उपर्युक्त कम्पनी में 1953 में मिला दिया गया। इस प्रकार भारतीय लोहा और इस्पात कम्पनी के अन्तर्गत तीन मुख्य इकाइयाँ (कुल्टी, हीरापुर तथा बर्नपुर के कारखाने) हैं। 1972 से इसका प्रबन्ध केन्द्र सरकार के हाथ में है। सन् 1923 में दक्षिण भारत में मैसूर सरकार द्वारा मैसूर लोहा और इस्पात कारखाना (Mysore Iron and Steel Works) की स्थापना की गयी। अप्रैल 1962 से इस कारखाने का प्रबन्ध मैसूर आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड कम्पनी (Mysore Iron and Steel Ltd. Company) के हाथ में चला गया। इस कारखाने का नाम अब बदलकर विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात लिमिटेड

(Visvesvaraya Iron and Steel Works Ltd.) कर दिया गया है। इन सब कारखानों का इस्पात 1939 में 8 लाख टन से कुछ अधिक और ढले लोहे का 18 लाख टन का था। द्वितीय विश्वयुद्ध काल में इस उद्योग की बड़ी प्रगति हुई। सन् 1950 में ढले लोहे का उत्पादन 15 लाख टन और इस्पात का 10 लाख टन हुआ था।

प्र.2. भारतीय लोहा और इस्पात कारखाने की स्थापना कब हुई थी? संक्षेप में बताइए।

When the Indian Iron and Steel Factory was established. Briefly describe.

उत्तर भारतीय लोहा और इस्पात का कारखाना (IISCO) सन् 1874 में स्थापित किया गया, जहाँ भारत में सबसे अधिक लोहे की ढलाई का काम होता रहा है। यह कारखाना कुल्टी में लोहे और कोयले के क्षेत्र के समीप ही दामोदर की शाखा बाराकर नदी पर स्थापित किय गया जो कोलकाता से 225 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम की ओर है इसकी कुल तीन इकाइयाँ हैं। हीरापुर की इकाई आसनसोल के दक्षिण में 6.5 किलोमीटर दूर, दूसरी इकाई कुल्टी में जो हीरापुर से 16 मिलोमीटर पश्चिम में है और तीसरी इकाई बर्नपुर में जो आसनसोल से 5 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में है। हीरापुर और बर्नपुर में ढला लोहा और इस्पात दोनों ही बनाये जाते हैं। ये तीनों कारखाने संगठित रूप में कार्य करते हैं। 1976 से इसका प्रबन्ध पूर्णत: सार्वजनिक क्षेत्रों में SAIL के पास आ गया है।

प्र.3. चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किस कारखाने का निर्माण किया गया था?

Which factory was built under the Fourth Five Year Plan?

उत्तर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत एक नया कारखाना बोकारो (झारखण्ड) में रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। यह दो चरणों में पूरा बनकर तैयार हुआ है। इसके लिए ₹ 333 करोड़ की पूँजी वाली कम्पनी बोकारो स्टील लिमिटेड की स्थापना की गयी है।

इसकी स्थापना के पीछे के कारण हैं—

(i) यहाँ जो इस्पात तैयार किया जाता है वह कम मूल्यों पर बनाया जाता है।

(ii) यह जमशेदपुर तथा झरिया के कोयला क्षेत्रों के निकट पड़ता है। अत: इसकी स्थापना से सम्पूर्ण इस्पात कोयला क्षेत्र में एक समन्वय होकर औद्योगिक क्षेत्र पूर्ण संगठित हो गया।

(iii) सिन्द्री के कारखाने के निकट होने के कारण यहाँ बनाया जाने वाला कोक रासायनिक खाद बनाने के लिए पर्याप्त है। यहाँ के चूने व लोहे के अवशिष्ट (Slag) का सीमेण्ट के कारखानों में उपयोग होता है। इस प्रकार बोकारो इस्पात संयन्त्र की स्थिति आदर्श मानी जाती है।

यहाँ डिब्बे, इंजन, साइकिलें, गाड़ियाँ तथा अनेक तरह का इस्पात का सामान बनाया जाता है। सभी इस्पात इकाइयों के साथ ऐसे कई उद्योगों की आवश्यकता पड़ती है जिनमें इस्पात से वस्तुएँ बनायी जा सकें। बोकारो से 40 किलोमीटर की दूरी पर मुरी में एलुमिनियम साफ करने का कारखाना, तन्दू, में (19 किलोमीटर की दूरी पर) सीसा, जस्ता आदि साफ करने का कारखाना तथा गुलमरी में टिन की चादरें बनाने तथा अन्य केन्द्रों में काँच और अग्नि-प्रतिरोधक ईंटों के बनाने का उद्योग और दामोदर नदी के निकट गोमिया में विस्फोटक पदार्थ बनाने का उद्योग केन्द्रित है। अत: बोकारो के आस-पास अनेक प्रकार के धातुशोधन व सहायक उद्योग स्थापित होने से यह चुनाव का आदर्श स्थल माना जाता है। इसकी उत्पादन क्षमता इस समय 37.80 लाख टन इस्पात पिण्डों (Steel Ingots) की है।

प्र.4. भारत में एलुमिनियम के उत्पादन एवं व्यापार से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए।

What you understand by the production and trade of aluminum in India? Explain.

उत्तर

उत्पादन एवं व्यापार
(Production and Trade)

भारत एलुमिनियम के उत्पादन में न सिर्फ स्वावलम्बी है बल्कि यह एलुमिना एवं शुद्ध धातु का 1985-86 से निर्यात करता रहा है। यहाँ का एलुमिना विदेशों में उत्तम किस्म का माना जाता है। वर्तमान में देश की उत्पादन क्षमता 875 हजार टन शुद्ध धातु बनाने की है, निर्यात वृद्धि हेतु निजी क्षेत्र में ₹ 1,200 करोड़ की लागत से शत-प्रतिशत निर्यात वाली एक इकाई आन्ध्र प्रदेश में स्थापित की जा रही है।

भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एलुमिनियम उत्पादक देश तथा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा एलुमिनियम उपभोक्ता देश है।

TOUCH 'n PASS

प्र.5. रासायनिक उद्योगों को कितने भागों में बाँटा जा सकता है, स्पष्ट कीजिए।
Make clear into how many parts can the Chemical Industries can be divided.

उत्तर रासायनिक उद्योग दो प्रकार के होते हैं—

1. **भारी रासायनिक पदार्थों** (Heavy Chemicals) के अन्तर्गत गन्धक का तेजाब, हाइड्रोक्लेरिक ऐसिड (नमक का तेजाब), शीरे का तेजाब, विभिन्न प्रकार के सल्फेट, कॉस्टिक सोडा, सोडा एश, अमोनिया, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन, पोटैशियम क्लोरेट और रासायनिक खादें। (अमोनिया सल्फेट, पोटैशियम नाइट्रेट, सुपरफॉस्फेट, शोरा) आदि का उत्पादन सम्मिलित किया जाता है। विविध आधारभूत रासायनिक पदार्थ जो कि नेप्था से तैयार किए जाते हैं एवं जिनसे अनेक प्रकार के फिलामेण्ट या रेशे प्राप्त होते हैं।
2. **कीमती और हल्के रासायनिक पदार्थों** (Fine Chemicals) के अन्तर्गत फोटोग्राफी में काम आने वाले रसायन, दवाइयाँ, रंग, पेण्ट, वार्निश और रोगन, विविध प्रकार के रेशे, विशेष अम्ल, लेप आदि भी सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें विशेष किस्म के सिलीकॉन, सुपर संवेदनशील रसायन, विशिष्ट गैसीय ईंधन, लेप आदि भी सम्मिलित हैं। इनका उपयोग सामान्य उद्योगों, विद्युत व इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगों एवं अन्तरिक्ष उद्योग में समान रूप से होता रहा है।

प्र.6. सूती वस्त्र उद्योग की प्रमुख विशेषताएँ लिखिए।
Write the main features of Cotton Textile Industry.

उत्तर भारत के सूती वस्त्र उद्योग की विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

1. यह संगठित उद्योगों में सबसे बड़ा उद्योग है। इसके उत्पादन का वार्षिक मूल्य ₹ 10,000 करोड़ से भी अधिक का होता है।
2. इस उद्योग में लगभग साढ़े तीन करोड़ श्रमिक रोजगार पाते हैं। कपड़ा उद्योग देश में कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा बड़ा क्षेत्र है।
3. कपास का वार्षिक औसत उपभोग 135 लाख गांठों का होता है।
4. इस उद्योग में मशीन उद्योग, मिल-स्टोर, रासायनिक पदार्थ, आदि उद्योगों का निर्मित माल औसत ₹ 300 से 450 करोड़ के मूल्य का खपता है।
5. सभी प्रकार के वस्त्रों के निर्यात से 2019-20 में ₹ 61,857 करोड़ की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई थी।
6. इस उद्योग की सबसे बड़ी आवश्यकता उद्योग के आधुनिकीकरण तथा मशीनों और संयन्त्रों के नवीनीकरण तथा उत्पादन के विभिन्नीकरण करने की है जिससे भारतीय कपड़ा विदेशी बाजारों में अन्य देशों से प्रतिस्पर्द्धा कर सके। 1975 के पश्चात् प्राय: सभी मिलों में कृत्रिम एवं मिश्रित रेशे का निरन्तर उपयोग बढ़ता जा रहा है। अत: प्राय: सभी मिलें विविध कृत्रिम रेशों से धागे अवश्य बनाती हैं इससे मिलों का लाभांश भी बढ़ जाता है।

प्र.7. जूट उद्योग से आप क्या समझते हैं संक्षेप में वर्णन कीजिए।
Briefly describe what you understand by Jute Industry.

उत्तर भारत में जूट को सोने का रेशा (Golden Fibre) कहकर पुकारा जाता है। कपास की भाँति जूट से भी खुरदरा और मोटे किस्म का कपड़ा तैयार करने में भारत प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध रहा है। इससे टाट, बोरों और परदों का कपड़ा तैयार किया जाता था। अब इसके उत्पादन में आश्चर्यजनक विविधता आ गई है। रंग-बिरंगे परदों, दरियाँ, फर्श, बिछावन, सोफों के कपड़े, वाटरप्रूफ कपड़ों के अतिरिक्त प्लास्टिक, फर्नीचर, कम्बल, बिजली-निरोधक सामान और ऊन या कपास के साथ मिलाकर कपड़े, सजावट की वस्तुएँ, आदि तैयार करने में भी इसका व्यापक उपयोग होने लगा है। टाट की गाँठें पैक करने, अनाज को गोदामों में रखने या जहाजों पर लादकर विदेशों में भेजने के लिए भी बोरों और टाटों का अधिक उपयोग होता रहा है।

प्र.8. जूट की माँग को निरन्तर बनाए रखने के लिए भारतीय केन्द्रीय जूट समिति ने क्या उपाय एवं निर्देश दिए हैं?
What measures and instructions have been given by the Central Jute Committee of India to maintain the demand for jute continuously?

उत्तर अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में जूट से बने माल की माँग निरन्तर बनाए रखने के लिए 'भारतीय केन्द्रीय जूट समिति' ने निम्न उपाय ढूँढे हैं एवं अनेक कार्य व शोधकर इसको दिशा निर्देश भी प्रस्तुत किए हैं—

TOUCH 'n' PASS

(i) **भवन निर्माण एवं सजावट के कार्यों में**—ताप निरोधक, प्लास्टिक की मेजों, कुर्सियों, कालीन, परदे, सोफा आदि पर बिछाने के कपड़े, कम्बल, दीवारों पर टाँगने की वस्तुएँ आदि।

(ii) **यातायात**—मोटर-गाड़ियों की गद्दी का कपड़ा, जल-निरोधक ढक्कन, जीन, रस्सी, डोरी, डांडियों का कपड़ा।

(iii) **उद्योग**—बिजली प्रवाह निरोधक, प्लास्टिक को सुदृढ़ बनाने के लिए।

(iv) **वस्त्र**—चिकने एवं मुलायम धुले हुए रेशों को ऊन एवं सूत के साथ मिलाकर इनकी माँग आठ गुनी बढ़ जाने की सम्भावना है।

खण्ड-स विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. 'लोहा और इस्पात उद्योग' का विस्तृत रूप से वर्णन कीजिए।
Describe in detail the 'Iron and Steel Industry'.

उत्तर इस्पात लोहे तथा कार्बन का मिश्रण होता है। विभिन्न कोटि की शक्ति और किस्म वाला इस्पात तैयार करने के लिए मैंगनीज, सिलिकॉन, क्रोमियम और वैनेडियम धातुएँ मिलायी जाती हैं। लोहा अपनी प्राकृतिक दशा में ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। उसमें मिट्टी, गन्धक, फॉस्फोरस तथा अन्य खनिज पदार्थ भी मिले होते हैं। इसलिए लोहे को इन प्राकृतिक मिश्रणों से अलग करके उसमें कार्बन आदि मिला देने से इस्पात तैयार हो जाता है। प्राचीन काल में लोहे को अन्य मिलावटों से अलग करने के लिए लकड़ी के कोयले से लौह-अयस्क गलाया जाता था, परन्तु इस विधि से अधिक मात्रा में लोहा तैयार नहीं होता था। 18वीं शताब्दी के मध्य से ही बढ़ती हुई माँग के कारण पत्थर के कोयले का उपयोग होने लगा, परन्तु सभी प्रकार के कोयले में आवश्यक शक्ति तथा रासायनिक गुण नहीं होते हैं। इसलिए कोयले से कोक तैयार किया जाता है जिसमें शक्ति और गुण दोनों ही अधिक होते हैं। जब लोहा कोक के साथ जलाया जाता है, तो कोक का कार्बन खनिज की ऑक्सीजन से मिलकर मोनोऑक्साइड बन जाता है जो गैस का रूप धारण करके वायु में उड़ जाता है। गन्धक, फॉस्फोरस, मिट्टी आदि की अन्य मिलावटें, चूना, मैंगनीज, आदि मिलाकर दूर कर दी जाती हैं। चूना और डोलोमाइट आदि के साथ मिलकर लोहे का सारा मैल (Slag) नीचे तलछट के रूप में जम जाता है। वर्तमान में यह तलछट (Slag) चूने की फैक्ट्रियों एवं सीमेण्ट उद्योग में काम में आता है।

इस्पात तैयार करने के संयन्त्र (Steel Plants)

इस्पात तैयार करने के संयन्त्र के चार विभाग होते हैं—

1. **कोक भट्टी** (Coke Oven) में पत्थर का कोयला जलाकर कोक बनाया जाता है।
2. **लपट वाली भट्टी** (Blast Furnance) में लौह-अयस्क को गलाकर लोहा बनाया जाता है।
2. **इस्पात गलाने के संयन्त्र** (Steel Melting Plant) में कार्बन तथा धातुएँ मिलाकर विविध ग्रेड किस्म का इस्पात बनाया जाता है।
4. **निर्मित माल मिल** (Rolling Mill) में इस्पात को ढालकर पटरियाँ, सरिए, चादरें, तार आदि बनाए जाते हैं।

उद्योग की संरचना (Industry Structure or Profile)

उत्पादों एवं उत्पादकों की श्रेणी के आधार पर इस उद्योग को निम्नांकित वर्गों में विभाजित किया जाता है—

1. **लौह अयस्क** (Iron Ore)—राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (NMDC), कुद्रेमुख लौह अयस्क कम्पनी (KIOC), सेसा (Sesa) गोवा देश में लौह-अयस्क उत्पादन के सबसे बड़े उत्पादक हैं। सेल (SAIL) और टाटा इस्पात की स्वयं की कैप्टिव लौह अयस्क खानें हैं।
2. **पिग आयरन** (Pig Iron)—**कुद्रेमुख** लौह-अयस्क कम्पनी, सेसा गोवा और ऊषा इस्पात देश में पिग आयरन के प्रमुख उत्पादक हैं। इनके अतिरिक्त मिनी ब्लास्ट फरनेस तथा सेल (SAIL) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड भी अपेक्षित मात्रा में पिग आयरन का उत्पादन करते हैं।
3. **स्पॉन्ज आयरन** (Sponge Iron)—एस्सार इस्पात, इस्पात इण्डस्ट्रीज, विक्रम इस्पात (ग्रासिम) देश में गैस आधारित स्पॉन्ज आयरन के प्रमुख उत्पादक हैं।

TOUCH 'n' PASS

4. **फ्लैट इस्पात उत्पाद** (Flat Steel Products)—सेल (SAIL), टाटा इस्पात, एस्सार इस्पात, इस्पात इण्डस्ट्रीज और जिन्दल विजयनगर (JVSL) देश में हॉट रोल्ड कोइल्स के बड़े उत्पादक हैं। सेल (SAIL), टाटा इस्पात, इस्पात इण्डस्ट्रीज, जिन्दल ग्रुप ऑफ कम्पनीज, उत्तम स्टील और भूषण स्टील देश में कोल्ड रोल्ड कोइल्स तथा गेल्वेनाइज्ड शीट्स के प्रमुख उत्पादक हैं।
5. **लोंग उत्पाद** (Long Products)—राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (RINL), सेल (SAIL) और टाटा इस्पात लोंग उत्पाद के प्रमुख उत्पादक हैं।
6. **एलॉय इस्पात उत्पाद** (Alloy Steel Products)— मुकन्द, महिन्द्रा यूजिन (Musco) और कल्याणी कारपेन्टर देश में एलॉय इस्पात के बड़े उत्पादक हैं। एलॉय इस्पात का उपयोग ऑटोमोटिव और इन्जीनियरिंग उद्योगों में होता है। उत्पादन विधि के आधार पर लोहा-इस्पात उद्योग को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—
   (i) **प्राथमिक या एकीकृत उत्पादक** (Integrated Producers)—सेल (SAIL), राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (RINL), टाटा इस्पात और जिन्दल विजयनगर इस्पात लि. देश में प्राथमिक विधि से इस्पात तैयार करने वाले सबसे बड़े उत्पादक हैं।
   (ii) **गौण उत्पादक** (Secondary Producers)—एस्सार स्टील, इस्पात इण्डस्ट्रीज और लॉयड्स स्टील (Lloyds Steel) देश में गौण विधि से इस्पात उत्पादित करने वाले सबसे बड़े उत्पादक हैं।

प्र.2. इस्पात उद्योग की मुख्य समस्याओं की विस्तृत रूप से विवेचना कीजिए।
Discuss in detail the main problems of Steel Industry.

उत्तर

इस्पात उद्योग की मुख्य समस्याएँ
(Problems of the Steel Industry)

वर्तमान में इस्पात उद्योग के तेजी से व निरन्तर विकसित नहीं होने के अनेक कारण रहे हैं। इनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं—

1. **अच्छे कोकिंग कोयले का अभाव**—लोहा गलाने के लिए अच्छे किस्म के कोकिंग कोयले की आवश्यकता पड़ती है, परन्तु भारत में इस प्रकार के कोयले का बहुत अभाव है। इस समस्या के समाधान के लिए कोयला खानों की व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है तथा उत्तम श्रेणी के कोयले के उत्पादन में वृद्धि की जा रही है। अब लिग्नाइट को साफ करके भी कोकिंग की टिकिया बनाई जा रही है। इसी भाँति विदेशों से (चीन व CIS के देशों से) उत्तम कोकिंग कोयले का आयात कर उसे स्वदेशी कोक में मिलाया जाने लगा है।
2. **प्रशिक्षित तकनीशियनों का अभाव**—लोहा-इस्पात उद्योग के लिए पर्याप्त संख्या में उच्च प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं मिल पाते। अत: अधिक संख्या में विदेशी विशेषज्ञों की नियुक्ति करनी पड़ती है। भिलाई, राउरकेला तथा दुर्गापुर कारखाने के बन जाने के कारण इस समस्या के समाधान हेतु अधिक संख्या में कर्मचारी रूस, जर्मनी तथा ब्रिटेन में प्रशिक्षण हेतु भेजे गए।
3. **इस्पात की कीमत सम्बन्धी समस्या**—देश में आवश्यकता से कम इस्पात का उत्पादन होता है, अत: इस्पात का आयात करना पड़ता है। स्वदेशी इस्पात तथा आयात किए हुए इस्पात के मूल्य में पर्याप्त अन्तर रहता है, परन्तु समता लाने के लिए दोनों प्रकार का इस्पात एक ही दर पर बेचा जाता है। अब अनेक प्रकार के करों को घटाकर एवं कार्यक्षमता एवं प्रति इकाई उत्पादन सुधारकर इस्पात के मूल्य को समरूपी एवं प्रतिस्पर्द्धात्मक किया गया है।
4. **क्षमता से कम उत्पादन**—देश का 90 प्रतिशत इस्पात का उत्पादन अब तक सार्वजनिक क्षेत्र में होता रहा है। 1990 तक यहाँ पर निरन्तर क्षमता से कम उत्पादन होता रहा अत: घाटा बढ़ता गया। अब व्यक्तिगत कम्पनियों को निश्चित स्तर पर घाटे की जिम्मेदारी व क्षमता के पूर्ण उपयोग की जिम्मेदारी आदि सौंपकर एवं निजी क्षेत्र में इस्पात निर्माण को छूट देकर इस पर नियन्त्रण किया जा रहा है।
5. **उत्पादन लागत अधिक**—अति पूँजीकरण, अधिक सामग्री लागत अथवा अत्यधिक श्रम लागत आदि के अधिक होने से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्द्धा करने में कठिनाई आती है।
6. **निर्यात सम्बन्धी कठिनाइयाँ**—बन्दरगाहों पर माल रखने के लिए पर्याप्त स्थानों का अभाव, बन्दरगाहों पर श्रम सम्बन्धी कठिनाइयाँ, भारतीय जहाजी कम्पनियों का अभाव तथा विदेशी जहाजी कम्पनियों द्वारा अधिक किराया लिया जाना निर्यात में कठिनाई पैदा करते हैं। अब इसमें तेजी से सुधार लाया गया है।

TOUCH 'n' PASS

प्र.3. एलुमिनियम निर्मित करने वाले प्रमुख कारखानों का विस्तार से वर्णन कीजिए।
Describe in detail the major factories manufacturing aluminium.

उत्तर ऐलुमिना और एलुमिनियम तैयार करने वाले कारखाने मुख्यत: निम्नलिखित क्षेत्रों में हैं—

1. **इण्डियन एलुमिनियम कम्पनी** (Indian Aluminum Company)—पूर्ण रूप से स्वावलम्बी है, क्योंकि बॉक्साइट से ऐलुमिना, ऐलुमिना से एलुमिनियम के पिण्ड और उसकी चादर, आदि बनाने के कार्य किये जाते हैं। बॉक्साइट की प्राप्ति **मुरी** से 32 किलोमीटर दूर झारखण्ड के लोहरदगा खानों से की जाती है जहाँ ऐलुमिना तैयार किया जाता है। दामोदर घाटी से मुरी को पानी व कोयला मिल जाता है। मुरी से ऐलुमिना 2,400 किलोमीटर दूर **अलवाये** (केरल) को भेजा जाता है, क्योंकि यहाँ पल्लीबासल योजना से सस्ती जल विद्युत-शक्ति मिल जाती है। यहाँ एलुमिनियम के पिण्ड तैयार किए जाते हैं। ये पिण्ड अलवाये से 2,400 किलोमीटर दूर **बेलूर** (पश्चिम बंगाल) में भेजे जाते हैं जहाँ इसकी चादरें तैयार की जाती हैं। एलुमिनियम का चूर्ण तथा पेस्ट बनाने का इस कम्पनी का कारखाना **थाना** (महाराष्ट्र) में है, इण्डियन एलुमिनियम कम्पनी के कारखानों में चादरें, छड़ें, रोगन व पेण्ट हेतु चूर्ण तथा पेस्ट आदि बनाये जाते हैं।
इस कम्पनी की एक इकाई हीराकुड बांध क्षेत्र में खोली गयी है जिसमें मुरी से एलुमिनियम मंगाकर एलुमिनियम तैयार किया जाता है। इसका दूसरा संयन्त्र **बेलगावी** (कर्नाटक) में चालू किया गया है।
वर्तमान में इस कम्पनी के संयन्त्रों की वार्षिक क्षमता 117 हजार टन की है। इसकी प्रत्येक इकाई को स्वावलम्बित व संगठित बनाने हेतु प्रत्येक स्थान पर सस्ती व पर्याप्त बिजली की प्राप्ति अत्यावश्यक है।
2. **भारत एलुमिनियम कम्पनी** (BALCO)—छत्तीसगढ़ में कोरबा में है जिसमें फुटका पहाड़ और अमरकंटक का बॉक्साइट काम में लाया जाता है। इसकी क्षमता 1.0 लाख टन की है। इसका दूसरा कारखाना आसनसोल में है। यहाँ चादरें, फायल, बर्तन आदि बनते हैं। 2 मार्च, 2004 को भारत सरकार ने इस कम्पनी की 51 प्रतिशत पूँजी और प्रबन्ध सम्बन्धी नियन्त्रण स्टरलाइट इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड को सौंप दिया है।
3. **हिन्दुस्तान एलुमिनियम कॉरपोरेशन (हिन्दाल्को)** (Hindustan Aluminium Corporation) का कारखाना उत्तर प्रदेश में सोन नदी की घाटी में मिर्जापुर के निकट **रेणुकूट** में है। यहाँ बॉक्साइट बिहार, झारखण्ड व मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। चूने का पत्थर विन्ध्याचल क्षेत्र से और सस्ती विद्युत-शक्ति रिहन्द बांध से मिलती है। यह भी पूर्णत: संगठित इकाई है। सम्पूर्ण कार्य एक ही स्थान पर किए जाते हैं। इसके संद्रावक की वार्षिक उत्पादन क्षमता 3.45 लाख टन की है एवं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी औद्योगिक इकाई है। इसका अपना शक्तिगृह 35 किलोमीटर दूर रेणुसागर में स्थित है जिसकी कुछ क्षमता 510 मेगावाट (380 + 150) है। अत: यह देश की सबसे बड़ी सुसंगठित एवं पूर्णत: आत्म-निर्भर इकाई है।
4. **मद्रास एलुमिनियम कम्पनी** (Madras Aluminium Company) का कारखाना मेटूर में है जहाँ शिवराय की पहाड़ियों से बॉक्साइट और चूने का पत्थर तथा मेटूर बांध से शक्ति प्राप्त होती है। इसकी क्षमता 25 हजार टन की है।
5. **नेशनल एलुमिनियम कम्पनी लिमिटेड** (NALCO) की स्थापना सन् 1981 में की गयी है। यह देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है। इसके तीन कारखाने मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश एवं ओडिशा में स्थित हैं। इसकी क्षमता 15.75 लाख टन ऐलुमिना तथा 2.88 लाख टन एलुमिनियम की है। इसके उत्पादन में नियमितता लाने के लिए कारखाने के ही ताप विद्युत-गृह में एक अतिरिक्त यूनिट अंगुल (ओडिशा) में लगाई जा चुकी है। NALCO की खानें पंचपत पहाड़ियाँ (कोरपाट) में ऐलुमिना बनाने का कारखाना दामनजोडी व अंगुल (कोरापुट) में निकट ही स्थित है। विशाखापट्टनम से लगभग 3.75 लाख टन ऐलुमिना प्रति वर्ष विदेशों में (यूरोप व अमेरिका) भेजा जाता है। नेशनल एलुमिनियम कम्पनी लिमिटेड 15.75 लाख टन प्रतिवर्ष की उत्पादन क्षमता के साथ एशिया का सबसे बड़ा ऐलुमिना उत्पादक कारखाना बन गया है।
अब भारत की सभी उपर्युक्त कम्पनियों को आत्म-निर्भर स्वयं के शक्तिगृहों सहित एवं मूल्य आधारित बनाया जा रहा है। इसी से स्वदेशी व विश्व बाजार में यह स्पर्द्धा कर पायेंगी। वैसे उद्योग का भविष्य उज्ज्वल माना जाता है।

TOUCH 'n' PASS

प्र.4. इन्जीनियरिंग उद्योग से आप क्या समझते हैं? विस्तृत रूप से वर्णन कीजिए।
What do you understand by Engineering Industry?

उत्तर

इन्जीनियरिंग उद्योग
(Engineering Industry)

इन्जीनियरिंग उद्योग के अन्तर्गत अनेक प्रकार की मिश्रित धातुओं, पूँजीगत माल, विविध मशीनरी, ढाँचे, पुर्जे, मशीनी औजार आदि का निर्माण किया जाता है। इसमें विविध कठोरता वाली धातुओं की आवश्यकता रहती है क्योंकि विविध क्षमता, दक्षता एवं कठोरता वाली मशीनें व उपकरण भी धातुओं के ही बने होते हैं। भारी ढाँचे व भारी इंजीनियरी सामान के निर्माण में अधिक पूँजी, विशेष तकनीकी ज्ञान और अनुभव, परिवहन की पूर्ण सुविधाएँ, रेल किराए में सौहार्दपूर्ण उदार नीति का पालन तथा सस्ती विद्युत ताप या शक्ति की व्यवस्था का होना आवश्यक है। इन्जीनियरिंग उद्योग के लिए उच्च तकनीकी वाले उपकरण व शुद्ध नियन्त्रण प्रणाली का विदेशों से भी आयात करना पड़ता है। ऐसा आयात मुख्यत: जापान, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली आदि से किया जाता रहा है।

सन् 1950 के बाद से ही इन्जीनियरी उद्योग में प्रगति हुई है और अब मशीनी औजार, रेल के डिब्बे व इंजन, बिजली की मोटरें, ट्रान्सफॉर्मर, चीनी वस्त्र व सीमेण्ट की मिलें, कोयला काटने की मशीनें व अन्य वाहन ट्रैक्टर, स्कूटर, साइकिलें, गीयर, फावड़े, बुलडोजर्स आदि वस्तुओं का उत्पादन बढ़ रहा है।

उद्योग के विकास के साथ-साथ इन्जीनियरिंग के सामान के निर्यात में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। सन् 1960-61 में इनका निर्यात केवल ₹ 22 करोड़ का था, जो बढ़कर सन् 1970-71 में ₹ 198 करोड़, 1990-91 में बढ़कर ₹ 3,872 करोड़ हो गया। यह वर्ष 2019-20 में ₹ 5,40,960.1 करोड़ तक जा पहुँचा है। यह निर्यात मुख्यत: म्यांमार, मलेशिया, ईरान, पूर्वी अफ्रीकी देशों, मिस्र, मध्यपूर्व, पाकिस्तान, सिंगापुर, ब्रिटेन, कनाडा और जर्मनी को किया जाता है।

यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018-19 में देश के कुल निर्यात में इन्जीनियरिंग उत्पादों का निर्यात 8.3% था, जो 2019-20 में बढ़कर 8.6% हो गया।

निर्माणकला (इन्जीनियरिंग) सम्बन्धी उद्योगों में कई प्रकार के उद्योग सन्निहित हैं। इसके अन्तर्गत स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग (Structural Engineering) (जिसके अन्तर्गत पुल आदि बनाना, तेल के कुएँ, हैंगर्स आदि दूसरे इस्पात के कामों का निर्माण करना आता है), औद्योगिक प्लाण्ट और मशीनरी (Industrial Plant and Machinery) के निर्माण का उद्योग, इंजन बनाने का उद्योग, मीटर आदि बनाने का उद्योग, हवाई जहाज बनाने का उद्योग, मशीन टूल्स (Machine Tools) (जिसके अन्तर्गत वे तमाम यान्त्रिक उपकरण आ जाते हैं जो लकड़ी या धातु के काटने, पॉलिश करने या उन पर काम करने के लिए अत्यन्त आवश्यक होते हैं), हल्की निर्माण कला के उद्योग (Light Construction Industry) (साइकिलें, सिलाई की मशीन, अन्य घरेलू उपयोग की मशीनें व उपकरण बनाने के उद्योग), बिजली के सामान सम्बन्धी उद्योग (Electrical Goods Industry) (पंखे, बत्तियाँ, मोटर्स, तार, सूखी बैटरियाँ, रेफ्रीजरेटर, कूलर्स A.C उपकरण, ट्रान्सफॉर्मर्स आदि), डीजल सम्बन्धी उद्योग, विद्युत की मशीनें, रेडियो और टेलीफोन के सामान बनाने के एवं इलेक्ट्रॉनिक्स व कम्प्यूटर उद्योगों का इसमें समावेश किया जाता है।

इंजीनियरिंग उद्योग को सामान्यत: दो भागों में बाँटा जाता है—

1. भारी मशीनों का इंजीनियरिंग उद्योग तथा
2. हल्की व कीमती मशीनों का इंजीनियरिंग उद्योग।

भारी मशीनों के इंजीनियरिंग उद्योग के अन्तर्गत औद्योगिक एवं कृषिगत मशीनों और उपकरणों का निर्माण सम्मिलित किया जाता है। भारी मशीनों, खनन मशीनों, भारी चादरों तथा संरचनाओं के उत्पाद हेतु अनेक कारखानों का निर्माण किया गया है। भारी इंजीनियरिंग सामान बनाने वाली मुख्य इकाइयाँ निम्न हैं—

भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड, राँची (Heavy Engineering Corporation Ltd., Ranchi)—भारी मशीनों एवं उपकरणों के उत्पादन की दिशा में "भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड राँची" की स्थापना 1958 में की गयी थी।

इसके अधीन 3 इंजीनियरिंग कारखाने हैं—

1. **भारी मशीनें बनाने का कारखाना (राँची)**—जो रूसी सहयोग से स्थापित किया गया है। इस कारखाने की वार्षिक उत्पादन क्षमता 80 हजार मीट्रिक टन भारी मशीनों के निर्माण की है।

2. **फाउण्ड्री फोर्ज कारखाना**—इस कारखाने की वार्षिक क्षमता प्रतिवर्ष 1 लाख 40 हजार मीट्रिक टन की है। इस प्लाण्ट की स्थापना में चेकोस्लोवाकिया से सहयोग मिला है।
3. **भारी मशीनी औजार बनाने का कारखाना**—यह कारखाना बोकारो व भिलाई स्टील प्लाण्ट को मशीनरी उपकरण, इस्पाती संरचनाएँ तथा मशीनी औजार की पूर्ति करता है। यह कारखाना अब लोहे के ढले हुए विशेष उत्पादों का, उपकरणों तथा मशीनरी औजारों का निर्यात करने लगा है। इसकी उत्पादन क्षमता 55 हजार मीट्रिक टन है।

खनन और सम्बद्ध मशीनरी निगम लिमिटेड, दुर्गापुर (Mining and Allied Machinery Corporation Ltd., Durgapur)—इस कारखाने की स्थापना खनन यन्त्र परियोजना के कार्य करने हेतु की गयी। प्रारम्भ में यह भारी इंजीनियरिंग निगम (राँची) का ही एक अंग था जिसे 1965 में सोवियत सरकार की सहायता से अलग अस्तित्व मिला। इस कारखाने में कोयला खनन के विभिन्न उपकरण; जैसे– कन्वेयर, कोल कटर, इन्जन, पंखे, पम्प, लदाई व गहरी खुदाई की भारी मशीनें व यन्त्र आदि तैयार किए जाते हैं। अब यहाँ बन्दरगाहों पर माल के चढ़ाने-उतारने सम्बन्धी उपकरणों, कोयला तथा खनिज शोधन यन्त्रों, खानों के रूफ सपोर्टर, इस्पात कारखानों के लिए कन्वेयर आदि का उत्पादन होने लगा है। विदेशों में निर्यात किए जाने वाले रेल के डिब्बों तथा लदान यन्त्रों का निर्माण हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि. के सहयोग से किया जाता है। ट्रैक्टरों के पुर्जों का निर्माण भी एच०एम०टी० के सहयोग से किया जाता है।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि.—यह सार्वजनिक क्षेत्र की एक नवरत्न कम्पनी है और ऊर्जा तथा आधारभूत संरचनात्मक क्षेत्र से सम्बन्धित सबसे बड़ा इन्जीनियरिंग और निर्माणी उपक्रम है। यह कम्पनी अपने 17 निर्माणी विभागों, 2 मरम्मत इकाइयों, 4 क्षेत्रीय कार्यालयों, 8 सेवा केन्द्रों, 15 क्षेत्रीय केन्द्रों, 1 सहायक कम्पनी और देश तथा विदेश में बड़ी मात्रा में परियोजना साइट्स के माध्यम से शक्ति सृजन एवं वितरण, उद्योग, परिवहन तथा सुरक्षा के क्षेत्र की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है।

भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वैसल्स लिमिटेड, विशाखापट्टनम (Bharat Heavy Plates and Vessels Ltd., Vishakhapatnam)—आन्ध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के निकट सन् 1966 में चेकोस्लोवाकिया की सहायता से इस कारखाने की स्थापना की गयी। इसमें रासायनिक खाद, पेट्रोलियम, पेट्रो-रसायन और इनसे सम्बन्धित सहायक उद्योगों के लिए आवश्यक भारी ढाँचे एवं विशेष उपकरण तैयार किए जाते हैं। इस कारखाने की वार्षिक उत्पादन क्षमता 25 हजार टन उपकरण तैयार करने की है।

प्र.5. सूती वस्त्र उद्योग के विकास एवं वर्तमान स्थिति का विस्तार से वर्णन कीजिए।
Describe in detail the development and present status of Cotton Textile Industry.

उत्तर

उद्योग का विकास और वर्तमान स्थिति
(Growth and Present Position of the Industry)

सूती वस्त्र उद्योग भारत में बहुत प्राचीन उद्योग रहा है। आज से 5,000 वर्ष पूर्व वैदिककाल में भी भारत में उत्तम कपड़ा बुना जाता था। सिन्धु की घाटी में ईसा से 3,000 वर्ष पूर्व के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थानों की खोज ने भी इसी बात को प्रमाणित किया है। मिस्र में ईसा से 2,000 वर्ष पूर्व पिरामिडों में मृत शरीर भारतीय मलमल एवं स्वदेशी लिनन में लिपटे हुए पाए गये हैं। प्राचीन रोम में भारतीय मलमल और छींट के वस्त्र पहनने में रोमन महिलाएँ गौरव समझती थीं। ढाका की मलमल से यूनानी भी परिचित थे जिसे **गंगा के देश वाला कपड़ा** (Gangetica) कहा गया। वास्तव में, ढाका की मलमल को इतना पसन्द किया जाता था कि इससे प्रभावित होकर विदेशियों ने, अनेक नाम दे रखे थे। उदाहरणार्थ, प्रवाहित जल (Running Water), वायुवितान (Woven Air) तथा **सांध्य सीकर** (Evening Dew)। भारतीय सूती वस्त्र उद्योग के सम्बन्ध में मुगलकालीन यात्री ट्रैवर्नियर लिखता है कि "भारतीय वस्तुएँ इतनी सुन्दर थीं कि वे तुम्हारे हाथ में हैं यह ज्ञान भी नहीं होता था। यह अति कोमलता से काते हुए धागों से बुना जाता था तथा एक पौण्ड रूई से 550 मील लम्बा धागा बुना जाता था। यह मलमल 400 नम्बर से भी ऊपर के सूत की बनाई जाती थी। एक युवा स्त्री का शरीर ढक जाने वाली मलमल का टुकड़ा अंगूठी में से निकाला जा सकता था।" आश्चर्य तो यह है कि यह सारा उद्योग उस समय हथकरघों द्वारा ही होता था। उद्योग के मुख्य केन्द्र पूर्वी तट पर, नागापट्टनम से ढाका के बीच तथा पश्चिमी तट पर मुम्बई, सूरत, भड़ौंच आदि मुख्य थे। कालीकट में कैलिको (Calico) कपड़ा विशेष रूप से बनाया जाता था। मसूलीपट्टनम में भी बढ़िया सुन्दर किस्म का सूती कपड़ा तैयार किया जाता था। अर्काट, अहमदाबाद तथा वाराणसी अन्य प्रमुख केन्द्र थे जहाँ सूती कपड़े के साथ सोने और चाँदी के तारों के धागे काम में लाये जाते थे। हथकरघा उद्योग 18वीं शताब्दी तक चलता रहा, किन्तु यूरोप की औद्योगिक क्रान्ति से इसको बड़ा धक्का पहुँचा। मशीनी युग ने इस उद्योग को और भी

TOUCH-n-PASS

जर्जर बना दिया। भारत में रेलों का विकास तथा पूर्व-पश्चिम के बीच स्वेज मार्ग का खुलना भारत के इस उद्योग के लिए अन्तिम आघात था। इन कारणों से भारत का गौरवशाली उद्योग अतीत के गर्भ में विलीन हो गया। इस सम्बन्ध में **डॉ. बुकानन** ने अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किए हैं— "भारत के लिए सूती वस्त्र अतीत का गौरव, भूत और वर्तमान का संकट और सदैव की आशा रहा है।"

आधुनिक ढंग का कारखाना पहले 1818 में कोलकाता में खोला गया, किन्तु यह प्रयास असफल रहा। सन् 1851 में मुम्बई में भी एक मिल खोली गयी। सन् 1854 में पहली भारतीय मिल कवासजी डाबर द्वारा स्थापित की गई। इसमें उत्पादन 1856 में आरम्भ हुआ। इसके पश्चात् 1861 तक 12 और मिलें खुल चुकी थीं। 1861-65 की अवधि में अमेरिकन गृह-युद्ध के कारण भारत में जब रूई का निर्यात इंग्लैण्ड को होने लगा तो इस व्यापार में काफी लाभ हुआ। इस लाभ से अनेक नई मिलें खोली गईं। सन् 1900 में 193 मिलें खुल चुकी थीं, जिनमें 1.5 लाख श्रमिक काम करते थे सन् 1905 के स्वदेशी आन्दोलन एवं दो महायुद्धों से इस उद्योग को विशेष प्रोत्साहन मिला। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व 379 मिलें थीं, जिनमें 1 करोड़ तकुए तथा 2 लाख करघे लगे थे तथा जिनके उत्पादन से देश की माँग का लगभग 64 प्रतिशत पूरा होता था शेष 27 प्रतिशत हाथकरघों से और 9 प्रतिशत आयात द्वारा होता था। द्वितीय महायुद्ध काल में विदेशों से कपड़े का आयात कम हो जाने से उद्योग को फिर बड़ा प्रोत्साहन मिला। 1945 में 417 मिलें थीं जिनमें 1.02 करोड़ तकुए तथा 2 लाख करघे थे। इनमें लगभग 3 लाख श्रमिक कार्य कर रहे थे। इनका उत्पादन 168 करोड़ पौण्ड सूत और 487 करोड़ गज कपड़े का था।

सन् 1947 में विभाजन के फलस्वरूप देश के 15 कारखाने और रूई उत्पादक 73 प्रतिशत क्षेत्र पाकिस्तान को चले जाने के फलस्वरूप 402 मिलें भारत में रह गयीं तथा कपास की कमी होने से कपड़े का उत्पादन भी केवल 419 करोड़ गज ही रहा गया। इसी कमी को पूरा करने के लिए योजना में निश्चित लक्ष्य निर्धारित किए गए। सन् 1951 में 453 मिलें थीं जिनमें 11 लाख तकुए और 2 लाख करघे लगे थे तथा 7.5 लाख के लगभग श्रमिक कार्य कर रहे थे। नियोजन के पिछले 70 वर्षों में मिलों की संख्या, तकुओं की संख्या तथा करघों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई। संगठित वस्त्र क्षेत्र में छोटे पैमाने के उद्योग और गैर छोटे पैमाने के उद्योग दोनों में 3,400 से अधिक वस्त्र मिलें हैं। तकलों की कुल स्थापित क्षमता 50 मिलियन से अधिक तकलों और 8,42,000 रोटर के साथ विश्व में दूसरे स्थान पर है। मिल क्षेत्र में 2500 मिलियन किग्रा. मानव निर्मित फाइबर और मानव निर्मित फिलामेंट यार्न के अतिरिक्त लगभग 2500 मिलियन वर्ग मीटर कपड़े का उत्पादन किया जाता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का महत्त्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि औद्योगिक उत्पादन, रोजगार के अवसर पैदा करने और विदेशी मुद्रा अर्जित करने में यह क्षेत्र महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वर्तमान में कुल औद्योगिक उत्पादन में इसका योगदान 12.75 प्रतिशत, सकल घरेलू उत्पाद में 2.2 प्रतिशत, और निर्यात आय में 15 प्रतिशत है। यह 10.5 करोड़ व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। कपड़ा उद्योग देश में कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है।

1 जनवरी, 2005 को कोटा-व्यवस्था के समाप्त होने और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू०टी०ओ०) में वस्त्र उद्योग के पूरी तरह समेकित किए जाने के बाद भारतीय वस्त्र उद्योग दोराहे पर खड़ा है। पिछले कुछ वर्षों से, वस्त्र सम्बन्धी कानूनों, विनियमों और निरीक्षण प्रणाली को सुधारकर, सूती वस्त्र उद्योग में वैकल्पिक सेनवेट व्यवस्था शुरू करके, मानव-निर्मित रेशों पर शुल्कों का यौक्तिकीकरण करके, बुने हुए वस्त्र के क्षेत्र में लघु उद्योग आरक्षण हटाकर और बुनाई क्षेत्र में लघु एककों के लिए निवेश सीमाएँ बढ़ाकर इस चुनौती और अवसर का सामना करने के लिए तैयारियाँ की जा रही हैं, लेकिन वस्त्र उद्योग के कार्य-निष्पादन में सुधार होने के प्रमाण अभी तक काफी नहीं हैं।

प्र.6. सूती वस्त्र उद्योग का स्थानीकरण किस पर निर्भर करता है? समझाइए।

On what does the localization of cotton textile industry depend? Explain.

उत्तर सूती वस्त्र उद्योग का स्थानीकरण विशेषत: कच्चे माल, रसायन, यन्त्र, मजदूर और कपड़े की माँग पर निर्भर है। इन कारणों में से किसी एक की प्रचुरता इस उद्योग के लिए पर्याप्त है। स्थापना की दृष्टि से रूई को शुद्ध रेशा माना जाता है, क्योंकि निर्माण क्रिया में रूई के भार में अधिक अन्तर नहीं पड़ता। अत: यह आवश्यक नहीं है कि सूती कपड़े की मिल कपास पैदा करने वाले क्षेत्रों में ही स्थापित किए जाएँ। यह उद्योग बाजार की समीपता से पूरी तरह प्रभावित रहा है न कि कच्चे माल की निकटता से। यह उद्योग अधिकतर वहीं स्थापित किया गया है जहाँ श्रमिकों अथवा विस्तृत बाजार की सुविधा है। अत: इस उद्योग के महत्त्वपूर्ण क्षेत्र गुजरात, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु राज्य हैं जहाँ देश के लगभग 53 प्रतिशत करघे और तकुए पाये जाते हैं। गुजरात व महाराष्ट्र की मुम्बई और अहमदाबाद की मिलों से समस्त देश के उत्पादन का प्राय: आधा सूत और वस्त्र मिलते हैं।

इस उद्योग के प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं—
(i) महाराष्ट्र और गुजरात, (ii) मालवा का पठार (मध्य प्रदेश), (iii) मुम्बई-दक्कन (भीमा और हजारी नदियों के मध्यमवर्ती भाग में), (iv) मध्य दक्षिणी तमिलनाडु, (v) पंजाब और हरियाणा (सतलज नदी के निकटवर्ती भागों में), (vi) गंगा की ऊपरी घाटी (दिल्ली से कानपुर तक का क्षेत्र), (vii) पश्चिम बंगाल (हुगली के निकटवर्ती क्षेत्र में)।
महाराष्ट्र और गुजरात राज्य सूती कपड़े के उद्योग में अग्रणी हैं। इसके निम्नांकित कारण हैं—

1. रूई पैदा करने वाला महत्त्वपूर्ण प्रदेश मुम्बई बन्दरगाह का पृष्ठदेश है। इसीलिए अधिकांश उत्पादक निर्यात के लिए मुम्बई व कांधला पर निर्भर हैं। अत: मुम्बई की मिलों के लिए स्वदेशी व लम्बे रेशे वाली रूई मिस्र व संयुक्त राज्य अमेरिका से मंगाने की भी सुविधा है।
2. मुम्बई यूरोप का सबसे निकट का बन्दरगाह है। अत: उत्कृष्ट मशीनें व अन्य सामान इंग्लैण्ड, जर्मनी, अमेरिका आदि देशों से मँगवाने की सुविधा प्राप्त है।
3. मुम्बई की आर्द्र जलवायु में धागा लम्बा व महीन बुना जा सकता है।
4. मुम्बई की मिलों को अब पश्चिमी घाट पर स्थित टाटा जल-विद्युत योजना से सस्ती विद्युत शक्ति प्राप्त हो जाती है।
5. मुम्बई व अहमदाबाद देश के प्रधान व्यापारिक केन्द्र हैं, इसलिए अपने पृष्ठ देश द्वारा रेलों एवं राजमार्गों से जुड़े हैं। अत: तैयार माल भीतरी भागों को सुविधापूर्वक भेजा जा सकता है।
6. मुम्बई, महाराष्ट्र, गुजरात एवं अहमदाबाद में पूँजीपतियों का जमाव सबसे अधिक है। अत: पूँजी पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है।
7. मुम्बई व अहमदाबाद में श्रमिक कोंकण, सतारा, शोलापुर और रत्नागिरि जिलों तथा दक्षिण के पठार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से आते हैं।
8. स्वयं मुम्बई के पारसी व भाटिया एवं अन्यों के हाथ में विदेशी व्यापार हैं। अत: इस उद्योग को भी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध हो सका है।
9. मुम्बई के उद्यमियों को पूर्वारम्भ का भी पूरा-पूरा लाभ मिला।

अत: आरम्भ से ही मुम्बई व अहमदाबाद सूती वस्त्रों के प्रमुख केन्द्र बन गए। मिलों की अधिकता तथा उत्पादन की विभिन्नता के कारण इसे सूती कपड़ों की राजधानी (Cottonopolis) कहा जाने लगा है। समस्त महाराष्ट्र में लगभग 181 मिलें हैं जिनमें से 138 कताई और 43 मिश्रित मिलें हैं।
महाराष्ट्र में मुम्बई के अतिरिक्त बरसी, अकोला, अमरावती, वर्धा, शोलापुर, पुणे, ठाणे, हुब्बाली, सतारा, कोल्हापुर, जलगाँव, सांगली, बिलीमोरिया, नागपुर, आमलनेर आदि नगरों में सूती कपड़े की मिलें हैं। महाराष्ट्र की मिलों में भीतरी क्षेत्रों की मिलों से स्पर्द्धा होने के कारण अब उत्तम श्रेणी का कपड़ा अधिक बनने लगा है। यहाँ की मिलों में लट्ठा, पोपलीन, मलमल, वायल, साड़ी, धोती, छींट, चद्दर, सफेद व रंगीन कपड़े बनाए जाते हैं।
गुजरात में 87 मिलें हैं जिसमें से आधे से अधिक मिलें अकेले अहमदाबाद में हैं। सबसे पहले अहमदाबाद में सन् 1859 में कपड़े की मिलें स्थापित की गईं।
यहाँ इस उद्योग के लिए निम्न सुविधाएँ प्राप्त थीं—

1. यहाँ साहसी व्यापारियों और सेठों की कमी नहीं है जिससे उद्योग के लिए पर्याप्त पूँजी मिल जाती है।
2. यह सौराष्ट्र और गुजरात के कपास उत्पादन केन्द्रों के मध्य में स्थित है।
3. सौराष्ट्र तथा गुजरात के बन्दरगाहों द्वारा विदेशों से मशीनें, आदि सुगमतापूर्वक मँगाई जा सकती हैं।
4. यहाँ बहुत प्राचीन काल से घरेलू धन्धे के रूप में कताई और बुनाई का उद्योग होता रहा है। अत: मिलों के लिए चतुर मजदूर मिलने की सुविधा है।
5. तैयार कपड़ा पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और सौराष्ट्र में आसानी से भेजा जा सकता है। यहाँ के कपड़े की माँग दिल्ली, कानपुर और अमृतसर तक है। इन कारणों से अहमदाबाद भारत में सूती कपड़े बनाने में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे **पूर्व का मानचेस्टर या बोस्टन** कहते हैं।

अहमदाबाद में उत्तम और महीन कपड़ा अधिक बनाया जाता है। धोतियाँ, शर्टिंग, सूटिंग, मलमल, वायल आदि कपड़े की किस्म के अनुसार अहमदाबाद में लंकाशायर की मिलों की तरह 'मिस्री कपड़े' और मुम्बई में 'अमेरिकी कपड़े' अधिक बनाए जाते हैं।
कालान्तर में अहमदाबाद के अतिरिक्त नए मिल राजकोट, मोरवी, वीरमगाँव, कलोल, नवसारी, भावनगर, अंजार, सिद्धापुर, नाडियाड, सूरत, भडौंच और वड़ोदरा में स्थापित किए गए।

TOUCH 'n PASS

प्र.7. बेबर के औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत एवं उद्योग की अवस्थिति पर श्रम तथा एकत्रीकरण के प्रभाव का वर्णन कीजिए।

Describe the industrial location theory of Weber and impact of industrial location on Labour and Colloboration.

उत्तर

वेबर का औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत
(Industrial Location Theory of Weber)

किसी उद्योग या कारखाने को स्थापित करने के लिए स्थान के चुनाव की समस्या सर्वप्रमुख होती है कोई भी पूँजीपति या उद्योगपति अपना उद्योग वहीं स्थापित करना चाहते हैं जहाँ पर सारी सुविधायें प्राप्त हो; जैसे– उपयुक्त भूमि परिवहन की सुविधा, माल को (कच्चे माल) एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में न्यूनतम लागत लगे इस प्रकार सर्वोत्तम स्थिति वह है जिसमें उद्योगों से लाभ प्राप्त हो। इन्हीं समस्याओं के निवारण के लिए अल्फ्रेड बेबर का सिद्धांत सर्वप्रमुख है।

अल्फ्रेड बेबर एक जर्मन अर्थशास्त्री थे जिन्होंने उद्योगों की उपस्थिति का सिद्धांत प्रतिपादित किया। जिसका प्रकाशन 1909 में जर्मन भाषा में लिखित पुस्तक अबर स्टान्डोर्ट डर इण्डस्ट्रियल में प्रकाशित हुआ।

सिद्धांत की मान्यताएँ—वेबर ने अपने उद्योगों की उपस्थिति के सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए कुछ मान्यताओं का सहारा लिया जो निम्नलिखित हैं—

1. कारखाना (उद्योग) की स्थापना के लिए प्रस्तावित क्षेत्र या प्रदेश एक ही प्रशासन के अधीन विलग इकाई है जहाँ पाई जाने वाली जलवायु, संस्कृति प्रौद्योगिकी आदि भौगोलिक दशाओं में समानता पायी जाती है।
2. उद्योग की अवस्थिति का विश्लेषण एक ही उत्पादन वस्तु के संदर्भ में किया गया है लगभग समान प्रकार की किंत भिन्न कणों वाली वस्तुओं को भिन्न वस्तुयें ही माना जायेगा।
3. कच्ची सामग्री के विषय में पूर्ण जानकारी उपलब्ध है।
4. उस भोग स्थानों के विषय में पूर्ण जानकारी है और ऐसे स्थान या बाजार एक दूसरे से अलग बिन्दु के रूप में स्थित है।
5. अर्थव्यवस्था स्वतंत्र बाजार पर आधारित है और बाजार में वस्तुओं की आपूर्ति हेतु पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति विद्यमान है।
6. श्रम सर्वत्र नहीं बल्कि कुछ निश्चित प्रदेशों में उपलब्ध है। ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पूर्व निर्धारित मजदूरी पर तथा आवश्यक संख्या में श्रमिक उपलब्ध है।
7. कच्चे माल पर निर्मित माल के रूप में वस्तु का परिवहन व्यय केवल भार और मजदूरी के अनुपात में बढ़ता है।

सिद्धांत की व्याख्या—वेबार के अनुसार सर्व प्रयत्न न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु का निर्धारण किया जाता है और श्रम तथा एकत्रीकरण से लाभ के प्रभाव पर विचार किया इस सिद्धांत का विश्लेषण दो दशाओं में किया गया।

कच्ची सामग्री का स्रोत और एक बाजार बिन्दु की दशा।

दो या अधिक कच्ची सामग्री स्रोत और एक बाजार बिन्दु की दशा।

प्रथम दशा में उद्योग में एक ही कच्ची सामग्री का प्रयोग होता है जो एक स्रोत से दूसरे स्थान पर जाती है इस स्थिति में उद्योग की स्थापना की निम्नलिखित सम्भावनायें हैं—

1. यदि उद्योग में कच्ची सामग्री का उपयोग होता है तो उद्योग तो कहीं भी स्थापित करने पर (कच्ची सामग्री) के परिवहन में कोई खर्च नहीं होता।
2. यदि कच्ची सामग्री स्थानीय है तो उद्योग को कच्ची सामग्री के स्रोत अथवा बाजार बिंदु के मध्य उद्योग स्थापित कर दिये जाते हैं क्योंकि लागत अधिकतर समान ही रहती है।
3. यदि उद्योग में कच्ची सामग्री के स्थान पर मिश्रित पदार्थ का उपयोग होता है तब उद्योग की स्थापना कच्ची सामग्री के स्रोत पर होगी इस पर परिवहन व्यय बहुत ही कम पड़ेगा।

द्वितीय दशा में—इसमें दो भिन्न प्रकार की कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। कारखानों की स्थापना निम्न आधार पर की जाती है—

1. यदि उद्योग में उपयोग में लायी जाने वाली कच्ची सामग्रीयाँ दो भिन्न-भिन्न प्रकार की हैं तो उद्योगों को बाजार बिन्दु पर स्थापित किया जाना अच्छा होगा।

TOUCH 'n' PASS

2. यदि दोनों कच्ची सामग्रीयाँ शुद्ध पदार्थ है तो कारखानों को बाजार केन्द्र पर स्थापित करना लाभप्रद होगा। इस स्थिति में दोनों कच्ची सामग्रियों का बाजार केन्द्र पर स्थापित कारखाने तक लाया जायेगा।
3. यदि उद्योग में सर्व सुलभ पदार्थ और शुद्ध सामग्री का उपयोग होता है। तब उद्योग की स्थापना बाजार केन्द्र पर ही होगी। इस परिस्थिति में उद्योग की स्थापना व परिवहन लागत न्यूनतम होगी।
4. जहाँ उद्योग स्थापित होते हैं वहाँ उपस्थिति का निर्धारण तब कठिन हो जाता है जब कच्ची सामग्रियाँ मिश्रित होती हैं। इस अवस्था को बेबर ने इस प्रकार प्रदर्शित किया है।

उदाहरण—कारखाने में दो मिश्रित पदार्थों का उपयोग कच्चे माल के रूप में होता है जो A व B बिंदु से प्राप्त होते हैं उत्पादित वस्तु C को माना है इस रचित में उद्योग तीनों में से कहीं भी स्थापित नहीं हो सकता क्योंकि A से B व B से C तथा C से पुन: A पर लाने में परिवहन लागत व्यय अधिक होगा इसलिये इन तीनों में से कहीं भी उद्योग स्थापित नहीं होगा उद्योग इन तीन स्थितियों के बीच में से स्थापित होगा जिसे P का नाम दिया गया है।

उद्योग की अवस्थिति पर श्रम तथा एकत्रीकरण का प्रभाव

1. **श्रम का प्रभाव** (Impact of labour)—**वेबर** के अनुसार, श्रम कुछ विशेष स्थानों पर ही होता है वह भी अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग होता है। श्रम को कम करने के उद्देश्य से उद्घोष वहीं स्थापित किये जाते हैं। जो परिवहन की वृद्धि से उत्तम है परिवहन व्यय की वृद्धि से सर्वोत्तम बिन्दु से हटने पर जिन-जिन बिंदुओं पर परिवहन व्यय में समान इकाई वृद्धि होती है उनको मिलाने वाली रेखा को आइसोडोवन कहते हैं।

एकत्रीकरण का प्रभाव—वेबर ने एकत्रीकरण को तीन भागों में बाँटा हैं—

1. उद्योग के विस्तार द्वारा
2. एक स्थान पर एक ही उद्योग के कई कारखानों के स्थापित होने से
3. एक स्थान पर विभिन्न प्रकार के उद्योगों के स्थापित होने से उद्योग यदि एक ही स्थान पर (एक से अधिक उद्योग) स्थापित होते हैं वह भी बड़े स्तर पर, इस प्रकार स्थापित होने से कई सुविधायें मिल जाती हैं; जैसे— तकनीकी सुविधा, निर्मित वस्तु के विक्रय सम्बन्धी सुविधा आदि बढ़ जाती हैं एक ही स्थान पर कई प्रकार के उद्योगों के स्थापित होने से परिवहन के साधन आदि उपलब्ध हो जाते हैं।

निष्कर्ष—उद्योग की उपस्थिति सिद्धान्त की व्याख्या के पश्चात् वेबर ने निम्न निष्कर्ष निकाला।

1. कच्चे माल के स्रोत पर उद्योग की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती बल्कि वह बाजार अन्य स्थानों पर भी हो सकता है।
2. उद्योग की अवस्थिति पर परिवहन हृदय के सामान्य स्तर पर नहीं बल्कि विभिन्न स्थानों के सापेक्षिक परिवहन व्यय का प्रभाव पड़ता है।
3. उद्योग मिश्रित पदार्थ वाली कच्ची सामग्री की ओर आकर्षित होता है।
4. स्थानीकरण त्रिभुज के भीतर उद्योग उस कच्ची सामग्री के स्रोत पर या उसके समीप स्थापित होगा जिसका सापेक्षिक भार अधिक होता है।
5. अधिक पदार्थ कच्ची सामग्री के स्रोत की ओर तथा कम पदार्थ बाजार केन्द्र की ओर आकर्षित होते हैं।

वेबर के सिद्धांत की आलोचनायें—वेबर की आलोचनायें निम्न हैं—

1. वेबर ने उद्योग की स्थापना का विश्लेषण कच्ची सामग्री के स्रोत तथा बाजार केन्द्र को विरचित बिन्दु मानकर किया है। कच्ची सामग्रियों की आपूर्ति विस्तृत क्षेत्र में होती है और उत्पादित वस्तु की माँग भी विस्तृत क्षेत्र में होती है।
2. वेबर के सिद्धांत में अधिकतर परिवहन लागत पर ही ध्यान दिया गया और उत्पादन प्रक्रिया में लगी हुई लागत पर ध्यान नहीं दिया गया।
3. परिवहन व्यय को दूरी तथा भार का आनुपातिक माना है। अत: अधिक दूरी के लिए परिवहन दर लघु दूरी के परिवहन दर की तुलना में कम होती है।
4. श्रम की आपूर्ति निश्चित मजदूरी पर प्राय: नहीं होती वेबर ने मजदूरी पर श्रम की असीमित आपूर्ति की कल्पना की है। बल्कि श्रमिक किसी विरचित क्षेत्र पर ही नहीं मिलते बल्कि एक स्थान से दूसरे पर प्रयास करते हैं।

इस प्रकार वेबर की कई आलोचनायें हैं।

TOUCH 'n PASS

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्र.1. भारत में प्रसिद्ध व्यवसायी जमशेदजी टाटा द्वारा टाटा लोहा-इस्पात कम्पनी (TISCO) की स्थापना कब और कहाँ की गयी?

(क) 1908, पश्चिम बंगाल (ख) 1907, झारखंड
(ग) 1911, उड़ीसा (घ) 1905, पश्चिम बंगाल

उत्तर (ख) 1907, झारखंड

प्र.2. किस कारखाने का नाम बदलकर विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात लिमिटेड कर दिया गया?

(क) मैसूर आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड कम्पनी (VISL)
(ख) हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड (HSL)
(ग) टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी (TISCO)
(घ) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर (क) मैसूर आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड कम्पनी (VISL)

प्र.3. लोहा तथा इस्पात कारखाना सर्वप्रथम कहाँ लगाया गया?

(क) पश्चिम बंगाल (ख) उत्तर प्रदेश (ग) गुजरात (घ) उड़ीसा

उत्तर (क) पश्चिम बंगाल

प्र.4. टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी कहाँ पर स्थित है?

(क) भिलाई (ख) हजारीबाग (ग) जमशेदपुर (घ) कोलकाता

उत्तर (ग) जमशेदपुर

प्र.5. देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र कम्पनी NALCO, इसकी तीन इकाईयाँ अलग-अलग राज्यों में शामिल है, निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य इसमें सही नहीं है?

(क) मध्य प्रदेश (ख) आंध्र प्रदेश (ग) उड़ीसा (घ) बिहार

उत्तर (घ) बिहार

प्र.6. निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है–

(क) राउरकेला इस्पात संयंत्र—उड़ीसा (ख) भिलाई लौह-इस्पात संयंत्र—छत्तीसगढ़
(ग) बोकारो लौह-इस्पात कारखाना—तमिलनाडु (घ) विजयनगर इस्पात उद्योग—कर्नाटक

उत्तर (ग) बोकारो लौह-इस्पात कारखाना—तमिलनाडु

प्र.7. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (I.F.C.I.) की स्थापना कब की गई?

(क) 1948 ई० (ख) 1956 ई० (ग) 1980 ई० (घ) 1974 ई०

उत्तर (क) 1948 ई०

प्र.8. नीचे कुछ इस्पात संयंत्रों के नाम व उनकी स्थापना में सहयोगी देशों के नाम दिये गये हैं, इनमें कौन-सा सही सुमेलित नहीं है?

(क) राउरकेला इस्पात संयंत्र—जर्मनी (ख) भिलाई इस्पात संयंत्र—रूस
(ग) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र—ब्रिटेन (घ) बोकारो इस्पात संयंत्र—अमेरिका

उत्तर (घ) बोकारो इस्पात संयंत्र—अमेरिका

प्र.9. भारत में सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ शुरू हुआ?

(क) मुम्बई (ख) कानपुर (ग) पटियाला (घ) मुम्बई

उत्तर (क) मुम्बई

प्र.10. भारत में सर्वप्रथम सूती वस्त्र मिल कब लगाई गयी?

(क) सन् 1954 में (ख) सन् 1932 में (ग) सन् 1854 में (घ) सन् 1836 में

उत्तर (ग) सन् 1854 में

TOUCH 'n' PASS

प्र.11. नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई?
(क) सन् 1989 में (ख) सन् 1991 में (ग) सन् 2000 में (घ) सन् 1995 में
उत्तर (ख) सन् 1991 में

प्र.12. देश की कौन-सी पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य देश के औद्योगिक विकास पर था?
(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना (ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना
(ग) (क) और (ख) दोनों (घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना
उत्तर (ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना

प्र.13. भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 ई० में कहाँ स्थापित किया गया था?
(क) चेन्नई (ख) रानीपेट (ग) झींकपानी (घ) पोर्टीनोवा
उत्तर (क) चेन्नई

प्र.14. जार्ज आकलैंड ने सर्वप्रथम भारत में 1855 ई० में किस स्थान पर जूट मिल की स्थापना की थी?
(क) टीटागढ़ (ख) बजबज (ग) रिसरा (घ) शिवपुर
उत्तर (ग) रिसरा

प्र.15. 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना (जो असफल रही) किस क्षेत्र में स्थापित की गई थी?
(क) पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में (ख) महाराष्ट्र के मुम्बई में
(ग) गुजरात के अहमदाबाद में (घ) उत्तर प्रदेश के कानपुर में
उत्तर (क) पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में

प्र.16. भारत में चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान है–
(क) महाराष्ट्र (ख) उत्तर प्रदेश (ग) तमिलनाडु (घ) हरियाणा
उत्तर (ख) उत्तर प्रदेश

प्र.17. निम्नलिखित राज्य समूहों में वह कौन-सा है, जहाँ यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है?
(क) पंजाब और तमिलनाडु (ख) उड़ीसा और पश्चिम बंगाल
(ग) तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल (घ) पश्चिम बंगाल और पंजाब
उत्तर (क) पंजाब और तमिलनाडु

प्र.18. सबसे बड़ा तेलशोधक कारखाना पाया जाता है–
(क) पोरबंदर (ख) जामनगर (ग) अहमदाबाद (घ) सूरत
उत्तर (ख) जामनगर

प्र.19. उत्तर प्रदेश में तेलशोधन कारखाना स्थित है–
(क) मुरादाबाद में (ख) मिर्जापुर में (ग) कानपुर में (घ) मथुरा में
उत्तर (घ) मथुरा में

प्र.20. पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केन्द्र कहाँ पर स्थित है?
(क) जामनगर (ख) अंकलेश्वर (ग) नूनामाटी (घ) ट्राम्बे
उत्तर (क) जामनगर

प्र.21. हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है?
(क) उदयपुर (ख) जोधपुर (ग) जैसलमेर (घ) जयपुर
उत्तर (क) उदयपुर

प्र.22. पोत निर्माण यार्ड-मझगाँव डाक कहाँ स्थित है?
(क) विशाखापट्टनम (ख) मुम्बई (ग) कोच्चि (घ) कोलकाता
उत्तर (ख) मुम्बई

TOUCH 'n' PASS

प्र.23. पेनिसिलिन के निर्माण का मुख्य केन्द्र निम्नलिखित में से किस शहर में है?
(क) सिंद्री (ख) दिल्ली (ग) पिंपरी (घ) अलवाये
उत्तर (ग) पिंपरी

प्र.24. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स उद्योग निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है?
(क) मुंबई (ख) चेन्नई (ग) हैदराबाद (घ) बेंगलुरु
उत्तर (घ) बेंगलुरु

प्र.25. भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है?
(क) जैसलमेर (ख) नागर कॉयल (ग) कच्छ का रण (घ) माधापुर
उत्तर (घ) माधापुर

प्र.26. मध्यप्रदेश में पीथमपुर को किसके लिए जाना जाता है?
(क) कागज (ख) ऑटोमोबाइल (ग) एल्युमीनियम (घ) जूट
उत्तर (ख) ऑटोमोबाइल

प्र.27. भारत में फरवरी 2023 तक महारत्न और नवरत्न कम्पनियों की संख्या है–
(क) 10 और 12 (ख) 12 और 12 (ग) 10 और 13 (घ) 11 और 10
उत्तर (ख) 12 और 12

प्र.28. बिहार में डालमियानगर किसके लिए प्रसिद्ध है?
(क) रेशम (ख) सीमेंट (ग) चमड़ा (घ) जूट
उत्तर (ख) सीमेंट

प्र.29. कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है?
(क) TISCO—जमशेदपुर (ख) VISL—भद्रावती
(ग) HSL—दुर्गापुर (घ) HSL—भिलाई
उत्तर (ख) VISL—भद्रावती

प्र.30. स्टील ऑथरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) की स्थापना कब हुई थी?
(क) 1960 ई० में (ख) 1964 ई० में
(ग) 1974 ई० में (घ) 1976 ई० में
उत्तर (ग) 1974 ई० में

TOUCH 'n' PASS

UNIT-VI

विश्व परिवहन

World Transportation

खण्ड-अ अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. परिवहन कितने प्रकार का होता है?
What are the types of Transport?

उत्तर परिवहन के तीन मुख्य माध्यम हैं जिन्हें क्रमश: स्थल परिवहन, जल परिवहन तथा वायु परिवहन के नाम से पुकारा जाता है।

प्र.2. बादशाहों में किसे सड़क निर्माता कहा जाता है?
Who among the emperors is called the Road Builder?

उत्तर बादशाहों में मुख्यत: शेरशाह को सड़क निर्माता के नाम से जाना जाता है।

प्र.3. राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को किस परियोजना में शामिल कर दिया गया है?
Which project has been included in the National Highway Development Project?

उत्तर भारतमाला परियोजना को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना में शामिल कर दिया गया है।

प्र.4. सेतु भारतम् कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है।
What is the objective of Setu Bharatam Programme?

उत्तर वर्ष 2016 में सरकार ने एक कार्यक्रम 'सेतु भारतम्' नाम से शुरू किया। जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर लेवल क्रासिंग के स्थान पर पुल के ऊपर सड़क तथा पुल के नीचे सड़क का निर्माण करना है।

प्र.5. वर्तमान में भारत में रेलवे स्टेशनों की कितनी संख्या है?
At present what is the number of Railway Stations in India?

उत्तर वर्तमान में भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या 7,321 है।

प्र.6. देश के आर्थिक जीवन में परिवहन के साधनों के महत्त्व को संक्षेप में बताइए।
Briefly explain the importance of means of transport in the economic life of the country.

उत्तर किसी देश के आर्थिक जीवन में परिवहन के साधनों का बड़ा महत्त्व होता है। यदि कृषि खनन और उद्योग-धन्धे किसी देश के आर्थिक जीवन का शरीर और हड्डियाँ मानी जाएँ तो परिवहन को उस आर्थिक ढाँचे की स्नायु-प्रणाली माना जा सकता है। देश की औद्योगिक उन्नति, व्यापार और कृषि सभी के विकास का आधार परिवहन के साधनों के विकास से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के एक बड़े भाग का सुचारू संचालन परिवहन एवं संचार के साधनों पर ही निर्भर करता है। वस्तुओं और जीव-जन्तु, मानव एवं विचार व दर्शन के प्रसार का यही मुख्य साधन है। देश में परिवहन के विभिन्न साधनों में सड़कों, रेलों, आन्तरिक जल मार्गों और वायुयान मार्गों का महत्त्व बहुत अधिक है।

प्र.7. स्थल परिवहन के अंतर्गत किन साधनों को सम्मिलित किया गया?
Which means have been included in land transport?

उत्तर स्थल परिवहन के अन्तर्गत स्थल मार्गों का उपयोग करने वाले सभी साधन सम्मिलित किए जाते हैं, यथा— (i) सड़कें, (ii) पाइप लाइनें या नल परिवहन, (iii) रेल-मार्ग या रेल परिवहन।

TOUCH 'n PASS

प्र.8. सड़क परिवहन की समस्याओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
Briefly describe the problems of Road Transport?

उत्तर भारत जैसे विशाल देश में अभी भी सड़कों का विकास देश की विशालता एवं प्रकृति को देखते हुए आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हुआ है। सड़कों के तीव्र गति से विकास में निम्न कारण बाधक रहे हैं—

1. भारत की अधिकांश सड़कें न केवल कच्ची हैं वरन् उनके 50 प्रतिशत भाग पर पूरे वर्ष मोटरें नहीं चलायी जा सकतीं। वर्षा में मण्डियों और अनेक गाँवों के बीच सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है।
2. सड़क परिवहन पर कर दर ऊँची है।
3. सड़कों पर चलने वाली मोटरगाड़ियों की हालत असन्तोषजनक है। उनकी भार या यात्री ढोने की कुशलता भी कम है।
4. सड़क परिवहन सम्बन्धी नियमन सभी राज्यों में सरल और एकरूप नहीं हैं।

प्र.9. परिवहन विकास परिषद् ने सड़क विकास में क्या सुझाव दिए हैं?
What suggestions have been given by the Transport Development Council in Road Development?

उत्तर 1965 में स्थापित परिवहन विकास परिषद् ने सड़क विकास के लिए निम्न सुझाव दिये हैं—

1. भारतीय सड़क परिवहन को प्राथमिक श्रेणी का व्यवसाय माना जाना चाहिए।
2. सड़क परिवहन की नयी कम्पनियों को आयकर से 'विकास छूट' दी जानी चाहिए।
3. सड़क परिवहन विकास से सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
4. सड़कों का सुधार किया जाना चाहिए।
5. सड़क परिवहन से सम्बन्धित क्षेत्रों में बहुमुखी करों में कमी की जानी चाहिए।

प्र.10. मेट्रो रेलवे-कोलकाता का परिचालन कब किया गया?
When was Metro Railway-Kolkata become operational?

उत्तर **मेट्रो रेलवे-कोलकाता**—यह रेलवे दमदम से टोलीगंज के भूमिगत 16.45 किसी लम्बे रेलमार्ग पर परिचालित होती है। 1972 में इसे आंशिक रूप से परिचालित किया गया, किन्तु 27 सितम्बर, 1995 से पूरे रेलमार्ग पर इसका परिचालन प्रारम्भ कर दिया गया है। इसके उपरांत इसे परियाघाट तक बढ़ा दिया गया।

खण्ड-ब लघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का विस्तृत रूप से विवरण दीजिए।
Give a detailed account of National Highway Development Project.

उत्तर

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एन०एच०डी०पी०)
(National Hishway Development Project)

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना देश में प्रमुख राजमार्गों के उच्च स्तर के उन्नयन, पुनर्निर्माण और उन्हें चौड़ा करने की परियोजना है। यह परियोजना 1998 में शुरू की गई थी। इस परियोजना का प्रबंधन सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। यह देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, 49260 किलोमीटर सड़कों और राजमार्गों के निर्माण का कार्य करता है।

एन०एच०डी०पी० को मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और राष्ट्रीय राजमार्ग संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा सात चरणों में कार्यान्वित किया जा रहा था। इस पर ₹ 6,00,000 करोड़ की लागत आने का अनुमान है। इस कार्यक्रम के तहत निर्मित कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों में चार महानगरों—दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज (लम्बाई 5846 किमी.), पूर्वोत्तर दक्षिण और पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर है, जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से और सिल्चर को पोरबंदर से जोड़ता है। जिसकी कुल लम्बाई 7142 किमी. है। यह सलेम से कोच्चि तक प्रमुख पत्तनों को देश के राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को भारतमाला परियोजना में शामिल कर दिया गया है।

TOUCH 'n' PASS

भारतमाला परियोजना—भारतमाला परियोजना या उद्देश्य सागरमाला के समाकलेन से सीमावर्ती क्षेत्रों को सड़क सम्पर्क से जोड़ना, छोटे पत्तनों के लिए सड़क सम्पर्कसहित तटवर्ती सड़कों का विकास करना राष्ट्रीय गलियारे की क्षमता में सुधार करना, आर्थिक गलियारे के विकास, अंतर-गलियारों और फीडरमार्गों के विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार करना है। इसके अतिरिक्त अत्यधिक ट्रैफिक पथों के रूकावटों को दूर करना तथा रिंग सड़कों (Ring Roads) का निर्माण करना भी इस परियोजना में शामिल है।

सेतु भारतम्—वर्ष 2016 में सरकार ने एक अलग कार्यक्रम 'सेतु भारतम्' नाम से शुरू किया है। जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर लेवल क्रासिंग के स्थान पर पुल के ऊपर सड़क (आर०ओ०बी)। पुल के नीचे सड़क (आर०यू०बी०) का निर्माण करना है।

चार धाम महामार्ग विकास परियोजना—यह योजना उत्तराखण्ड में स्थित चार प्रसिद्ध धाम-गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ व बद्रीनाथ की यात्रा को सुगम बनाने के लिए इनके सम्पर्क मार्गों के विकास के सम्बन्ध में है। इस परियोजना के तहत समाकृति की दो लेन वाली 889 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाना है।

प्र.2. भारत में रेलों के विकास पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालिए।

Give a detailed account of the Development of Railways in India.

उत्तर

भारत में रेलों का विकास
(Development of Railways in India)

भारत में रेलमार्गों का विकास 19वीं शताब्दी के मध्य से हुआ है। सर्वप्रथम 1845 में लॉर्ड डलहौजी के राज्यकाल में तीन रेलमार्गों को स्वीकृति दी गई। पहला रेलमार्ग **ईस्ट इण्डियन रेलवे** था जो कलकत्ता से रानीगंज तक 183 किलोमीटर लम्बा था यह 1854 में ही बनाया गया। दूसरा रेलमार्ग 1853 में **ग्रेट इण्डियन पेनिनसुला रेलवे** द्वारा बम्बई से थाणे के बीच 34 किलोमीटर लम्बा मार्ग बनाया गया एवं सन् 1854 में कलकत्ता और पंडुआ के बीच 63 किलोमीटर लम्बा रेलमार्ग बनाया गया। 1856 में मद्रास से अरकोनम के बीच 70 किलोमीटर लम्बा रेलमार्ग बनाया गया। 1870 में भारत में रेलमार्गों की लम्बाई 6,840 किलोमीटर थी। 1871 तक कोलकाता (कलकत्ता), मुम्बई (बम्बई) और चेन्नई (मद्रास) एक-दूसरे से जोड़े जा चुके थे। ये अमृतसर और कालीकट से भी एक शाखा द्वारा जोड़ दिए गए थे। 2019-20 तक रेलयात्रा का दायरा 67.6 हजार किमी तक पहुँच चुका है।

ईस्ट इण्डियन रेलवे द्वारा गंगा की उपजाऊ घाटी तथा ग्रेट इण्डियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा दक्कन के पठार के कपास उत्पादक क्षेत्रों को लाभ पहुँचाया गया। ये दोनों रेलमार्ग इलाहाबाद में मिलते थे। मद्रास में दक्षिण मराठा रेलवे व जी०पी० रेलवे रायचूर पर मिलती थी तथा यहाँ से शाखाओं द्वारा बेंगलुरू और कालीकट से। मुम्बई से एक रेलमार्ग अहमदाबाद, लाहौर और दिल्ली के बीच बनाया गया। इसके उपरान्त 1872-79 में आर्थिक कारणों से मीटर गेज या छोटी लाइनों के निर्माण पर ध्यान दिया गया। चेन्नई में तूतीकोरिन, अहमदाबाद से आगरा और दिल्ली तथा दिल्ली और वाराणसी के बीच छोटी लाइनें डाली गयीं। बाद में पहाड़ी भागों तथा उजाड़ क्षेत्रों में कम दूरी की संकरी लाइनें बनायी गयी। 1906 तक कोलकाता और चेन्नई तथा कोलकाता, नागपुर और बम्बई के बीच बड़ी लाइन बन चुकी थी, किन्तु सबसे अधिक विकास छोटी लाइनों का किया गया— अहमदाबाद को दिल्ली, आगरा को कानपुर, ब्रह्मपुत्र की घाटी और डेल्टाई भागों को जोड़ने के लिए बंगाल-असम रेलवे तथा बंगाल और उत्तर-पश्चिमी रेलवे और तिरहुत-रुहेलखण्ड-कुमाऊँ रेलवे का निर्माण भी किया गया।

विभाजन के समय अविभाजित भारत में 66,208 किलोमीटर लम्बे रेलमार्ग थे। विभाजन के उपरान्त भारत को 54,969 किलोमीटर लम्बे रेलमार्ग मिले, तथा 9 में से 7 रेलमार्ग पूरी तरह भारत को मिले। शेष दो में से बंगाल-असम और उत्तरी-पश्चिमी रेलमार्गों और जोधपुर राज्य रेलमार्ग को भारत और पाकिस्तान के बीच बाँटा गया। विभाजन के उपरान्त पश्चिम बंगाल और असम में कई रेलमार्ग बनाने पड़े, क्योंकि इन दोनों का देश के अन्य भागों में सीधा सम्पर्क टूट गया था। असम रेलमार्ग गंगा नदी पर मनिहारीघाट से फकीराग्राम तक 425 किलोमीटर लम्बा बनाया गया। यह बांग्लादेश और नेपाल के बीच 20 किलोमीटर चौड़े भाग में बनाया गया। इसका निर्माण तत्कालीन लाइनों का उपयोग कर 230 किलोमीटर का नया मार्ग बनाकर असम को बिहार और उत्तर प्रदेश से छोटी लाइनों द्वारा जोड़ा गया। मनिहारीघाट से सेकरीगली घाट के बीच असम रेलमार्ग पर अब गंगा पर बड़ा पुल बनाया गया है। बिहार में मोकामाह के निकट गंगा पर एक नया पुल बनाकर वाराणसी तक सीधा रेल सम्पर्क स्थापित किया गया। रानीगंज और कोलकाता के बीच बढ़ते हुए व्यापार की माँग को पूरा करने के लिए चार मार्ग डाले गए तथा कई मार्गों को दुहरा किया गया। अब तो देश के कई भागों में लिंक मार्ग व अन्य मार्ग बनाये गये हैं।

TOUCH 'n' PASS

इस तरह, आज देशभर में रेलों का व्यापक जाल बिछा हुआ है। वर्तमान में रेलवे स्टेशनों की संख्या 7,321 तथा रेलमार्ग की कुल लम्बाई 99.2 हजार किमी है।

प्र.3. विद्युतचालित रेलमार्ग के बारे में विस्तार से लिखिए।
Write in detail about Electrified Railroutes.

उत्तर

विद्युतचालित रेलमार्ग
(Electrified Rail Routes)

भारत में मुम्बई और चेन्नई में उपनगरीय रेलों के विद्युतीकरण पर सबसे पहले 1920 में विचार किया गया, किन्तु प्रथम विश्वयुद्ध के कारण इस पर कार्य 1925 में आरम्भ हुआ। विद्युत की रेल का सबसे पहला सेक्शन विक्टोरिया टर्मिनल्स से कुर्ला तक था। 1928 तक जी०आई०पी० रेलवे ने इस सेवा का विस्तार मुम्बई से लगभग 64 किलोमीटर दूर कल्याण तक कर दिया। 1928 में बी०बी० एण्ड सी०आई० रेलवे ने भी चर्चगेट-बोरीवली सेक्शन में और बाद में बिरार तक की लगभग 68 किलोमीटर की दूरी में विद्युत रेल चलाई। 1931 से चेन्नई और तम्बरम के बीच की लगभग 29 किलोमीटर की दूरी भी विद्युत रेल द्वारा तय की जाने लगी। 1936 से 1952 तक रेलमार्ग को विकास स्थिर सा रहा। अत: विद्युत रेलमार्गों का भी विकास नहीं हो पाया।

मुम्बई में विद्युतचालित उपनगरीय गाड़ियाँ बहुत लोकप्रिय हुईं और उनसे मुम्बई की बाहरी बस्तियों का बहुत विस्तार हुआ है। वहाँ की जनसंख्या 1930 में लगभग 15 लाख थी जो लोक 1951 में 35 लाख हो चुकी थी। 1926-27 में मुम्बई की इन गाड़ियों में 480 लाख लोगों ने यात्रा की थी और 1951-52 में यह संख्या बढ़कर 3,000 लाख हो गयी थी। मुम्बई में आज मध्य और पश्चिमी रेलों की प्रतिदिन लगभग 1000 उपनगरीय गाड़ियाँ चलती हैं, किन्तु यात्रियों की संख्या और भीड़ को देखते हुए वे भी अपर्याप्त हैं। मुम्बई के पूर्व में पश्चिमी घाट की चढ़ाई-उत्तराई में भाप के इंजनों से गाड़ियों ले जाने में बहुत कठिनाई और खर्च अधिक बैठता था, इसलिए मुम्बई से पुणे और मुम्बई से इगतपुरी सेक्शनों में भी 1927 से विद्युत रेलें चलायी जाने लगीं। दिसम्बर 1957 में 22 किलोमीटर लम्बे टुकड़े पर हावड़ा और शिवराफूली के बीच पहली बार विद्युत रेल चलायी गयी।

वर्ष 2019-20 तक भारतीय रेलवे के पास विद्युतचालित 39.9 हजार किमी. मार्ग का नेटवर्क है, जो कुल नेटवर्क का 59.0 प्रतिशत है और 64.50 प्रतिशत माल ढुलाई करता है और 53.70 प्रतिशत कोचिंग ट्रैफिक का वहन करता है।

प्र.4. भारत के एक्सप्रेस राजमार्ग या महामार्ग का विस्तार से वर्णन कीजिए।
Describe in detail the express Highways or Highways of India.

उत्तर

भारत के एक्सप्रेस राजमार्ग या महामार्ग
(Express Highways or Highways of India)

भारत में सर्वप्रथम दिसम्बर 1998 में नई दिल्ली में विशेष सम्मेलन **'एक्सप्रेस राजमार्ग या महामार्गों'** के निर्माण पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किया गया। इसका उद्देश्य देश में उत्तर-दक्षिण एवं पूर्व-पश्चिम में 7,000 किलोमीटर लम्बे एक्सप्रेस मार्गों के निर्माण को अनिवार्य माना गया क्योंकि इन्हीं महामार्गों के द्वारा ही राष्ट्रीय राजमार्गों पर बढ़ते परिवहन के दबावों को रोका जा सकेगा। इसके अन्तर्गत **पहला** प्रधान मार्ग कन्याकुमारी से बेंगलुरू, नागपुर, झांसी, दिल्ली व चण्डीगढ़ होता हुआ जम्मू तक जायेगा। इससे पश्चिमवर्ती राजमार्ग बेंगलुरू से चित्रदुर्ग, बेलगावी पूर्व व मुम्बई होता हुआ अहमदाबाद, उदयपुर व जयपुर होकर दिल्ली में प्रधान मार्ग से मिल जाएगा। इसका दूसरा पूर्ववर्ती मार्ग मदुरै के निकट से प्रारम्भ होकर चेन्नई एवं वहाँ से पूर्वी तट के सहारे होता हुआ कोलकाता तक जाएगा। यह सभी उत्तर-दक्षिण-महामार्ग के ही भाग हैं।

दूसरा पूर्व-पश्चिम महामार्ग कांधला बन्दरगाह से प्रारम्भ होकर उदयपुर-कोटा होता हुआ झांसी-लखनऊ-गोरखपुर होता हुआ रक्सौल होकर वहाँ से गंगटोक व दिसपुर तक पूर्व-पश्चिम का मार्ग तय कर दक्षिण में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के निकट तक जायेगा। इस सम्पूर्ण सुपर राजमार्गों अथवा महामार्गों की लम्बाई 7,000 किलोमीटर है।

रज्जूपथ या रस्से के मार्ग (Ropeways)

इस प्रकार के मार्गों का उपयोग सामान्यतया बड़ी मात्रा में मिट्टी, कोयला, पत्थर, खनिज पदार्थ ढोने के लिए उन भागों में किया जाता है जहाँ दुर्गम घाटियों, तेज जलप्रवाह अथवा तीव्र ढाल के कारण रेलमार्ग या सड़कें बनाना कठिन और व्ययसाध्य होता है। हिमालय की निचली पहाड़ियों, कोयले की खानों, चाय के बागान तथा पुल एवं बाँध बनाने के क्षेत्रों में ऐसे मार्गों का प्रयोग किया जाता है।

भारत में पूर्वी भागों बिहार एवं पश्चिम बंगाल में 28 ऐसे मार्ग हैं जिनकी कुल लम्बाई 120 किलोमीटर है। इनकी ढुलाई क्षमता 120 लाख टन प्रति वर्ष की है, किन्तु इनके द्वारा अभी लगभग 80/90 लाख टन माल ही ढोया जाता है। रानीगंज और झरिया की खानों के निकट 205 किलोमीटर लम्बे रज्जू मार्ग बनाए गए हैं जिनकी ढुलाई क्षमता प्रति घण्टा 4,640 टन की है। इन दोनों को मिलाकर कुछ क्षमता 335 लाख टन वार्षिक की है।

खण्ड-स विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. भारत की सड़क परिवहन प्रणाली एवं सड़कों के प्रकार पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखते हुए समझाइए कि राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास प्रारूप ने किस प्रकार अन्य प्रान्तीय मार्गों को प्रभावित किया है?

Writing a detailed note on India's road transport system and types of roads, explain how the development pattern of national Highways has Influenced other Provincial Routes.

उत्तर

सड़क परिवहन
(Road Transport)

स्थल परिवहन के अन्तर्गत स्थल मार्गों का उपयोग करने वाले सभी साधन (Means) सम्मिलित किए जाते हैं, यथा— (i) सड़कें, (ii) पाइप लाइनें या नल परिवहन, (iii) रेलमार्ग या रेल परिवहन।

आदिकाल से ही भारत में परिवहन-पथों में सड़कों का महत्त्व विशेष रहा है। यह परिवहन के अन्य सभी साधनों का आधार-स्तम्भ है तथा रेल, जहाज एवं विमान की पूरक हैं। सड़क परिवहन के सर्वोपरि गुण उसकी लचक सेवा का व्यापक क्षेत्र, घर या व्यवसाय स्थल तक माल की सुरक्षापूर्ण डिलीवरी, समय की बचत और बहुमुखी एवं सस्ती सेवा का होना है।

भारत में सड़कों की व्यवस्था बहुत पुरानी है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पाकालीन क्षेत्रों की खुदाई से पता लगा है कि 6,000 वर्ष पूर्व भी भारत में पक्की सड़कें थीं जिन पर दो पहिए वाले विशेष प्रकार के रथ चलते थे। भारतीय सम्राटों ने अपनी राजधानी को बाहरी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए अनेक सड़कें बनवायी थीं। चन्द्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को उत्तर-पश्चिमी सीमान्त से जोड़ने के लिए एक महान सड़क बनवायी थी। यह पक्की थी तथा जल बहकर चले जाने की भी व्यवस्था रखी गयी थी। सम्राट अशोक ने इस सड़क का एवं अन्य सड़कों का विस्तार किया तथा सभी राजकीय राजमार्गों को सुधारा। 200 ई०पू० तथा 300 ई० के बीच उत्तरी भारत में दो मार्गों से आन्तरिक व्यापार होता था, जो पाटलिपुत्र से काबुल और सिन्धु की घाटी तक जाते थे। एक बड़ी सड़क महाराष्ट्र और मालवा के बीच थी जो बुरहानपुर होकर जाती थी। 700 ई० में चीनी यात्री (ताओसन) के अनुसार, भारत और चीन के बीच तीन मुख्य व्यापारिक मार्ग थे। एक मार्ग लॉय झील से तिब्बत और नेपाल तक एवं दूसरा शानशान से कोयन तक तथा तीसरा मार्ग भारत से चीन जाता था।

शेरशाह ने बंगाल में ढाका से वाराणसी, आगरा, दिल्ली होते हुए लाहौर और वहाँ से सिन्धु नदी तक ग्रांड ट्रक रोड बनवायी जिसकी शाखाएँ आगरा से जोधपुर, आगरा से इन्दौर और लाहौर से मुल्तान तथा आगरा से चित्तौड़गढ़ तक जाती थीं। इन सड़कों के सहारे अनेक छायादार वृक्ष तथा सराय बनायी गयी थीं। जिसे अंग्रेजों द्वारा 1880 में सुधारा गया। इसके उपरान्त मिर्जापुर से जबलपुर, नागपुर व मुम्बई तक ग्रेट डैकन रोड और आगरा से झांसी होकर मुम्बई जाने वाली वैस्टर्न डैकन रोड बनावायी गयी, किन्तु 1870 के उपरान्त अंग्रेजों का ध्यान रेलमार्गों को विकसित करने की ओर होने से सड़कों के निर्माण का कार्य उतना तीव्र गति से नहीं किया जा सका। केवल उन्हीं सड़कों के निर्माण पर ध्यान दिया गया जिनका सामाजिक महत्त्व था। ये सड़कें 1900 तक बन चुकी थीं। 1900 से 1947 के बीच सड़कों के निर्माण में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। अत: स्वतन्त्रता के पश्चात् ही सभी प्रकार की सड़कों का विकास सम्भव हो पाया।

सड़कों के प्रकार (Types of Roads)

हमारे देश की सड़क प्रणाली विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चात् दूसरी सबसे बड़ी सड़क प्रणाली है। इस समय देश में सड़कों की कुल लम्बाई 63.86 लाख किमी है। इनमें से 2.0 प्रतिशत सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग वर्ग में आती हैं। ये 13,32,500 किमी लम्बी सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग/एक्सप्रेसवे वाली सड़कें हैं। 40 प्रतिशत यातायात इन्हीं राजमार्गों से होकर गुजरता है। देश में 24 प्रतिशत राजमार्ग चार या छ: लेन के हैं, लगभग 52 प्रतिशत दो लेन के हैं और 24 प्रतिशत एक लेन वाले हैं। देश के सड़क मार्गजाल में राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यों के राजमार्ग, प्रमुख या अन्य जिला सड़कें और ग्रामीण और शहरी सड़कें सम्मिलित हैं।

वाहनों की संख्या में पिछले कुछ वर्षों से 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की तीव्र गति से वृद्धि हो रही है और सड़क यातायात 7 से 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की गति से बढ़ रहा है। कुल यातायात में सड़कों के माध्यम से होने वाले माल यातायात और यात्री यातायात का जो प्रतिशत 1950-51 में 13.8 और 15.4 प्रतिशत था वह अब बढ़कर क्रमश: 60 और 87.4 प्रतिशत हो गया है। स्पष्ट है कि यातायात की वर्तमान और भावी जरूरतों को पूरा करने के लिए सड़क मार्गजाल का तेजी से विस्तार करने और उसे मजबूत बनाने की आवश्यकता है ताकि देश के सभी भागों में पहुँच की गम्यता को आसान बनाया जा सके—

1. **राष्ट्रीय राजमार्ग या महामार्ग**—यह देश की सबसे महत्त्वपूर्ण सड़क प्रणाली है जिसका निर्माण एवं रखरखाव केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। देश में 1950-51 में राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई 19,800 किमी थी, जो वर्तमान समय में बढ़कर 13,32,500 किमी हो गई है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई देश की कुल सड़क लम्बाई का मात्र 2.0 प्रतिशत है, लेकिन यातायात में इनकी भागीदारी 40 प्रतिशत की है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भी राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम का एक अंग है।

   देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लम्बाई महाराष्ट्र (17,930.60 किमी) राज्य में तत्पश्चात उत्तर प्रदेश (11,830.88 किमी) राज्य में और राजस्थान (10,350.12 किमी) में हैं। वर्तमान में देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 223 से भी अधिक है। राष्ट्रीय राजमार्ग-7 देश में सर्वाधिक लम्बा है। इसकी लम्बाई 2,369 किमी है। यह वाराणसी से कन्याकुमारी जाता है। इस पर स्थित प्रमुख नगरों में जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरू और मदुरै उल्लेखनीय हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग-6 देश का दूसरा सबसे लम्बा राजमार्ग है। यह 1,946 किमी लम्बा है और कोलकाता से धुले तक जाता है। इस पर स्थित प्रमुख नगर सम्बलपुर, रायपुर और नागपुर हैं। ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग-1 कहते हैं। यह दिल्ली और अमृतसर को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग-2 दिल्ली और कोलकाता के बीच है। राष्ट्रीय राजमार्ग-8 दिल्ली और मुम्बई को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग-15 पठानकोट और कांडला के मध्य विद्यमान है। यह राजमार्ग राजस्थान के मरुस्थल से होकर गुजरता है।

   राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एन०एच०डी०पी०)—राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना देश में प्रमुख राजमार्गों के उच्च स्तर के उन्नयन, पुनर्निर्माण और उन्हें चौड़ा करने की परियोजना है। यह परियोजना 1998 में शुरू की गई थी। इस परियोजना का प्रबंधन सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। यह देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, 49260 किलोमीटर सड़कों और राजमार्गों के निर्माण का कार्य करता है।

   एन०एच०डी०पी० को मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और राष्ट्रीय राजमार्ग संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा सात चरणों में कार्यान्वित किया जा रहा था। इस पर ₹ 6,00,000 करोड़ की लागत आने का अनुमान है। इस कार्यक्रम के तहत निर्मित कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों में चार महानगरों— दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज (लम्बाई 5846 किमी०), पूर्वोत्तर दक्षिण और पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर है, जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से और सिल्चर को पोरबंदर से जोड़ता है। जिसकी कुल लम्बाई 7142 किमी० है। यह सलेम से कोच्चि तक प्रमुख पत्तनों को देश के राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ता है।

   राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को भारतमाला परियोजना में शामिल कर दिया गया है।

   भारतमाला परियोजना—भारतमाला परियोजना का उद्देश्य सागरमाला के समाकलन से सीमावर्ती क्षेत्रों को सड़क सम्पर्क से जोड़ना, छोटे पत्तनों के लिए सड़क सम्पर्क सहित तटवर्ती सड़कों का विकास करना, राष्ट्रीय गलियारे की क्षमता में सुधार करना, आर्थिक गलियारे के विकास, अंतर-गलियारों और फीडरमार्गों के विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार करना है। इसके अतिरिक्त अत्यधिक ट्रैफिक पथों की रूकावटों को दूर करना तथा रिंग सड़कों (ring roads) का निर्माण करना भी इस परियोजना में शामिल है।

   सेतु भारतम्—वर्ष 2016 में सरकार ने एक अलग कार्यक्रम 'सेतु भारतम्' नाम से शुरू किया है। जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर लेवल क्रासिंग के स्थान पर पुल के ऊपर सड़क (आर०ओ०बी०)। पुल के नीचे सड़क (आर०यू०बी०) का निर्माण करना है।

TOUCH 'n' PASS

चारधाम महामार्ग विकास परियोजना—यह योजना उत्तराखण्ड में स्थित चार प्रसिद्ध धाम-गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ व बद्रीनाथ की यात्रा को सुगम बनाने के लिए इनके सम्पर्क मार्गों के विकास के सम्बन्ध में है। इस परियोजना के तहत समाकृति की दो लेन वाली 889 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाना है।

2. **प्रान्तीय राजमार्ग** (State Highways)—यह राज्यों की प्रमुख सड़कें हैं जिनका महत्त्व व्यापार और उद्योग की दृष्टि से अधिक है। ये सड़कें राष्ट्रीय राजमार्गों एवं जिला केन्द्रों से मिली हुई हैं। इन सड़कों के निर्माण और उनको ठीक दशा में रखने का दायित्व राज्य सरकारों पर होता है। इस समय इन सड़कों की लम्बाई लगभग 1.86 लाख किलोमीटर है।

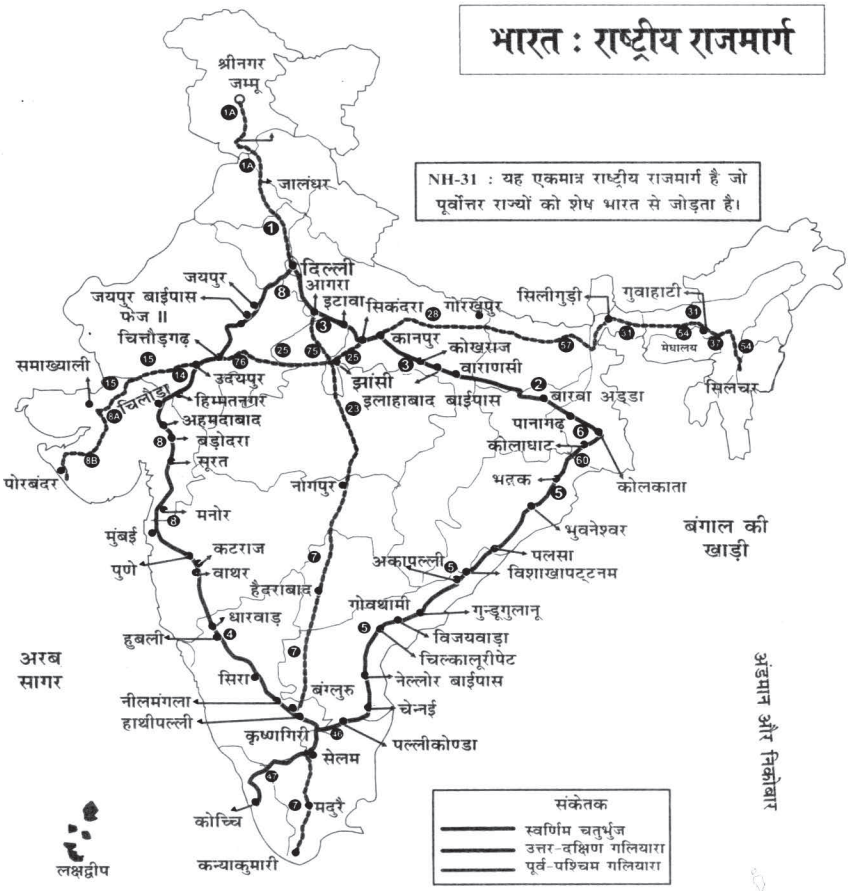

चित्र : 1

अब राष्ट्रीय व प्रान्तीय राजमार्गों के महत्त्वपूर्ण पुलों का निर्माण भूतल परिवहन मन्त्रालय करता है तथा उसकी वसूली वाहनों से करता है।

3. **स्थानीय या जिले की सड़कें** (Local or District Roads)—जिले के विभिन्न भागों को इसके मुख्य कस्बों, उत्पादक केन्द्रों और मण्डियों से जोड़ती हैं। बड़ी सड़कों तथा रेलवे स्टेशनों से भी उनका सम्बन्ध होता है। इनको बनाने का दायित्व जिला बोर्डों का होता है। इसमें से अधिकांश सड़कें कच्ची हैं जो वर्षा के दिनों में सर्वथा अनुपयुक्त हो जाती हैं। इन सड़कों की लम्बाई लगभग 6.32 लाख किलोमीटर है।
4. **गाँव की सड़कें** (Village roads)—विभिन्न गाँवों को आपस में एक-दूसरे से मिलाती हैं। इनका सम्बन्ध निकटवर्ती जिले और राज्यों की सड़कों से भी होता है। प्राय: ये मौसमी मार्ग मात्र होती हैं, जो अधिकतर ग्रामवासियों के सहायोग से ही निर्मित की जाती हैं। देश में ग्रामीण सड़कों की कुल लम्बाई 45.35 लाख किमी० है।

5. **शहरी सड़कें** (Urban roads)—देश में शहरों के अन्तर्गत संचालित कुल सड़कों की लम्बाई 5.44 लाख किमी० है।

अन्तर्राष्ट्रीय राजमार्ग (International Highways)

एशिया एवं सुदूरपूर्व आर्थिक आयोग (ECAFE) के एक निश्चय के अनुसार यह नयी योजना कार्यान्वित की गई है। इसके अनुसार भारत के राष्ट्रीय मार्गों को इस अन्तर्राष्ट्रीय राजमार्ग से मिला दिया गया है। ये अन्तर्राष्ट्रीय राजमार्ग दो प्रकार के होंगे। एक, वे जो विभिन्न देशों की राजधानियों को मिलायेंगे और मुख्य मार्ग होंगे। दूसरे, वे जो मुख्य मार्गों को नगरों एवं बन्दरगाहों से मिलायेंगे। प्रथम राजमार्ग 63,500 किलोमीटर लम्बा है। यह सिंगापुर से होचीमिह्न नगर, बैंकॉक और माण्डले (म्यांमार) होता हुआ बांग्लादेश, भारत व पाकिस्तान को जोड़ता हुआ तुर्की होकर एशियाई राजमार्ग को यूरोपीय अन्तर्राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ता है। भारत में इस राजमार्ग का भाग 2,860 किलोमीटर लम्बा है। यह पाकिस्तान की सीमा पर अमृतसर-दिल्ली, आगरा-कानपुर, कोलकाता-ढाका, आगरा-ग्वालियर-हैदराबाद-बेंगलुरू-धनुषकोटि और बरही से काठमांडू को जोड़ता है। दूसरा राजमार्ग फिरोजपुर के निकट भारत में आरम्भ होकर दिल्ली, मुरादाबाद, टनकपुर (नेपाल की सीमा) तक 900 किलोमीटर लम्बा है। इसकी अन्य शाखाएँ आगरा, मुम्बई, दिल्ली-मुल्तान, कोलकाता-चेन्नई तथा गोलाघाट-लीडो मार्ग हैं।

सड़कों का भौगोलिक वितरण (Geographical Distribution of Roads)

देश में उच्चावचीय स्वरूपों की विविधता के कारण सड़कों का वितरण समान नहीं है।

देश में सड़कों की सर्वाधिक लम्बाई महाराष्ट्र राज्य में तत्पश्चात् उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा तथा बिहार राज्यों में है। उल्लेखनीय है कि सड़क लम्बाई से पहुँच की गम्यता स्पष्ट नहीं होती है। पहुँच की गम्यता के निर्धारण की सही माप सड़क घनत्व है। सड़क घनत्व से तात्पर्य प्रति 100 वर्ग किमी क्षेत्र में विद्यमान सड़कों की लम्बाई से है। सड़कों का राष्ट्रीय घनत्व 115.30 किमी है, जो केरल में सबसे अधिक 517.77 किमी तथा सबसे कम जम्मू-कश्मीर में 12.14 किमी है। लगभग सभी उत्तरी राज्यों और प्रमुख दक्षिणी राज्यों में सड़कों का घनत्व अधिक है। यह हिमालयी प्रदेश, उत्तर-पूर्वी राज्यों, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कम है। भूमि का स्वरूप और आर्थिक विकास का स्तर सड़कों के घनत्व के मुख्य निर्धारक हैं।

देश की कुल सड़कों का आधे से अधिक भाग दक्षिण के पठार पर है क्योंकि यहाँ सड़कें बनाने के लिए कठोर चट्टानें पाई जाती हैं तथा धरातल पहाड़ी होने के कारण सड़कें उत्तरी भारत की अपेक्षा कठोर और सुदृढ़ होती हैं। अत: दक्षिणी भारत में पक्की सड़कें ही अधिक पाई जाती हैं, जबकि उत्तरी भारत में पत्थरों की कमी होने से अधिकांश सड़कें कच्ची अथवा ईंटों के खुरे से बनाई जाती हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आने, पूर्व में दलदली भाग एवं पश्चिम में मरुस्थल के कारण सड़कें बनाना बड़ा व्यय साध्य हो जाता है, इसलिए सड़कों की कमी पाई जाती है। यहाँ कच्ची सड़कें या बैलगाड़ी के मार्ग पाए जाते हैं। पहाड़ी भागों में पगडण्डियों व कच्चे मार्गों पर केवल मनुष्य एवं पशु ही आ जा सकते हैं।

उत्तरी मैदान में अधिकांश सड़कें बाढ़ के समय नष्ट हो जाती हैं। अतएव इन सड़कों पर वर्षा ऋतु में यात्रा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी-कभी तो नदियों पर पुल न होने के कारण गन्तव्य स्थान तक पहुँचने के लिए काफी लम्बा चक्कर लगाना पड़ता है। वर्षा ऋतु में सड़कों पर भारी बोझ ले जाना दुष्कर हो जाता है। सड़कों में कई जगह गड्ढे हो जाने से भी आवागमन में बड़ी कठिनाई पड़ती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान में आज भी वर्षा ऋतु में अनेक छोटे-बड़े गाँव द्वीप की तरह अलग-थलग पड़ जाते हैं।

अब आधारित-अवसंरचना के रूप में सड़कों के महत्त्व को स्वीकार कर लिया गया है। सम्पूर्ण देश में सड़क-निर्माण की दिशा में क्रान्ति सी आ गई है। वर्तमान में देश के सभी नगर, कस्बे एवं 2,500 से अधिक जनसंख्या वाले सभी गाँव पक्की सड़कों से जुड़े हैं। वर्तमान में सभी गाँवों को सभी मौसम के लिए उपयुक्त सड़कों से जोड़ दिया गया है।

सड़क परिवहन की समस्याएँ (Problems of Road Transport)

भारत जैसे विशाल देश में अभी भी सड़कों का विकास देश की विशालता एवं प्रकृति को देखते हुए आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हुआ है। सड़कों के तीव्र गति से विकास में निम्न कारण बाधक रहे हैं—

1. भारत की अधिकांश सड़कें न केवल कच्ची हैं वरन् उनके 50 प्रतिशत भाग पर पूरे वर्ष मोटरें नहीं चलायी जा सकतीं। वर्षा में मण्डियों और अनेक गाँवों के बीच सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है।
2. सड़क परिवहन पर कर दर ऊँची हैं।
3. सड़कों पर चलने वाली मोटरगाड़ियों की हालत असन्तोषजनक है। उनकी भार या यात्री ढोने की कुशलता भी कम है।

4. सड़क परिवहन सम्बन्धी नियमन सभी राज्यों में सरल और एकरूप नहीं हैं।

सड़कों के विकास की आवश्यकता
(Need for Development of Roads)

सभी राजमार्गों की समुचित व व्यवस्थित विकास की वर्तमान में अत्यन्त आवश्यकता है। बढ़ती जनसंख्या, राजमार्गों पर ट्रकों व छोटे वाहनों कान्ट्रेक्ट यात्री कोच आदि का अत्यधिक आवागमन, वीडियोकोच बसों की संख्या में भारी वृद्धि, उद्योगों के कच्चे व पक्के माल एवं मशीनरी का परिवहन तथा कृषि और ग्रामीण परिवहन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सड़क परिवहन के विकास पर अधिक ध्यान देना चाहिए। राजमार्गों का विकास करना निम्न तथ्यों के कारण भी आवश्यक हो जाता है—

1. **तुलनात्मक अधिक सेवा**—एक सड़क रेलमार्ग से तिगुनी ट्रैफिक के लिए उपयुक्त मानी गयी है क्योंकि एक लाइन पर एक समय में एक ही गाड़ी निकल सकती है, जबकि सड़क पर निरन्तर मोटरें चलती ही रहती हैं।
2. एक बढ़िया दो लेन वाली सड़क बनाने में अनुमानत: 1994 से पूर्व ₹ 40 लाख प्रति 2 किलोमीटर पर व्यय होता है, जबकि चौड़े गेज वाली 2 किलोमीटर लम्बी लाइन पर ₹ 80 लाख से ₹ 100 लाख व्यय होता है।
3. रेलों की औसत दैनिक गति 400 से 500 किलोमीटर है, जबकि मोटरों की गति इससे दुगुनी अधिक होती है। अस्तु, सड़क मार्गों पर लगायी गयी पूँजी पर रेलमार्गों पर लगायी गयी पूँजी की अपेक्षा अधिक और तीव्र गति से लाभ होता है।
4. समान मात्रा में सामान ढोने पर सड़क व्यवसाय में रेलों की तुलना में सात गुना अधिक रोजगार मिलता है।
5. देश में 6 लाख गाँव दूर-दूर बिखरे हैं, अत: उनका मण्डियों से सम्बन्ध स्थापित करने के लिए सड़कों का विकास अनिवार्य है, क्योंकि अधिकांश गाँवों एवं कस्बों को सिर्फ सड़कों से ही आसानी से जोड़ा जा सकता है।

1965 में स्थापित परिवहन विकास परिषद् ने सड़क विकास के लिए निम्न सुझाव दिये हैं—

1. भारतीय सड़क परिवहन को प्राथमिक श्रेणी का व्यवसाय माना जाना चाहिए।
2. सड़क परिवहन की नयी कम्पनियों को आयकर से 'विकास छूट' दी जानी चाहिए।
3. सड़क परिवहन विकास से सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
4. सड़कों का सुधार किया जाना चाहिए।
5. सड़क परिवहन से सम्बन्धित क्षेत्रों में बहुमुखी करों में कमी की जानी चाहिए।

1993-94 में सरकार ने सिद्धान्तत: पहली बार राष्ट्रीय एवं प्रान्तीय राजमार्गों के खण्डवार निर्माण के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग की बात स्वीकार कर इसके लिए संसद में मई 1995 में व्यवस्थित अधिनियम भी बना दिया है। इसके अनुसार B.O.T. को नई व्यवस्था की स्वीकृति दी गई है अर्थात् राष्ट्रीय राजमार्ग के विशेष आवंटित खण्ड अथवा पुल का निर्माण सम्बन्धित निजी फर्म विशेष निर्धारित शर्तों पर कराए एवं इस खर्चे को हासिल करने के लिए वहाँ से गुजरने वाले वाहनों पर पूर्व निर्धारित दर पर कर लगाकर उस मार्ग की व्यवस्था निर्धारित समय तक सुचारू रखे एवं उसके पश्चात् सम्पूर्ण सड़क व्यवस्था राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण को सौंप दे।

भारत के एक्सप्रेस राजमार्ग या महामार्ग
(Express Highways or Highways in India)

भारत में सर्वप्रथम दिसम्बर 1998 में नई दिल्ली में विशेष सम्मेलन **'एक्सप्रेस राजमार्ग या महामार्गों'** के निर्माण पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किया गया। इसका उद्देश्य देश में उत्तर-दक्षिण एवं पूर्व-पश्चिम में चित्र के अनुसार 7,000 किलोमीटर लम्बे एक्सप्रेस मार्गों के निर्माण को अनिवार्य माना गया क्योंकि इन्हीं राजमार्गों के द्वारा ही राष्ट्रीय राजमार्गों पर बढ़ते परिवहन के दबावों को रोका जा सकेगा। इसके अन्तर्गत **पहला** प्रधान मार्ग कन्याकुमारी से बेंगलुरू, नागपुर, झांसी, दिल्ली व चण्डीगढ़ होता हुआ जम्मू तक जायेगा। इससे पश्चिमवर्ती राजमार्ग बेंगलुरू से चित्रदुर्ग, बेलगावी पूर्व व मुम्बई होता हुआ अहमदाबाद, उदयपुर व जयपुर होकर दिल्ली में प्रधान मार्ग से मिल जाएगा। इसका दूसरा पूर्ववर्ती मार्ग मदुरै के निकट से प्रारम्भ होकर चेन्नई एवं वहाँ से पूर्वी तट के सहारे होता हुआ कोलकाता तक जाएगा। यह सभी उत्तर-दक्षिण-राजमार्ग के ही भाग हैं।

दूसरा पूर्व-पश्चिम राजमार्ग कांधला बन्दरगाह से प्रारम्भ होकर उदयपुर-कोटा होता हुआ झांसी-लखनऊ-गोरखपुर होता हुआ रक्सौल होकर वहाँ से गंगटोक व दिसपुर तक पूर्व-पश्चिम का मार्ग तय कर दक्षिण में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के निकट तक जायेगा। इस सम्पूर्ण सुपर राजमार्गों अथवा महामार्गों की लम्बाई 7,000 किलोमीटर है।

रज्जूपथ या रस्से के मार्ग (Ropeways)

इस प्रकार के मार्गों का उपयोग सामान्यतया बड़ी मात्रा में मिट्टी, कोयला, पत्थर, खनिज पदार्थ ढोने के लिए उन भागों में किया जाता है जहाँ दुर्गम घाटियों, तेज जल प्रवाह अथवा तीव्र ढाल के कारण रेलमार्ग या सड़कें बनाना कठिन और व्ययसाध्य होता है। हिमालय की निचली पहाड़ियों, कोयले की खानों, चाय के बागान तथा पुल एवं बांध बनाने के क्षेत्रों में ऐसे मार्गों का प्रयोग किया जाता है।

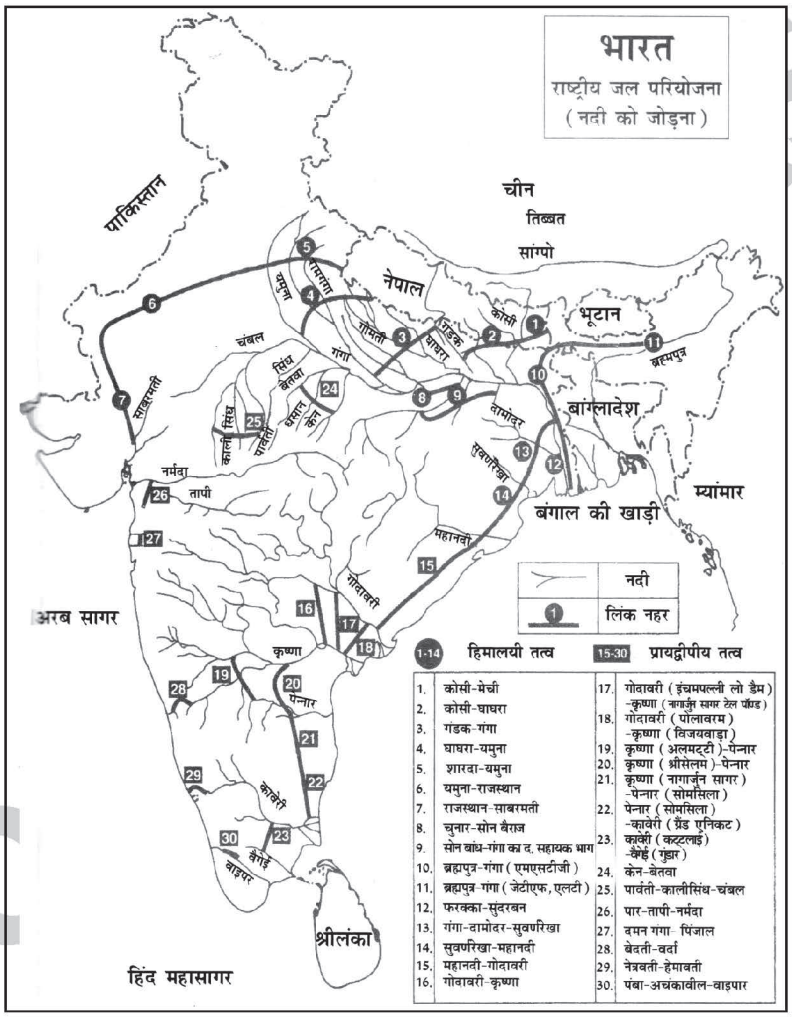

भारत के पूर्वी भागों बिहार एवं पश्चिम बंगाल में 28 ऐसे मार्ग हैं जिनकी कुल लम्बाई 120 किलोमीटर है। इनकी ढुलाई क्षमता 120 लाख टन प्रति वर्ष की है, किन्तु इनके द्वारा अभी लगभग 80/90 लाख टन माल ही ढोया जाता है। रानीगंज और झरिया की खानों के निकट 205 किलोमीटर लम्बे रज्जू मार्ग बनाए गए हैं। जिनकी ढुलाई क्षमता प्रति घण्टा 4,640 टन की है। इन दोनों को मिलाकर कुछ क्षमता 335 लाख टन वार्षिक की है।

प्र.2. भारत के विकास के लिए रेल परिवहन मार्गों का विकसित किया जाना आवश्यक हैं ऐसा क्यों? विवरण दीजिए।
Why is it necessary to develop rail transport routes for India' development? Explain.

उत्तर

रेल-परिवहन
(Rail Transport)

भारतीय रेल देश का प्रमुख परिवहन संगठन है। यह एशिया में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है तथा विश्व में दूसरा सबसे बड़ा एकल प्रबन्धन है। इनका विकास निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जाता रहा है—

1. अधिकांश रेलमार्ग उन क्षेत्रों में बनाये गये हैं जो बहुत उपजाऊ और घने बसे हैं क्योंकि ऐसे ही क्षेत्रों से रेलों को मुसाफिर और माल ढोने को अधिक मिलता है। फलत: रेलमार्गों का विस्तार गंगा की घाटी से अधिक हुआ है।
2. रेलमार्ग प्रसिद्ध बन्दरगाहों, राजधानियों, औद्योगिक और व्यापारिक केन्द्रों से जोड़ते हैं और यह विदेशों में आयातित माल को भीतरी भागों में वितरण करने में सहयोग देते हैं। कृषि क्षेत्रों के उत्पादन को कारखानों तक एवं निर्यात हेतु बन्दरगाहों तक पहुँचाते हैं।
3. ये अकाल एवं अन्य दैवीय आपत्ति के समय अकाल पीड़ित और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को अन्न, दवाइयाँ और अन्य आवश्यक सामग्री पहुँचाने में योगदान देते हैं।
4. सुरक्षा सेनाओं की गतिशीलता बनाये रखते हैं।

भारत में रेलों का विकास (Development of Railways in India)

भारत में रेलमार्गों का विकास 19वीं शताब्दी के मध्य से हुआ था। सर्वप्रथम 1845 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में तीन रेलमार्गों को स्वीकृति दी गई। पहला रेलमार्ग ईस्ट इण्डियन रेलवे था जो कलकत्ता से रानीगंज तक 183 किलोमीटर लम्बा था यह 1854 में ही बनाया गया। दूसरा रेल मार्ग 1853 में ग्रेट इण्डियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर लम्बा मार्ग बनाया गया एवं सन् 1854 में कलकत्ता और पंडुआ के बीच 63 किलोमीटर लम्बा रेलमार्ग बनाया गया। 1856 में मद्रास से अरकोनम के बीच 70 किलोमीटर लम्बा रेलमार्ग बनाया गया। 1870 में भारत में रेलमार्गों की लम्बाई 6,840 किलोमीटर थी। 1871 तक कोलकाता (कलकत्ता), मुम्बई (बम्बई) और चेन्नई (मद्रास) एक-दूसरे से जोड़े जा चुके थे। ये अमृतसर और कालीकट से भी एक शाखा द्वारा जोड़ दिए गये थे। 2019-20 तक रेलयात्रा का दायरा 67.6 हजार किमी तक पहुँच चुका है।

ईस्ट इण्डियन रेलवे द्वारा गंगा की उपजाऊ घाटी तथा ग्रेट इण्डियन पेनिनसुली रेलवे द्वारा दक्कन के पठार के कपास उत्पादक क्षेत्रों को लाभ पहुँचाया गया। ये दोनों रेलमार्ग इलाहाबाद में मिलते थे। मद्रास में दक्षिण मराठा रेलवे व जी०पी० रेलवे रायचूर पर मिलती थी तथा यहाँ से शाखाओं द्वारा बेंगलुरू और कालीकट से। मुम्बई से एक रेलमार्ग अहमदाबाद, लाहौर और दिल्ली के बीच बनाया गया। इसके उपरान्त 1872-79 में आर्थिक कारणों से मीटर गेज या छोटी लाइनों के निर्माण पर ध्यान दिया गया। चेन्नई में तूतीकोरिन, अहमदाबाद से आगरा और दिल्ली तथा दिल्ली और वाराणसी के बीच छोटी लाइनें डाली गयीं। बाद में पहाड़ी भागों तथा उजाड़ क्षेत्रों में कम दूरी की संकरी लाइनें बनायी गयीं। 1906 तक कोलकाता और चेन्नई तथा कोलकाता, नागपुर और बम्बई के बीच बड़ी लाइन बन चुकी थी, किन्तु सबसे अधिक विकास छोटी लाइनों का किया गया— अहमदाबाद को दिल्ली, आगरा को कानपुर, ब्रह्मपुत्र की घाटी और डेल्टाई भागों को जोड़ने के लिए बंगाल-असम रेलवे तथा बंगाल और उत्तर-पश्चिमी रेलवे और तिरहुत-रुहेलखण्ड-कुमायूं रेलवे का निर्माण भी किया गया।

विभाजन के समय अविभाजित भारत में 66,208 किलोमीटर लम्बे रेलमार्ग थे। विभाजन के उपरान्त भारत को 54,969 किलोमीटर लम्बे रेलमार्ग मिले तथा 9 में से 7 रेलमार्ग पूरी तरह भारत को मिले। शेष दो में से बंगाल-असम और उत्तरी-पश्चिमी रेलमार्गों और जोधपुर राज्य रेलमार्ग को भारत और पाकिस्तान के बीच बाँटा गया। विभाजन के उपरान्त पश्चिम बंगाल और असम में कई रेलमार्ग बनाने पड़े, क्योंकि इन दोनों का देश के अन्य भागों से सीधा सम्पर्क टूट गया था। असम रेलमार्ग गंगा नदी पर मनिहारीघाट से फकीराग्राम तक 425 किलोमीटर लम्बा बनाया गया। यह बांग्लादेश और नेपाल के बीच 20 किलोमीटर चौड़े भाग में बनाया गया। इसका निर्माण तत्कालीन लाइनों का उपयोग कर 230 किलोमीटर मार्ग नया बनाकर असम को बिहार और उत्तर प्रदेश से छोटी लाइनों द्वारा जोड़ा गया। मनिहारीघाट से सेकरीगली घाट के बीच असम रेलमार्ग पर अब गंगा पर बड़ा पुल बनाया गया है। बिहार में मोकामाह के निकट गंगा पर एक नया पुल बनाकर वाराणसी तक सीधा रेल सम्पर्क स्थापित किया गया। रानीगंज और कोलकाता के बीच बढ़ते हुए व्यापार की माँग को पूरा करने के लिए चार मार्ग बनाए गए तथा कई मार्गों को दोहरा किया गया। अब तो देश के कई भागों में लिंक मार्ग व अन्य मार्ग बनाये गये हैं।

TOUCH 'n PASS

इस तरह, आज देशभर में रेलों का व्यापक जाल बिछा हुआ है। वर्तमान में रेलवे स्टेशनों की संख्या 7,321 तथा रेलमार्ग की कुल लम्बाई 67.6 हजार किमी है।

रेलमार्गों का वितरण (Distribution of Rail Routes)

उत्तरी भारत में

देश में रेलमार्गों की लम्बाई का लगभग आधा भाग सतलज और गंगा के मैदान में है क्योंकि यहाँ भारत की अधिकांश जनसंख्या बसी है। यहाँ की भूमि बड़ी उपजाऊ है और यहीं भारत के बड़े-बड़े नगर बसे हैं। भूमि का धरातल समान होने के कारण रेलमार्ग बनाने की सुविधाएँ भी यहाँ अधिक पायी जाती हैं। देश के विभाजन के पूर्व यहाँ की सबसे लम्बी रेलवे लाइन (N.W.R.) 12,640 किलोमीटर थी। देश की सबसे अधिक सामान ढोने वाली व कमाई देने वाली रेलवे (E.I.R.) भी इसी मैदान में है। भारत की सबसे अधिक लाभ देने वाली रेलवे (शादरा लाइट रेलवे), जिससे 10 प्रतिशत लाभ प्रतिवर्ष होता था, इसी मैदान में है।

इस मैदान में रेलमार्गों की पहली विशेषता यह है कि समतल धरातल होने से मीलों तक उनका मार्ग सीधा है। समतल होने से रेलमार्ग बनाने में सुविधा होती है, किन्तु घनी वर्षा और हिमालय से आने वाली बड़ी-बड़ी नदियों द्वारा रेलमार्गों को बहुधा हानि पहुँचती है। बाढ़ के समय कहीं-कहीं रेलवे लाइनें कट जाती हैं अथवा उनके पुल टूट जाते हैं। इसके अतिरिक्त, रेलमार्गों के किनारे डालने के लिए पत्थर की गिट्टी बहुत दूर पहाड़ी-पठारी भागों से मँगवानी पड़ती है।

इन रेलमार्गों की दूसरी विशेषता यह है कि इनकी शाखाएँ बहुत हैं। देश में रेलमार्गों की इतनी संख्या अन्यत्र नहीं मिलती। शाखाएँ विशेषत: पूर्वी भारत के कोयला एवं औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक पायी जाती हैं। यहाँ रेल के डिब्बों की माँग माल लाने-ले जाने में निरन्तर बनी रहती है।

तीसरी विशेषता यह है कि इस मैदान के रेलमार्गों का पूर्व में अन्त कोलकाता में होता है। वहाँ यह स्वतन्त्रता से पूर्व का सबसे बड़ा बन्दरगाह, महानगर 1911 तक भारत की राजधानी एवं विशाल व्यापारिक मण्डी रहा है। अत: यह देश का विशाल जंक्शन है। देश का उच्च तकनीक का हावड़ा का पुल भी यहीं स्थित है। मैदान के उत्तर में हिमालय पर्वत की ओर दार्जिलिंग, शिमला, कांगड़ा आदि स्थानों में पहाड़ों को पार कर रेल की छोटी-छोटी लाइनें पहुँचती हैं।

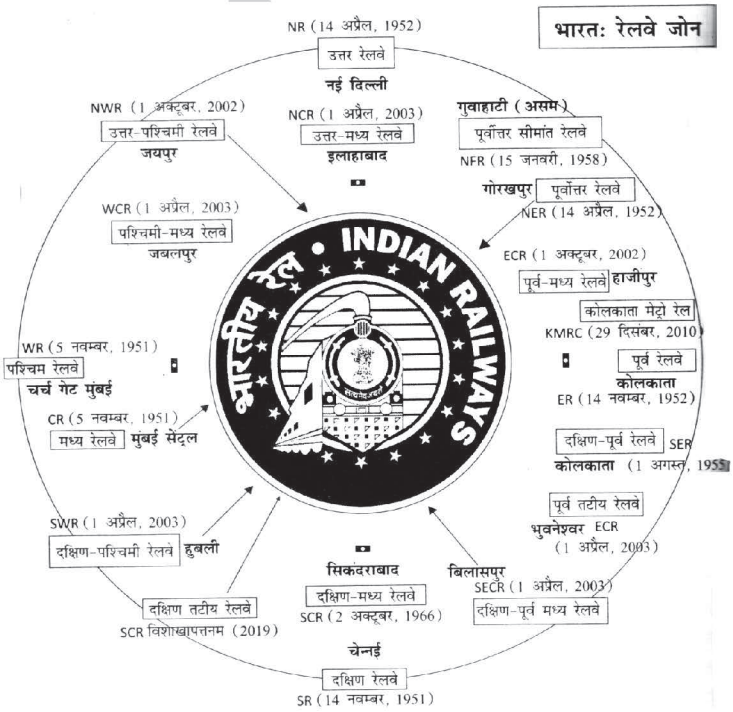

चित्र

दक्षिणी भारत में

दक्षिण के पठार पर जो रेलमार्ग पाए जाते हैं वे प्राय: टेढ़े-मेढ़े हैं। इसका मुख्य कारण पठार के धरातल का ऊँचा-नीचा होना और टूटी-फूटी पहाड़ियों का अधिक होना है। इससे बचने के लिए तथा भूमि के अधिक ढाल से दूर रहने के उद्देश्य से रेलमार्ग बहुधा टेढ़े-मेढ़े बनाना ही आवश्यक हो जाता है। पठार में कहीं-कहीं रेलमार्ग को इतने अधिक खड़े ढाल पर चलाना पड़ता है कि वहाँ रेलगाड़ी में एक इंजन पीछे ठेलने के लिए लगाना आवश्यक है। इस प्रकार के ढाल मध्य प्रदेश में होशंगाबाद और महाराष्ट्र में इगतपुरी में देखने को मिलते हैं। पठार में कहीं-कहीं रेलमार्गों को निकालने के लिए पहाड़ों में सुरंगें भी बनानी पड़ती हैं, विशेषत: ऐसे भागों में जहाँ घूमकर पहाड़ों के दूसरी ओर रेल नहीं जा सकतीं। पठार में चलने वाले सभी रेल मार्गों में कहीं न कहीं सुरंगें बनी हैं। अत: रेलमार्गों का बनाना न केवल दुसाध्य ही होता है वरन् खर्चीला भी अधिक होता है। पश्चिमी घाट में थालघाट, भोरघाट, पालघाट आदि सुरंगें और राजस्थान के उदयपुर तथा जोधपुर सम्भागों के बीच अरावली श्रेणियों में गोरमघाट में सुरंगें बनानी पड़ी हैं। वास्को और लौंडा जंक्शन के बीच 18 और पुणे तथा मुम्बई के बीच 26 छोटी-बड़ी सुरंगें हैं।

भारत के रेलमार्ग के मानचित्र को देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि यहाँ कई क्षेत्रों में रेलमार्गों का प्राय: अभाव है, यथा— पश्चिम के राजस्थान, थार की मरूभूमि, बिहार के छोटा नागपुर, उड़ीसा के पहाड़ी भाग तथा असम राज्य में। यहाँ भूमि बड़ी ऊँची-नीची अथवा बालू मिट्टी वाली है तथा जनसंख्या कम होने से रेलों की आवश्यकता भी कम ही है। पर्वतीय क्षेत्रों में भी रेलमार्गों का अभाव पाया जाता है।

अत: देश के कई भागों में विशेषत: औद्योगिक क्षेत्रों में परिवहन की सुविधा देने के लिए नये रेलमार्ग बनाये गये हैं; जैसे—

1. राउरकेला और राँची (हटिया) के बीच;
2. मुरी और राँची के बीच;
3. राँची और चन्द्रपुरा के बीच;
4. बरौनी और बिहार के उत्तरी भागों के बीच;
5. असम को जोड़ने के लिए रेलमार्ग (Assam Link Railways);
6. छोटा नागपुर क्षेत्र, दामोदर घाटी क्षेत्र आदि में खनिजों व इस्पात केन्द्रों का विकास करने हेतु रेलमार्गों का विस्तार किया गया है;
7. पठानकोट से जम्मू-तवी तक रेलमार्ग 1972 में बनाया गया।

पहाड़ी भागों में रेलमार्ग या तो छोटी या संकरी लाइन के हैं; जैसे— पठानकोट और जोगिन्द्रनगर के बीच: कालका से शिमला के बीच; सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग के बीच; मेतूपलायम से उटकमंड के बीच और माथेरान के बीच।

भारतीय रेलों की प्रशासनिक व्यवस्था
(Administrative Set-up of Indian Railways)

भारत में रेलप्रणाली का संचालन केन्द्रीय सरकार (रेल मन्त्रालय) के अधीन है। इसके द्वारा भारत में होने वाले व्यापार में बड़ी सहायता मिलती है। भारतीय रेल प्रणाली एशिया की सबसे बड़ी एवं विश्व की पाँचवीं बड़ी रेल प्रणाली है।

प्रारम्भ में 1949 तक भारतीय रेल व्यवस्था के अन्तर्गत (9 सरकारी और 28 देशी राज्यों की रेलवे प्रणालियाँ) थीं। इनका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार हैं—

A. सरकारी रेल मार्ग

1. ईस्ट इण्डिया रेलवे (East India Railway), 2. बंगाल-नागपुर रेलवे (Bengal-Nagpur Railway), 3. अवध-तिरहुत रेलवे (Oudh-Tirhoot Railway), 4. असम रेलवे (Assam Railway), 5. साउथ इण्डियन रेलवे (South Indian Railways), 6. मद्रास, मराठा रेलवे (M.S.M. Railway), 7. मुम्बई, वडोदरा, सेण्ट्रल इण्डिया रेलवे (B.V. and C.I. Railway), 8. ग्रेट इण्डियन पेनिनसुला रेलवे (G.I.P. Railway), 9. पूर्वी पंजाब रेलवे (East Punjab Railway)।

B. देशी राज्यों (रियासतों) के रेलमार्ग

1. बीकानेर रेलवे, 2. कच्छ स्टेट रेलवे, 3. धौलपुर स्टेट रेलवे, 4. जयपुर स्टेट रेलवे, 5. जोधपुर स्टेट रेलवे, 6. मैसूर स्टेट रेलवे, 7. निजाम स्टेट रेलवे, 8. सौराष्ट्र रेलवे, 9. सिन्धिया स्टेट रेलवे, 10. उदयपुर-चित्तौड़ (मेवाड़) रेलवे, 11. बैजवाड़ा रेलवे, 12. दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, 13. मरहट्ठा रेलवे, 14. मद्रास रेलवे आदि।

TOUCH 'n' PASS

भारत के रेल खण्ड (Railway Zones of India)

क्रम	रेलवे जोन	मुख्यालय	स्थापना तिथि	सम्मिलित डिवीजन
1.	दक्षिण	चेन्नई	14 अप्रैल, 1951	चेन्नई, मदुरै, पालघाट त्रिची, तिरुवनन्तपुरम
2.	मध्य	मुम्बई	5 नवम्बर, 1951	भुसावल, नागपुर, मुम्बई (सी०एस०टी०), शोलापुर, पुणे
3.	पश्चिम	मुम्बई (चर्चगेट)	5 नवम्बर, 1951	भावनगर, मुम्बई सेन्ट्रल, रतलाम, राजकोट, बडोदरा, अहमदाबाद
4.	पूर्व	कोलकाता	1 अगस्त, 1955	माल्दा, हावड़ा, सिलादेह, आसनसोल
5.	उत्तर	नई दिल्ली	4 अप्रैल, 1952	अम्बाला, फिरोजपुर, लखनऊ, मुरादाबाद दिल्ली
6.	पूर्वोत्तर	गोरखपुर	14 अप्रैल, 1955	लखनऊ, वाराणसी, इज्जतनगर
7.	दक्षिण-पूर्व	कोलकाता	1 अगस्त, 1955	खड़गपुर, चक्रधरपुर, अद्रा, राँची
8.	पूर्वोत्तर सीमा	मालीगाँव (गुवाहाटी)	15 जनवरी, 1958	कटिहार, लुमडिंग, तिनसुखिया, अलीपुरद्वार, रांगिया
9.	दक्षिण-मध्य	सिकन्दराबाद	2 अक्टूबर, 1966	सिकन्दराबाद, हैदराबाद, नान्देड
10.	पूर्वी-तटीय	भुवनेश्वर	1 अप्रैल, 2003	खुर्दारोड़, वाल्टेयर, सम्बलपुर
11.	उत्तर-मध्य	प्रयागराज (इलाहाबाद)	1 अप्रैल, 2003	इलाहाबाद, झांसी, आगरा
12.	पूर्व-मध्य	हाजीपुर	1 अक्टूबर 2002	दानापुर, धनबाद, सोनपुर, मुगलसराय, समस्तीपुर
13.	उत्तर-पश्चिम	जयपुर	1 अक्टूबर 2002	बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर
14.	दक्षिण-पश्चिम	हुब्बाली	1 अप्रैल, 2003	बेंगलुरू, मैसूरू, हुब्बाली
15.	पश्चिम-मध्य	जबलपुर	1 अप्रैल, 2003	जबलपुर, भोपाल, कोटा
16.	दक्षिण-पूर्व-मध्य	बिलासपुर	1 अप्रैल, 2003	नागपुर, बिलासपुर, रायपुर
17.	कोलकाता मेट्रो	कोलकाता	25 दिसम्बर, 2010	कोलकाता
18.	दक्षिण तटीय रेलवे	विशाखापट्टनम	27 फरवरी, 2019	गुन्तकल, गुन्टूर, विजयवाड़ा

यद्यपि सारे रेलमार्ग सरकारी क्षेत्र में ही हैं फिर भी 454 किलोमीटर लम्बे मार्ग गैर-सरकारी क्षेत्र में हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र के रेलमार्ग ये हैं—

(i) आरा-सासाराम लाइट रेलमार्ग, 104.8 किलोमीटर,
(ii) डेहरी-रोहतास 66.7 किलोमीटर,
(iii) फतवा-इस्लामपुर, 43.5 किलोमीटर,
(iv) हावड़ा-आमटा, 70.3 किलोमीटर,
(v) हावड़ा-शीखला, 27.2 किलोमीटर,
(vi) शाहदरा-सहारनपुर, 148.8 किलोमीटर। ये सभी संकरी लाइनें हैं। केवल हावडा-शीखला मार्ग लाइट लाइन (0.610 मीटर) है।

विद्युतचालित रेल मार्ग (Electrified Rail Routes)

भारत में मुम्बई और चेन्नई में उपनगरीय रेलों के विद्युतीकरण पर सबसे पहले 1920 में विचार किया गया, किन्तु प्रथम विश्वयुद्ध के कारण इस पर कार्य 1925 में आरम्भ हुआ। विद्युत चालित रेल का सबसे पहला सेक्शन **विक्टोरिया टर्मिनस** से कुर्ला तक था। 1928 तक जी०आई०पी० रेलवे ने इस सेवा का विस्तार मुम्बई से लगभग 64 किलोमीटर दूर कल्याण तक कर दिया। 1928 में बी०बी० एण्ड सी०आई० रेलवे ने भी चर्चगेट-बोरीवली सेक्शन में और बाद में बिरार तक की लगभग 68 किलोमीटर की दूरी में विद्युत रेल चलाई। 1931 से चेन्नई और तम्बरम के बीच की लगभग 29 किलोमीटर की दूरी भी विद्युत रेल द्वारा तय की जाने लगी। 1936 से 1952 तक रेलमार्ग का विकास स्थिर सा रहा। अत: विद्युत रेलमार्गों का भी विकास नहीं हो पाया।

TOUCH 'n PASS

मुम्बई में विद्युत चालित उपनगरीय गाड़ियाँ बहुत लोकप्रिय हुईं और उनसे मुम्बई की बाहरी बस्तियों का बहुत विस्तार हुआ है। वहाँ की जनसंख्या 1930 में लगभग 15 लाख थी, जो 1951 में 35 लाख हो चुकी थी। 1926-27 में मुम्बई की इन गाड़ियों में 480 लाख लोगों ने यात्रा की थी और 1951-52 में यह संख्या बढ़कर 3,000 लाख हो गयी थी। मुम्बई में आज मध्य और पश्चिमी रेलों की प्रतिदिन लगभग 1000 उपनगरीय गाड़ियाँ चलती हैं, किन्तु यात्रियों की संख्या और भीड़ को देखते हुए वे भी अपर्याप्त हैं। मुम्बई के पूर्व में पश्चिमी घाट की चढ़ाई-उतराई में भाप के इंजनों से गाड़ियाँ ले जाने में बहुत कठिनाई और खर्च अधिक बैठता था, इसलिए मुम्बई से पुणे और मुम्बई से इगतपुरी सेक्शनों में भी 1927 से विद्युत रेलें चलायी जाने लगीं। दिसम्बर 1957 में 22 किलोमीटर लम्बे टुकड़े पर हावड़ा और शिवराफूली के बीच प्रथम बार विद्युत गाड़ी चलायी गयी।

वर्ष 2019-20 तक भारतीय रेलवे के पास विद्युतचालित 39.9 हजार किमी मार्ग का नेटवर्क है, जो कुल नेटवर्क का 59.0 प्रतिशत है और 64.50 प्रतिशत माल ढुलाई करता है और 53.70 प्रतिशत कोचिंग ट्रैफिक का वहन करता है।

मेट्रो रेलवे-कोलकाता—यह रेलवे दमदम से टोलीगंज के भूमिगत 16.45 किमी लम्बे रेलमार्ग पर परिचालित होती है। 1972 में इसे आंशिक रूप से परिचालित किया गया किन्तु 27 दिसम्बर, 1995 से पूरे रेलमार्ग पर इसका परिचालन प्रारम्भ कर दिया गया है। इसके उपरांत इसे परियाघाट तक बढ़ा दिया गया।

मेट्रो रेलवे-दिल्ली—इस परियोजना के प्रथम चरण की मंजूरी सितम्बर 1996 में दी गई थी। वर्तमान में यह रेलवे दिल्ली विश्वविद्यालय से केन्द्रीय सचिवालय 11 किमी भूमिगत मार्ग से संचालित है। इसके साथ ही शाहदरा-रिठाला गलियारा में भी दिल्ली मेट्रो रेल प्रणाली कार्य कर रही है। दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना चरण-2 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय-कश्मीरी गेट, कश्मीरी गेट-केन्द्रीय सचिवालय, कीर्तिनगर, कीर्तिनगर-द्वारका एवं इन्द्रप्रस्थ-बाराखम्भा रोड तक मेट्रो रेल प्रणाली कार्य कर रही है। इस परियोजना के तीसरे चरण का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को पर्यावरण के अनुकूल निर्माण व संचालन के लिए आई०एस०ओ० 14001 प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ है। यह देश में प्रथम द्रुतगामी परिवहन प्रणाली होगी जो अन्तर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करेगी तथा इसमें नई प्रौद्योगिकी को शामिल किया गया है।

देश के कोलकाता, दिल्ली, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, मुम्बई, चेन्नई, बेंगलुरू, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, कोच्चि जैसे शहरों में मेट्रो सेवा संचालित है।

प्र.3. भारत के बड़े बन्दरगाहों के रूप में हल्दिया और चेन्नई के विकास हेतु उत्तरदायी कारकों का विश्लेषण कीजिए।
Analyse the factors responsible for the development of Haldia and Chennai as major ports of India.

उत्तर

बड़े बन्दरगाह
(Major Ports)

तटवार भारत के 12 बड़े प्रमुख बन्दरगाहों की स्थिति निम्न प्रकार से है—

पश्चिमी तट पर—दीनदयाल (कांडला), मुम्बई, शेवा व नवी मुम्बई में जवाहरलाल नेहरू, मोरमूगाओ, नया मंगलौर और कोच्चि।

पूर्वी तट पर—वी०ओ० चिदम्बरनार, चेन्नई, कामराज (एन्नौर), विशाखापत्तनम, पारादीप, कोलकाता।

कोलकाता (Kolkata)

यह भारत का ही नहीं, सम्पूर्ण एशिया का प्रमुख बन्दरगाह है। कोलकाता बन्दरगाह के अन्तर्गत कोलकाता गोदी प्रणाली (Kolkata Dock System) और हल्दिया गोदी संकुल (Haldia Dock Complex) सम्मिलित हैं। कोलकाता गोदी प्रणाली के अन्तर्गत खिदरपुर गोदी, नेताजी सुभाष गोदी, बजबज पेट्रोलियम गोदी तथा सागोर सेण्डहेड्स और डायमण्ड हार्बर पोताश्रय सम्मिलित हैं।

स्थिति एवं पृष्ठ प्रदेश—कोलकाता गोदी प्रणाली हुगली नदी के बाएँ किनारे पर अवस्थित है। इस प्रणाली का संचालन स्टेशन (Pilotage station) गेस्पर/सागोर रोड है और यहाँ से कोलकाता गोदी प्रणाली तक की संचालन दूरी 145 किमी है। कोलकाता गोदी प्रणाली 20°32′53″ उत्तरी अक्षांश तथा 88°18′15″ पूर्वी देशान्तर पर अवस्थित है। हल्दिया गोदी संकुल संचालन स्टेशन से 60 किमी दूर अवस्थित है। ज्यामितीय दृष्टि से यह 22°02′ उत्तरी अक्षांश और 88°06′ पूर्वी देशान्तर पर अवस्थित है।

TOUCH 'n' PASS

यह गंगा-ब्रह्मपुत्र घाटी का मुख्य सामुद्रिक द्वार है। इसका पृष्ठ प्रदेश धनी है। इसके पृष्ठ प्रदेश में पूर्वांचल के सातों राज्य, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखण्ड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश सम्मिलित हैं। इन सभी भागों से यह पूर्वी उत्तर-पूर्वी, मध्य और पूर्वी सीमान्त रेलमार्गों, राष्ट्रीय राज मार्गों वायुमार्गों नदियों और नहरों द्वारा जुड़ा है। अत: सभी प्रकार की पैदावार एवं उत्पादन सहज में ही कोलकाता लाया जा सकता है और विदेशों से प्राप्त माल को भिन्न-भिन्न भागों में पहुँचाया जा सकता है। यह वायु मार्गों द्वारा सम्पूर्ण विश्व से जुड़ा हुआ है।

इसके पृष्ठ प्रदेश में अनेक प्रकार के कृषिगत एवं औद्योगिक कच्चा माल, सब्जियाँ, फल, जूट, चाय, प्लाई, लकड़ी इन्जीनियरिंग सामान रसायन वस्त्र एवं अन्य निर्मित वस्तुओं का भारी मात्रा में उत्पादन होता है। साथ ही भारत के प्रधान औद्योगिक प्रदेश इसके पृष्ठ प्रदेश में स्थित हैं, अत: वहाँ धातु शोधन उद्योग, भारी, हल्के व कीमती इंजीनियरी एवं रासायनिक सामान, इलेक्ट्रोनिक व विद्युत सम्बन्धित निर्माण उद्योग स्थित हैं। अत: यहाँ से सभी प्रकार की आयात-निर्यात सेवा उपलब्ध है।

मुख्य कोलकाता बन्दरगाह नदी तट पर स्थित होने से वहाँ बड़े जहाजों एवं टैंकर के प्रवेश एवं निकासी तथा शीघ्र घूमने में विशेष कठिनाई रहती है। इसी कारण नदी के मुहाने या सामुद्रिक प्रवेश मार्ग पर हल्दिया बन्दरगाह का निर्माण एवं विकास किया गया। अत: अब यहीं से निरन्तर बढ़ते भार की माँग पूरा करने के लिए हल्दिया बन्दरगाह क्षेत्र में समुचित सुविधाओं का विकास किया गया।

हुगली नदी में कोलकाता से समुद्र तट तक अनेक मोड़ हैं तथा कई स्थानों पर नदी में अवसाद व बालू भर जाने से जल की गहराई बहुत कम हो गयी है, जिस कारण बड़े जहाज नहीं निकल पातें। इनमें से भी गंगासागर के आस-पास केवल 7 से 9 मीटर तक ही जल गहरा रहता है। अत: बन्दरगाह में जहाज आने के पूर्व इस बात की परीक्षा कर ली जाती है कि यहाँ जल पर्याप्त गहरा है। अन्यथा जहाजों को हुगली नदी के गहरे जल में ज्वार आने तक खड़ा रहना पड़ता है।

कोलकाता की सबसे बड़ी समस्या हुगली नदी में निरन्तर मिट्टी भरते जाना है। 1938-39 में जल की गहराई 30 फीट थी, किन्तु 1973-74 में वह केवल 26 फीट ही रह गयी। इस दोष को दूर करने के लिए 64 किलोमीटर दूर खुली खाड़ी में डायमण्ड पोताश्रय का निर्माण किया गया है। यहाँ जल की पर्याप्त गहराई के कारण 10,000 टन से अधिक भार वाले जहाज पहुँचकर यहाँ विश्राम करते हैं। ज्वार के समय से जहाज खिदिरपुर तक जाते हैं, जो कोलकाता की मुख्य गोदी है। इस प्रकार जहाजों का आवागमन ज्वार-भाटे की ऊँचाई पर निर्भर करता है। हुगली के मुहाने से कोलकाता तक जहाजों के आने में लगभग 6 घण्टे का समय लगता है। हुगली तट पर उत्तर में सिरामपुर से लेकर दक्षिण में बजबज तक यह बन्दरगाह अनेक स्थानों पर जेटियाँ, गोदाम एवं व्यावसायिक केन्द्र स्थित हैं। अब पोताश्रय की सुविधा बढ़ाना सबसे बड़ी समस्या है। मुख्य बन्दरगाह क्षेत्र के आसपास का भाग घना आबाद होने व अतिरिक्त स्थान के अभाव के कारण एवं नदी के कम गहरी होने से यहाँ बड़े जहाजों के लिए सुविधा नहीं जुटाई जा सकती।

इस बन्दरगाह के विकास के प्रमुख कारण हैं—

1. इसका पृष्ठ प्रदेश सघन जनसंख्या वाला है।
2. यहाँ सभी प्रकार के यातायात के साधन विकसित हैं।
3. समीप स्थित पूर्वी एशियाई देश भारतीय माल के अच्छे ग्राहक हैं।
4. कोयला से प्राप्त ताप-विद्युत तथा जल-विद्युत काफी मात्रा में उपलब्ध है।
5. समीपवर्ती प्रदेश में सस्ते मजदूर काफी संख्या में मिल जाते हैं।

खिदिरपुर सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण पोताश्रय है यहाँ तीन शुष्क डॉक हैं। पहला डॉक 792 मीटर लम्बा 183 मीटर चौड़ा है। इनके निकट जल 9 मीटर (30 फीट) गहरा रहता है। दूसरा डॉक 1,371 मीटर लम्बा तथा 122 मीटर चौड़ा है। यहाँ भी जल की गहराई 9 मीटर है। यहाँ मशीनों से सामान उतारने की सुविधा है। यहाँ लगभग 18 बर्थ हैं जिनमें 6 बर्थ कोयला आदि चढ़ाने के लिए बने हैं। **नेताजी सुभाष डॉक** दूसरा महत्वपूर्ण डॉक है, जो 213 मीटर लम्बा तथा 27 मीटर चौड़ा है। यहाँ सामान उतारने-चढ़ाने के 10 बर्थ हैं और पेट्रोलियम पदार्थों के लिए एक और बर्थ है। पूरे बन्दरगाह में 5 शुष्क डॉक भी हैं जिनमें से 3 खिदिरपुर और 2 नेताजी सुभाष डॉक में स्थित हैं। बजबज में पेट्रोलियम के गोदाम की व्यवस्था है। अन्य स्थानों पर विविध प्रकार के अनेक गोदाम बने हुए हैं।

पिछले तीन सौ वर्षों में कोलकाता बन्दरगाह का विस्तार अधिकतम हो चुका है। अब नदी की न्यूनतम गहराई ज्वार के समय 9 मीटर अन्यथा 6 से 8 मीटर बनाए रखने के लिए भी निरन्तर ड्रेजर सेवा का उपयोग वर्ष भर किया जाता है। हल्दिया से कोलकाता तक 15 से 20 हजार टन तक के जहाजों के आने जाने के लिए ही सारे मार्ग पर समुचित प्रकाश व्यवस्था, लाइट हाउस, बेतार व

TOUCH 'n PASS

संचार सेवा, अग्निशमन सेवा एवं अन्य आपातकालीन सेवा सुविधा सुलभ की गई है, क्योंकि कोलकाता का सम्पूर्ण पृष्ठ प्रदेश सघन आबाद, सुविकसित एवं उत्तम यातायात से जुड़ा है। अत: आयात-निर्यात में निरन्तर व्यवस्था बनी रहती है।

चित्र

कोलकाता बन्दरगाह से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएँ तापीय कोयला, धात्विक कोक, जूट और जूट से बना सामान, चाय, लौह-अयस्क, लोहा और इस्पात, मशीनरी, कास्टिंग किया हुआ लौह सामान, पिग आयरन, अभ्रक, धातु और धातु उत्पाद, गेहूँ, चावल, शक्कर, फ्लाई ऐश, आदि हैं। इस बन्दरगाह द्वारा आयात की गई प्रमुख वस्तुओं में उर्वरक, उर्वरक हेतु कच्चा माल, अखबारी कागज, कोकिंग कोयला, धात्विक कोक, चूना पत्थर, लौह-इस्पात, पेट्रोलियम कोक, मशीनरी, टिम्बर, दालें, वनस्पति तेल, एल०पी०जी०, आदि हैं। कोलकाता बन्दरगाह का देश के प्रमुख बन्दरगाहों में तीसरा स्थान है।

हल्दिया (Haldia)

हल्दिया बन्दरगाह तेजी से कोलकाता का स्थानापन्न बन्दरगाह बनता जा रहा है। यह बन्दरगाह हुगली नदी के मुहाने पर मुख्य समुद्र तट पर स्थित है। यहाँ के विशाल कटान व सुरक्षित पोताश्रय में सागर की गहराई 15 मीटर एवं अधिक है। अत: यहाँ बड़े से बड़े जहाज एवं टैंकर भी आसानी से प्रवेश पाकर पुन: लौट सकते हैं। इसी कारण (i) जो जहाज कोलकाता तक हुगली की धारा से होकर नहीं पहुँच पाते उनके लिए यहाँ कम समय में शीघ्र सामान लादा व उतारा जा सकता है। (ii) कोलकाता में अब स्थानाभाव के कारण विकास सम्भव नहीं हैं, जबकि यहाँ पर भारी कीमती व अन्य सामान के लिए एवं कण्टेनर सुविधा के लिए पर्याप्त स्थान व सुविधा उपलब्ध है।

यहाँ पर विदेशों से आयातित कोयला, शोधनशाला के लिए पेट्रोलियम पदार्थ एवं उर्वरकों के लिए स्वतन्त्र बर्थ व जेट्टियाँ बनाई गई हैं। यहाँ विशेष सामान व निर्मित एवं कीमती सामान के लादने उतारने के लिए विशेष बर्थ है। कोलकाता से आकर अण्डमान, रंगून, सिंगापुर आदि स्थानों के सैलानियों व यात्रियों के लिए भी यहाँ विशेष व्यवस्था है। मुख्य यार्ड में भारी कीमती, विविध प्रकार के एवं कण्टेनर सामान के लिए विशाल एवं स्वनियन्त्रित प्रणाली के विशेष गोदाम बनाए गए हैं। अधिकांश जहाजों व टैंकरों के भारी सामान को कम्प्यूटर नियन्त्रण द्वारा शीघ्र व बिना हानि के खाली किया जाता है। यहाँ पर 1992-93 में खनिज तेल के आयात

की सुविधा के लिए दूसरी तेल जेट्टी का निर्माण किया गया है। इससे शोधनशाला की क्षमता का विस्तार किया जा सकेगा। अब यहाँ पोताश्रय के बाहरी क्षेत्र में पेट्रोरसायन कॉम्पलेक्स का तेजी से विकास होता जा रहा है।

इसके अतिरिक्त कोलकाता पोताश्रय कॉम्पलेक्स में न्यूनतम सुविधाएँ बनाये रखने के लिए 1991 में दो ड्रेजर खरीदे गए। इससे हुगली नदी की धारा की गहराई 5 से 7 मीटर के मध्य रखी जाती है। अत: अब यहाँ 18 से 25 हजार टन तक के जहाज आ जा सकते हैं। बड़े जहाज अपना माल हल्दिया में खाली करते हैं एवं छोटे जहाजों व स्टीमरों द्वारा कोलकाता के खिदिरपुर एवं किंग जार्ज डॉक तक पहुँचाया जाता है। वर्तमान में हल्दिया में कोयला के 6 बर्थ एवं तेल के 3 बर्थ हैं। नवनिर्मित लौह-अयस्क के बर्थ को सामान्य बर्थ की भाँति विकसित किया गया है। यहाँ के बढ़ते सामान्य व्यापार को देखते हुए यहाँ का तेजी से विकास व विस्तार अनिवार्य हो गया है। अत: इसे कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का ही अंग मानकर अब विकसित किया जा रहा है।

चेन्नई (Chennai)

स्थिति एवं पृष्ठ प्रदेश पूर्वी तट पर यह भारत का प्रमुख कृत्रिम बन्दरगाह है। यद्यपि प्राकृतिक पोताश्रय की दृष्टि से यह स्थल उपयुक्त नहीं है। स्थानीय माँग के कारण कृत्रिम रूप से इसका विकास किया गया है। विस्तृत खुले समुद्रों में जहाज को लहरों से होने वाली असुविधाओं को दूर करने के लिए 90 मीटर की गहराई की नींव पर तट से 3 किलोमीटर दूर दो कंक्रीट की 914 मीटर लम्बी दीवारें बनाकर लगभग 200 एकड़ समुद्र के जल को रोका गया है। बन्दरगाह का मुख्य द्वार 120 मीटर लम्बा है। यहाँ साधारण जल की गहराई 10 मीटर तक रहती है, किन्तु ज्वार आने पर यह 12 मीटर तक हो जाती है। इस सुरक्षित पोताश्रय में वर्षा और तूफान के समय जहाज सरलता से खड़े रहते हैं। बड़े जहाज भी साधारणत: 8 मीटर गहरे भागों तक आते हैं। इस पोताश्रय में एक साथ 16 जहाज ठहर सकते हैं, किन्तु अक्टूबर-नवम्बर में जब बंगाल की खाड़ी में तूफान आने से समुद्र का जल लहर के रूप में ऊँचा उठ जाता है और हानि की सम्भावना रहती है, अत: जहाजों को ऐसे समय में पोताश्रय छोड़ना अनिवार्य हो जाता है।

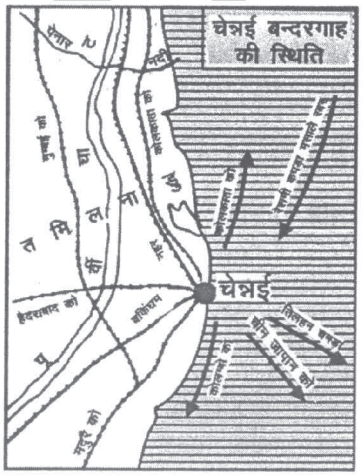

चित्र

चेन्नई का पृष्ठप्रदेश दक्षिणी प्रायद्वीप के पूर्वी और दक्षिणी राज्यों तक विस्तृत है। इसमें दक्षिणी आन्ध्र प्रदेश, सम्पूर्ण तमिलनाडु और कर्नाटक के पूर्वी भाग तक विस्तृत है। मुम्बई और कोलकाता की भाँति न तो यह इतना उपजाऊ और समृद्ध ही है और न ही इतना घना बसा है। इसके पृष्ठप्रदेश में व्यापारिक फसलों का उत्पादन अधिक किया जाता है— तिलहन, प्याज, लहसुन, तम्बाकू, रेंडी, मूँगफली, चाय, नारियल, कहवा, इमारती लकड़ी व चमड़ा और खालें भी यहाँ पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो जाती हैं। यह अपने पृष्ठप्रदेश में सड़कों और रेलमार्गों द्वारा अन्य राज्यों से जुड़ा है और चेन्नई नगर स्वयं एक औद्योगिक नगर है जहाँ सूती वस्त्र उद्योग, सीमेण्ट, सिगरेट, रेशमी वस्त्र, चमड़ा आदि उद्योग स्थापित हैं।

व्यापार—चेन्नई बन्दरगाह से निर्यात सूती और रेशमी कपड़े, चमड़ा, कहवा, हड्डी, खाद, रबड़, तम्बाकू, तिलहन, हल्दी, अभ्रक, मूँगफली का तेल, मैंगनीज, मछली, प्याज, वाहन, इंजीनियरिंग, सामान, वस्त्र इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, परिधान व कलात्मक सामग्री आदि वस्तुएँ निर्यात की जाती हैं। आयात व्यापार में कोयला, कोक, अनाज, मोटरें, रंग, पेट्रोलियम, कागज, चीनी, दवाइयाँ, धातुएँ मशीनें और रासायनिक पदार्थ मुख्य हैं। यह मुम्बई के पश्चात् दूसरा सर्वाधिक व्यापार वाला बन्दरगाह है। वर्तमान में यह मुम्बई के बराबर माल का व्यापार कर दूसरे स्थान पर है।

बन्दरगाह का विकास—1875 के पूर्व मद्रास (चेन्नई) का पोताश्रय के रूप में कोई महत्त्व नहीं था। 1976 में दो जलतोड़ दीवारें बनाकर समुद्र को घेरा गया। इसमें पूर्व की ओर 167 मीटर लम्बे मार्ग द्वारा इस बन्द भाग तक पहुँचा जा सकता है। 1905 में पुन: इसका पुनर्निर्माण किया गया। तब 4 घाट, 1 यात्रियों के छावन तथा तीन मंजिले गोदाम और लकड़ियाँ रखने के लिए भण्डार बनाए गए। 1931 में एक कोयला घाट, एक जैटी तथा 1936 में दूसरा घाट (South Quay-1) तैयार किया गया। इससे बन्दरगाह की व्यापार क्षमता 11 लाख टन की हो गयी। 1951 में यहाँ 9 घाट थे तथा व्यापार क्षमता 21.5 लाख टन थी। 1966 में यहाँ 518 मीटर × 15 मीटर जल क्षेत्र घेरकर 11 मीटर गहरा जवाहर डॉक बनाया गया जिसमें 6 घाट, छावन तथा नयी क्रेनें लगायी गयीं। तीन नये घाट (South Q-III) लौह-अयस्क के व्यापार के लिए, South Q-IV तथा South Q-V कोयले के व्यापार के लिए बनाए गए। इनसे घाटों की लम्बाई 1,302 मीटर से बढ़कर 2,987 मीटर हो गयी। रोयापुरम खाड़ी में समुद्र को

सुखाकर वहाँ का विकास कर 1974 तक वहाँ बड़े जहाजों व विशाल टैंकरों के लिए भागीरथी डॉक बनाया गया, जिसके अन्तर्गत एक घाट तेल के लिए तथा एक धातु अयस्कों के लिए था, इस डॉक द्वारा 81 हेक्टेयर जल क्षेत्र को रोका गया है। तेल वाले घाट में तेल भरने के लिए पाइप लाइनें बनायी गयी हैं। धातु वाले डॉक में यन्त्रों की सहायता से प्रतिवर्ष 80 लाख टन अयस्क भरा जाता है।

बन्दरगाह में 60 विद्युतचालित क्रेनें हैं, जिनकी क्षमता 18 से 50 टन की है। 40 घूमने वाली क्रेनें, 1 तैरने वाली क्रेन (150 टन भार उठाने की क्षमता वाली), 100 किलोमीटर लम्बा रेलमार्ग, 16 बड़े गोदाम, 20 छावन, 5 संग्राहक हौजें (जिनकी क्षमता 20,000 टन होती है जिसमें गोश्त, खाने का तेल, गन्ने की छोई आदि भरी जा सकें), मछली पकड़ने को पोताश्रय (6 मीटर गहरा) आदि का विकास किया गया है। इस प्रकार अब यह बन्दरगाह मुम्बई की भाँति बहुत ही धनी एवं सुविकसित हो गया है। इसे कृत्रिम पोताश्रय को भी भारत में प्राकृतिक पोताश्रय की भाँति ही सुविकसित किया गया है। यहाँ पर मुम्बई व कोलकाता की भाँति स्वतन्त्र प्राधिकरण या पोर्ट ट्रस्ट बन्दरगाह के विकास एवं कार्य प्रणाली को सम्भालता है।

चेन्नई बन्दरगाह पर निरन्तर बढ़ते भार को सम्भालने के दो स्तरीय परियोजनाएँ हाथ में ली गई हैं—

1. ₹ 100 करोड़ की लागत से कन्टेनर सेवा टर्मिनल का बहु-स्तरीय विकास वर्ष 2000 तक पूरा करना था; South Quay-III का विस्तार एवं नवीकरण; North व West Quay के बर्थ का विस्तार व नवीकरण (दोनों का खर्च ₹ 90 करोड़); बहुमंजिला ट्रांजिट शेड (₹ 18.4 करोड़) का निर्माण एवं ₹ 75 करोड़ की लागत से नया ड्रेजर खरीदना शामिल है।
2. चेन्नई के निकट ₹ 900 करोड़ की लागत से एन्नोर नामक स्थान पर नये बन्दरगाह के प्रथम चरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। यहाँ पर कुल चार बर्थ होंगी। इनमें से दो यहाँ के सुपर ताप विद्युत-गृह के कोयले की आपूर्ति हेतु होंगी दूसरे चरण का कार्य इसके बाद शुरू होगा।

प्र.4. भारत में प्रारम्भ से ही अन्तर्देशीय जलमार्गों के विकास की गति धीमी क्यों रही है? विस्तार से समझाइए।
Why has the speed of development of Inland waterways in India has been slow right from the beginning? Explain in detail.

उत्तर

राष्ट्रीय जलमार्ग
(National Water Ways)

देश की परिवहन प्रणाली में अन्तर्देशीय जल परिवहन को महत्त्वपूर्ण स्थान दिलाने, अन्तर्देशीय जलमार्ग एवं उसके विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखकर सरकार ने अब तक पाँच जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है तथा छठवाँ जलमार्ग प्रस्तावित है जिनका विवरण निम्न प्रकार है—

राष्ट्रीय जलमार्ग-1—प्रयागराज (इलाहाबाद) हल्दिया खण्ड, 1,620 किमी लम्बी गंगा नदी प्रणाली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-1 है। इस जलमार्ग पर प्रतिवर्ष 18 मिलियन टन माल ढोने की क्षमता होने का अनुमान है।

राष्ट्रीय जलमार्ग-2—संदया - धुबरी खण्ड, 891 किमी लम्बी ब्रह्मपुत्र नदी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या-2 है। यहाँ से प्रतिवर्ष औसतन 1.2 मिलियन टन माल ढोया जाता है।

राष्ट्रीय जलमार्ग-3—कोट्टापुरम-कोल्लाम खण्ड, 168 किमी पश्चिमी तटवर्ती नहर के साथ 23 किमी चम्पाकार नहर और 14 किमी उद्योगमण्डल नहर को राजमार्ग संख्या 3 (कुल 205 किमी.) घोषित किया गया है। इस जलमार्ग पर लगभग 4 मिलियन टन माल प्रतिवर्ष ढोया जाता है।

राष्ट्रीय जलमार्ग-4—इसमें तीन प्रखण्ड शामिल हैं जो कृष्णा नदी का बजीराबाद-विजयवाड़ा प्रखण्ड, गोदावरी नदी का भद्रचलम-राजमुन्द्री प्रखण्ड तथा कालूवेली टैंक एवं कैनालों का काकीनाडा-पुडुचेरी प्रखण्ड (1,078 किमी)।

राष्ट्रीय जलमार्ग-5—इसमें ब्राह्मणी नदी का तलचर-धमरा प्रखण्ड, पूर्वी तट कैनाल का जियोनरवली-चरबतिया प्रखण्ड, मताई नदी का चरबतिया-धमरा प्रखण्ड तथा महानदी डेल्टा नदियों का मंगलगढ़ी पारादीप प्रखण्ड (588 किमी) शामिल हैं।

प्रस्तावित राष्ट्रीय जलमार्ग-6—असम राज्य में भागा से लखीमपुर तट (121 किमी) बराक नदी।

उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में राष्ट्रव्यापी आईडब्ल्यूटी नेटवर्क विकसित करने की योजना बनाई है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत 106 अतिरिक्त अन्तर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग (N.W) घोषित किया गया है, जिससे देश में 111 जलमार्गों का राष्ट्रीय जलमार्ग नेटवर्क हो गया है। आर्थिक-तकनीकी अध्ययनों

के आधार पर वर्ष 2017-18 में 8 नए राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास किया जा रहा है। इनमें राष्ट्रीय जलमार्ग-16 (बराक नदी), गोवा में तीन राष्ट्रीय जलमार्ग: राष्ट्रीय जलमार्ग-27 (कुम्बरजुआ), राष्ट्रीय जलमार्ग-68 (मंडोली) एवं राष्ट्रीय जलमार्ग-111 (जुआरी); राष्ट्रीय जलमार्ग-86 (रूप नारायण नदी); राष्ट्रीय जलमार्ग-97 (सुन्दरवन); राष्ट्रीय जलमार्ग-9 (एलाप्पुझा-कोट्टम-अतीरामपुझा नहर) और राष्ट्रीय जलमार्ग-37 (गंडक नदी) शामिल हैं।

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI)—उपरोक्त जलमार्गों को नौ-संचालन के लिए विकसित कर रहा है। इस प्राधिकरण की स्थापना 27 अक्टूबर, 1986 को की गई थी। इसे राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास, रख-रखाव और नियमन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह प्राधिकरण राष्ट्रीय जलमार्गों पर अन्तर्देशीय जल परिवहन से सम्बन्धित बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए विभिन्न योजनाएँ चलाता है। इसका मुख्यालय नोएडा में तथा क्षेत्रीय कार्यालय पटना, कोलकाता, गुवाहाटी और कोच्चि में तथा शाखा कार्यालय प्रयागराज (इलाहाबाद), वाराणसी, भागलपुर, फरक्का व कोल्लम में हैं।

केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम, कोलकाता में स्थित एक सार्वजनिक प्रतिष्ठान है। यह निगम मुख्य रूप से गंगा-भागीरथी, हुगली, सुन्दरवन और ब्रह्मपुत्र नदियों में अन्तर्देशीय माल लाने-ले-जाने का काम करता है। यह निगम कोलकाता और पाण्डु (गुवाहाटी के निकट), कोलकाता और करीमगंज (असम), कोलकाता एवं बांग्लादेश तथा हल्दिया और पटना के बीच नियमित माल वहन सेवाएँ चलाता है।

वाराणसी में भारत का प्रथम मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन 12 नवम्बर, 2018 को किया गया और गंगा पर प्रथम कंटेनर पारेषण जिसे कोलकाता से भेजा गया था, बनारस मल्टी मॉडल टर्मिनल (एम०एम०टी०) पर उसी दिन प्राप्त किया गया था। एम०एम०टी० का मुख्य उद्देश्य अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ावा देना है क्योंकि जल मार्ग पर्यावरण के अनुकूल होते हैं।

अन्तर्देशीय जल परिवहन और व्यापार के बारे में संधि—अन्तर्देशीय जल परिवहन और व्यापार के बारे में भारत-बांग्लादेश सन्धि नवम्बर, 1972 से प्रभावी हुई। इसका नवीनीकरण समय-समय पर किया जाता रहा है। यह संधि भारत और बांग्लादेश के जहाजों को अन्तर्देशीय एवं पारगमन जलमार्गों से संचालन करने में मदद देती है। इसके अन्तर्गत स्वीकृत मार्ग—(i) कोलकाता-पाण्डु, (ii) कोलकाता-करीमगंज, (iii) राजशाही—धुलियाना और (iv) पाण्डु-करीमगंज हैं।

आन्तरिक जलमार्गों का अपूर्ण उपयोग

यद्यपि भारत में नदियाँ बहुत हैं, किन्तु फिर भी आन्तरिक आवागमन के लिए उनका पूर्ण उपयोग नहीं होता। इसका मुख्य कारण भूमि की रचना तथा अब तक सरकार का ध्यान केवल रेलमार्गों की उन्नति करना ही रहा है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित मुख्य कारण हैं—

1. भारत की अधिकांश नदियों में वर्षा ऋतु में बाढ़ें आती रहती हैं। इस समय नदी की धारा तेज होती है, अत: उसमें नावें खेना बड़ा ही कठिन होता है।
2. ग्रीष्म ऋतु में अधिकांश नदियाँ सूखी रहती हैं जो कुछ थोड़ा बहुत जल नदियों में मिलता है वह शीत और ग्रीष्म ऋतु के आरम्भ में यहाँ की विशाल नहर व्यवस्था को जल देने के लिए उपयोग में आ जाता है। सिंचाई के लिए जल को इस तरह उपयोग कर देने से नदियों में ग्रीष्म ऋतु में नौवहन हेतु जल नहीं रहता।
3. दक्षिण की नदियाँ पठारी भूमि पर बहने के कारण नावें चलाने के योग्य ही नहीं हैं, क्योंकि इनके मार्गों में प्रपात पड़ते हैं।
4. कभी-कभी नदियाँ अपने मार्ग भी बदला करती हैं इस कारण भी उनका उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे एक किनारे की ओर पतली धारा के रूप में बहने लगती हैं। अधिकतर नदियों के किनारे पर बहुत दूर तक मोटी मिट्टी जमती रहती है। इस कारण नदी के किनारे तक लदी हुई नावों या स्टीमरों का आना कठिन हो जाता है।
5. प्राय: सभी नदियाँ छिछले तथा बालूमय डेल्टाओं में गिरती हैं, अत: समुद्री किनारों से देश के भीतरी भागों में जहाज नहीं जा सकते।

आन्तरिक जलपरिवहन के विकास की आवश्यकता और उसकी सम्भावनाएँ

देश की विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था के लिए आन्तरिक जलमार्गों से प्राप्त होने वाले लाभ इस प्रकार हैं—

1. उत्तर-पूर्वी भारत में प्रतिवर्ष बाढ़ें आती हैं जिससे अनेक बार कई महीनों के लिए सड़क यातायात बन्द हो जाता है, ऐसे समय जलमार्ग लाभदायक हो सकते हैं।

TOUCH 'n PASS

2. लम्बी यात्रा के लिए तथा अधिक परिमाण में जाने वाले माल के लिए जल परिवहन रेल और सड़क दोनों से सस्ता पड़ता है। कोलकाता से असम को मशीनें, भारी नल एवं अन्य भारी उपकरण जलमार्गों से ही भेजे जा सकते हैं। इसी प्रकार असम से कोलकाता को चाय, जूट तथा चावल लाया जा सकता है।
3. सामान्यत: स्टीमरों की चाल मोटर और रेल दोनों से ही कम होती है, किन्तु एक साथ अधिक परिमाण में जाने वाले माल को नदी से भेजने में समय की बचत होती है, क्योंकि बहुत-सा माल एक साथ बिना मार्ग में रुके निर्दिष्ट स्थान पर पहुँच जाता है।
4. रेलें और सड़कें वर्तमान परिवहन वृद्धि के अनुरूप नहीं बढ़ायी जा सकतीं, क्योंकि उनके लिए पर्याप्त पूँजी उपलब्ध नहीं है जबकि जलमार्ग प्राकृतिक हैं जिनको परिवहन योग्य बनाने के लिए अपेक्षाकृत बहुत कम पूँजी की आवश्यकता पड़ती है। भारत में 1.6 किलोमीटर रेलमार्ग निर्माण में ₹ 70 से 90 लाख चाहिए जबकि 1.6 किलोमीटर साधारण सड़क 60,000 ₹ की पूँजी से (राष्ट्रीय राजपथ ₹ 25 से 40 लाख से बनता है), किन्तु नदी मार्ग के लिए विशेष पूँजी आवश्यक नहीं, क्योंकि यह प्रकृति की देन है।

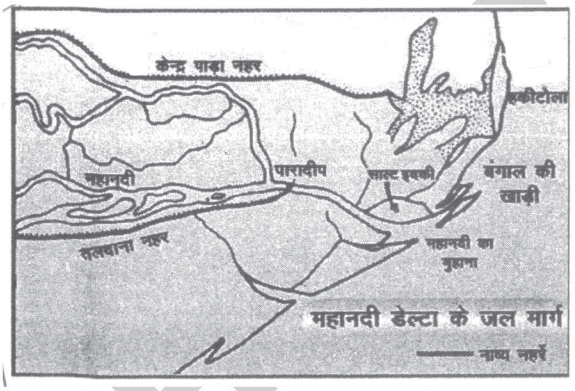

चित्र

5. युद्ध के समय अथवा अन्य राष्ट्रीय संकट के दिनों में जल परिवहन के लिए उतना भय नहीं जितना रेल अथवा सड़क के लिए। अत: आन्तरिक जल परिवहन का विकास राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से करना वांछनीय है।

भारत को प्रकृति-दत्त इतने अमूल्य जल परिवहन के आन्तरिक साधन मिले हैं जिसका अनुमान साधारणत: लगाना सरल नहीं है। अधिकांश भारतीय नदियाँ सदावाहिनी हैं जो सदा हिम से मुक्त रहती हैं। ये अधिकतर समतल भूमि पर होकर बहती हैं। अतएव हमें उतने जलावरोधों (Locks) की भी आवश्यकता नहीं पड़ती जितनी अन्य देशों में। यह सौभाग्य ही है कि उत्तरी भारत में गंगा और उसकी सहायक नदियाँ मिलकर एक विस्तृत जल-मार्ग बनाती हैं। इसी प्रकार मेघना और ब्रह्मपुत्र पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा की अनेक छोटी नदियाँ भी उपयोगी हैं। दक्षिणी भारत में महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ताप्ती, आदि नदियों की अब तक उपेक्षा की जाती रही है। इन सभी का राष्ट्रीय जलमार्गों की भाँति विकास कर हरिद्वार से एवं नंगल से कावेरी तक का जलमार्ग आपस में मिलाकर उसके महत्त्व को बढ़ाना चाहिए।

केन्द्रीय जल-शक्ति सिंचाई और नौका संचालन आयोग (CWINC)—भारत जल परिवहन के विकास में प्रयत्नशील है। इसका कार्य वर्तमान जलमार्गों को सुधारना, नए जलमार्गों की स्थापना करना और उनको नावें चल सकने के योग्य बनाना है। नदी जलमार्ग के विकास में एक बड़ी कठिनाई सिंचाई की नहरों के कारण उनमें जल की कमी हो जाती है। अत: जल संचय (water conservation) की उचित व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। यह व्यवस्था बड़ी खर्चीली होती है। केवल जल-परिवहन के लिए इतना खर्च करना सम्भव नहीं हो सकता। नदियों की बहुमुखी परियोजनाओं (सिंचाई, बिजली, बाढ़ नियन्त्रण, यातायात, आदि) के विकास करने से ही यह सम्भव हो सकता है। इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने बहुमुखी परियोजनाओं के विकास की नीति को स्वीकार किया है। नए बाँधों के निर्माण से बनने वाली झीलों को पड़ोस की नदियों के बाँधों तक नाव्य मार्ग बनाकर जोड़ने से भी इनका व्यावसायिक महत्त्व बढ़ सकता है एवं माल ढुलाई भी सस्ती व सुगम हो सकती है।

राष्ट्रीय यातायात सर्वेक्षण समिति ने आन्तरिक जलमार्गों की उन्नति के लिए निम्न सुझाव दिए—

1. कोलकाता बन्दरगाह पर आयतित खाद्यान्न का जो भाग उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए नियत किया जाए उसका 25 प्रतिशत जलमार्गों से ले जाया जाए।
2. कोयले और खनिज तेल से यातायात का एक अंश रेलों से हटाकर जलमार्गों के लिए सुरक्षित कर दिया जाए।
3. जलमार्गों के क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए जिससे उन्हें पर्याप्त यातायात उपलब्ध हो सके।

केन्द्रीय जलशक्ति, सिंचाई तथा नौका संचालन आयोग ने भारत के विभिन्न भागों में जलमार्गों की उन्नति करने की निम्न योजनाएँ बनायी हैं—

1. **पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी योजना** के अन्तर्गत रानीगंज की कोयले की खानों को एक नहर द्वारा हुगली नदी से मिलाया गया है। गंगा अवरोधक परियोजना के अन्तर्गत भी एक नहर बनाने की योजना है जो भागीरथी नदी से झांसीपुर के पास मिलेगी। गंगा और भागीरथी के बीच जलमार्ग, तिस्ता नदी परियोजना के अन्तर्गत उत्तरी तथा पूर्वी पश्चिम बंगाल और कोलकाता के बीच के जलमार्गों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। इस योजना के अनुसार, गंगा नदी पर राजमहल स्थान पर एक बाँध बनाया जाएगा। इसकी सहायता से गंगा नदी के जल को नहर द्वारा भागीरथी नदी की तलहटी में डाल दिया जाएगा। यह परियोजना निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनायी जा रही है—
   (i) बंगाल-बिहार की सीमा पर गंगा नदी के आर-पार एक बाँध बनाकर भागीरथी तथा पश्चिम बंगाल की अन्य नदियों में अधिक जल की व्यवस्था की जाएगी।
   (ii) कोलकाता और गंगा के बीच का जलमार्ग नाव्य बनाया जाएगा।
   (iii) हुगली नदी में अधिक जल आ जाने से उसमें नावें चलाई जा सकेंगी। इस परियोजना के पूरे होने पर भागीरथी में वर्षभर जल आ जाने से उसमें नावें चलाई जा सकेंगी। इस परियोजना के पूरे होने पर भागीरथी में वर्षभर जल भरा रहेगा, हुगली नदी के जल का खारापन जाता रहेगा और कोलकाता से बिहार और उत्तर प्रदेश तक सीधा जलमार्ग बन जाएगा तथा वर्तमान मार्ग 800 किलोमीटर से छोटा हो जाएगा।
2. असम की अन्य नदियों को नौवहन योग्य बनाना।
3. बिहार की गण्डक, सोन व कोसी के जलमार्गों का राष्ट्रीय जलमार्ग की भाँति विकास करना।
4. महानदी की निम्न घाटी में हीराकुड बाँध से 483 किलोमीटर तक का नाव्य क्षेत्र का विकास कार्य पूरा किया गया।
5. उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश-तेलंगाना व तमिलनाडु की तटीय नहरों को आपस में जोड़कर इन्हें दामोदर होकर हुगली तक मिलाना, इससे यह मार्ग सीधे असम तक नाव्य बन सकेगा।
6. कोलकाता से कटक और तमिलनाडु होकर वहाँ से तटीय भाग से कोच्चि तक का अन्तर्देशीय व तटीय (सम्मिलित) जलमार्ग कोच्चि से असम तक विकसित करना।

फरक्का अवरोधक बाँध (Farakka Barrage)

कोलकाता बन्दरगाह की नाव्य क्षमता बनाए रखने व मिट्टी नहीं जमने देने के लिए पश्चिम बंगाल के उत्तर में गंगा के मोड के निकट 2,245 मीटर लम्बा एवं 25 मीटर ऊँचा बाँध फरक्का बाँध बनाया गया है। यहाँ से 38.5 किलोमीटर लम्बी नहर से 45,000 क्यूसेक पानी हुगली नदी में बहाया जाता है। इस बाँध पर ₹ 160 करोड़ खर्च हुए हैं। इसके बनने से अब कोलकाता तक ज्वार के समय 10 मीटर डूब वाले जलयान भी पहुँच सकते हैं।

गंगा-कावेरी संगम योजना (Ganga-Cauvery Link)

देश की जलराशि का अधिकाधिक उपयोग करने हेतु गंगा-कावेरी संगम की एक भव्य योजना 1970 से ही विचाराधीन है, जिसके अनुसार गंगा नदी को कावेरी नदी से सम्बद्ध किया जाएगा। वर्षाकाल में गंगा में असीम जल रहता है। इस अतिरिक्त जल के 20 से 40 हजार क्यूसेक (cusec) जल नहर शृंखलाओं के माध्यम से कावेरी तक पहुँचाकर उसका उपयोग किया जा सकता है। पहले इस जल का उपयोग राजस्थान की मरुभूमि और कर्नाटक के पठार को उपजाऊ बनाने में किया जायेगा। गंगा के जल को कावेरी से भी आगे धुर दक्षिण में ताम्रपर्णी नदी तक ले जाया जा सकेगा।

योजना के अनुसार पटना और सोन नदी के बीच गंगा पर एक अवरोधक बनाया जाएगा जिसमें गंगा के जल को ऊँचा उठाकर दर्घा और मोरहर में डाला जा सके। इसके लिए सभी नदियों पर समुद्र तल से 8,300 मीटर ऊँचाई पर अवरोधक बनाने पड़ेंगे। इसके

बाद यह नहर मोरहर नदी और उत्तर कोयल नदी के बीच ऊँचे भू-भाग को पार करेगी। फिर यह नहर रिहन्द नदी बेसिन में प्रवेश करेगी। रिहन्द और उसकी सहायक नदियों पर बाँध बनाने पड़ेंगे, जिससे यह नहर रिहन्द और महानदी के बेसिन को अलग करने वाले भू-भाग को पार कर सके।

इसके बाद यह नहर नर्मदा और महानदी को अलग करने वाले ऊँचे भू-भाग से होकर निकलेगी। नर्मदा बेसिन को पार करते समय गंगा के कुछ जल को राजस्थान के उपयोग के लिए नर्मदा में छोड़ा जा सकेगा।

नर्मदा बेसिन को पार करने के बाद यह नहर नर्मदा और बैनगंगा नदी को अलग करने वाले भू-भाग में प्रवेश करेगी। इस भू-भाग को पार करने के बाद यह नहर बैनगंगा बेसिन से होकर जाएगी और फिर पेंच नदी को पार कर बैनगंगा और ताप्ती को अलग करने वाले भू-भाग में प्रवेश करेगी। फिर यह नहर बैनगंगा बेसिन होती हुई बैनगंगा और गोदावरी के बेसिनों को अलग करने वाले भू-भाग को पार करेगी, फिर इस नहर को पोचम्पाद बाँध के निकट गोदावरी की एक शाखा में गिराया जाएगा। यहाँ से फिर इस जल को नहर द्वारा पुणे की ओर ले जाने का विचार है, जिसमें इसे जायकवाड़ी बाँध के निकट गोदावरी में गिराया जा सके।

यह सम्भव है कि पोचम्पाद जलाशय से (जिसकी ऊँचाई समुद्र जल से 364 मीटर है) इस नहर को कृष्णा नदी के श्रीशैलम जलाशय की ओर मोड़ा जाए (जिसकी ऊँचाई समुद्र तल से 295 मीटर है)। इसे जोड़ने के लिए लगभग 270 मील लम्बी नहर बनानी पड़ेगी।

श्रीशैलम जलाशय पर बूस्टर मोटरों से पानी का स्तर 100 मीटर की ऊँचाई तक उठाकर चित्रावती नदी तक नहर से ले जाया जाएगा। गंगा के जल का पूरा-पूरा उपयोग करने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि चित्रावती नदी के साथ-साथ कुछ स्थानों पर बैराज बनाए जाऐ जिसमें इस जल को लगभग 700 मीटर की ऊँचाई तक उठाया जा सके। इससे कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्रों में अभी जल का जो अभाव है उसकी पूर्ति की जा सकती है। इससे पलार, पेनार आदि नदियों के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को भी लाभ पहुँचेगा। चित्रावती के इस ऊँची नहर को भूमि की प्राकृतिक ढलान के साथ कावेरी नदी पर बने मेटूर जलाशय में गिराया जा सकता है, जिसकी ऊँचाई समुद्र तल से 265 मीटर है। यहाँ इसके गिरने का उपयोग विद्युत शक्ति के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। इसके बाद भी यह सम्भव है कि इस गंगा जल को कावेरी नदी से और दक्षिण से जाकर भारत की अन्तिम महत्त्वपूर्ण नदी ताम्रपर्णी में गिराया जाए।

राजस्थान की मरुभूमि और कर्नाटक के पठार की सिंचाई की सम्भावनाओं को देखते हुए तथा इतनी दूरी तय करने में जो जल सूखेगा उसे ध्यान में रखते हुए, अनुमानत: गंगा-कावेरी नहर से सीमित क्षेत्र में ही भूमि की सिंचाई हो सकेगी।

इस सम्पूर्ण योजना पर प्रारम्भिक दिनों में ही आज से 28/30 वर्ष पूर्व इस पर ₹ 3,000 करोड़ खर्च होने की सम्भावना थी, आज यह खर्च 25 गुना बढ़ चुका है। अत: ऐसा भारी खर्च किसी योजना के बजट में क्या अकेला केन्द्र ही उठा पाऐगा? सभी राज्यों की स्वीकृति के अभाव, भारी बजट खर्च, विशिष्ट तकनीकी क्षमता के उपयोग के लिए निरन्तर उच्च दक्षता की आवश्यकता एवं लम्बे समय तक (10 से 12 वर्ष) खर्चा ही करते रहना आदि कारणों से यह सारी योजना-मात्र विद्वानों के चिन्तन तक ही सिकुड़ कर रह गई है।

प्र.5. सामुद्रिक जलमार्गों के विकास की दृष्टि से भारत की स्थिति उत्तम है। भारतीय उपमहाद्वीप के निकट से होकर जाने वाले सामुद्रिक मार्गों का वर्णन कीजिए।

India's location is pretty good from the viewpoint of development of oceanic waterways. Mention the oceanic waterways that pass close to the Indian subcontinent.

उत्तर

सामुद्रिक जलमार्ग
(Oceanic Waterways)

देश के विदेशी व्यापार में जहाजरानी उद्योग की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। देश के व्यापार की कुल मात्रा का 95 प्रतिशत और मूल्य की दृष्टि से 68 प्रतिशत का व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। भारत की लगभग 7,517 किमी० लम्बी तटीय रेखा के निकट 12 बड़े और लगभग 200 छोटे बन्दरगाह हैं। 6 बड़े बन्दरगाह—कोलकाता, पाराद्वीप, विशाखापत्तनम, कामराज (एन्नौर), चेन्नई और वी०ओ० चिंदम्बरनार पूर्व तट पर हैं। अन्य बड़े बन्दरगाह कोच्चि, न्यू मंगलुरू मोर मोरमुगाओ, मुम्बई, जवाहर लाल नेहरू बन्दरगाह (न्हावा शेवा, नवी मुम्बई) और दीन दयाल (पहले का कांडला) पश्चिम तट पर हैं। बड़े बन्दरगाह केन्द्र सरकार के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियन्त्रण में हैं। भारत के सभी बन्दरगाहों से होने वाले कुल परिवहन यातायात में से 57% बड़े और 43% छोटे

TOUCH 'n' PASS

बन्दरगाहों के द्वारा होता है। भारत हिन्द महासागर के सिरे पर स्थित है जिनमें से होकर पूर्व से पश्चिम को व्यापारिक मार्ग निकलते हैं। यहाँ से पूर्व और दक्षिण-पूर्व को सामुद्रिक मार्ग चीन, जापान, इण्डोनेशिया, मलेशिया और आस्ट्रेलिया को; दक्षिण और पश्चिम में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप तथा अफ्रीका को और दक्षिण में श्रीलंका को जाते हैं। इस प्रकार पश्चिम के औद्योगिक व सम्पन्न देशों को दक्षिण-पूर्व व पूर्वी एशिया के विकासशील एवं कृषि प्रधान देशों से मिलाने के लिए एक कड़ी का काम करता है।

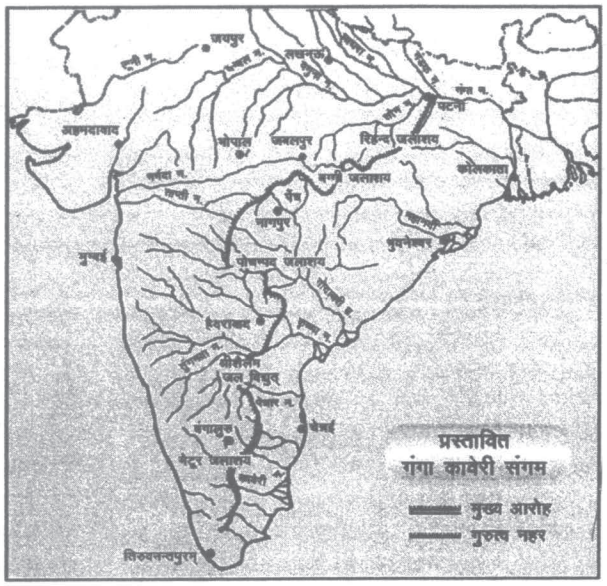

चित्र : गंगा-कावेरी संगम

भारत के बन्दरगाहों पर मिलने वाले प्रधान जलमार्ग निम्न हैं—

(क) **स्वेज जलमार्ग** (Suez Route)—इसके खुल जाने से भारत और यूरोप के बीच का व्यापार बहुत बढ़ गया है। इस मार्ग द्वारा भारत यूरोप को कच्चा माल और खाद्य पदार्थ भेजता है तथा बदले में तैयार माल और मशीनें मँगवाता है।

(ख) **उत्तमाशा अन्तरीप जलमार्ग** (Cape of Good Hope Route)—भारत को दक्षिण अफ्रीका और पश्चिम अफ्रीका से जोड़ता है। कभी-कभी दक्षिण अमेरिका जाने वाले जहाज भी इसी मार्ग से आते हैं। भारत इस मार्ग से अपने यहाँ रुई, शक्कर आदि मँगवाता है।

(ग) **सिंगापुर जलमार्ग** (Singapore Route)—इसका आवागमन की दृष्टि से स्वेजमार्ग के बाद दूसरा स्थान है। यह मार्ग भारत को चीन और जापान से जोड़ता है। इस मार्ग द्वारा भारत पश्चिमी संयुक्त राज्य कनाडा और न्यूजीलैण्ड के बीच भी व्यापार होता है। भारत में इस मार्ग से सूती-रेशमी कपड़ा, लोहा और इस्पात का सामान, मशीनें, चीनी के बर्तन, खिलौने, रासायनिक पदार्थ, कागज आदि आते हैं और बदले में रुई, लोहा, मैंगनीज, जूट, अभ्रक, आदि निर्यात होते हैं।

(घ) **सुदूर-पूर्व या आस्ट्रेलियन जलमार्ग** (Far Eastern or Australian Route) भी महत्त्वपूर्ण है। यह मार्ग भारत को आस्ट्रेलिया से जोड़ता है। इस मार्ग से भारत में कच्ची ऊन, घोड़े, फल, अयस्क, आदि वस्तुओं का आयात होता है और बदले में जूट, चाय, अलसी, परिधान व इन्जीनियरिंग सामान, आदि निर्यात होते हैं।

अभी तक इस मार्ग पर यूरोपीय कम्पनियों का ही आधिपत्य रहा। 1975 के पश्चात् धीरे-धीरे स्थिति बदलती जा रही है क्योंकि भारतीय व्यावसायिक जलयान भी अब बेहतर सेवा प्रदान करने लगे हैं।

इधर पिछले विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका, कनाडा, जापान, आस्ट्रेलिया तथा बाद में रूस, चीन व भारत में जलयानों का भी आना-जाना इन मार्गों से होकर बढ़ा है।

भारत के सामुद्रिक मार्ग विशेषत: कोलकाता, हल्दिया, विशाखापत्तनम, चेन्नई, कोच्चि, कांडला एवं मुम्बई के बन्दरगाहों से ही आरम्भ होते हैं। नीचे उपर्युक्त बन्दरगाहों से आरम्भ होने वाले प्रमुख मार्गों को बताया गया है—

TOUCH PASS

कोलकाता

1. कोलकाता–सिंगापुर–न्यूजीलैण्ड, 2. कोलकाता–कोलम्बो–पर्थ–एडीलेड–सिडनी, 3. कोलकाता–कोलम्बो–अदन–पोर्ट सईद, 4. कोलकाता–सिंगापुर–हांगकांग–शंघाई–टोक्यो, 5. कोलकाता–विशाखापत्तनम–चेन्नई–कोलम्बो–मुम्बई, 6. कोलकाता–रंगून- सिंगापुर, 7. कोलकाता–सिंगापुर–वटाविया–मनीला–तैपे।

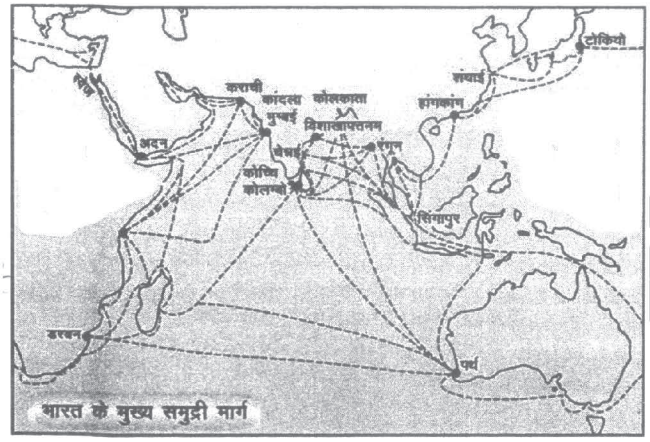

विशाखापत्तनम

1. विशाखापत्तनम–पारादीप–सिंगापुर–यावाता–टोक्यो, 2. विशाखापत्तनम–चेन्नई–कोलम्बो–डरबन, 3. विशाखापत्तनम–कोलम्बो–अदन–पोर्ट सईद व यूरोप, 4. विशाखापत्तनम–कोलकाता, 5. विशाखापत्तनम–चेन्नई–मुम्बई–कांधला।

चेन्नई

1. चेन्नई–कोलम्बो–मॉरीशस, 2. चेन्नई–कोलम्बो–अदन–फारस की खाड़ी–पोर्ट सईद, 3. चेन्नई–रंगून–सिंगापुर, 4. चेन्नई–विशाखापत्तनम–कोलकाता, 5. चेन्नई–मुम्बई–दीनदयाल।

कोच्चि

1. कोच्चि –मुम्बई–कराची–फारस की खाड़ी, 2. कोच्चि–मुम्बई–अदन–पोर्ट सईद–मार्सेलिस–लन्दन, 3. कोच्चि–कोलम्बो–कोलकाता–पर्थ–सिडनी– ऑकलैण्ड, 4. कोच्चि–कोलम्बो–चेन्नई–विशाखापत्तनम–कोलकाता।

मुम्बई

1. मुम्बई–कोलम्बो–पर्थ–एडीलेड–सिडनी–न्यूजीलैण्ड, 2. मुम्बई–मॉरीशस–मोम्बासा–डरबन–केपटाउन, 3. मुम्बई–कोलम्बो–सिंगापुर–हांगकांग–शंघाई, 4. मुम्बई–कराची–अदन–अबादान, 5. मुम्बई–पोर्ट सईद व यूरोप, 6. मुम्बई–पणजी–कोच्चि–तिरुवनन्तपुरम–कोलम्बो–चेन्नई–कोलकाता।

भारतीय जहाजरानी या पोतचालन का विकास
(Development of Indian Shipping)

भारतीय पोतचालन का विकास बहुत प्राचीन काल से ही हो गया था। जैसाकि प्राचीन ग्रन्थों से पता लगता है। भारतीय अच्छे नाविक भी रहे हैं। हाजी के अनुसार, "पुरानी दुनिया के महाद्वीपों के बीच में एक नगीने की तरह स्थित 6,049 किलोमीटर से भी अधिक समुद्रतटीय रेखा तथा अपनी भूमि की उर्वरा शक्ति के लिए प्रख्यात देश भारत प्रकृति की कृपा से ही समुद्री व्यापार करने में उपयुक्त है।" **डॉ० राधाकमल मुखर्जी** का कहना है कि भारतीय जहाजी बेड़े के विकास के फलस्वरूप ही भारतीय सभ्यता अपनी चरम सीमा तक पहुँच चुकी थी जिसका प्रभाव विदेशी सभ्यताओं पर बहुत अधिक पड़ा। पूरी तीस शताब्दियों तक भारत की स्थिति पुरानी दुनिया के मध्य में उसी प्रकार महत्त्वपूर्ण रही; जैसे—मानव शरीर में हृदय की। भारत विश्व के सामुद्रिक राष्ट्रों में एक अग्रणी राष्ट्र और महान् सामुद्रिक शक्ति बना रहा कम्बोडिया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो एवं जापान तक के सुदूर–पूर्वी देशों में उस समय भारतीय उपनिवेश थे। दक्षिणी चीन, मलाया, प्रायद्वीप अरब तथा ईरान के सभी मुख्य नगरों एवं अफ्रीका के सारे पूर्वी तट पर भारत की व्यापारिक बस्तियाँ थीं। भारत का व्यापारिक सम्पर्क एशिया से ही नहीं, यूरोप के साथ भी था। उस समय भारत

TOUCH 'n PASS

का प्रभाव इतना अधिक था कि देश के इतिहासकारों ने इसे **पूर्वी सागरों की रानी** (Mistress of The Eastern Seas) की उपाधि दी थी।

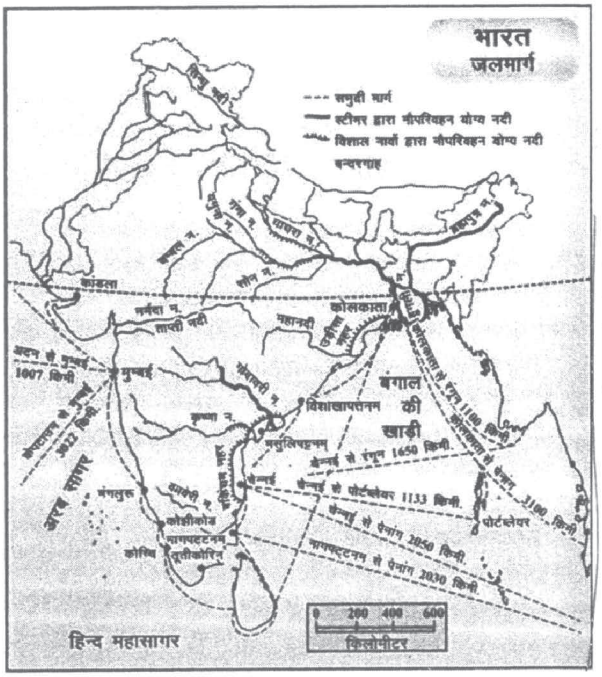

चित्र

परन्तु उत्तर मध्य युग में सत्रहवीं से उन्नीसवीं सदी के मध्य निरन्तर आन्तरिक कलह, केन्द्रीय सत्ता का लड़खड़ाना, यूरोपीय व्यापारियों द्वारा स्वदेशी व्यापार तन्त्र को नष्ट करने एवं नुकसान पहुँचाने जैसे उठाए गए कदम आदि के कारण भारत की जहाजरानी भी उन्नीसवीं सदी के अन्त तक विखण्डित होकर समाप्त हो गई। अंग्रेजों ने भी भारत के बने जहाजों, गोदियों व जहाज निर्माण केन्द्रों का निरन्तर बहिष्कार कर ब्रिटिश जहाजों को ही प्रश्रय दिया, अत: यह उद्योग भी बेसहारा बनकर धूमिल हो गया। फिर भी भारतीय समुद्री बेड़े की आवश्यकता प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् विशेष रूप से अनुभव की जाने लगी। इसी कारण सितम्बर 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध आरम्भ हुआ तो भारत सरकार को यह अनुभव हुआ कि भारतीय जहाजी बेड़े की कितनी आवश्यकता है? इस काल में बहुत से भारतीय जहाज सरकार ने युद्ध कार्य के लिए अपने अधिकार में ले लिए जिससे देश की रक्षा की जा सके। कई जहाज शत्रुओं द्वारा नष्ट भी कर दिए गए।

भारतीय नौ-परिवहन सांख्यिकी 2018 के अनुसार, भारत के पास 12.68 मिलियन की सकल पंजीकृत टन भार (Gross Registered Tonnage—GRT) के साथ 1,400 जहाजों (Vessels) का बेड़ा था। 31 दिसम्बर, 2019 को भारत के पास 12.74 मिलियन जी०आर०टी० के साथ 1,429 जहाजों का बेड़ा था।

देश की जहाजरानी नीति की यह विशेषता है कि इसमें देश को विदेशी व्यापार में आत्मनिर्भर बनाए रखने के साथ-साथ आयात-निर्यात व्यापार में पूंजी निवेशकों के हितों को भी सुरक्षित रखा गया है। देश के राष्ट्रीय ध्वजपोत कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिए परिवहन का अनिवार्य माध्यम है। विदेशी मुद्रा अर्जित करने में राष्ट्रीय जहाजरानी का महत्त्वपूर्ण योगदान है। स्पष्ट है कि परिवहन क्षेत्र में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में जहाजरानी की प्रमुख भूमिका है। देश का लगभग 95 प्रतिशत (मूल्य स्तर पर 68 प्रतिशत) व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। विकासशील देशों में भारत के पास व्यापारिक जहाजों का सबसे बड़ा बेड़ा है। भारतीय जहाजरानी क्षेत्र न केवल राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय माल की ढुलाई करता है, बल्कि माल लादने-उतारने की सेवाएँ, पोतों का निर्माण एवं रख-रखाव, माल अग्रेषण (Freight forwarding), प्रकाश स्तम्भ व्यवस्था, आदि सेवाएँ भी प्रदान करता है।

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपरान्त पोतचालन विकास के लिए निम्न कार्यक्रम अपनाये गये हैं—

भारत में जहाजों का निर्माण करना—भारत में जहाज बनाने का सर्वप्रथम कारखाना सिंधिया कम्पनी द्वारा 1947 में विशाखापत्तनम में स्थापित किया गया। सन् 1948 में इस कारखाने में प्रतिवर्ष दो जहाज बनने लगे, किन्तु सन् 1949 से ही निरन्तर घाटे में चलने के कारण सिंधिया कम्पनी से मार्च 1952 में भारत सरकार ने इसे अधिगृहीत कर हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कम्पनी की स्थापना की। यहाँ अब विस्तार एवं विकास के बाद प्रतिवर्ष 6 से 7 जहाज बनाये जाते हैं जिनका प्रत्येक का भार 21,000 टन से 50,000 टन होता है। अब तक यहाँ से 123 जहाजों का निर्माण किया जा चुका था। हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की सूची गोदी में 70,000 टन तक के जहाजों की मरम्मत की जा सकती है। दूसरा कारखाना कोच्चि में बनाया गया है जहाँ 1,10,000 टन के जहाज या टैंकर बनाये जाते हैं। यहाँ 1,25,000 टन तक के जहाजों या टैंकरों की मरम्मत की सुविधा है। यहाँ पहला जहाज 75,000 टन भार का बनाया जा चुका है। इस यार्ड ने देश के लिए बड़े आकार के 9 और 36 छोटे जहाजों का निर्माण किया है। इसके अतिरिक्त कोलकाता, मुम्बई एवं मोरमूगाओं में तटीय परिवहन के जलयान, स्टीमर व यन्त्रीकृत नावें भी बनायी जाती हैं।

देश में ही छोटे जहाज बनाने का कार्य मझगाँव डॉक, मुम्बई और गार्डन रीच, कोलकाता एवं मोरमूगाओ की गोदी में भी किया जाता है। यहाँ पर मछली पकड़ने के आधुनिक जहाज, स्टीमर, तटरक्षक नावें एवं विशेष फ्रिगेड (लियण्डर किस्म के) भी बनाए जाते हैं। पहले के जहाजों को नवीन तकनीक से सुसज्जित भी किया जाता है।

निम्न लघु पोताश्रयों के घाटों पर यन्त्र चालित व पालदार, नावें भी बनाई जाती हैं। इनमें मांडवी, अंजार, सलाया, जोद्या, जामनगर (बेदी), सिक्का, नवलखी, पोरबन्दर, वीरावल, भावनगर, नवसारी, बल्साड, बिलीमोरा, दामन, बेसीन, थाना, ऊड़न, पनवेल, अलीबाग, अजनवल, जयगढ़, रत्नागिरि, देवगढ़, मालवां, वेंगुरला, मोरमूगाओ, करवाड़, अंकोला, हनोवर, मंगलुरू, कासरगोड़, बेपुर, कोच्चि, तूतीकोरिन, मसुलिपट्टनम, राजमुन्द्री, काकीनाडा और कोलकाता।

केन्द्र सरकार ने दो बड़ी गोदियाँ व शिपयार्ड बनाने का निर्णय किया है। इसमें से एक पश्चिमी तट पर एवं एक पूर्वी तट पर स्थापित होंगे। 1994 से पूर्व इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित करने की योजना थी, किन्तु अब इन्हें निजी क्षेत्र में ही स्थापित करना तय किया गया।

कुल मिलाकर भारत में 27 शिपयार्ड हैं। इनमें से 6 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र, 2 राज्य सरकार के अधीन और 19 निजी क्षेत्र में हैं। सभी यार्डों की वर्तमान क्षमता लगभग 5,00,000 DWT है।

सार्वजनिक क्षेत्र की जहाजरानी कम्पनी भारतीय जहाजरानी निगम लि. (SCI) की स्थापना 2 अक्टूबर, 1961 को हुई थी। सकल पंजीकृत क्षमता (GRT) के सन्दर्भ में देश की कुल भारवहन क्षमता में भारतीय जहाजरानी की भागीदारी लगभग 36% की है। कम्पनी के वर्तमान बेड़े में 79 पोत हैं, जिनकी सकल पंजीकृत क्षमता लगभग 32.6 लाख टन है। कम्पनी की सेवाओं में लाइनर और यात्री सेवाएँ, बल्क कैरियर और टैंकर सेवाएँ तथा अपतटीय सेवाएँ एवं विशेषज्ञ सेवाएँ सम्मिलित हैं।

भारतीय जहाजरानी निगम (SCI) के मालवाहक जहाज लगभग सभी सामुद्रिक व्यापार मार्गों पर चलते हैं। निकटवर्ती भागों पर यात्री एवं माल सेवाएँ तथा समुद्र पार को तेल पोत सेवा एवं भारी माल सेवाएँ चलाई जाती हैं।

सामुद्रिक यात्रीपोत सेवाएँ (Liner Services) इन मार्गों पर चल रही हैं—

1. भारत-पूर्वीतट-बांग्लादेश-आस्ट्रेलिया, 2. भारत-पश्चिमी तट-आस्ट्रेलिया-न्यूजीलैण्ड, 3. भारत-पूर्वीतट-सुदूर पूर्व-जापान, 4. भारत-पाकिस्तान-इंग्लैण्ड-यूरोप-एड्रियाटिक सागर के बन्दरगाह, 5. भारत-पोलैण्ड, 6. भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका, 7. भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका-कनाडा, 8. भारत-संयुक्त अरब-गणराज्य, 9. भारत-पूर्वी तट-पश्चिमी एशिया, 10. भारत-पश्चिमी तट-पूर्वी अफ्रीका, 11. भारत-कालासागर, 12. भारत-जर्मनी, 13. भारत-मॉरीशसं, 14. भारत-पश्चिमी तट-पूर्वी अफ्रीका, 15. भारत-इंग्लैण्ड-यूरोप महाद्वीप के देश।

यात्री एवं माल मार्ग इस प्रकार हैं—

1. मुम्बई-पूर्वी अफ्रीका, 2. तमिलनाडु-मलेशिया-सिंगापुर, 3. भारत-अण्डमान निकोबार, 4. पश्चिमी तट-पाकिस्तान एवं अरब देश, 5. रामेश्वरम्-तलाईमनार (श्रीलंका), 6. भारत-लक्षद्वीप।

भारतीय जहाजरानी निगम (SCI) के टैंकर जहाजों का बड़ा भाग मध्य पूर्व के देशों से खनिज तेल आयात-कर बन्दरगाहों, टर्मिनल अथवा तट पर स्थित शोधनशाला तक लाता है। साथ ही कुछ छोटे टैंकर जहाज शोधनशालाओं से शुद्ध तेल तटीय भागों में होकर माँग के अनुसार देश के अन्य तटीय बन्दरगाहों तक ले जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों से भारतीय जहाजरानी निगम के शुद्ध लाभ में भी वृद्धि होती रही है।

TOUCH 'n' PASS

भारतीय जहाजरानी निगम निम्नलिखित क्षेत्रों में अग्रणी है—

(i) कच्चे तेल, पी०ओ०एल० और ड्राई बल्क कार्गो,
(ii) क्रायोजेनिक ऑपरेशन (एल०एन०जी० और एल०पी०जी०),
(iii) जहाजरानी क्षेत्र के संयुक्त उद्यम तथा अन्य भागीदारी उद्यम तथा
(iv) जहाजरानी परामर्श सेवा।

वर्तमान में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में 140 जहाजरानी कम्पनियाँ कार्य कर रही हैं।

निजी क्षेत्र की एक लाख या इससे अधिक GRT भार क्षमता वाली प्रमुख कम्पनियाँ निम्न हैं—

1. ग्रेट इण्डिया शिपिंग कम्पनी लिमिटेड,
2. एस्सार शिपिंग कम्पनी लिमिटेड,
3. चौगुले स्टीम शिप लिमिटेड,
4. वरुण शिपिंग कम्पनी लिमिटेड,
5. सन्मार शिपिंग,
6. सुरेन्द्र ओवरसीज लिमिटेड,
7. रेडियन्ट शिपिंग,
8. वेस्ट एशिया मारिटाइम लिमिटेड,
9. टोनाली शिपिंग कम्पनी,
10. साउथ इण्डियन शिपिंग कम्पनी लिमिटेड।

समुद्री एजेण्डा 2010-20

समुद्रीय क्षेत्र के समग्र विकास के लिए केन्द्रीय सरकार ने समुद्री एजेण्डा 2010-20 नामक नवीन नीति जारी की है, जिसकी रूपरेखा जहाजरानी मन्त्री जी०के० वासन ने जनवरी 2011 में प्रस्तुत की। ₹ 1,65,000 करोड़ के विनियोग वाली यह योजना भारतीय जहाजरानी क्षेत्र के अगले 10 वर्ष का विजन दस्तावेज है, जिसमें 2020 तक जहाजरानी तथा बन्दरगाह की क्षमता विकास के साथ-साथ उसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने की रूपरेखा का उल्लेख है। इस एजेण्डा के प्रमुख लक्ष्य निम्न प्रकार हैं—

समुद्री परिवहन में भारत की भागीदारी

1. अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री परिवहन में भारत में भागीदारी को वर्तमान 6% से बढ़कर 9% करना।
2. जहाज निर्माण के क्षेत्र में भारत की वर्तमान भागीदारी 1% से बढ़ाकर 5% करना।

बन्दरगाह के लक्ष्य

1. बन्दरगाहों की क्षमता बढ़ाकर 3,200 मीट्रिक टन करना, जिससे वह 2,500 मीट्रिक टन तक के कार्गो को संचालित कर सके।
2. भारतीय बन्दरगाहों की क्षमता बढ़ाकर इसे विश्व के सर्वश्रेष्ठ बन्दरगाहों के समकक्ष लाना।
3. तटीय समुद्री परिवहन को विकसित करके सड़क परिवहन का भार कम करना।
4. देश के पूर्वी और पश्चिमी तट पर एक-एक नए बन्दरगाह की स्थापना करना।
5. भारतीय बन्दरगाहों के मध्य सहयोग एवं प्रतियोगिता की नीति विकसित करना।
6. कार्गो संचालन एवं रख-रखाव को पूरी तरह यन्त्रीकृत करना।

अन्तर्देशीय जलमार्ग के लक्ष्य

1. राष्ट्रीय जलमार्ग 4 तथा 5 का विकास एवं राष्ट्रीय जलमार्ग 3 का विस्तार केरल तक करना।
2. एक नया भारतीय बन्दरगाह अधिनियम लाना।

अन्य लक्ष्य

1. उपयुक्त नीति के द्वारा भारतीय जहाजरानी की टनेज क्षमता में वृद्धि।
2. भारत एवं पड़ोसी देशों के मध्य नौका सेवाएँ प्रारम्भ करना।
3. कोचीन शिपयार्ड का विस्तार।
4. जहाज निर्माण उद्योग को आधारभूत दर्जा प्रदान करना।
5. खम्भात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी एवं अन्य उपयुक्त स्थानों पर पर्यटक नौका सेवाएँ प्रारम्भ करना।

TOUCH 'n' PASS

प्र.6. नागरिक उड्डयन या वायु परिवहन के विकास एवं वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए।
Describe the present state and development of Air Transport of Civil Aviation.

उत्तर

नागरिक उड्डयन
(Civil Aviation)

वर्तमान शताब्दी में जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ अपने को समन्वित करने का प्रयास कर रही है, आधारिक अवसंरचनाओं में सुधार एवं आधुनिकीकरण निर्णायक महत्त्व का है। वर्तमान में वायु परिवहन समृद्ध एवं विशिष्ट वर्ग के लोगों का परिवहन माध्यम होने के साथ-साथ व्यापार और पर्यटन के सतत विकास का भी माध्यम है। अत: वायु परिवहन उद्योग की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए वायु अड्डा जैसी अवसंरचनाओं का शीघ्र विकास अत्यावश्यक है। उल्लेखनीय है कि वायु परिवहन एक सघन-पूँजी आधारित उद्योग है, अत: इसके विकास हेतु सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का संयुक्त सहयोग जरूरी है। वायुपत्तन आर्थिक गतिविधियों के नाभिक हैं और इसलिए राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में इनका अत्यधिक महत्त्व है। वायुपत्तन रूपी अवसंरचना की गुणवत्ता जोकि सम्पूर्ण परिवहन मार्ग जाल का आवश्यक तत्व है की गुणवत्ता प्रत्यक्षत: देश की विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा क्षमता और विदेशी निवेश के प्रवाह को प्रभावित करती है। भारत में वायु परिवहन द्वारा होने वाले माल की ढुलाई देश से होने वाले कुल माल की मात्र 1% है, लेकिन मूल्य की दृष्टि से यह 1% मात्रा कुल निर्यात मूल्य का 35% है। इसी प्रकार देश में आने वाले कुल विदेशी पर्यटकों का 97% भाग वायु परिवहन से ही आता है। पर्यटन देश का दूसरा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा के विनिमय वाला उद्योग है।

देश के दूरस्थ, पर्वतीय और अगम्य स्थानों पर पहुँच के लिए वायु परिवहन ही सबसे त्वरित एवं एकमात्र माध्यम है। देश की पश्चिमी, उत्तरी और उत्तर-पूर्वी सीमाओं पर स्थित संवेदनशील क्षेत्रों में शीघ्रताशीघ्र पहुँच के लिए वायु परिवहन ही एकमात्र साधन है। देश में विभिन्न स्थानों पर पहुँच की गम्यता को बढ़ाने के लिए वायु पत्तनों का परिवहन के अन्य माध्यमों; जैसे—रेल एवं सड़क मार्गों द्वारा अच्छी तरह से जुड़े होने की आवश्यकता है।

वायु परिवहन का विकास (Development of Air Transport)

भारत में सर्वप्रथम हवाई उड़ान 1911 में आरम्भ हुई। 1932 में टाटा सन्स लिमिटेड के प्रयत्नों से दिल्ली व मुम्बई से कराँची और मद्रास के बीच विमान सेवा चालू की गयी। इसी को डाक ले जाने का कार्य भी सौंपा गया। 1933 में इण्डियन नेशनल एयरवेज कम्पनी बनायी गयी जिसके विमान कराची और लाहौर के बीच चलाए गए। 1935 में टाटा एयरवेज कम्पनी द्वारा मुम्बई-तिरुवनन्तपुरम् और 1937 में मुम्बई-दिल्ली मार्गों पर भी नवीन विमान सेवा चालू की गयी। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय इण्डियन नेशनल एयरवेज और टाटा एयरवेज के विमान 16 मार्गों पर चलाए गए। 1947 में भारत सरकार द्वारा विमान परिवहन जाँच समिति बनायी गयी। इसने अपने प्रतिवेदन में अनेक कठिनाइयों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया; जैसे—कम्पनियों की संख्या आवश्यकता से अधिक होना। लाइसेन्स में देरी होना, अधिक साज-सज्जा का होना, तेल के ऊँचे मूल्यों के कारण संचालन व्यय में वृद्धि होना आदि। इस समिति ने वायु परिवहन के राष्ट्रीयकरण किए जाने का सुझाव दिया। फलत: 1953 में विमान परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और सभी विमान कम्पनियों को दो नवनिर्मित निगमों के अधीन रखा गया। एक का उद्देश्य देश के भीतरी क्षेत्रों तथा दूसरे का विदेशों में वायु सेवाएँ देने का था। देश में नागर विमानन क्षेत्र की परिचालन कार्यप्रणाली के अन्तर्गत इण्डियन एयरलाइन्स, अलायन्स एयर इण्डिया (इण्डियन एयर लाइन्स की सहयोगी), निजी अनुसूचित एयरलाइन्स एवं एयर टैक्सी कम्पनियाँ घरेलू विमान सेवाएँ उपलब्ध कराती हैं, जबकि एयर इण्डिया अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाएँ प्रदान करती हैं। पवन-हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल और प्राकृतिक गैस निगम को समुद्र-तटवर्ती क्षेत्रों तथा दुर्गम एवं दूर-दराज के दुर्गम स्थानों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएँ प्रदान करता है। सरकार ने एयर कॉरपोरेशन अधिनियम, 1953 समाप्त करके इण्डियन एयरलाइंस और एयर इण्डिया का एकाधिकार समाप्त कर दिया है।

विमान सेवाओं के घरेलू नेटवर्क में इस समय चार मान्यता प्राप्त निजी विमान कम्पनियाँ कार्य कर रही हैं, जिससे यात्रियों को यात्रा के पर्याप्त विकल्प उपलब्ध हो गए हैं। इसके अतिरिक्त 37 एयर टैक्सी ऑपरेटर गैर-अधिसूचित विमान सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। विदेशी एयरलाइन्स की घरेलू सेवा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष या परोक्ष निवेश प्रतिबन्धित हैं। एयर टैक्सी सेवाओं से सम्बद्ध वर्तमान नीति में वायु मार्ग विस्तारण योजना का प्रावधान है, ताकि पूर्वोत्तर क्षेत्र, अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और जम्मू एवं कश्मीर के लिए अनुसूचित एयरलाइन्स के माध्यम से न्यूनतम संख्या में उड़ानें (सेवाएँ) सुनिश्चित की जा सकें।

वायु परिवहन की वर्तमान स्थिति (Present Condition of Air Transport)

वर्तमान में वायु परिवहन कम्पनियाँ सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र अर्थात् दोनों ही क्षेत्र में हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियाँ—सार्वजनिक क्षेत्र की 'इण्डियन एयरलाइन्स' एवं 'एयर इण्डिया' का अगस्त 2007 में विलय करके इसका नाम 'द नेशनल एविएशन कम्पनी ऑफ इण्डिया लि.' कर दिया गया, लेकिन नवम्बर 2010 में इसका नाम बदल कर एयर इण्डिया लि. कर दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य कम्पनियाँ हैं—इण्डियन चार्टर्स लि. (एयर इण्डिया एक्सप्रेस) और एलायंस एयर। वर्ष 2019-20 में एयर इण्डिया लिमिटेड के बेड़े में 127 जहाज, एयर इण्डिया एक्सप्रेस के बेड़े में 25 जहाज तथा एलायंस एयर के बेड़े में 19 जहाज थे। वर्ष 2019-20 में एयर इण्डिया लिमिटेड द्वारा 224.8 लाख, एयर इण्डिया एक्सप्रेस द्वारा 48.3 लाख तथा एलायंस एयर द्वारा 16.4 लाख यात्रियों को ले जाया गया।

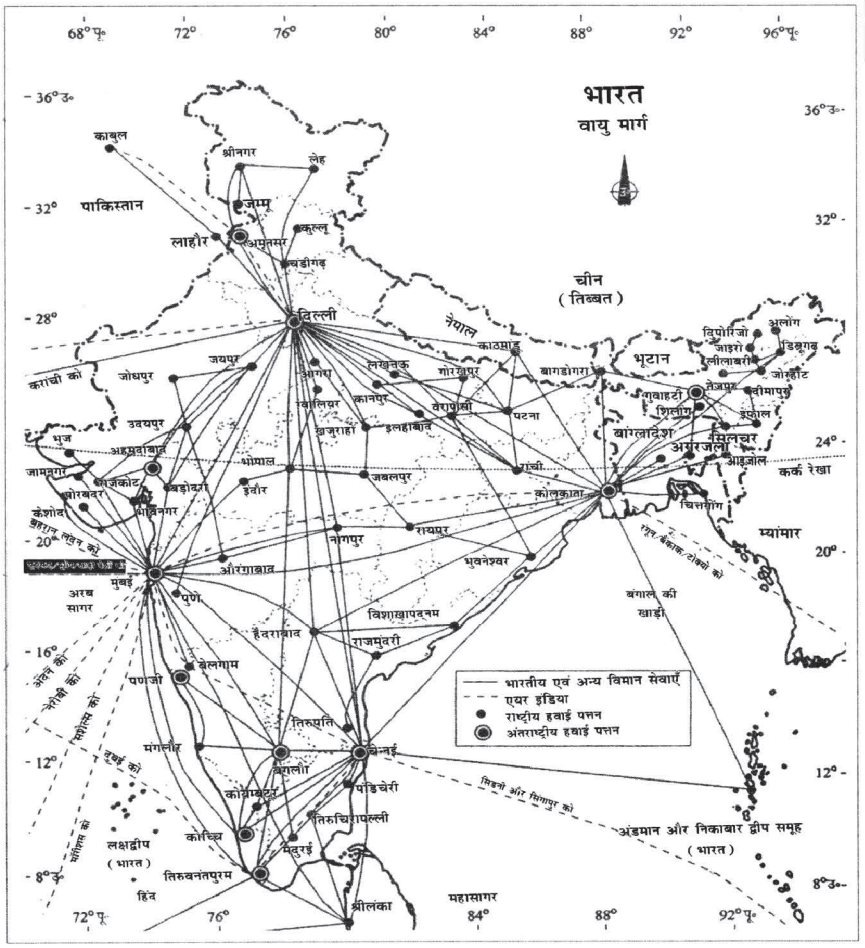

चित्र

निजी क्षेत्र की कम्पनियाँ—निजी क्षेत्र में 6 अनुसूचित एयर लाइन्स हैं। इनमें जेट एयरवेज (इण्डिया) लि., जेटलाइन्स एयरलाइन्स, पैरामाउंट एयरवेज प्रा. लिमिटेड, स्पाइस जेट, गो एयरलाइंस (इण्डिया) प्राइवेट लि., इण्टर ग्लोब एविएशन (इण्डिगो) उल्लेखनीय हैं। देश में तीन कार्गो एयरलाइन्स कार्गो सेवाएँ प्रदान कर रही है। ये हैं—ब्लू डार्ट एविएशन प्रा. लि., डकन कार्गो एण्ड एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स (प्रा.) लि. तथा मे. क्विकजेट।

वर्ष 2019-20 में अन्य निजी अनुसूचित एयर लाइन्स के बेड़े में 498 जहाज थे जिनके द्वारा 1349.8 लाख यात्रियों को ले जाया गया। वर्ष 2020-21 में देश में कुल हवाई जहाजों की संख्या 713 हो गई जबकि वर्ष 2019-20 में इनकी संख्या 669 थी।

निजी क्षेत्र का भारत का पहला हवाई अड्डा

केरल राज्य शासन द्वारा निजी क्षेत्र में भारत का पहला हवाई अड्डा कोच्चि में बनाया गया है। इसका निर्माण कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड नामक कम्पनी द्वारा किया गया है। यह हवाई अड्डा अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए भी सुविधाएँ उपलब्ध कराता है। हवाई अड्डे का प्रबन्धन कोचीन अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन लिमिटेड, जिसमें राज्य शासन की प्रमुख शेयरधारिता है, द्वारा किया जा रहा है।

हवाई अड्डे (Aerodromes)

प्राधिकरण के पास 125 हवाई अड्डे हैं (96 चालू और 29 बंद अवस्था में)। इनमें से 21 अन्तर्राष्ट्रीय (3 सिविल एन्क्लेव), 8 सीमा शुल्क हवाई अड्डे (4 सिविल एन्क्लेव), 77 घरेलू हवाई अड्डे और 19 घरेलू सिविल एन्क्लेव हैं। प्राधिकरण ने 60 हवाई अड्डों के उन्नयन और आधुनिकीकरण का काम पूरा कर लिया है। अब तक अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण (International Airport Authority of India— AAI) द्वारा इन हवाई अड्डों का प्रबन्ध किया जाता था, परन्तु 1 अप्रैल, 1995 को राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण (NAA) तथा अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण (IAAI) का विलय करके भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (Airport Authority of India—AAI) की स्थापना कर दिए जाने के बाद अब यह दायित्व भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा उठाया जाता है।

क्षेत्रीय सम्पर्क योजना–'उड़े देश का आम नागरिक'

क्षेत्रीय दृष्टि से महत्त्वपूर्ण शहरों में जनता के लिए विमान सेवाओं को सुलभ और सस्ता बनाने के लिए अक्टूबर, 2016 में 'क्षेत्रीय सम्पर्क योजना-उड़ान' (आर०सी०एस० -उड़ान) योजना शुरू की गई। इस योजना के दो उद्देश्य हैं— (i) सन्तुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना और (ii) विमान यात्रा को सस्ता करना। यह योजना 10 वर्ष तक लागू रहेगी। 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने आर०सी०एस० उड़ान के तहत केन्द्र सरकार के साथ समझौता किया है। निजी क्षेत्र की कई एयर लाइनें इस योजना में सक्रिय भागीदारी कर रही हैं।

इस योजना के तहत मौजूदा हवाई पट्टियों और हवाई अड्डों का पुनरुद्धार कर हवाई सम्पर्क सुविधा से वंचित क्षेत्रों में यह सुविधा पहुँचाई जाएगी।

ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट

बेंगलुरू अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा—सार्वजनिक-निजी भागीदारी के रूप में इसे बेंगलुरू के नजदीक देवनहल्ली में स्थापित किया गया। इस हवाई अड्डे को कुल आमदनी का 4 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार को देना होगा।

हैदराबाद अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (राजीव गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा)—इसकी स्थापना आन्ध्र प्रदेश सरकार ए०ए०आई०, जी०एम०आर० ग्रुप तथा मलेशिया एयरपोर्ट होल्डिंग्स बरेहाद (एम०ए०एच०बी) ने मिलकर शेयरधारकों के रूप में की है। ये संस्थाएँ मिलकर हवाई अड्डे का संचालन करेंगी। 30 वर्षों तक के इस समझौते को आगे 30 वर्षों के लिए और बढ़ाया जा सकता है। 23 मार्च, 2008 को यह हवाई अड्डा व्यावसायिक संचालन के लिए शुरू हो गया।

जीवन रेखा उड़ान—नगर विमानन मंत्रालय ने, मार्च 2020 में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में तेजी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 'जीवन रेखा उड़ान' सेवा प्रारम्भ की। इसके अन्तर्गत देश के सभी भागों तक व्यक्तिगत संरक्षात्मक साधन (पी०पी०ई०) तथा दवाओं इत्यादि की आपूर्ति भी की गई।

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्र.1. भारतमाला परियोजना किससे सम्बन्धित है?

(क) सड़कों के संयोजन (कनेक्टिविटी) को उन्नत करना
(ख) पत्तनों और रेलों को परस्पर जोड़ना
(ग) नदियों को परस्पर जोड़ना
(घ) प्रमुख शहरों को गैस पाइपलाइनों से जोड़ना

उत्तर (क) सड़कों के संयोजन (कनेक्टिविटी) को उन्नत करना

प्र.2. परिवहन के मुख्य साधन हैं–

(क) सड़क परिवहन (ख) वायु परिवहन (ग) जल परिवहन (घ) ये सभी

उत्तर (घ) ये सभी

TOUCH 'n' PASS

प्र.3. भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग है–
(क) 100% (ख) 80% (ग) 60% (घ) 40%
उत्तर (ख) 80%

प्र.4. किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई सर्वाधिक है?
(क) NH-1 (ख) NH-26 (ग) NH-44 (घ) NH-5
उत्तर (ग) NH-44

प्र.5. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 निम्नांकित में से किन-किन नगरों से होकर गुजरता है?
(क) नागपुर, हैदराबाद, विजयवाड़ा (ख) बेंगलुरु, चेन्नई, सलेम
(ग) नागपुर, हैदराबाद, सलेम (घ) भुवनेश्वर, हैदराबाद, नागपुर
उत्तर (ग) नागपुर, हैदराबाद, सलेम

प्र.6. राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई की दृष्टि से राज्यों का सही अवरोही क्रम है–
(क) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान (ख) राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश
(ग) राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश (घ) महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश
उत्तर (घ) महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश

प्र.7. निम्न में से किस राज्य में सड़कों की सघनता सबसे कम है?
(क) गुजरात (ख) उत्तर प्रदेश (ग) तमिलनाडु (घ) महाराष्ट्र
उत्तर (घ) महाराष्ट्र

प्र.8. निम्नलिखित में से कौन-सा राष्ट्रीय राजमार्ग अण्डमान एवं निकोबार में स्थित है?
(क) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-3 (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4
(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-6
उत्तर (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4

प्र.9. स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है?
(क) महानगरों को जोड़ने वाला रेलमार्ग (ख) प्रमुख वायु मार्ग
(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना (घ) स्वर्ण व्यापार का मार्ग
उत्तर (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना

प्र.10. भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है–
(क) दिल्ली-मुम्बई-चेन्नई-कोलकाता को (ख) दिल्ली-झाँसी-बेंगलुरु-कन्याकुमारी को
(ग) श्रीनगर-दिल्ली-कानपुर-कोलकाता को (घ) पोरबन्दर-बेंगलुरु-कोलकाता-कानपुर को
उत्तर (क) दिल्ली-मुम्बई-चेन्नई-कोलकाता को

प्र.11. किसी वस्तु या सेवा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण कहलाता है–
(क) संक्रमण (ख) परिवहन (ग) संचार (घ) प्रगमन
उत्तर (ख) परिवहन

प्र.12. 'जवाहर सुरंग' कहाँ से गुजरती है?
(क) पीरपंजाल (ख) बनिहाल (ग) बुर्जिल (घ) जोजिला
उत्तर (क) पीरपंजाल

प्र.13. रोहतांग सुरंग के निर्माण के विषय में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
(क) यह 5000 फीट की ऊँचाई पर स्थित है।
(ख) इससे लाहौल और स्फीति घाटी के साथ पूरे वर्ष सम्बन्ध (संलग्नता) उपलब्ध होगा।
(ग) यह सड़क सीमा सड़क संगठन द्वारा गनवाई गयी है।
(घ) इससे लेह-मनाली राजमार्ग (हाईवे) की लम्बाई लगभग 50 किमी कम हो जाएगी।
उत्तर (क) यह 5000 फीट की ऊँचाई पर स्थित है।

TOUCH 'n' PASS

प्र.14. भारत की पहली रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच कब चली?
(क) दिल्ली-आगरा के बीच 1854 ई० में (ख) मुम्बई-पूना के बीच 1853 ई० में
(ग) मुम्बई-थाणे के बीच 1853 ई० में (घ) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (क) दिल्ली-आगरा के बीच 1854 ई० में

प्र.15. भारत में पहली बार मेट्रो रेलवे का परिचालन कब शुरु हुआ?
(क) वर्ष 1981 (ख) वर्ष 1984 (ग) वर्ष 1989 (घ) वर्ष 1994
उत्तर (ख) वर्ष 1984

प्र.16. बड़ी लाइन या ब्रॉड गेज के अन्तर्गत रेल की दोनों पटरियों के बीच की चौड़ाई कितनी होती है?
(क) 1 मीटर (ख) 1.67 मीटर (ग) 1.97 मीटर (घ) 1.25 मीटर
उत्तर (ख) 1.67 मीटर

प्र.17. किस रेल खण्ड पर प्रथम सी०एन०जी० ट्रेन शुरू की गई?
(क) दिल्ली-आगरा खण्ड पर (ख) रोहतक-चण्डीगढ़ खण्ड पर
(ग) दिल्ली-चण्डीगढ़ खण्ड पर (घ) रेवाड़ी-रोहतक खण्ड पर
उत्तर (घ) रेवाड़ी-रोहतक खण्ड पर

प्र.18. निम्नलिखित राज्यों में से कौन-सा राज्य ऐसा पहला राज्य बना, जहाँ पी०पी०पी० मॉडल पर रेल ट्रैक बनाया गया?
(क) केरल (ख) गुजरात (ग) कर्नाटक (घ) महाराष्ट्र
उत्तर (ख) गुजरात

प्र.19. कोंकण रेलवे कॉरिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
(क) बेंगलुरु (ख) पंजिम (पणजी) (ग) नवी मुम्बई (घ) वास्को-डि-गामा
उत्तर (ग) नवी मुम्बई

प्र.20. निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है?
(क) कानपुर (ख) लखनऊ (ग) हाजीपुर (घ) न्यू जलपाईगुडी
उत्तर (ग) हाजीपुर

प्र.21. भारत में निम्न राज्यों में से कौन रेल सेवा से वंचित है?
(क) त्रिपुरा (ख) मेघालय (ग) अरुणाचल प्रदेश (घ) मिजोरम
उत्तर (ग) अरुणाचल प्रदेश

प्र.22. भारत में सबसे ऊँचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन ..... राज्य में स्थित है।
(क) उत्तर प्रदेश (ख) पश्चिम बंगाल (ग) सिक्किम (घ) जम्मू-कश्मीर
उत्तर (ख) पश्चिम बंगाल

प्र.23. भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है?
(क) गोरखपुर (ख) सोनपुर (ग) वाराणसी (घ) मुगलसराय
उत्तर (क) गोरखपुर

प्र.24. पहली UDAY (उत्कृष्ट डबल-डेकर एयर कण्डीशण्ड यात्री) एक्सप्रेस ट्रेन किन स्टेशनों के बीच चलती है?
(क) दिल्ली और कालका (ख) बेंगलुरु और कोयम्बटूर
(ग) चेन्नई और विशखापत्तनम (घ) चेन्नई और बेंगलुरु
उत्तर (ख) बेंगलुरु और कोयम्बटूर

प्र.25. स्वदेशी रूप से निर्मित ट्रेन 18 को भारतीय रेल द्वारा निम्नलिखित में से कौन-सा एक नाम दिया गया है?
(क) हमसफर एक्सप्रेस (ख) वन्दे भारत एक्सप्रेस
(ग) अनन्या एक्सप्रेस (घ) गतिमान एक्सप्रेस
उत्तर (ख) वन्दे भारत एक्सप्रेस

TOUCH 'n PASS

प्र.26. वन्दे भारत एक्सप्रेस दिल्ली को किस शहर से जोड़ती है?
(क) मुम्बई (ख) वाराणसी (ग) कोलकाता (घ) चेन्नई
उत्तर (ख) वाराणसी

प्र.27. निम्नलिखित में से कौन-सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है?
(क) उत्तर-पूर्व रेलवे—गोरखपुर (ख) दक्षिण-पूर्व रेलवे—भुवनेश्वर
(ग) पूर्वी रेलवे—कोलकाता (घ) दक्षिण-पूर्व मध्य रेलवे—बिलासपुर
उत्तर (ख) दक्षिण-पूर्व रेलवे—भुवनेश्वर

प्र.28. भारत की प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रारम्भ की गई थी–
(क) कराची एवं मुम्बई के बीच (ख) कराची एवं कोलकाता के बीच
(ग) कराची एवं दिल्ली के बीच (घ) कराची एवं चेन्नई के बीच
उत्तर (ग) कराची एवं दिल्ली के बीच

प्र.29. भारत में निजी हिस्सेदारी स्वामित्व वाला भारत का प्रथम विमानपत्तनम कौन-सा है?
(क) कोचीन (ख) गुवाहाटी (ग) नागपुर (घ) हैदराबाद
उत्तर (क) कोचीन

प्र.30. एयर इण्डिया की स्थापना की गई–
(क) जून, 1944 (ख) जून, 1948 (ग) जून, 1951 (घ) जून, 1954
उत्तर (ख) जून, 1948

प्र.31. पाक्योंग विमानपत्तनम कहाँ स्थित है?
(क) सिक्किम (ख) जम्मू-कश्मीर (ग) अरुणाचल प्रदेश (घ) मिजोरम
उत्तर (क) सिक्किम

प्र.32. निम्नलिखित में से कौन-सा राष्ट्रीय जलमार्ग नम्बर 1 है?
(क) गोदावरी-कृष्ण बेसिन जलमार्ग (ख) महानदी-ब्राह्मणी नदी जलमार्ग
(ग) ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग (घ) गंगा-भागीरथी-हुगली नदी जलमार्ग
उत्तर (घ) गंगा-भागीरथी-हुगली नदी जलमार्ग

प्र.33. गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है?
(क) इलाहाबाद से हल्दिया तक (ख) हरिद्वार से कानुपर तक
(ग) कानपुर से इलाहाबाद तक (घ) नरौरा से पटना तक
उत्तर (क) इलाहाबाद से हल्दिया तक

प्र.34. केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ है?
(क) पटना (ख) नोएडा (ग) कोलकाता (घ) पणजी
उत्तर (ग) कोलकाता

प्र.35. सेतुसमुद्रम परियोजना, जिन्हें जोड़ती है, वे हैं–
(क) पाक खाड़ी और पाक जलसन्धि (ख) पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी
(ग) कुमारी अन्तरीप और मन्नार की खाड़ी (घ) मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी
उत्तर (घ) मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी

प्र.36. भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन है–
(क) काण्डला एवं हल्दिया (ख) हल्दिया एवं कोच्चि
(ग) पाराद्वीप एवं काण्डला (घ) पाराद्वीप एवं हल्दिया
उत्तर (घ) पाराद्वीप एवं हल्दिया

TOUCH 'n' PASS

प्र.37. निम्नलिखित में से कौन-सी एक पाराद्वीप पत्तन से होने वाले निर्यात प्रमुख मद है?
(क) चावल (ख) चाय (ग) मछली (घ) लौह-अयस्क
उत्तर (घ) लौह-अयस्क

प्र.38. निम्नलिखित में से कौन-सा बन्दरगाह पोर्ट ऑफ कोल की सुविधा उपलब्ध कराता है?
(क) पोर्ट ब्लेयर (ख) तूतीकोरिन (ग) पाराद्वीप (घ) विशाखापत्तनम
उत्तर (क) पोर्ट ब्लेयर

प्र.39. भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बन्दरगाह है?
(क) कोलकाता में (ख) मद्रास में (ग) तूतीकोरिन में (घ) विशाखापत्तनम में
उत्तर (घ) विशाखापत्तनम में

प्र.40. कोलकाता किस प्रकार के बन्दरगाह का उदाहरण है?
(क) नौसैनिक (ख) तैल (ग) नदीय (घ) प्राकृतिक
उत्तर (ग) नदीय

प्र.41. काण्डला पत्तन (पोर्ट) कहाँ पर स्थित है?
(क) खम्भात की खाड़ी (ख) कोरी क्रीक (सँकरी खाड़ी)
(ग) कच्छ की खाड़ी (घ) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (क) खम्भात की खाड़ी

प्र.42. दीनदयाल बन्दरगाह (पोर्ट) कहाँ अवस्थित है?
(क) केरल (ख) गुजरात (ग) महाराष्ट्र (घ) गोवा
उत्तर (ख) गुजरात

प्र.43. निम्नलिखित में से भारत का कौन-सा सबसे बड़ा कण्टेनर बन्दरगाह है?
(क) जवाहरलाल नेहरू पोर्ट (ख) कोच्चि
(ग) मुम्बई (घ) विशाखापत्तनम
उत्तर (क) जवाहरलाल नेहरू पोर्ट

प्र.44. निम्नलिखित में से किस बन्दरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है?
(क) मुम्बई (ख) कोलकाता (ग) कोच्चि (घ) काण्डला
उत्तर (क) मुम्बई

प्र.45. भारत के निम्नलिखित बन्दरगाहों में से कौन-सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है?
(क) हल्दिया (ख) मुम्बई (ग) पाराद्वीप (घ) विशाखापत्तनम
उत्तर (ग) पाराद्वीप

प्र.46. भारत में निम्नलिखित में से कहाँ सबसे बड़ा पोत-प्रांगण (शिपयार्ड) है?
(क) कोलकाता (ख) कोच्चि (कोचीन)
(ग) मुम्बई (घ) विशाखापत्तनम
उत्तर (ख) कोच्चि (कोचीन)

प्र.47. भारत में रेडियो का प्रसारण रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा कब प्रारम्भ किया गया था?
(क) वर्ष 1920 में (ख) वर्ष 1923 में (ग) वर्ष 1935 में (घ) वर्ष 1940 में
उत्तर (ख) वर्ष 1923 में

प्र.48. ऑल इण्डिया रेडियो का नाम बदलकर कब आकाशवाणी किया गया?
(क) वर्ष 1952 (ख) वर्ष 1955 (ग) वर्ष 1957 (घ) वर्ष 1959
उत्तर (ख) वर्ष 1955

TOUCH 'n PASS

प्र.49. भारत में टेलीविजन सेवा कब प्रारम्भ हुई?
(क) वर्ष 1955 (ख) वर्ष 1959 (ग) वर्ष 1962 (घ) वर्ष 1966
उत्तर (ख) वर्ष 1959

प्र.50. दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई (TRAI) का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
(क) गुजरात (ख) नई दिल्ली (ग) लखनऊ (घ) पुणे
उत्तर (ख) नई दिल्ली

प्र.51. निम्नलिखित में से किस नदी घाटी को 'भारत का रूर' कहते हैं?
(क) गोदावरी घाटी (ख) महानदी घाटी (ग) दामोदर घाटी (घ) नर्मदा घाटी
उत्तर (ख) महानदी घाटी

प्र.52. निम्नलिखित में से कौन-सी जल परिवहन नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है?
(क) स्वेज नहर (ख) पनामा नहर (ग) कील नहर (घ) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (ग) कील नहर

प्र.53. आन्तरिक जल यातायात हेतु सबसे उपयुक्त एवं महत्त्वपूर्ण नदी है–
(क) राइन नदी (ख) कांगो नदी (ग) मिसिसिमी नदी (घ) हवांगहो नदी
उत्तर (क) राइन नदी

प्र.54. संसार की सबसे महत्त्वपूर्ण जहाजी नहर कौन-सी है?
(क) स्वेज नहर (ख) पनामा नहर (ग) कील नहर (घ) सु नहर
उत्तर (क) स्वेज नहर

प्र.55. विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन-सा है?
(क) उत्तरी अटलांटिक महासागर (ख) हिंद महासागर
(ग) प्रशांत महासागर (घ) दक्षिण अटलांटिक महासागर
उत्तर (क) उत्तरी अटलांटिक महासागर

प्र.56. ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग की कुल लम्बाई कितनी है?
(क) 8115 किमी (ख) 11174 किमी (ग) 9332 किमी (घ) 7050 किमी
उत्तर (ग) 9332 किमी

प्र.57. विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली?
(क) 1853 (ख) 1854 (ग) 1834 (घ) 1825
उत्तर (घ) 1825

प्र.58. संसार में रेलों का सबसे बड़ा जाल वाला देश कौन-सा है?
(क) भारत (ख) चीन (ग) यूएसए (घ) रूस
उत्तर (ग) यूएसए

प्र.59. विश्व की सबसे लम्बी सड़क मार्ग कौन-सी है?
(क) ट्रांस कनाडियन महामार्ग (ख) अलास्का महामार्ग
(ग) पैन अमेरिकन महामार्ग (घ) स्टुअर्ट महामार्ग
उत्तर (ग) पैन अमेरिकन महामार्ग

प्र.60. विश्व में सड़क मार्ग की लम्बाई की दृष्टि से प्रथम-3 देशों का अवरोही क्रम है–
(क) USA, ब्राजील, भारत (ख) USA, भारत, चीन
(ग) USA, रूस, भारत (घ) USA, जापान, भारत
उत्तर (ख) USA, भारत, चीन ❑

TOUCH 'n' PASS

UNIT-VII

डब्ल्यू०टी०ओ० तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार
W.T.O. and International Trade

खण्ड-अ अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आप क्या समझते हैं?

What do you understand by International Trade?

उत्तर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं या क्षेत्रों के आर-पार पूँजी, माल और सेवाओं का आदान-प्रदान है। अधिकांश देशों में यह सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के महत्त्वपूर्ण अंश का प्रतिनिधित्व करता है।

प्र.2. अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के कारण बताइए।

Give the causes of International Trade.

उत्तर अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय का आधारभूत कारण है कि देश अपनी आवश्यकता की वस्तुओं का भली प्रकार से एवं सस्ते मूल्य पर उत्पादन नहीं कर सकते। इसका कारण उनके बीच प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण अथवा उनकी उत्पादकता में अंतर हो सकता है। वैसे विभिन्न राष्ट्रों में श्रम की उत्पादकता एवं उत्पादन लागत में भिन्नता विभिन्न सामाजिक-आर्थिक, भौगोलिक एवं राजनैतिक कारणों से होती है। इन्हीं कारणों से यह कोई असाधारण बात नहीं है कि कोई एक देश अन्य देशों की तुलना में श्रेष्ठ गुणवत्ता वाली वस्तुओं एवं कम लागत पर उत्पादन की स्थिति में हो।

प्र.3. आर्थिक विकास के निर्धारक तत्त्वों को संक्षेप में लिखिए।

Write the elements of Economic Development in short.

उत्तर किसी समाज या देश के आर्थिक विकास का स्तर अनेक कारकों द्वारा निर्धारित होता है, जिन्हें दो वर्गों में रखा जा सकता है—

1. **आर्थिक कारक**—प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक संरचना, उत्पादकता, कच्चे माल, उपभोक्ता वस्तुएँ।
2. **सामाजिक कारक**—शिक्षा एवं साक्षरता, स्वास्थ्य एवं जन कल्याण।
3. **जनांकिकीय कारक**—शिशु मर्त्युता दर, प्राकृतिक वृद्धि दर, आयु संरचना, रोगों के वितरण एवं नियंत्रण का स्तर।
4. **पर्यावरणीय कारक**—संसाधन सम्पन्नता।

प्र.4. व्यापारिक नीति के सिद्धान्त को संक्षेप में लिखिए।

Write the theory of Trade Policy in short.

उत्तर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित सरकारी नीति को व्यापारिक नीति कहते हैं। एक देश या तो स्वतन्त्र व्यापार नीति या संरक्षण नीति को अपनाता है। स्वतन्त्र व्यापार नीति से अभिप्राय उस नीति से है जिसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। निर्यातकों तथा आयातकों को अनुमति होती है कि वे बिना किसी प्रकार के निर्यात या आयात शुल्क के व्यापार करने में स्वतन्त्र होते हैं।

इसके विपरीत संरक्षणवाद या संरक्षणवादी नीति से अभिप्राय स्थानीय उत्पादकों को (विदेशी प्रतियोगिता से) संरक्षण देने की नीति है। यह संरक्षण शुल्क लगाकर या गैर-कर रोके लगाकर प्रदान किया जाता है। गैर-कर रोको में कोटा निर्धारित करना या सीमा शुल्क कार्य प्रणाली को जान-बूझकर जटिल बनाना जिससे आयातों को निरुत्साहित किया जा सके।

TOUCH 'n PASS

प्र.5. स्वतन्त्र व्यापार के दो लाभ बताइए।
What are the advantages of Free Trade?

उत्तर 1. **उत्पादन का अधिकतमीकरण**—तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत के अनुसार, प्रत्येक देश उस वस्तु के उत्पादन में विशेषता प्राप्त करेगा। जिसके लिए वह अधिक उपर्युक्त है या जिसके उत्पादन में उसे तुलनात्मक अधिक लाभ प्राप्त होता है। इसके फलस्वरूप संसार में विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन अधिकतम होगा।

2. **संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग**—क्योंकि उत्पादन तुलनात्मक लागत लाभ के सिद्धान्त के अनुसार किया जाता है, इसलिए संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग किया जाता है प्रत्येक देश आगतों के न्यूनतम लागत संयोग द्वारा वस्तुओं का उत्पादन करता है।

प्र.6. स्वतन्त्र व्यापार के कोई दो नुकसान बताइए।
Mention any two disadvantages of Free Trade.

उत्तर 1. स्वतन्त्र व्यापार के लिए अहस्तक्षेप की नीति तथा पूर्ण प्रतियोगी कीमत संयन्त्र की प्रक्रिया का क्रियाशील होना आवश्यक है। किन्तु ये शर्तें वर्तमान समय के संसार में नहीं पायी जाती हैं। एकाधिकार क्रेताधिकार, कार्टेल, अपूर्ण श्रम बाज़ार तथा सीमा शुल्कों के प्रचलन में होने के कारण स्वतन्त्र व्यापार को त्यागना पड़ा था।

2. स्वतन्त्र व्यापार की नीति के अन्तर्गत कुछ उद्योगों को तुलनात्मक लाभ प्राप्त होते हैं तथा अन्य उद्योग विकसित नहीं होते। अत: इस कारण अर्थव्यवस्था का एक-पक्षीय विकास ही हो पाता है।

खण्ड-ब लघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख व्यापारिक संगठन का उल्लेख कीजिए।
Explain the Major Trade Blocks of International Trade.

उत्तर औद्योगिक क्रान्ति के बाद 19वीं शताब्दी में यह मान्यता थी कि मुक्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार था यह दोनों ही पक्षों के लिये लाभदायक था। यह मूल्य के श्रम सिद्धान्त पर आधारित था। किन्तु आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तुलनात्मक लाभ के सिद्धान्त पर आधारित है। जिसे डेविस रिकार्डो (1912) ने प्रस्तुत किया था।

प्रमुख व्यापारिक संगठन (गुट)
(Major Trade Blocks)

1. **यूरोपीय संघ** (EU)—दिसम्बर, 1991 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के तत्कालीन 12 राष्ट्रों ने 'मास्ट्रिश्च सन्धि' के तहत एक नये एकीकृत 'यूरोपीय संघ' को जन्म दिया। 2004 में इसकी सदस्यता 15 से बढ़कर 25 हो गयी। 2007-08 में इसकी सदस्य संख्या 27 हो गयी। इनमें से 17 देशों की संयुक्त मुद्रा 'यूरो' है।
2. **पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक** (OPEC)—यह संगठन 1960 में पेट्रोलियम के मूल्य सम्बन्धी नीतियों को लागू करने के लिये पेट्रोलियम उत्पादक देशों द्वारा बनाया गया था। इसके 13 सदस्य हैं-अल्जीरिया, गैबौन, अंगोला, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सउदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात तथा वेनेजुएला। इसका मुख्यालय वियना (आस्ट्रिया) में हैं।
3. **दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ आसियान** (ASEAN)—अगस्त 1967 में इसका औपचारिक गठन बैंकाक की घोषणा के द्वारा किया गया। इसके मूल सदस्य इण्डोनेशिया, फिलीपीन्स, मलेशिया, सिंगापुर, तथा थाईलैण्ड थे। बाद में ब्रूनेई, वियतनाम, लाओस, म्यामार तथा कम्बोडिया इसमें सम्मिलित हो गये। इसके 10 सदस्य हैं। इसका केन्द्रीय सचिवालय जकार्ता में है। (भारत भी इसका सह-सदस्य है)।
4. **दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन-सार्क** (SAARC)—इसकी स्थापना दिसम्बर 1987 में भारत, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान तथा नेपाल के द्वारा की गयी। इसका मुख्यालय काठमाण्डू (नेपाल) में है। 1993 में इन देशों ने SAPTA का गठन किया। अफगानिस्तान इसका 8वाँ सदस्य है, जो 2007 में शामिल हुआ।
5. **उत्तरी अमेरिका मुख्य व्यापार संघ** (NAFTA)—इसकी स्थापना 1988 में संयुक्त राज्य एवं कनाडा द्वारा की गयी, 1994 में मैक्सिको भी इसमें सम्मिलित हो गया।

TOUCH 'n' PASS

6. **लैटिन अमेरिकी मुक्त व्यापार संघ** (LAFTA)—इसकी स्थापना 1960 में पेरू, पराग्वे, अर्जेन्टिना, मैक्सिको, ब्राजील तथा चिली द्वारा की गयी। ये सभी विकासशील देश में है।
7. **एशिया प्रशान्त आर्थिक सहयोग** (APEC)—इसकी स्थापना 1989 में की गयी। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। इसके 21 सदस्य हैं—आस्ट्रेलिया, ब्रूनेई, कनाडा, चिली, चीन, हांगकांग, इण्डोनेशिया, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैण्ड, पापुआ न्यूगिनी, पेरू, फिलीपीन्स, रूस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान, थाईलैण्ड संयुक्त राज्य एवं वियतनाम।

प्र.2. आर्थिक विकास के सिद्धान्तों का उल्लेख कीजिए।
Explain the principles of Economic Development.

उत्तर

आर्थिक विकास के सिद्धान्त
(Principles of Economic Development)

एडम स्मिथ (1976) ने सर्वप्रथम यह मत प्रकट किया था कि आर्थिक प्रगति के लिए पूँजी-संचय तथा श्रम विभाजन आवश्यक दशाएँ हैं। रिकार्डो (1912) भी इसी शास्त्रीय सिद्धान्त के समर्थक थे, किन्तु उन्होंने पूँजी के वितरण तथा संचय से सम्बन्धित सिद्धान्त प्रस्तुत किया। किन्तु शास्त्रीय सिद्धान्त में आर्थिक विकास के स्थानीय भिन्नताओं का कोई स्थान नहीं था। नवशास्त्रीय सिद्धान्तों में भूमि (प्राकृतिक संसाधनों) के बजाय प्राविधिकी पर अधिक बल दिया गया। शूम्पीटर (1911) इसके प्रणेता थे। 1950 तथा 1960 के दशकों में अनेक सिद्धान्त प्रस्तुत किये गये जिन्हें दो वर्गों में रखा जाता है— 1. आधुनिकीकरण सिद्धान्त तथा 2. पराश्रितता सिद्धान्त। लेविस (1954 रोस्तोव 1960), नर्क्से, हिर्शमान आदि ने विकास के विभिन्न मॉडल प्रस्तुत किये। जापानी अर्थशास्त्री अकामात्सु कानामें ने एक अन्य आधुनिकीकरण सिद्धान्त प्रस्तुत किया।

पराश्रितता सिद्धान्त केन्द्र में स्थित धनी (विकसित) देशों तथा उपान्त पर स्थित विकासशील देशों के मध्य संरचनात्मक अन्तर (Gap) पर आधारित है। इस सिद्धान्त के प्रतिपादक आन्द्रेई प्रेडोल (1954) थे। इस सिद्धान्त के अनुसार औद्योगीकरण से आर्थिक विकास होता है। जैसा कि सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ था। द्वितीय चरण में औद्योगीकरण का प्रसार उत्तरी अमेरिका में, तथा तीसरे चरण में सोवियत संघ में हुआ। अन्ततः जापान में औद्योगीकरण हुआ तथा विश्व की अर्थव्यवस्था बहुकेन्द्रीय हो गयी।

केन्द्र उपान्त (Cure penphery) प्रक्रिया का विस्तृत विवरण गुन्नार मिरडाल (1957) ने दिया है। उन्होंने संचयी कारणवाद (currulative causation) के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया तथा यह बताया कि शास्त्रीय सिद्धान्त के विपरीत, आर्थिक (बाजार) शक्तियाँ प्रादेशिक अन्तरों में वृद्धि करती है। मिरडाल के अनुसार कोई भी देश विकास की तीन अवस्थाओं से होकर गुजरता है— 1. औद्योगिक पूर्व अवस्था, 2. आर्थिक विकास के प्रारम्भ (take off) तथा तीव्र विस्तार की अवस्था तथा 3. विकास के प्रसार प्रभाव (spread effect) की अवस्था जो प्रादेशिक अन्तरों को घटाती है। मिरडाल के मूलभूत सिद्धान्त आधुनिक विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर विशेषतः लागू होते हैं।

अधिक विकसित अर्थव्यवस्थाओं में प्रादेशिक विषमताओं को स्पष्ट करने के लिये अन्य मॉडल प्रस्तुत किये गये हैं जिनमें परलॉफ (1962) का मॉडल उल्लेखनीय है। यह मॉडल किसी प्रदेश की आर्थिक प्रगति के लिये उसके निर्यात आधार की भूमिका पर बल देता है।

'विकास ध्रुव' (Growth Poles) के सिद्धान्त का प्रतिपादन मूलतः पेरू प्रादेशिक विषमता के बजाय किया था। यह सिद्धान्त अर्थव्यवस्था की प्रादेशिक संगठनात्मक पहलू पर बल देता है।

प्रावस्था आधारित सिद्धान्तों में रोस्तोव मॉडल (1955) विशेषतः उल्लेखनीय हैं। उन्होंने आर्थिक विकास की पाँच प्रावस्थाएँ बतायी—1. परम्परागत समाज, 2. विकास-प्रारम्भ (take off) की पूर्वदशाएँ (शर्तें), 3. विकास प्रारम्भ, 4. प्रौढ़ावस्था, 5. व्यापक उपभोग की अवस्था।

आर्थिक विकास का केन्द्र उपान्त मॉडल फ्रीडमैन (1966) द्वारा प्रस्तुत किया गया। मैक्स वेबर तथा उनके समर्थकों की यह मान्यता है कि आर्थिक विकास की व्याख्या मात्र आर्थिक तत्त्वों से नहीं की जा सकती है। महबूब उल हक (मानव विकास रिपोर्ट के संस्थापक) के अनुसार विकास मानवीय चयन का वृद्धिकरण है। जोसेफ स्टिगलिट्ज के अनुसार विकास में समाज का रूपान्तरण है। अमर्त्यसेन के अनुसार "विकास स्वतंत्रता है।" इस प्रकार विकास का विस्तार व्यापक हो गया है।

TOUCH 'n PASS

प्र.3. आर्थिक प्रदेश एवं प्रादेशीकरण की व्याख्या कीजिए।
Explain Economic State and Regionalisation.

उत्तर

आर्थिक प्रदेश एवं प्रादेशीकरण
(Economic State and Regionalisation)

आर्थिक प्रदेश की संकल्पना आर्थिक भूदृश्य की समरसता से सम्बद्ध है। आर्थिक प्रदेश ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें सामान्य आर्थिक भूदृश्य की समरसता (Homogeneity) पायी जाती है जो उसे प्रदेश के भौगोलिक तत्त्व की विशेषताओं को प्रकट करती हैं। आर्थिक प्रदेशों के सीमांकन के निम्नलिखित कारक (तत्त्व) हैं—

1. संसाधन आधा
2. संसाधन उपयोग की प्राविधिकी,
3. आर्थिक विकास हेतु अवसंरचना (infrastructure) की उपलब्धता,
4. आर्थिक विकास की अवस्था (stage) तथा
5. आर्थिक तंत्र का स्वरूप तथा सामान्य आर्थिक कल्याण की दशाएँ।

किसी देश या प्रदेश के आर्थिक विकास के लिये प्रादेशिक नियोजन आवश्यक है, किन्तु सैद्धान्तिक तथा प्रशासनिक रूप से प्रादेशीकरण की समस्या बहुत जटिल है सभी देशों में क्षेत्रवाद/प्रदेशवाद की भावना प्रबल होती है, तथा सभी प्रदेश राष्ट्रीय बजट या स्थानीय आर्थिक क्रियाओं के वितरण में बड़ा हिस्सा चाहते हैं। इसके अतिरिक्त सभी देशों में विभिन्न कारणों से कुछ पिछड़े क्षेत्र भी होते हैं। अतएव, राष्ट्रीय, प्रादेशिक या क्षेत्रीय स्तर पर प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों के विकास हेतु उचित प्रादेशीकरण आवश्यक है। आर्थिक प्रादेशीकरण की तकनीकों के विकास में रूसी विद्वानों का बहुत योगदान है। आर्थिक प्रादेशीकरण की तकनीकों में 'क्षेत्रीय उत्पादन सम्मिश्रण' (territorial production complex) सबसे महत्त्वपूर्ण है। इस सिद्धान्त के अनुसार समस्त आर्थिक क्रिया को प्राविधिकी, श्रम विभाजन, क्षेत्रीय संसाधन समुच्चय, उत्पादन प्रक्रिया, कच्चे माल तथा ऊर्जा के स्रोतों के आधार पर विशिष्ट समुच्चयों (aggregates) में विभाजित किया जाता है। जिन्हें 'उत्पादन चक्र' (production cycles) कहा जाता है।

उत्पादन चक्रों की संकल्पना के आधार पर क्षेत्रीय प्रादेशीकरण किया गया है। वैश्विक स्तर पर आर्थिक विकास के अनुसार प्रादेशीकरण किया गया है। बेरी (1960) ने आर्थिक विकास मापने के लिये दो आधार बताये— 1. जनांकिकीय प्रतिरूप एवं 2. प्राविधिक प्रतिरूप। इनके सूचकों (43 तत्त्व) के आधार पर विश्व को विभिन्न स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। विश्व विकास रिपोर्ट (WDR) के आधार पर भी आर्थिक प्रदेश सीमांकित किये जा सकते हैं।

प्र.4. विश्व व्यापार संगठन के लाभों को लिखिए।
Write the advantages of World Trade Organisation.

उत्तर

विश्व व्यापार संगठन के लाभ
(Advantages of World Trade Organisation)

1995 में स्थापना के समय से ही विश्व व्यापार संगठन ने वर्तमान बहु-आयामी व्यापार प्रणाली की वैधानिक एवं संस्थागत आधारशिला तैयार करने के लिए एक लम्बा सफर तय किया है। यह न केवल व्यापार को सुगम बनाने बल्कि जीवन स्तर में सुधार एवं सदस्य देशों में पारस्परिक सहयोग में मददगार रहा है। विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख लाभ निम्न हैं—

1. विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देता है एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय को सुगम बनाता है।
2. सदस्य देशों के बीच विवादों को आपसी बातचीत से निपटाता है।
3. नियम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं संबंधों को मृदु एवं संभाव्य बनाते हैं।
4. स्वतन्त्र व्यापार के कारण विभिन्न प्रकार की अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं को प्राप्त करने के पर्याप्त अवसर मिलते हैं।
5. स्वतन्त्र व्यापार के कारण आर्थिक विकास में तीव्रता आई है।
6. यह प्रणाली श्रेष्ठ शासन को प्रोत्साहित करती है।
7. विश्व व्यापार संगठन विकासशील देशों के विकास का, व्यापार से संबंधित मामलों में विशेष ध्यान रखकर प्राथमिकता के आधार पर व्यवहार कर पोषण करने में सहायक होता है।

TOUCH 'n PASS

प्र.5. WTO की निर्णयन प्रक्रिया को समझाइए।
Explain the decision making process of WTO.

उत्तर

निर्णयन प्रक्रिया
(Decision Making Process)

WTO का संचालन सदस्य देशों की सरकारों द्वारा किया जाता है। सभी महत्त्वपूर्ण निर्णय सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से किये जाते हैं, जो या तो मंत्रियों द्वारा, जिनकी बैठक दो वर्ष में एक बार होती है, या उनके राजदूतों अथवा प्रतिनिधियों के द्वारा, जिनकी बैठके जेनेवा में नियमित रूप से होती है। निर्णय सामान्यत: सर्वसम्मति से लिये जाते हैं। इस संदर्भ में WTO कुछ अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भिन्न है। WTO में शक्ति का स्थानांतरण निदेशक मंडल या संस्था के प्रमुख को नहीं किया गया है। जब WTO किसी देश की नीतियों पर अनुशासन या नियम लागू करता है तो यह पूर्व में हुई WTO सदस्यों की वार्ता का परिणाम होता है। ये नियम सदस्य देशों द्वारा स्वयं पर लागू किये गये निर्धारित प्रक्रिया से लागू होता है जिसमें व्यापार प्रतिबंध भी संभव है। ये प्रतिबंध सभी सदस्य देशों द्वारा लगाये जाते हैं। इस तरह यह अन्य एजेंसियों से बिल्कुल भिन्न है, जिनका अधिकारीवर्ग किसी देश विशेष की नीतियों को प्रभावित करने के लिए ऋण रोकने की धमकी देता है।

सर्वसम्मति से किसी निर्णय पर पहुँचना सभी सदस्य देशों के लिए कठिनाई भरा हो सकता है परंतु इसका मुख्य लाभ यह है कि सभी सदस्य देशों के लिए यहाँ लिये गये निर्णय ज्यादा बेहतर तरीके से स्वीकार्य होते हैं। तथापि, छोटे कार्यपालिका इकाईयों का गठन सम्बन्धी प्रस्ताव जैसे एक निदेशक मंडल, जिसमें प्रत्येक सदस्य एक वर्ग के सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी सदस्यता आवर्ती होती है।

परन्तु वर्तमान में WTO सदस्यों द्वारा संचालित, सर्वसम्मति पर आधारित संगठन है, इसलिए WTO सदस्य देशों का संगठन है। इसमें देशों के द्वारा अपने निर्णय विभिन्न परिषदों और समितियों के माध्यम से लिए जाते हैं, जिसके सदस्य WTO के सभी सदस्य देश होते हैं।

इसमें सर्वोच्च इकाई मंत्रिस्तरीय बैठक है, जिसकी दो वर्ष में एक बार बैठक होती है। मंत्रिस्तरीय बैठक किसी भी बहुपक्षीय व्यापार संधि से सम्बन्धित सभी मुद्दों पर निर्णय ले सकती है।

प्र.6. विश्व व्यापार संगठन की उभरती भूमिका का उल्लेख कीजिए।
Mention the evolving role of world Trade Organisation.

उत्तर

विश्व व्यापार संगठन (WTO) की उभरती भूमिका
[(Evolving Role of World Trade Organisation (WTO)]

WTO के 147 सदस्य देश हैं और यह विश्व व्यापार के 97% भाग पर अधिकार रखता है। यह एकमात्र अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के मध्य होने वाले व्यापार के वैश्विक नियमों से सम्बन्धित है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि WTO का मुख्य लक्ष्य विश्व व्यापार के प्रवाह को तीव्र प्रवाहमान एवं मुक्त बनाना है जो वस्तुओं, सेवाओं तथा बौद्धिक संपदा के बहुपक्षीय व्यापार को उदारीकरण के माध्यम से बढ़ावा देने से ही संभव है। WTO का मुख्य कार्य तथा इसका ढाँचा, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमन के मुख्य लक्ष्य को स्पष्ट करता है। WTO की मुख्य ताकत जिनमें से कई इसकी स्थापना के महत्त्वपूर्ण कारण रहे हैं, मुक्त व्यापार के लाभों को प्रोत्साहन और इसका एक नियमबद्ध संस्था होना है।

WTO बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रोत्साहन देने के लाभों को बताता है, जिनमें से कई इसकी स्थापना के कारण है। ये लाभ निम्न हैं—

1. WTO अन्तर्राष्ट्रीय शासन की एक व्यवस्था बन गया है जो अन्तर्राष्ट्रीय शांति में योगदान देता है।
2. WTO को विवाद निपटारे तथा संधि के सृजन की शक्ति है जो सदस्यों पर बाध्यकारी होती है। WTO की यह ताकत व्यापारिक विवादों को युद्ध में परिणत होने से बचाता है।
3. WTO असमानता को कम करने, नियमबद्ध संगठन के उत्पाद तथा भेदभाव रहित व्यवस्था बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ किये गये समझौते विकसित और विकासशील देशों, दोनों की समान भागीदारी से लिए गए सर्वसम्मत नियमों पर आधारित होते हैं, जिससे नियमन प्रक्रिया तथा विवादों के निस्तारण में मदद मिलती है।

4. विकासशील और संक्रमणकारी अर्थव्यवस्थाओं को WTO सचिवालय स्वयं या अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से बैठक, सेमिनार, प्रायोगिक तकनीकी सहयोग के द्वारा इन देशों की सरकारों एवं अधिकारियों की मद्द करता है, जिससे वे सदस्यता वार्ता, WTO से सम्बन्धित प्रतिबद्धता तथा वार्ताओं और बहुपक्षीय वार्ताओं में प्रभावी भूमिका निभा सके।
5. WTO सचिवालय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाता है। यह विकासशील देशों के अधिकारियों के लिए वर्ष में दो बार जेनेवा में होता है। 1955 में इसके प्रारंभ से लेकर 1994 के अंत तक 125 देशों तथा 10 क्षेत्रीय संगठनों के 1400 व्यापार अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। 1991 से विशेष कार्यक्रम पूर्ववर्ती केन्द्रीकृत योजना वाली अर्थव्यवस्थाओं जो बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित हो रही है, के अधिकारियों को प्रतिवर्ष जेनेवा में प्रशिक्षण दिया जाता है।
6. WTO के मत का एक महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि यह अपनी भूमिका निभाने में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक तथा अन्य बहुपक्षीय संस्थाओं का सहयोग लेता है जिससे व्यापक आर्थिक वैश्विक नीति निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त करता है।

प्र.7. पारस्परिक अंतर-क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के बीच अंतर बताइए।
State difference between Internal, Inter-Regional and International Trade.

उत्तर

पारस्परिक अंतर-क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के बीच अंतर
(Difference Between Internal, Inter-Regional and International Trade)

प्रत्येक व्यक्ति को बिना व्यापार के आत्मनिर्भर होना होगा। यदि व्यक्ति सभी भोजन, कपड़े, आश्रय, चिकित्सा सेवाओं, मनोरंजन और विलासिता आदि का उत्पादन करेगा, लेकिन यह विशेष व्यक्ति के लिए असंभव है, इसलिए व्यक्ति के बीच व्यापार लोगों को गतिविधियों में विशेषज्ञ बनाने की अनुमति देता है। जिनमें वे अपेक्षाकृत अच्छी तरह से कर सकते हैं और उन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदें जिन पर उनके द्वारा आसानी से उत्पादन नहीं किया जा सकता है। इसे पारस्परिक व्यापार कहा जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी पारस्परिक व्यापार पर आधारित है। प्रत्येक क्षेत्र आत्मनिर्भर होने के लिए मजबूर होगा यदि व्यापार इन क्षेत्रों के बीच मौजूद नहीं है। लेकिन व्यापार उस क्षेत्र में मौजूद है जहाँ प्रत्येक क्षेत्र उन वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन में विशेष कर सकता है जिनके लिए उसके पास कुछ प्राकृतिक संसाधन है, मैदानी क्षेत्र उस विशेष माल का उत्पादन कर सकते हैं जो प्राकृतिक संसाधनों में प्रचुर मात्रा में है। उदाहरण के लिए, मैदानी क्षेत्र विभिन्न खाद्यान्नों का उत्पादन कर सकते हैं जबकि पर्वतीय क्षेत्र खनन और वन उत्पादों के विशेषज्ञ हो सकते हैं।

इसलिए प्रत्येक क्षेत्र उस माल का उत्पादन करता है। जिसमें उसके पास कुछ प्राकृतिक संसाधन हैं या लाभ प्राप्त किया है और व्यापार के अन्य उत्पादों को प्राप्त करता है जब सभी क्षेत्र आत्मनिर्भर होते हैं।

पारस्परिक और अंतर क्षेत्रीय सिद्धांत जिनका उल्लेख राष्ट्रों के मामले में किया गया है उनसे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पन्न होता है। लगभग सभी देश अपने निवासियों की खपत की तुलना में कुछ वस्तुओं का अधिक उत्पादन करते हैं। इसी समय, वे उस विशेष वस्तुओं से अधिक का उपभोग करते हैं जिसका उत्पादन कर रहे हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार उस लाभ को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है जो अन्तर्राष्ट्रीय विशेषता संभव बनाती है। व्यापार प्रत्येक व्यक्तिगत क्षेत्र या राष्ट्र को उन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर ध्यान केन्द्रित करने की अनुमति देता है जो वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए व्यापार करते समय अपेक्षाकृत कुशल पैदा करते हैं कि वे दूसरों की तुलना में कम कुशलता से उत्पादन करेंगे।

प्र.8. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के निर्धारक तत्त्वों का उल्लेख कीजिए।
Explain the determinants of International Trade.

उत्तर

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के निर्धारक तत्त्व
(Determinants of International Trade)

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार या अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं—

1. **प्राकृतिक निधि**—प्राकृतिक निधि अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण का आधार है। इससे अभिप्राय एक देश के उस संसाधन से है जो प्रकृति से नि:शुल्क उपहार के रूप में प्राप्त होता है। प्राकृतिक निधि में प्रकृति और भूमि का उपजाऊपन तथा जलवायु सम्बन्धी स्थितियाँ भी शामिल होती हैं। इसलिए भारत और श्रीलंका ने चाय के लिए उपर्युक्त जलवायु स्थितियों के कारण चाय के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त की हुई है।

2. **तकनीकी स्थिति**—अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण का एक निर्णायक निर्धारक तत्त्व तकनीकी ज्ञान है। अपनी प्रौद्योगिकी के विकास के कारण, विश्व के विकसित देशों ने प्राकृतिक निधि की सभी रुकावटों पर काबू पा लिया है। उदाहरण के लिए, जापान केवल एक तटीय देश है जिसके पास न के बराबर प्राकृतिक संसाधन आधार है, परन्तु इसकी तकनीकी वरिष्ठता ने मोटरगाड़ी उत्पादन के क्षेत्र में एक बहुत ही विकसित देश की विशिष्टता प्राप्त कर ली है।
3. **लागत अन्तर**—उत्पादन की लागत में अन्तर, अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण का वास्तव में मुख्य आधार है। विभिन्न देश उन वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त कर लेते हैं, जिनमें निरपेक्ष अथवा तुलनात्मक लागत अन्तर होता है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा का महत्त्वपूर्ण मापक उत्पादित वस्तुओं की लागत से अलग है।
4. **नई आर्थिक प्रणाली**—बहु-राष्ट्रीय निगमों के माध्यम तथा नई आर्थिक प्रणाली के उदय होने से विश्व बाजार के वैश्वीकरण (Globalisation) ने विभिन्न राष्ट्रों को शेष विश्व के साथ समन्वित होने के लिए बाध्य कर दिया है, जिससे विशिष्टीकरण और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्त्व बढ़ गया है।

प्र.9. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं आर्थिक गतिविधि के उभरते प्रतिरूप का उल्लेख कीजिए।
Explain the evolving pattern of economic activity and international trade.

उत्तर

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं आर्थिक गतिविधियों के उभरते प्रतिरूप
(Evolving Pattern of Economic Activity and International Trade)

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, सीमाओं के पार पूँजी, वस्तुओं तथा सेवाओं का विनिमय है। अधिकांश देशों में, यह सकल घरेलू उत्पाद के महत्त्वपूर्ण हिस्से को प्रदर्शित करता है। ऐतिहासिक समय से ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मौजूद रहा है तथा इसके आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक महत्त्व वर्तमान समय में अत्यधिक बढ़ गये हैं। औद्योगिकरण, उन्नत परिवहन, वैश्वीकरण, बहुराष्ट्रीय निगमों और आउट सोर्सिंग (Outsourcing) आदि सभी ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को अत्यधिक प्रभावित किया है। वैश्वीकरण की निरंतरता के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ोत्तरी आवश्यक है। किसी भी देश के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आर्थिक राजस्व का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है जो उसके विश्व शक्ति बनने के लिए आवश्यक समझा जाता है। बिना अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के, कोई भी देश केवल अपनी सीमाओं के भीतर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं में ही सीमित रह जाएगा। एक वैश्विक अर्थव्यवस्था में कोई भी देश पूर्णत: आत्म-निर्भर नहीं है। प्रत्येक देश विभिन्न स्तरों पर उन पदार्थों को बेचने के लिए जिसका वह उत्पादन करता है, कमी वाली वस्तुओं का अधिग्रहण करने के लिए तथा अपने अन्य व्यापारिक भागीदारों से अधिक सक्षम रूप से कुछ आर्थिक क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए व्यापार में संलग्न रहता है। पारम्परिक आर्थिक सिद्धान्तों के मतानुसार— व्यापार बहुविध प्रकार के वस्तुओं को प्राय: कम कीमतों पर उपलब्ध करवाकर आर्थिक सक्षमता को प्रोत्साहित करता है। उत्पादन का वैश्वीकरण व्यापार के वैश्वीकरण का सहवर्ती है तथा ये एक दूसरे के बिना कार्य नहीं कर सकते हैं। यद्यपि आधुनिक युग के प्रारम्भ से पूर्व ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में था जैसा कि प्राचीन व्यापारिक मार्गों से स्पष्ट है क्योंकि देशों तथा क्षेत्रों के आर्थिक जीवन में अत्यधिक सक्रिय भागीदारी के लिए पिछले 600 वर्षों में वृहत् पैमाने पर व्यापार हुआ है।

1970 के दशक से ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्राओं, पैमानों तथा दक्षता में बढ़ोत्तरी हुई है। वास्तव में, एक ऐसा समय आता है जब वृहत् दूरियों तक व्यापार अपेक्षाकृत कम समय और वह भी समान या कम कीमतों पर होता है। पहले के मुकाबले अब विश्व के विभिन्न भागों से ज्यादा व्यापार संभव हो सका है। विशेषकर, उत्पादन की प्रक्रिया का वर्गीकरण एवं विभाजन ने भी व्यापार को फैला दिया है। व्यापार ने उत्पादन लागत कम करने में भी योगदान दिया है।

बिना अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के कुछ ही देश एक समुचित जीवन स्तर को बनाए रखने में सक्षम हैं। केवल घरेलु संसाधनों की बदौलत, एक देश सीमित मात्रा में ही वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं तथा कमी अवश्यम्भावी है। वैश्विक व्यापार विविध प्रकार के संसाधनों की पूर्ति करता है। यह विश्व के अलग-अलग हिस्सों में उत्पादित विविध प्रकार की वस्तुओं के वितरण की सुविधा उपलब्ध करवाता है। आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्रीय विशेषीकरण के माध्यम से सम्पदा में वृद्धि को अनुमानित किया जाता है। इस प्रकार उत्पादन लागत में कमी, उत्पादकता में वृद्धि तथा अधिशेष की उत्पत्ति होती है, जो उन क्षेत्रों को हस्तगत किया जाता है जहाँ वे उत्पाद सुलभ नहीं है या उत्पादन लागत ज्यादा है।

परिणामस्वरूप, वैश्विक रूप से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सकल उत्पादन लागत को कम करता है। उपभोक्ता अपनी उसी कमाई से ज्यादा मात्रा में वस्तु खरीद सकता है जिससे उनके जीवन स्तर में वृद्धि होती है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार न केवल वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है बल्कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा उसके एकीकरण एवं क्षेत्रीय अर्न्तनिर्भरता को भी बढ़ावा देता है। यह

अर्न्तनिर्भरता पूँजी, वस्तुएँ, कच्चा माल एवं सेवाओं के प्रवाह के रूप में विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में सम्बन्ध स्थापित करता है। बहुराष्ट्रीय निगमों के मध्य बढ़ते हुए विनिमय भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का एक अन्य महत्त्वपूर्ण गुण है।

खण्ड-स विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. विश्व व्यापार संगठन के संरचना, उद्देश्य एवं कार्यों का वर्णन कीजिए।

Describe the structure, objectives and works of World Trade Organisation.

उत्तर

विश्व व्यापार संगठन की संरचना
(Structure of World Trade Organisation)

डब्ल्यूटीओ की मूल संरचना में निम्नलिखित निकाय हैं—

मंत्रीस्तरीय सम्मेलन, (Ministerial Council)—इसमें सभी सदस्य देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री होते हैं। यह डब्ल्यूटीओ का शासी निकाय है। यह संगठन की रणनीतिक दिशा तय करने और अपने अधिकार क्षेत्र के तहत समझौतों पर सभी अंतिम निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होता है।

जनरल काउंसिल (General Council)—इसमें सभी सदस्य देशों के वरिष्ठ प्रतिनिधि (आम तौर पर राजदूत स्तर के) होते हैं। यह डब्ल्यूटीओ के रोजाना कारोबार और प्रबन्धन की देखरेख के लिए जिम्मेदार होता है। व्यवहार में, ज्यादातर मामलों के लिए यह डब्ल्यूटीओ का फैसला करने वाला मुख्य अंग है। नीचे वर्णित निकायों में से कई सीधे जनरल काउंसिल को रिपोर्ट करते हैं।

व्यापार नीति समीक्षा निकाय (The Trade Policy Review Body)—इसमें भी डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्य होते हैं और यह उरुग्वे राउंड के बाद बने व्यापार नीति समीक्षा तंत्र की देखरेख करता है। यह सभी सदस्य देशों की व्यापार नीतियों की आवधिक समीक्षा करता है।

विवाद निपटान निकाय (Dispute Settlement Body)—जिन देशों के बीच व्यापार सम्बन्धी कोई विवाद होता है तो वे इसी निकाय के सामने अपील कर न्याय माँगते हैं। इसमें भी डब्ल्यूडीओ के सभी सदस्य होते हैं। यह सभी डब्ल्यूटीओ समझौतों के लिए विवाद समाधान प्रक्रिया के कार्यान्वयन और प्रभावशीलता एवं डब्ल्यूटीओ विवादों पर दिए गए फैसलों के कार्यान्वयन की देखरेख करता है।

वस्तुओं एवं सेवाओं में व्यापार पर परिषद् (The Councils on Trade in Goods and Trade in Services)—यह जनरल काउंसिल के जनादेश के तहत काम करती हैं और इसमें सभी सदस्य देश शामिल रहते हैं यह वस्तुओं (कपड़ा और कृषि जैसे) और सेवाओं में व्यापार पर हुए आम एवं विशेष समझौतों के विवरणों की समीक्षा के लिए तंत्र प्रदान करते हैं।

डब्ल्यूटीओ का सचिव और महानिदेशक जेनेवा में निवास करते हैं। सचिवालय जिसमें अब सिर्फ 550 लोग काम करते हैं और संगठन के सभी पहलुओं के संचालन का प्रशासनिक कार्य संभालते हैं। सचिवालय के पास कानूनी निर्णय लेने की कोई शक्ति नहीं है लेकिन ऐसा करने वालों को यह महत्त्वपूर्ण सेवाएँ और परामर्श प्रदान करता है।

विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य (Objectives of World Trade Organisation)

विश्व व्यापार संगठन के समझौते लम्बे और जटिल होते हैं क्योंकि इनका पाठ कानूनी होता है और यह गतिविधियों की व्यापक क्षेत्र को कवर करते हैं—

1. एक देश को अपने व्यापार भागीदारों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए और इसे अपने और विदेशी उत्पादों, सेवाओं और नागरिकों के बीच भी भेदभाव नहीं करना चाहिए।
2. व्यापार को प्रोत्साहित करने के सबसे स्पष्ट तरीकों में से एक है व्यापार बाधाओं को कम करना। इन बाधाओं में शामिल है— सीमा शुल्क (या टैरिफ) और आयात प्रतिबंध या कोटा, एंटी डंपिंग शुल्क जो मात्रा को चुनिंदा तरीके से प्रतिबंधित करता है।
3. विदेशी कम्पनियों, निवेशकों और सरकारों को व्यापार बाधाओं को मनमाने ढंग से नहीं बढ़ाया जाना सुनिश्चित करना चाहिए। स्थिरता एवं पूर्वानुमेयता के साथ निवेश प्रोत्साहित होता है, रोजगार के अवसर बनते हैं और उपभोक्ता प्रतिस्पर्धा का पूरी तरह से लाभ-पसंद और कम कीमत, उठा सकते हैं।

TOUCH 'n PASS

4. 'अनुचित' प्रथाओं को हतोत्साहित करना जैसे बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए निर्यात सब्सिडियों और डंपिंग उत्पादों की लागत कम कर देना; मुद्दे जटिल हैं और नियम क्या सही है और क्या गलत है कि स्थापना करने की कोशिश करते हैं और सरकारें कैसे प्रतिक्रिया करती हैं, खासकर अनुचित व्यापार द्वारा हुए नुकसान की भरपाई के लिए अतिरिक्त आयात शुल्क लेकर।
5. डब्ल्यूटीओ के समझौते सदस्यों को न सिर्फ पर्यावरण बल्कि जन स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य एवं ग्रह के स्वास्थ्य के सरंक्षण के उपाय करने की अनुमति देते हैं। हालाँकि, ये उपाय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों पर ही एक ही तरीके से लागू किए जाने चाहिए।

डब्ल्यूटीओ के कार्य (Works of WTO)

डब्ल्यूटीओ का संचालन उसके सदस्य देशों की सरकारें करती हैं। सभी प्रमुख फैसले पूर्ण सदस्यों द्वारा चाहे वह मंत्रियों (जो आम तौर पर दो वर्षों में कम-से-कम एक बार बैठक करते हैं) या उनके राजदूत या प्रतिनिधियों द्वारा (जो जेनेवा में नियमित रूप से बैठक करते हैं) किया जाता है। डब्ल्यूटीओ अपने सदस्य देशों द्वारा संचालित है, अपनी गतिविधियों को समन्वित करने के लिए यह बिना अपने सचिवालय द्वारा काम नहीं कर सकता। सचिवालय में 600 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं और इनमें— वकील, अर्थशास्त्री, सांख्यिकीविद् और संचार विशेषज्ञ होते हैं— जो डब्ल्यूटीओ के सदस्यों को अन्य बातों के अलावा दैनिक आधार पर, वार्तालाप प्रक्रिया के सुचारू होने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों को सही तरह से लागू करना सुनिश्चित करता है।

व्यापार वार्ता—डब्ल्यूटीओ समझौते, वस्तुओं, सेवाओं और बौद्धिक संपदा को कवर करते हैं। यह उदारीकरण के सिद्धांतों और अनुचित अपवादों की व्याख्या करते हैं। इसमें व्यक्तिगत देशों की कम सीमा शुल्क टैरिफ और अन्य व्यापार बाधाओं के प्रति प्रतिबद्धता एवं सेवा बाजार को खोलने एवं उसे खुला रखना शामिल है। विवादों के निपटान के लिए ये प्रक्रियाओं का निर्धारण करते हैं। ये समझौते स्थायी नहीं होते, समय-समय पर इन पर फिर से बात-चीत की जाती है और पैकेज में नए समझौते जोड़े जा सकते हैं। नवंबर 2001 में दोहा (कतर) में डब्ल्यूटीओ के व्यापार मंत्रियों द्वारा शुरू किए गए दोहा विकास एजेंडा, के तहत अब कई समझौते किए जा चुके हैं।

कार्यान्वयन और निगरानी—डब्ल्यूटीओ समझौते के तहत सरकारों को लागू कानूनों एवं अपनाए गए उपायों के बारे में डब्ल्यूटीओ को सूचित कर अपनी व्यापार नीतियों को पारदर्शी बनाने की आवश्यकता होती है। डब्ल्यूटीओ के कई परिषद और समितियाँ इस बात को सुनिश्चित करती हैं कि नियमों का पालन किया जा रहा है। या नहीं और डब्ल्यूटीओ के समझौतों का कार्यान्वयन उचित तरीके से हो रहा है या नहीं। समय-समय पर डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्यों की व्यापार नीतियों और प्रथाओं की समीक्षा की जाती है, प्रत्येक समीक्षा में सम्बन्धित देश और डब्ल्यूटीओ सचिवालय द्वारा दी गई रिपोर्ट होती है।

विवादों का निपटारा—विवाद निपटान समझौते के तहत व्यापार सम्बन्धी झगड़ों का समाधान करने की डब्ल्यूटीओ की प्रक्रिया नियमों को लागू करने और व्यापार प्रवाह का सुचारू होना सुनिश्चित करने के लिए महत्त्वपूर्ण है। अगर किसी देश या किन्हीं देशों को लगता है कि समझौते के तहत उनके अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है तो वे उस विवाद को डब्ल्यूटीओ में पेश करते हैं। विशेष रूप से नियुक्त किए गए स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा किए गए फैसले समझौते की व्याख्याएँ और अलग-अलग देशों की प्रतिबद्धताओं पर आधारित होते हैं।

व्यापार क्षमता का निर्माण—डब्ल्यूटीओ के समझौतों में विकासशील देशों के लिए विशेष प्रावधान होते हैं। इसमें समझौतों और प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए अधिक समय, उनके व्यापार अवसरों को बढ़ाने के लिए उपाय और उनके व्यापार क्षमता के निर्माण, विवादों से निपटने और तकनीकी मानकों को लागू करने में मद्द करने के लिए समर्थन देना शामिल है। डब्ल्यूटीओ सालाना विकासशील देशों के लिए तकनीकी सहायता मिशनों का आयोजन करता है। साथ ही यह सरकारी अधिकारियों के लिए जेनेवा में हर वर्ष कई पाठ्यक्रमों या आयोजन भी करता है। विकासशील देशों को उनके व्यापार में विस्तार के लिए जरूरी कौशल एवं संरचनात्मक ढाँचे के विकास हेतु व्यापार के लिए सहायता (Aid for trade) प्रदान करता है।

आउटरीच—डब्ल्यूटीओ सहयोग को बढ़ाने एवं संस्था की गतिविधियों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों, सांसदों, अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, मीडिया और आम जनता से डब्ल्यूटीओ के अलग-अलग पहलुओं एवं चालू दोहा वार्ता पर नियमित तौर पर बातचीत करता है।

TOUCH 'n' PASS

प्र.2. व्यापार एवं प्रशुल्क पर सामान्य समझौता तथा विश्व व्यापार के गठन पर विवेचना कीजिए।
Deliberate on General Agreement on Trade & Tariffs and Formation of World Trade Organisation.

उत्तर व्यापार एवं प्रशुल्क पर सामान्य समझौता तथा विश्व व्यापार का गठन (The GATT and Formation of WTO)

द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के पश्चात् विजेता पक्ष अर्थात् संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों ने निश्चय किया कि समृद्ध और चिरस्थायी शांति केवल एक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था पर ही नहीं आधारित है बल्कि इसके लिए एक स्थिर उदार अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की भी जरूरत है। विजेता गुट एक संस्था का सृजन करना चाहती थी जो युद्ध के कारणों को रोकेगी। उनका सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं की मद्द से युद्ध के आर्थिक कारणों को भी हटाना था। ये तीन संस्थायें थी— अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संघ (ITO)। इन तीनों को "ब्रेटनवुड" के नाम से जाना जाता था। इन ब्रेटनवुड् संस्थाओं का आर्थिक दर्शन परम्परागत आर्थिक नव-उदारवाद था।

मूल रूप से ITO का मसौदा हवाना (क्यूबा) में तैयार की गई थी और इसकी योजना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों में एक औपचारिक वैश्विक व्यापार प्रबंधन संघ का गठन था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना पर कोई आपत्ति नहीं की लेकिन ITO के गठन पर इस आधार पर इंकार कर दिया कि यह अन्तर्राष्ट्रीय संस्था अधिक मात्रा में संप्रभुता का परित्याग की माँग करता है, तब ITO के औपचारिक गठन पर अमेरिका के नेतृत्व में राजनीतिक अस्वीकार्यता हो गई, भागीदारों ने ITO के संविधान से महत्त्वपूर्ण तथ्यों को लेकर उसे पुर्नजीवित करने की सोची और एक अलग औपचारिक और स्वतंत्र "व्यापार और प्रशुल्क पर सामान्य समझौता (GATT)" का निर्माण किया।

GATT पर सन् 1947 में हस्ताक्षर किये गये, जो 150 देशों की बहुपक्षीय समझौते पर आधारित व्यापार नियामक थी। इसकी प्रस्तावना के अनुसार, GATT का उद्देश्य "प्रशुल्क तथा अन्य व्यापारिक बाधाओं में सतत् कटौती और परस्पर लाभ पर आधारित तथा संरक्षणात्मक गतिविधियों को रोकना था।" GATT की एक संस्था के रूप में स्थापना 1948 में हुई जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के नियमों द्वारा शासित थी। इसने व्यापार हेतु नियम एवं नियामक प्रदान किया। GATT की अवधि में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वाणिज्य में सराहनीय वृद्धि देखी गयी।

GATT की स्थापना के प्रारंभिक विषम (कठिन) 20 वर्षों में, इसके सदस्यों का मुख्य कार्य बातचीत द्वारा आयात प्रशुल्कों को कम करना था। बातचीत के कई दौर में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपिय आर्थिक समिति के सदस्यों, ब्रिटेन, जापान तथा अन्य औद्योगिक देशों ने विनिर्माण क्षेत्रों में प्रशुल्क में सतत् कटौती की बात स्वीकारी।

अपने पूरे समय में GATT प्रशुल्क कटौती और अन्य व्यापार की बाधाओं को दूर करने में सतत् एवं प्रभावशाली भूमिका निभाता रहा। लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं था। जैसे-जैसे समय बीता नई समस्याऐं उठती रही। विशेषकर 1970 और 1980 के प्रारंभ में आर्थिक मंदी में सरकारें विदेशी प्रतिस्पर्धा से घरेलू क्षेत्रों को बचाने हेतु नये हथियारों का प्रयोग करने लगी। उच्च बेरोजगारी दरें और निरंतर कारखाना बंदी के कारण उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप की सरकारें द्विपक्षीय बाजार व्यवस्था को अपनाने को बाध्य हुए और उन्होंने अपने कृषि व्यापार में सब्सिडी देने की गति को बढ़ा दिया।

1970 तक, जहाँ अधिकांश वस्तुओं के प्रशुल्क में पर्याप्त कटौती हो गई, विश्व तेल की बढ़ती कीमतों और मुद्रास्फीति के चक्र में फसने के कारण अपने-अपने उद्योगों को आयात प्रतिस्पर्धा से संरक्षण के लिए अप्रशुल्क बाध सम्बन्धि नीतियों का अनुसरण या कार्यान्वयन करने लगी।

ये बदलाव GATT की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता को कम कर रही थी। तब 1970 के टोक्यों दौर की वार्ता से इसे दूर करने की कोशिश की गई परन्तु यह सीमित थी। यह GATT की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता के लिए एक कठिन समय के संकेत थे।

समस्या केवल यह नहीं थी कि व्यापार नीति प्रभावित हो रही है। 1980 के प्रारम्भ में ही यह स्पष्ट हो चुका था कि कोई भी आर्थिक व्यवस्था 1940 के व्यवस्था के अनुरूप नहीं चल सकती थीं। विश्व व्यापार 40 साल पहले के मुकाबले अधिक जटिल और महत्त्वपूर्ण हो गयी थी। वैश्विक आर्थिक भूमंडलीकरण की प्रक्रिया जारी थीं, निवेश भी बढ़ रहा था तथा सेवा क्षेत्रों में भी अधिकाधिक देशों की रूचि बढ़ी, जो गैट के अधीन नहीं आते थे।

सेवा क्षेत्र में व्यापार का विस्तार और विश्व वाणिज्य व्यापार एक-दूसरे से निकटता से सम्बन्धित हो गये थे। गेट की संरचना और इसके विवाद सुलझाने की प्रणाली भी चिंता का विषय बन गई थीं। इन तथा कुछ अन्य तथ्यों को देखते हुए गैट के सदस्यों ने एक नया प्रयास प्रारम्भ किया, जो बहुपक्षीय प्रणाली पर आधारित तथा विस्तारित हो। इस प्रयास का नतीजा उरुग्वे दौर, मराकश घोषणा और WTO के सृजन के रूप में सामने आया।

व्यापार में उदारीकरण की गति ने यह सुनिश्चित किया कि गैट के संपूर्ण युग की तुलना उत्पादन में सतत् वृद्धि हुई जिससे बहुपक्षीय लाभ सुनिश्चित हुआ। उरुग्वे दौर में नये सदस्यों की भीड़ से यह प्रदर्शित हुआ कि बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली उनके आर्थिक विकास का साधन और व्यापार में सुधार के लिए एक मंच के रूप में स्थापित हुआ है।

सबसे अन्तिम तथा वृहद दौर उरुग्वे दौर थी, जो 1986 से 1994 तक चली। उरुग्वे दौर के बीच नवम्बर 1982 में गैट सदस्यों के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (जेनेवा) में देखने को मिला। हालाँकि मंत्रिस्तरीय सम्मेलन ने एक नवीन मसौदा जारी करने का प्रयास किया परन्तु यह सम्मेलन कृषि तथा अन्य कुछ मुद्दों पर असहमति के कारण असफल हो गया। तथापि उरुग्वे दौर के वार्ता के आधार के रूप में सम्मेलन के निष्कर्षों को शामिल करने पर सहमति बनी।

तत्पश्चात्, इसे अपने मुद्दों को स्पष्ट करने तथा आपसी विश्वास के निर्माण और मंत्रियों को एक नये एजेंडे के तहत एक नए दौर की वार्ता को प्रारम्भ करने में चार वर्ष लग गये। ऐसा उन्होंने सितम्बर 1986 में पुंटा-डेल-एस्टेट (उरुग्वे) में किया। उन्होंने बातचीत पर आधारित ऐसा मसौदा तैयार किया, जो व्यापार नीति के प्रत्येक पक्ष को सम्मिलित करता था। वार्ता में कुछ अन्य नये क्षेत्रों को भी शामिल किया गया, जिनमें विशेषकर सेवाओं के व्यापार तथा बौद्धिक सम्पदा एवं कृषि तथा वस्त्र जैसे संवदेनशील मुद्दे भी शामिल थे। गैट के सभी मूल अनुच्छेदों का पुनरीक्षण किया गया। वार्ता का यह मसौदा सबसे बड़ा व्यापारिक सम्मेलन था, जिसे पूरा करने में मंत्रियों ने चार वर्षों का समय लिया।

दो वर्ष पश्चात् जब वार्ता अपने अर्द्धबिंदु पर थी, तब प्रगति की समीक्षा के लिए दिसम्बर, 1988 में वे फिर मांट्रियल (कनाडा) में मिले। इसका उद्देश्य शेष समयावधि के लिए एजेंडे का स्पष्टीकरण करना था। लेकिन यह वार्ता एक गतिरोध के साथ सम्पन्न हुआ, जिसका समाधान अगले वर्ष अप्रैल में हुए जेनेवा बैठक के दौरान हुआ।

समस्याओं के बावजूद मांट्रियल बैठक के दौरान मंत्रिगण शीघ्र परिणाम लाने हेतु एक मसौदे पर सहमत हुए। उष्ण-कटिबंधीय उत्पादों के बाजार पहुँच में छूट और विशेषत: विकासशील देशों की मदद के साथ एक प्रभावी विवाद निस्तारण प्रणाली और व्यापार नीति के पुनरीक्षण की व्यवस्था शामिल थी। इसने गैट के सदस्य देशों को राष्ट्रीय व्यापार नीति के पुन:निर्धारण के लिए एक समग्र, प्रणालीगत तथा नियमित व्यवस्था प्रदान की।

राजनीतिक असहमतियों के बावजूद तकनीकी विषयों पर कार्य जारी रहा जिसने अंतिम विधिक समझौते हेतु प्रथम प्रारूप तैयार किया। यह प्रारूप जो "फाइनल एक्ट" के नाम से जाना गया, को गैट के महानिदेशक आर्थर डंकल के द्वारा तैयार किया गया, जो आधिकारिक स्तरीय वार्ता के भी अध्यक्ष थे। इसे दिसम्बर, 1991 में जेनेवा में प्रस्तुत किया गया। इसने पुंटा-डेल-एस्टेट घोषणा-पत्र के प्रत्येक भाग की प्रतिपूर्ति एक अपवाद के साथ की, जिसमें सहभागी देशों हेतु आयात-शुल्क में कटौती हेतु प्रतिबद्धता तथा सेवा क्षेत्र को खोलने की बात शामिल नहीं थीं। यही प्रारूप अंतिम समझौते का आधार बना।

आगामी दो वर्षों में वार्ता सफलता एवं असफलता के मध्य झूलती रही। कितनी अंतिम तिथियाँ आई और गई। वार्ता में गतिरोध प्रमुख मुद्दों में कुछ नये बिन्दुओं के उभरने से हुआ। ये मुद्दे थे— कृषि, सेवा, बाजार, पहुँच, एंटीडंपिंग नियम तथा एक प्रस्तावित नये संगठन का सृजन। संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) तथा यूरोपियन यूनियन (E.U.) के मध्य गतिरोध सफल अंतिम निष्कर्ष का केन्द्रबिन्दु बन गया।

नवम्बर, 1992 में U.S. तथा E.U. ने कृषि क्षेत्र में अपने अधिकांश गतिरोध को "Blair House Accord" के माध्यम से सुलझा लिया। जुलाई, 1993 तक U.S.,E.U., जापान और कनाडा ने प्रशुल्क तथा सम्बन्धित मुद्दों (बाजार पहुँच) पर वार्ता में महत्त्वपूर्ण प्रगति की घोषणा की। इसमें 15 दिसम्बर 1993 तक सभी मुद्दों को अंतिम रूप में सुलझाना और वस्तुओं तथा सेवाओं की बाजार पहुँच जैसे मुद्दों पर वार्ता सम्पन्न करना सुनिश्चित किया गया। 15 अप्रैल, 1994 को मराकश (मोरक्को) में 123 भागीदार देशों के मंत्रियों द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर किये गये, जिसने WTO का निर्माण किया। WTO ए 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आया।

प्र.3. विश्व व्यापार संगठन का वर्णन करते हुए WTO और व्यापार व्यवस्था के सिद्धांतों का विवरण दीजिए।
Describing the world Trade Organisation, give details of the principles of WTO and Trading System.

उत्तर

विश्व व्यापार संगठन (WTO)
(World Trade Organisation)

विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आया जिसका कार्य विश्व के देशों के मध्य होने वाले व्यापार का नियमन तथा संचालन था। WTO एक मात्र ऐसा वैश्विक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के मध्य व्यापार सम्बन्धी नियमों को बनाता है।

इसके मूल में वे WTO संधियाँ हैं, जो विश्व के व्यापारिक देशों के द्वारा की गई तथा जिन पर उनके संसदों द्वारा सहमति प्राप्त है। इसका उद्देश्य वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादकों, निर्यातकों तथा आयातकों के मध्य व्यापार में सहयोग करना है।

विशेष रूप में, WTO एक ऐसा संगठन है जो विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं वाले सरकारों को वार्ता और व्यापारिक संधियों के लिए उदार मंच प्रदान करता है। GATT के विपरीत WTO की संधियाँ, सेवाओं तथा नवीन व्यापारिक खोजों, सृजन तथा प्रारूप (बौद्धिक संपदा) को भी शामिल करता है।

WTO उन संधियों पर वार्ता के लिए मंच प्रदान करता है जिसका उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की बाधाओं को दूर करना तथा सभी के लिए एक समान परिस्थिति उपलब्ध कराना जो उनके आर्थिक संवृद्धि एवं विकास में योगदान दे सके। WTO इन संधियों के कार्यान्वयन एवं पर्यवेक्षण के लिए एक विधिक तथा संस्थागत ढाँचा उपलब्ध कराता है जो इस व्यापार संधियों की व्याख्या और क्रियान्वयन से उत्पन्न विवादों का समाधान भी करता है। व्यापार संधियों के वर्तमान WTO ढाँचे में 16 विभिन्न बहुपक्षीय संधियाँ WTO के सभी सदस्यों से सम्बन्धित; तथा दो विभिन्न बहुल (Plurilateral) संधियाँ (जिसमें WTO के कुछ ही सदस्य हैं) सम्मिलित हैं। WTO की विशिष्ट गतिविधियाँ इस प्रकार हैं—

1. व्यापार में आने वाली बाधाओं को वार्ता के माध्यम से कम अथवा समाप्त करना जैसे—आयात प्रशुल्क व्यापार सम्बन्धि अन्य बाधाएँ तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्रियान्वयन से सम्बन्धित विनियमनों का पालन जैसे— एंटी डंपिंग, सब्सिडी, उत्पाद मानक आदि।
2. WTO के संदर्भ में सहमति प्राप्त नियमों, जिनमें वस्तुगत व्यापार, सेवा व्यापार तथा व्यापार सम्बन्धी बौद्धिक संपदा अधिकार आदि के अनुप्रयोग का प्रशासन एवं निगरानीं।
3. सदस्य देशों के व्यापार नीतियों की निगरानी एवं पुनरीक्षण के साथ ही क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय व्यापार संधियों में पारदर्शिता को सुनिश्चित करना।
4. अपने सदस्य देशों के मध्य संधि के अनुप्रयोग तथा व्याख्या से उत्पन्न विवादों का समाधान करना।
5. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में विकासशील देशों की सरकारों के क्षमता निर्माण में वृद्धि करना।
6. लगभग ऐसे 30 देशों के विकास की प्रक्रिया में सहयोग करना जो अभी तक इस संगठन के सदस्य नहीं है।
7. WTO की अन्य मुख्य गतिविधियों में सहयोग के लिए आर्थिक आँकड़ों का एकत्रीकरण तथा मूल्यांकन एवं आर्थिक शोध कार्यों को करना।

WTO की निर्माणकारी एवं कार्यकारी सिद्धांतों में खुली सीमा को बढ़ाना, अति प्रिय राष्ट्र (Most Favoured Nation) सिद्धांत की गारन्टी तथा बिना भेदभाव वाली संधियों को अपने सदस्य राष्ट्रों के मध्य बढ़ाना और अपने क्रियाकलापों में पारदर्शिता दिखाना शामिल है। राष्ट्रीय बाजारों को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए कुछ न्याय-संगत अपवादों अथवा पर्याप्त सुविधाओं के साथ खोलना जिससे सतत् विकास को प्रोत्साहन एवं बढ़ावा मिले, जनकल्याण को प्रोत्साहन मिले एवं गरीबी में कमी तथा शांति एवं स्थिरता की प्राप्ति हो। इस संदर्भ में इन बाजारों को ऐसी सक्षम घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों के साथ खोलना है जो उनके आर्थिक संवृद्धि एवं विकास को बढ़ावा दे तथा जो प्रत्येक सदस्य देशों की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति कर सके।

पिछले 60 वर्षों में GATT तथा उसके पश्चवर्ती WTO, जिसका गठन 1995 में हुआ, ने एक मजबूत एवं समृद्धकारी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था के निर्माण में सहयोग किया है। जिसने अभूतपूर्व वैश्विक आर्थिक समृद्धि को प्रदान किया है। वर्तमान में WTO के 153 सदस्य है जिसमें से 117 सदस्य विकासशील देश हैं या फिर विशिष्ट सीमाशुल्क क्षेत्र में आते हैं। WTO की क्रियाकलापों में सहयोग के लिए 700 कर्मचारियों से युक्त एक सचिवालय की स्थापना की गई है जिसका प्रमुख WTO का महानिदेशक होता है। यह सचिवालय जेनेवा, स्विट्जरलैण्ड में स्थित है तथा इसका वार्षिक बजट लगभग 180 मिलियन डॉलर का है। WTO की तीन आधिकारिक भाषाएँ— अंग्रेजी, फ्रेंच तथा स्पेनिश है।

सामान्यत: WTO में लिये जाने वाले निर्णय सभी सदस्य देशों की आम सहमति पर आधारित होते हैं। इसकी सर्वोच्च संस्थागत इकाई मंत्रिस्तरीय बैठक है। जिसकी बैठक दो वर्षों में एक बार होती है। मंत्रिस्तरीय बैठकों के बीच की अवधि में संगठन के क्रियाकलाप एक सामान्य परिषद् द्वारा संपादित किये जाते हैं। इन दोनों में सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। अन्य विशिष्ट सहयोगी इकाइयाँ; जैसे— परिषदें, समितियाँ, उपसमितियाँ आदि में भी WTO संधियों के अधीन सभी सदस्य देश शामिल होते हैं जो इसकी कार्यवाही को प्रशासित एवं पर्यवेक्षित करते हैं।

TOUCH 'n PASS

विश्व व्यापार संगठन तथा व्यापार व्यवस्था के सिद्धांत
(WTO and the Principles of Trading System)

WTO की संधियाँ लम्बी एवं जटिल है क्योंकि इनमें विधिक बातों के साथ-साथ बहुत बड़ी मात्रा में क्रियाकलापों को भी शामिल किया गया है। जिनमें कृषि, वस्त्र एवं परिधान, बैंकिंग, दूरसंचार, सरकारी खरीद, औद्योगिक मानक एवं उत्पाद सुरक्षा, खाद्य स्वच्छता नियमन तथा बौद्धिक संपदा शामिल है। परन्तु बड़ी संख्या में कुछ सामान्य मूलभूत सिद्धांत इसके लगभग सभी दस्तावेजों में पाये जाते हैं। ये सिद्धांत ही बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के आधार हैं।

WTO द्वारा प्रशासित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं—

1. **अति प्रिय राष्ट्र** (Most Favoured Nation)—विश्व व्यापार समझौतों के अधीन सामान्यत: कोई देश अपने व्यापारिक सहयोगियों के मध्य विभेद नहीं कर सकता है। इसमें अगर किसी उत्पाद विशेष के लिए किसी देश को विशेष लाभ; जैसे— न्यूनतम सीमा शुल्क दरें आदि दी जाती हैं तो यह WTO के सभी सदस्य देशों को देना होगा यह सिद्धांत ही अति प्रिय राष्ट्र का व्यवहार कहलाता है।

   तथापि कुछ अपवाद स्वीकार्य हैं— जैसे कोई देश मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना एक विशेष समूह बनाकर बाहर से आने वाली वस्तुओं के मुकाबले वहाँ की वस्तुओं को वरीयता दे सकता है, या फिर वे विकासशील देशों को विशेष बाजार पहुँच की सुविधा दे सकते हैं या फिर कोई देश किसी विशेष देश के अनुचित व्यापार को रोकने के लिए बाधाओं को बढ़ा सकता है। सेवाओं के संदर्भ में देशों को विभेद करने की बहुत सीमित स्वतंत्रता दी गई है। ये सभी अपवाद केवल कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में ही लागू हो सकता है। सामान्यत: अति प्रिय राष्ट्र (MFN) का अर्थ है कि जब भी कोई देश अपनी व्यापार बाधाओं को कम करता है या अपने बाजारों को खोलता है तो यह उसे उस वस्तु या सेवा के लिए सभी व्यापारिक साझीदारों के लिए करना होगा चाहे वे अमीर हो या गरीब, मजबूत हो या कमजोर।
2. **राष्ट्रीय व्यवहार** (National Treatment)—आयातित एवं स्थानीय वस्तुगत उत्पाद के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए खासतौर पर तब जब विदेशी वस्तु बाजार में प्रवेश कर चुकी है। ठीक यही बात विदेशी एवं घरेलू सेवाओं, व्यापार चिन्ह (Trademark), कॉपीराइट तथा पेटेंट पर भी लागू होता है। राष्ट्रीय व्यवहार का यह सिद्धांत कि राष्ट्रीय एवं विदेशी वस्तुओं के साथ समान व्यवहार हो, WTO की तीनों मुख्य संधियों में शामिल है। GATT का अनुच्छेद 3, GATS का अनु. 17 तथा TRIPS का अनु. 3; फिर भी यह सिद्धांत तीनों में अलग-अलग तरीकों से प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय व्यवहार केवल उन वस्तुओं, सेवाओं या बौद्धिक संपदा पर लागू होता है जो बाजार में प्रवेश कर चुके हैं। इसीलिए आयात पर सीमा शुल्क लेना राष्ट्रीय व्यवहार का उल्लंघन नहीं है।
3. **मुक्त व्यापार** (Free Trade)—व्यापार को प्रोत्साहन देने के एक महत्त्वपूर्ण साधन के रूप में बाधाओं को दूर करना शामिल है इन बाधाओं में सीमा शुल्क या प्रशुल्क की ऊँची दरे तथा कुछ कदम जैसे—आयात प्रतिबन्ध या मात्रात्मक प्रतिबंध हेतु विशिष्ट कोटा निर्धारण आदि शामिल हैं।
4. **पुर्वानुमान** (Predictability)—कभी-कभी व्यापार बाधाओं को न बढ़ाने का आश्वासन उन्हें कम करना जितना ही महत्त्वपूर्ण होता है क्योंकि यह आश्वासन भविष्य की अवसरों के संदर्भ में एक स्पष्ट दृष्टिकोण को बताता है। स्थायित्व एवं पूर्वानुमान के कारण निवेश को प्रोत्साहन मिलता है, रोजगार का सृजन होता है और उपभोक्ताओं को कम मूल्य तथा प्रतिस्पर्धा का लाभ भी मिलता है। WTO के अधीन बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था सरकारों के व्यापारिक परिवेश को स्थिर और पूर्वानुमान योग्य बनाने का प्रयास है। बहुत सारी WTO संधियाँ सरकारों को अपने देश में अथवा WTO को सूचित करके अपनी नीतियों एवं कार्यान्वयन को सार्वजनिक करने से सम्बन्धित है। राष्ट्रीय व्यापार नीतियों का व्यापार नीति पुनरीक्षण व्यवस्था के द्वारा सतत् निरीक्षण, घरेलू एवं बहुपक्षीय दोनों स्तरों पर पारदर्शिता को बढ़ाने का एक अन्य साधन है।
5. **स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा** (Promotion of Fair Competition)—कभी-कभी WTO को "मुक्त व्यापार" संस्था के रूप में निरूपित किया जाता है, परन्तु यह पूर्णत: सत्य नहीं है। यह व्यवस्था प्रशुल्कों को तथा सीमित स्तर पर अन्य प्रकार के संरक्षण की भी अनुमति देती है। यह कहना ज्यादा सत्य होगा कि यह खुला, स्वच्छ, अविकृत प्रतिस्पर्धा वाले नियमों पर आधारित व्यवस्था है। WTO की कुछ अन्य संधियों का लक्ष्य कृषि, बौद्धिक संपदा सेवाऐं आदि में स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देना है।

TOUCH 'n PASS

6. **विकास एवं आर्थिक सुधारों को बढ़ावा** (Promotion of Development and Economic Reforms)—WTO व्यवस्था विकास में योगदान देती है। वहीं दूसरी ओर विकासशील देशों को WTO संधियों के कार्यान्वयन हेतु अपनी नीतियों में नम्यता लाने की आवश्यकता होती है। ये संधियाँ GATT के उन पूर्ववर्ती प्रावधानों को भी शामिल करती है जो विकासशील देशों के लिए विशेष सहायता और व्यापार रियायत देती है जिससे वे उच्च संवृद्धि और विकास को प्राप्त कर सके।

प्र.4. अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण अथवा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ एवं व्यापार से लाभ का वर्णन कीजिए।
Describe International Specialisation or the advantages of International Trade and benefits of trade.

उत्तर

अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण अथवा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ
(International Specialisation or Advantages of International Trade and Benefits from Trade)

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अथवा विशिष्टीकरण के मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं—

1. **प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग**—अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण के कारण प्राकृतिक साधनों का सम्पूर्ण उपयोग किया जा सकता है। अल्पविकसित देश अपने खनिज पदार्थों का स्वयं उपयोग करने की स्थिति में नहीं है ये देश अपने कच्चे माल का निर्यात विकसित औद्योगिक देशों में करते हैं।
2. **सस्ती वस्तुएँ**—अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण के कारण, सभी देशों को कम कीमतों पर वस्तुएँ उपलब्ध हो जाती हैं। इसका कारण यह है कि प्रत्येक देश उन वस्तुओं का उत्पादन करता है जिनके बनाने में तुलनात्मक लागत कम आती है। तद्नुसार अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण या व्यापार ने उच्च स्तर की खपत को सुविधाजनक बनाया और इसलिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता हुई।
3. **अतिरिक्त उत्पादन**—अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण के कारण प्रत्येक देश को अपने अतिरिक्त उत्पादन को बेचने का अवसर मिलता है। कुछ देश वस्तुओं का उत्पादन अपनी आवश्यकता से अधिक कर लेते हैं। इन अतिरिक्त वस्तुओं को अन्य देशों में बेचकर कीमतों में होने वाली कमी को रोका जा सकता है।
4. **थोक उत्पादन और पैमाने की अर्थव्यवस्थाएँ**—अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण के कारण विभिन्न देश अकेले उन वस्तुओं के उत्पादन में विशेषज्ञ हैं जिनमें वे अनुकूल उत्पादन की स्थिति का आनंद लेते हैं। परिणामस्वरूप वस्तुओं का बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्थाओं के साथ कम कीमत पर बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। मक्कोनल के शब्दों में, "अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का ऐसा साधन है जिसके द्वारा राष्ट्र अपने संसाधनों की उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं और इससे बड़े उत्पादन का एहसास हो सकता है।"
5. **आर्थिक विकास की सम्भावना**—किसी भी देश का आर्थिक विकास अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर करता है। अल्पविकसित देश विकसित देशों से मशीनरी, तकनीकी ज्ञान तथा अन्य सहायक उपकरणों का आयात करके उपलब्ध प्राकृतिक साधनों तथा कच्चे माल का इष्टतम अथवा अनुकूलतम उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार उत्पादन के बढ़ाने में वे सक्षम हो सकते हैं और आर्थिक विकास की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। रॉबर्टसन के अनुसार, "अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संवृद्धि का इंजन है।"
6. **अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग**—अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण विभिन्न देशों में परस्पर सहयोग की भावना को प्रोत्साहन देता है। यह व्यापारिक देशों के बीच सद्भावना, सौहर्दपूर्णता और मित्रता की भावना को जागृत करता है। हेनरी गोमज के शब्दों में, "अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण लोगों को सभ्य बनाने का सबसे बड़ा माध्यम है।"

व्यापार के लाभ (Benefits of Trade)

व्यापार या दी गई लागत के साथ विशिष्टीकरण से लाभ

व्यापार से प्राप्त लाभ अलग-अलग सिद्धांत पर निर्भर करता है जिसके बारे में नीचे चर्चा की गई है। इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न देशों में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन की लागत में अंतर होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार है। लागतों में अंतर निम्न प्रकार का हो सकता है—

TOUCH 'n' PASS

लागतों में निरपेक्ष अंतर

एड्म स्मिथ ने निरपेक्ष अंतर लागत सिद्धांत दिया। सिद्धांत के अनुसार, विभिन्न देशों में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन की लागत में निरपेक्ष अन्तर अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण व्यापार के पीछे मूल कारण है। लागतों में निरपेक्ष अन्तर उस समय पाया जाता है जबकि कोई एक देश किसी वस्तु को, दूसरे देश की तुलना में, काफी कम लागत पर उत्पन्न कर लेता है तथा दूसरा देश किसी अन्य वस्तु को पहले देश की तुलना में काफी कम लागत पर उत्पन्न कर लेता है। यह तब संभव होता है जबकि एक देश में विशेष प्रकार की भूमि, जलवायु, परिस्थितियाँ तथा सुविधाएँ पाई जाती हैं। इस प्रकार एक देश एक वस्तु के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त करके उसका अधिक उत्पादन करता है और उसका निर्यात करता है तथा दूसरी वस्तु का दूसरे देश से आयात करता है। जिसमें कि दूसरा देश विशिष्टता प्राप्त करता है। इसको तालिका द्वारा आगे और स्पष्ट किया गया है—

तालिका : दो देशों की लागतों में निरपेक्ष अन्तर

देश	चावल	गेहूँ
भारत	2	4
नेपाल	4	2
कुल	6	6

तालिका से स्पष्ट है कि भारत में श्रम की 1 इकाई द्वारा 2 इकाइयाँ चावल या 4 इकाइयाँ गेहूँ उत्पन्न किया जाता है, जबकि नेपाल में श्रम की 1 इकाई द्वारा 4 इकाइयाँ चावल या 2 इकाइयाँ गेहूँ उत्पन्न किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि

भारत में 1 इकाई चावल = 2 इकाइयाँ गेहूँ

नेपाल में 1 इकाई चावल = 0.5 इकाई गेहूँ

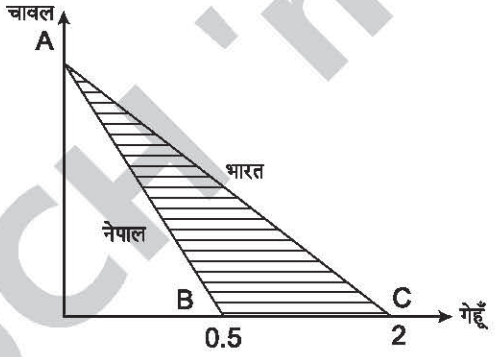

चित्र : 1

उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि भारत को गेहूँ के उत्पादन में और नेपाल को चावल के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की एक आवश्यक शर्त है कि दो देशों के बीच वस्तुओं की उत्पादन लागत का अनुपात भिन्न होना चाहिए। भारत में गेहूँ के लिए चावल का लागत अनुपात 1 : 2 है और नेपाल में यह 1 : 0.5 है। यदि ये दोनों देश दोनों वस्तुओं का ही उत्पादन करें और परस्पर व्यापार न हो तो दोनों देशों में दो दिन के श्रम के फलस्वरूप गेहूँ का कुल उत्पादन 6 इकाइयाँ और चावल का कुल 6 इकाइयों का उत्पादन ही होगा। मान लीजिए भारत गेहूँ में तथा नेपाल चावल में विशिष्टता प्राप्त करते हैं और व्यापार करते हैं।

चित्र में AB नेपाल की और AC भारत की उत्पादन संभावना वक्र है। उत्पादन संभावना वक्र से यह ज्ञात होता है कि उत्पादन के साधनों की एक निश्चित मात्रा का उपयोग करने से किसी वस्तु की एक इकाई का अधिक उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु की कितनी इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा। इन रेखाओं के ढ़लान द्वारा विभिन्न वस्तुओं की अवसर लागत (opportunity cost) स्पष्ट हो जाती है अवसर लागत से अभिप्राय यह है कि किसी वस्तु की एक अधिक इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की कितनी इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा। यह चित्र सामान लागत के नियम पर आधारित है। इसीलिए उत्पादन संभावना रेखाएँ सीधी रेखाएँ हैं। AB रेखा से ज्ञात होता है कि यदि नेपाल चावल की 1 इकाई का उत्पादन करता है तो उसे गेहूँ की 0.5 इकाई का त्याग करना होगा। इसलिए यदि उसे चावल की एक इकाई देकर गेहूँ की 0.5 इकाई से अधिक प्राप्त हो जाती है तो उसे लाभ होगा। इसी

TOUCH 'n' PASS

प्रकार AC रेखा से ज्ञात होता है कि यदि भारत चावल की 1 इकाई का उत्पादन करेगा तो उसे गेहूँ की 2 इकाई का त्याग करना पड़ेगा, इसलिए यदि भारत को गेहूँ की 2 से कम इकाई देने पर चावल की 1 इकाई प्राप्त हो जाती है तो भारत को गेहूँ का उत्पादन करने में लाभ होगा। चित्र में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले लाभों को ABC क्षेत्र की सहायता से प्रदर्शित किया गया है। इन दोनों देशों में लाभ का बँटवारा दोनों देशों के बीच स्थापित व्यापार की शर्तों के आधार पर होगा। व्यापार की शर्तें प्रत्येक वस्तु के लिए सम्बन्धित देशों में अनुवर्ती माँग (Reciprocal Demand) द्वारा निर्धारित होती हैं।

प्र.5. वैश्विक व्यापार प्रतिरूप एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के गुण व हानियों का वर्णन कीजिए।
Describe the Global Trade Pattern and merits and demerits of Foreign Direct Investment.

उत्तर

वैश्विक व्यापार प्रतिरूप
(Global Trade Pattern)

वैश्विक अर्थव्यवस्था में भार एवं मूल्य दोनों के संदर्भ में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि एक उभरती हुई प्रवृत्ति है। वैश्विक व्यापार प्रतिरूप के उद्‌भव को स्पष्ट रूप से तीन प्रमुख अवस्थाओं में बाँटा जा सकता है—

प्रथम अवस्था—1970 के दशक तक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पारम्परिक दृष्टिकोण से चलता रहा, जिसमें उत्पादन के साधनों की गतिशीलता अत्यन्त कम थी। विशेषत: कच्चे माल, निर्मित एवं अनिर्मित उत्पादों की भी सीमित गतिशीलता थी। इस अवस्था में विदेशी स्वामित्व वाली कम्पनियाँ प्रशुल्क, नियतांश, सीमा आदि के द्वारा विनियमित होती थी। इस अवधि में एक श्रेणी विशेष के उत्पाद विशेषकर उपभोक्ता वस्तुएँ जो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं में निर्मित रूप में उपलब्ध नहीं होती थी, व्यापार की एक प्रमुख वस्तु थी। व्यापार संरक्षणवाद, विनियमन तथा अपेक्षाकृत अधिक परिवहन मूल्यों के कारण सामान्यत: सीमित था। इस समय व्यापार आर्थिक दक्षता बढ़ाने का माध्यम न होकर वस्तुओं की कमी से निबटने का साधन मात्र था।

द्वितीय अवस्था—1970 के दशक से उत्पादन के साधनों विशेषत: पूँजी की गतिशीलता संभव हो सकी। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु बनाए गए भौतिक एवं विधिक वातावरण ने क्षेत्रीय विशिष्टता के तुलनात्मक लाभ के कार्यान्वन को अग्रसर किया, इसके साथ ही क्षेत्रीय व्यापार संधियों के उद्‌भव तथा वैश्विक व्यापार ढाँचा को मजबूत करने हेतु विधिक एवं सक्षम कार्य सम्पादक दृष्टिकोण उभरा। पुराने औद्योगिक क्षेत्रों में उच्च उत्पादन लागत के कारण श्रम-गहन क्रियाकलापों का स्थानान्तरण धीरे-धीरे कम लागत वाली नई अवस्थितियों की ओर हुआ। यह प्रक्रिया राष्ट्रीय रूप में प्रारम्भ हुई जो सीमावर्ती देशों से होकर एक विश्व-व्यापी परिघटना बन गई। इस प्रकार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के द्वारा अपनी परिसम्पत्ति के वैश्विक स्थानान्तरण में लचीलापन आने के कारण नए विनिर्माण क्षेत्रों की ओर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह में तेजी आई।

तृतीय अवस्था—इस अवस्था में विविध प्रकार के सेवाओं, जो पहले मुख्यत: क्षेत्रीय बाजारों तक ही सीमित थी, के उत्पादन के साधनों में गतिशीलता में प्रवाह के फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में तीव्र वृद्धि हुई। जब से यह प्रवृत्तियाँ सुस्थापित हुई है तब से उत्पादन, वितरण तथा उपभोग के संदर्भ में भौगोलिक एवं कार्यात्मक एकीकरण को प्रमुखता प्राप्त हुई है, जो वैश्विक उत्पादन प्रतिरूप के उद्‌भव के साथ हुआ। इन जटिल तंत्रों में उपभोक्ता, निर्मित एवं अनिर्मित उत्पाद तथा सूचना का प्रवाह सम्मिलित है, जो परिवहन एवं वितरण में आई तीव्रगतिशीलता के फलस्वरूप हुआ।

इस प्रकार वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को सेवा, वित्त, खुदरा, विनिर्माण तथा वितरण में बढ़ते एकत्व के रूप में निरूपित किया जा सकता है जो मुख्यत: बेहतर परिवहन एवं संचार-तंत्र, क्षेत्रीय तुलनात्मक लाभों का अधिक बेहतर तरीकों से दोहन तथा वैश्विक व्यापार में विधिक एवं वित्तीय जटिलताओं हेतु समर्थनकारी कार्य निष्पादक पर्यावरण के फलस्वरूप हुआ। अतएव कई विकासशील देशों की अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ती सहभागिता से वैश्विक व्यापार की प्रवृत्ति में परिवर्तन आया है। वैश्विक उपभोक्ता कड़ी के उद्‌भव के फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रकृति में भी बदलाव आया है। यह बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के द्वारा अपने उत्पादक परिसम्पत्तियों का निम्न लागत क्षेत्रों की ओर स्थानान्तरण तथा परिवहन किराया एवं वितरण तंत्र के सशक्तता को बनाए रखते हुए नये बाजारों के लाभ को अधिकतम करने की प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है। इसके अलावा एक महत्त्वपूर्ण प्रवृत्ति विकासशील देशों से ऊर्जा, उपभोक्ता एवं कृषिगत उत्पादों का बढ़ता निर्यात है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि का सबसे महत्त्वपूर्ण कारण विकासशील देशों में उत्पादक गतिविधियों के फलस्वरूप इनके हिस्से में बढ़ोतरी है, जो उत्पादकों के द्वारा आपूर्ति के विविध स्तरों की ओर स्थानान्तरण के कारण हुई है। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में परिवर्तन की साम्यता, विनिर्माण, उत्पादन एवं उपभोग में परिवर्तन से स्पष्ट होता है। तथापि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में उतार-चढ़ाव के लिए मुख्यत: आर्थिक चक्र में तेजी व मंदी, कच्चे माल की कीमतों में अस्थिरता के साथ ही विघ्नकारी भू-राजनीतिक तथा

TOUCH 'n PASS

आर्थिक घटनाएँ जिम्मेवार होती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय उत्पादन व्यवस्था में वर्गीकरण के फलस्वरूप विनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हुई जिससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में इसकी भागीदारी बढ़ रही है। इसमें अपेक्षाकृत कम भार वाले तरल पदार्थ (जैसे—खनिज तेल) तथा अपेक्षाकृत शुष्क भार और सामान्य भार वाले पदार्थों का व्यापार होता है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के भूगोल पर अभी भी कुछ ही देशों का वर्चस्व हैं— विशेषकर अमेरिका एवं यूरोप। अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और जापान विश्व व्यापार के एक तिहाई भाग पर कब्जा रखते हैं, परन्तु अब इन देशों के एकाधिकार को गंभीर चुनौती मिली है। पुन: जी-7 देशों ने (प्रफांस, जर्मनी, इटली, जापान, यू०एस०, ब्रिटेन तथा कनाडा) पिछले 100 वर्षों से विश्व के कुल व्यापार के आधे से अधिक हिस्सों पर एकाधिकार बनाए रखा है। एशिया के विकासशील देशों, विशेषत: चीन की वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी में निरपेक्ष एवं सापेक्ष दोनों ही दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई है। यह भौगोलिक तथा आर्थिक परिवर्तन इस तथ्य से भी स्पष्ट होता है कि अटलांटिक पारीय व्यापार के मुकाबले प्रशांत पारीय व्यापार में तीव्र वृद्धि हुई है।

वैश्विक व्यापार का एक प्रमुख लक्षण इसका प्रादेशिकीकरण या क्षेत्रीयकरण है। अधिकांश अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रादेशिकता के लक्षण से अभिहित है, जो आर्थिक प्रखण्डों की अवस्थिति एवं सामीप्यता के कारण बढ़ी है; जैसे—नाफ्रटा और यूरोपीय यूनियन। निकटस्थ आर्थिक व्यवस्था के आपस में अधिक व्यापार की संभावना होती है, जिसे पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के मध्य होने वाले सघन व्यापार से समझा जा सकता है। एशिया में इसी प्रकार की एक नवीन प्रवृत्ति उभरी है, जो विशेष रूप से जापान, चीन, कोरिया और ताइवान के मध्य परिलक्षित होती है।

आर्थिक रूप से शक्तिशाली अधिकांश देशों ने मुक्त व्यापार का जोरदार तरीके से समर्थन किया है। परन्तु वे स्वयं रणनीतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण उद्योगों को चयनात्मक समर्थन देने में लगे हुए है। उदाहरणस्वरूप, यू०एस० तथा यूरोप ने कृषि क्षेत्र हेतु चयनात्मक संरक्षण प्रदान किया है। जब नीदरलैंड तथा ब्रिटेन आर्थिक रूप से समर्थ थे तब उन्होंने भी मुक्त व्यापार की जोरदार वकालत की। वर्तमान समय में यू०एस०, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया तथा जापान इसके प्रमुख समर्थक हैं। तथापि बहुत से अन्य देश (जैसे—भारत, चीन और रूस) जो आर्थिक रूप से अधिक सशक्त हो रहे हैं, ने भी इसका भरपूर समर्थन किया है। प्रशुल्क स्तरों में गिरावट के उपरांत इन देशों ने गैर-प्रशुल्क बाधाओं जिनमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रबंधन तथा व्यापार सुविधायें शामिल हैं, पर भी बातचीत की इच्छा इन देशों ने जताई है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा पूँजी का अंतर्प्रवाह
(Foreign Direct Investment and Capital Inflows)

किसी देश की एक कम्पनी द्वारा दूसरे देश में भौतिक निवेश के माध्यम से कारखाने की स्थापना को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह एक विदेशी द्वारा एक उद्यम की स्थापना है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वह अवस्था है जिसमें कोई निवेशक अपने किसी ऐसे उद्यम में अपने बेहतर लाभ के लिए निवेश करता है जो उसके अर्थव्यवस्था के बाहर स्थित है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एक उद्यम के उद्भव या पितृ—उद्यम तथा एक बाह्य या विदेशी सम्बद्धता को इंगित करता है, जो साथ मिलकर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का निर्माण करते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होने की आवश्यक शर्तें हैं— जब अपने विदेशी सम्बद्ध उद्यमों पर पितृ-उद्यम का पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इस नियंत्रण को उद्यम का 10% या उससे अधिक का अंश या उद्यम में मतदान अधिकार या निगमित व अनिगमित उद्यमों में समान अधिकार, या निम्न स्वामित्व वाले अंश, जिन्हें पोर्टफोलियों निवेश कहा जाता है, के रूप में परिभाषित करता है।

भूमि, खदान, कारखानों आदि उत्पादक परिसम्पत्तियों में विदेशी स्वामित्व को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मापक के रूप में प्रयोग किया जाता है। बढ़ते विदेशी निवेश को बढ़ते आर्थिक वैश्वीकरण का एक मापक माना जा सकता है। विदेशी निवेश में अधिकतम प्रवाह औद्योगिक देशों के मध्य सम्पन्न होता है (उत्तर अमेरिका, उत्तर-पश्चिमी यूरोप तथा जापान)। तथापि, बदलते समय में गैर-औद्योगीकृत देशों में भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है।

अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को निम्नरूपों में वर्गीकृत किया जाता है एक व्यक्ति, सम्बन्धित व्यक्तियों का एक समूह, एक निगमित या गैर-निगमित इकाई, एक सार्वजनिक या निजी कम्पनी, सम्बन्धित उद्यमों का एक समूह, एक सरकारी संस्था अथवा कोई परिसंपत्ति।

किसी भी मेजबान अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विभिन्न तरीकों से सम्भव हो सकता है किसी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी को समाविष्ट करना, किसी सम्बद्ध कंपनी के अंशों को धरित करना, असम्बद्धित उद्यमों के ग्रहण एवं अधिग्रहण तथा किसी अन्य निवेशक या उद्यम के साथ मिलकर संयुक्त उद्यम में सहभागिता करना। बहुत सारे मेजबान देश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

को आकर्षित करने के लिए कई प्रकार के प्रोत्साहन उपलब्ध करवाते हैं; जैसे— निगम कर की निम्न दर, कर-अवकाश, विभिन्न प्रकार की कर रियायतें, अधिमानी प्रशुल्क, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों का निर्माण, निवेशगत वित्तीय सहायता, उदार ऋण या ऋण प्रत्याभूति, पुनर्स्थापन तथा निर्वासन सहायता, रोजगार प्रशिक्षण तथा रोजगार सब्सिडी, आधारभूत संरचना सब्सिडी तथा शोध एवं अनुसंधान सहायता को बढ़ावा।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के गुण/लाभ (Merits of FDI)

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का एक महत्त्वपूर्ण लाभ यह है कि उस देश में जहाँ यह निवेश होता है, उसका आर्थिक विकास तीव्र हो जाता है। यह बात मुख्यतया विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों पर लागू होती है। नब्बे के दशक से आर्थिक रूप से विकास कर रहे अधिकांश देशों के लिए वित्त का बाह्य स्रोत ही है। यह भी देखा गया है कि कई देशों को आर्थिक संकट का सामना करने में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने मद्द की है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तकनीकों के स्थानांतरण की भी अनुमति प्रदान कर रहा है। यह मुख्यत: पूँजीगत आगतों के रूप में होता है। तकनीकों के स्थानान्तरण का महत्त्व इसी बात से प्रकट होता है कि वस्तुओं तथा सेवाओं के व्यापार तथा वित्तीय संसाधनों के निवेश से यह भिन्न होता है। यह किसी देश के स्थानीय आगत बाजार (Local input market) में प्रतिस्पर्द्धा को भी बढ़ावा देता है।

वैसे देश, जो दूसरे देशों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करते हैं, अपने देश के उस व्यवसाय विशेष में मानव संसाधन को रोजगार एवं प्रशिक्षण द्वारा उन्नत बनाते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश उत्पन्न लाभ पर निगम कर प्राप्त करते हैं, जो उस देश के राजस्व संसाधन को भी बढ़ाते हैं।

जिस किसी भी देश में निवेश होता है वहाँ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश रोजगार के नये अवसरों को जन्म देते हैं। यह कामगारों के वेतन वृद्धि में भी सहयोग करता है। यह उनके जीवन-स्तर तथा जीवन-यापन की सुविधाओं को और अधिक बेहतर बनाता है। सामान्यत: यह देखा गया है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ग्रहणकर्ता देशों के विनिर्माण क्षेत्रों के विकास में भी योगदान देते हैं।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करों के माध्यम से उत्पन्न राजस्व के द्वारा आय स्तर में भी वृद्धि करता है। यह मेजबान देश की उत्पादन क्षमता की वृद्धि में भी बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो देश दूसरे देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करते हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिलता है। इन देशों की कम्पनियाँ इन पूँजियों के माध्यम से नये बाजारों को तलाशती है तथा अपने लाभ एवं आय दोनों को अर्जित करती है।

इसके माध्यम से, प्राप्तकर्त्ता या ग्राह्य देश बेहतरीन तकनीकी संसाधनों के फलस्वरूप निर्यात के अधिक अच्छे अवसर प्राप्त करता है। दूसरे देशों से प्राप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाले देशों में इसके फलस्वरूप ब्याज दरों को निम्न स्तर पर बनाए रखने में मद्द मिलती है। इससे व्यापारिक उद्यमों को निम्न ब्याज दरों पर आसान ऋण प्राप्त करना सुलभ हो जाता है। इसका लाभ छोटे एवं मध्यम आकार के उद्यमों को सर्वाधिक होता है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से हानियाँ/इसके अवगुण (Demerits of FDI)

कार्मिक तथा व्यक्तिगत एवं निवेश के क्षेत्र में लाभ का संचालन तथा उसके वितरण से सम्बन्धित मुद्दों से ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सर्वाधिक कमियाँ सम्बन्धित है। एक अन्य सबसे बड़ी खामी या कमी है एक कम्पनी का किसी बाह्य देश में स्वामित्व खोने का खतरा। प्राय: यह किसी कम्पनी के द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में अत्यधिक सतर्कता बरतने के कारण होता है। यह भी देखा गया है कि एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में समय-समय पर अस्थिरता उत्पन्न होती रहती है, जिससे निवेशकर्त्ताओं को व्यापक असुविधा होती है। किसी मेजबान देश का आकार, उसकी स्थिति तथा बाजार भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए महत्त्वपूर्ण आधार तैयार करता है। मेजबान देशों के अपने प्रगतिशील पड़ोसियों से बेहतर परिवहन एवं संचार सुविधा का अभाव भी, निवेशकर्त्ता के समक्ष चुनौती उत्पन्न करता है।

यह भी देखा गया है कि मेजबान देशों की सरकारें भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से समस्याओं का सामना करती हैं। इन सरकारों का इन कम्पनियों पर नियंत्रण अत्यन्त कम होता है क्योंकि ये कम्पनियाँ किसी विदेशी कम्पनी के अनुषंगी कम्पनी के रूप में कार्य करती हैं। फलत: यह कई गंभीर विवादों को जन्म देती हैं। निवेशक जहाँ निवेश करते हैं, उस देश की आर्थिक नीतियों के प्रति पूर्ण आज्ञाकारी नहीं होते हैं। कभी-कभी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रतिकूल प्रभाव भुगतान संतुलन पर भी देखने को मिलता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की इन समस्त खामियों पर ध्यान देने के बावजूद यह कहा जा सकता है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने विश्व के कई देशों के भाग्य-निर्धारण में मद्द दी है।

TOUCH 'n' PASS

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्र.1. विश्व व्यापार संगठन कब प्रभाव में आया?
(क) 6 मार्च, 1996 (ख) 8 अप्रैल, 1994 (ग) 5 फरवरी, 1994 (घ) 1 जनवरी, 1995
उत्तर (घ) 1 जनवरी, 1995

प्र.2. विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य मौजूद हैं?
(क) 207 (ख) 195 (ग) 160 (घ) 164
उत्तर (घ) 164

प्र.3. विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
(क) ऑस्ट्रिया (ख) जेनेवा (ग) न्यूयॉर्क (घ) वाशिंगटन डीसी
उत्तर (ख) जेनेवा

प्र.4. इनमें से कौन-सा संस्थान विश्व बैंक समुदाय का हिस्सा नहीं है?
(क) आईएफसी (ख) आईडीए (ग) विश्व व्यापार संगठन (घ) आईबीआरडी
उत्तर (ग) विश्व व्यापार संगठन

प्र.5. विश्व बैंक और ..... के साथ, विश्व व्यापार संगठन विश्वव्यापी आयामों का तीसरा आर्थिक स्तंभ है।
(क) अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संघ (आईईए) (ख) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)
(ग) अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक (आईडीबी) (घ) इंटरनेशनल फंडिंग ऑर्गनाइजेशन (IFO)
उत्तर (ख) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)

प्र.6. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है?
(क) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का वोट शेयर 10% है।
(ख) IMF और IBRD दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन में है।
(ग) IBRD को विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है।
(घ) आईएमएफ और विश्व बैंक दोनों को ब्रेटन वुड्स जुड़वाँ के रूप में जाना जाता है।
उत्तर (क) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का वोट शेयर 10% है।

प्र.7. निम्नलिखित विकल्पों में से कौन-सा विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य नहीं है?
(क) पर्यावरण की रक्षा के लिए
(ख) सदस्य देशों के भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार करना
(ग) सदस्य देशों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना
(घ) वस्तुओं के उत्पादन और व्यापार को बढ़ाना
उत्तर (ख) सदस्य देशों के भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार करना

प्र.8. विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान (2023 में) महानिदेशक कौन है?
(क) पास्कल लैमी (ख) न्गोजी ओकोंजो-इवेला (ग) चेदली क्लीबी (घ) रॉबर्टो एजेवेडो
उत्तर (ख) न्गोजी ओकोंजो-इवेला

प्र.9. TRIPS (बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधित पहलू) समझौते को ..... द्वारा प्रशासित किया जाता है।
(क) विश्व बैंक (डब्ल्यूबी)
(ख) संयुक्त राष्ट्र संगठन (यूएनओ)
(ग) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)
(घ) व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीटीएडी)
उत्तर (ग) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)

TOUCH 'n' PASS

प्र.10. निम्नलिखित में से कौन-सा सदस्य OPEC में शामिल नहीं है–
(क) अल्जीरिया (ख) गैबोन (ग) कांगो (घ) इण्डोनेशिया
उत्तर (घ) इण्डोनेशिया

प्र.11. आसियान (ASEAN) में सदस्य देशों की संख्या है–
(क) 9 (ख) 10 (ग) 11 (घ) 8
उत्तर (ख) 10

प्र.12. आसियान (ASEAN) का केन्द्रीय सचिवालय कहाँ पर स्थित है?
(क) जकार्ता (ख) नई दिल्ली (ग) मनीला (घ) सिंगापुर
उत्तर (क) जकार्ता

प्र.13. सार्क (SAARC) का मुख्यालय कहाँ पर है?
(क) नई दिल्ली (ख) काठमाण्डू (ग) कोलम्बो (घ) माले
उत्तर (ख) काठमाण्डू

प्र.14. सार्क (SAARC) की स्थापना कब की गई थी?
(क) 1980 (ख) 1990 (ग) 1985 (घ) 1987
उत्तर (घ) 1987

प्र.15. टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता (GATT) कब प्रभावी हुआ?
(क) 1 जनवरी, 1950 (ख) 1 जनवरी, 1961
(ग) 1 जनवरी, 1948 (घ) 1 जनवरी, 1987
उत्तर (ग) 1 जनवरी, 1948

प्र.16. निम्नलिखित में से कौन-सा देश विश्व व्यापार संगठन (WTO) का सदस्य नहीं है?
(क) चीन (ख) रूस (ग) ईरान (घ) ताइवान
उत्तर (ग) ईरान

प्र.17. निम्नलिखित में से कौन-सा WTO का कार्य है?
(क) व्यापार समझौते के कार्यान्वयन, प्रशासन और संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए
(ख) अपने सदस्यों देशों की व्यापार नीतियों की समय-समय पर समीक्षा करना
(ग) भुगतान की बहुपक्षीय प्रणाली की स्थापना में सहायता करना
(घ) (क) और (ख) दोनों
उत्तर (घ) (क) और (ख) दोनों

प्र.18. 30 अक्टूबर, 1947 को जेनेवा में पालिस डेस नेशंस में कितने देशों ने GATT पर हस्ताक्षर किए?
(क) 24 (ख) 25 (ग) 23 (घ) 27
उत्तर (ग) 23

प्र.19. विश्व व्यापार संगठन (WTO) की पहली महिला और पहली अफ्रीकी महानिदेशक कौन बनी है?
(क) यू मायुंग-हे (ख) अमीना मोहम्मद
(ग) कामेन ओकोन्जो (घ) नोमोजी ओकोन्जो-इवेला
उत्तर (घ) नोमोजी ओकोन्जो-इवेला

प्र.20. GATT को विश्व व्यापार संगठन (WTO) में समाहित किया गया–
(क) 1 जनवरी, 1990 (ख) 1 जनवरी, 1995
(ग) 1 जनवरी, 1983 (घ) 1 जनवरी, 2000
उत्तर (ख) 1 जनवरी, 1995

TOUCH 'n' PASS

प्र.21. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में ..... शामिल है।
(क) बौद्धिक गुण (ख) मानव संसाधन (ग) मूर्त सामान (घ) अमूर्त सामान
उत्तर (ग) मूर्त सामान

प्र.22. FDI के तीन विवाद ..... से अधिक है।
(क) एक सोच (ख) ब्याज (ग) सम्मान (घ) शौक
उत्तर (ख) ब्याज

प्र.23. ऑस्ट्रिया यूरोपीय संघ में कब शामिल हुआ?
(क) 1997 (ख) 1993 (ग) 1995 (घ) 1999
उत्तर (ग) 1995

प्र.24. सूचना के प्रसार के लिए, विदेश नीति के निर्णयकर्त्ता ..... पर भरोसा करते हैं।
(क) नौकरशाह (ख) राजनेता (ग) मीडिया (घ) सार्वजनिक
उत्तर (ग) मीडिया

प्र.25. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अधिक विस्तार से ..... को बढ़ावा मिल सकता है।
(क) मुनी सर्कुलेशन (ख) माँग (ग) रोजगार (घ) बेरोजगार
उत्तर (ग) रोजगार

प्र.26. जब ग्राहक विषम होंगे तो ऑफर कर्व कैसे प्रतिक्रिया करेगा?
(क) शून्य चतुर्भुज (ख) नकारात्मक चतुर्भुज
(ग) इष्टतम चतुर्भुज (घ) सकारात्मक चतुर्भुज
उत्तर (ख) नकारात्मक चतुर्भुज

प्र.27. जब पूँजी और श्रम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थानांतरित किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन-सा सुधार होता है?
(क) आर्थिक विकास लाभ (ख) पूँजीगत लाभ
(ग) आय से लाभ (घ) व्यापार से लाभ
उत्तर (ग) आय से लाभ

प्र.28. किस उद्योग में मुफ्त प्रवेश होगा?
(क) खनिज खनन (ख) केबल टेलीविजन
(ग) टी-शर्ट सिल्क स्क्रीनिंग (घ) सैटेलाइट रेडियो
उत्तर (ग) टी-शर्ट सिल्क स्क्रीनिंग

प्र.29. इसे क्या कहा जाता है जब कोई देश किसी विशेष वस्तु में विशिष्ट होता है और फिर वह अन्य देशों के साथ वस्तु का व्यापार करता है?
(क) समझौता (ख) परस्पर निर्भरता (ग) सहसंबंध (घ) निर्भरता
उत्तर (ख) परस्पर निर्भरता

प्र.30. विश्व व्यापार संगठन (WTO) द्वारा व्यापार सुगमता समझौता (TFA) कब लागू हुआ?
(क) 1 जनवरी, 2015 (ख) 22 फरवरी, 2016
(ग) 22 फरवरी, 2017 (घ) 22 फरवरी, 2019
उत्तर (ग) 22 फरवरी, 2017

❑

TOUCH 'n' PASS

UNIT-VIII

विकासशील देशों पर वैश्वीकरण का प्रभाव

Effect of Globalisation on Developing Countries

खण्ड-अ अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. वि-वैश्वीकरण क्या है?

What is De-globalisation?

उत्तर वि-वैश्वीकरण (De-globalisation) शब्द का उपयोग आर्थिक और व्यापार जगत के आलोचकों द्वारा कई देशों की उन प्रवृत्तियों को उजागर करने के लिये किया जाता है जो फिर से उन आर्थिक और व्यापारिक नीतियों को अपनाना चाहते हैं जो उनके राष्ट्रीय हितो को सबसे ऊपर रखें।

ये नीतियाँ अक्सर टैरिफ अथवा मात्रात्मक बाधाओं का रूप ले लेती हैं जो देशों के बीच श्रम, उत्पाद और सेवाओं के मुक्त आवागमन में बाधा उत्पन्न करती हैं।

इन सभी संरक्षणवादी नीतियों का उद्देश्य आयात को महँगा बनाकर घरेलू विनिर्माण उद्योगों को रक्षा प्रदान करना और उन्हें बढ़ावा देना है।

प्र.2. वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए।

What do you understand by Globalisation?

उत्तर आज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से आपस में जुड़ी हुई है उस जुड़ाव को वैश्वीकरण कहते हैं। इसे समझने के लिए गूगल का उदाहरण लेते हैं। यह अमेरिका में स्थित है लेकिन इसके उपभोक्ता दुनिया के हर कोने में हैं। आप दिल्ली में हों या देहरादून में, गूगल की मद्द से कोई भी सूचना आपको चुटकियों में मिल सकती है। आज इस कंपनी के ऑफिस भारत जैसे कई देशों में हैं। गूगल आज वैश्वीकरण का एक जीता जागता उदाहरण है।

प्र.3. भारत सरकार द्वारा विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाने के क्या कारण थे? इन अवरोधकों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी?

What was the reasons for the Indian government putting up barriers in the way of foreign trade and foreign investment? Why did the government want to remove them?

उत्तर आजादी के समय भारत के निजी उद्यमियों के पास पूँजी की कमी थी। इसलिए उस समय स्थानीय उद्योग को संरक्षण की जरूरत थी। स्थानीय उद्योग-धंधे फल-फूल सकें, इसलिए भारत सरकार ने विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाये गये। धीरे-धीरे स्थितियाँ बदलने लगीं और भारत का बाजार आकर्षक बन गया। उसके बाद सरकार ने इन अवरोधकों को हटाने का निर्णय लिया।

प्र.4. श्रम कानूनों में लचीलापन कम्पनियों को कैसे मदद करेगा?

How will flexibility in labour laws help the companies?

उत्तर श्रम कानूनों में लचीलापन कम्पनियों को लाभ पहुँचाएगा। इस कानून की मदद से कम्पनियाँ श्रमिकों की संख्या को नियंत्रित कर पाएँगी। कई व्यवसाय में श्रमिकों की माँग कुछ खास महीनों में ही होती है। अन्य महीनों में ऐसे श्रमिकों की मजदूरी पर का खर्च कम्पनियों को घाटे में ला देता है। लचीले कानून होने से इस बात से छुटकारा मिलेगा और कम्पनी के मुनाफे में सुधार होगा।

TOUCH 'n' PASS

प्र.5. दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ किस प्रकार उत्पादन या उत्पाद पर नियंत्रण स्थापित करती हैं?
How do multinational companies establish control over production or products in other countries?

उत्तर दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ कई तरीकों से उत्पादन या उत्पाद पर नियंत्रण स्थापित करती हैं। इनमें कुछ निम्न प्रकार हैं—

1. अधिकतर MNC शुरु में किसी स्थानीय कम्पनी से साझा वेंचर करते हैं ताकि उनका काम शुरु हो सके। ऐसा इसलिए किया जाता है कि स्थानीय कम्पनी को स्थानीय बाजार का जो ज्ञान होता है उसका लाभ उठाया जा सके। स्थानीय कम्पनी का व्यवसाय पहले से ही जमा जमाया होने का लाभ भी मिलता है।
2. एक समय आता है जब व्यवसाय में अच्छी खासी बढ़ोतरी होती है। उसके बाद MNC साझा वेंचर को समाप्त कर देती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि व्यवसाय पर नियंत्रण और भी बेहतर हो जाये।
3. कुछ MNC पहले दिन से ही स्वतंत्र रूप से काम करना शुरु करती है। ऐसी कम्पनी अक्सर शुरु से ही अपना पूरा नियंत्रण रखना चाहती है।
4. कुछ MNC केवल स्थानीय बाजार के लिये उत्पादन करती है, वहीं कुछ अन्य निर्यात के लिये उत्पादन करती है।

प्र.6. विकसित देश, विकासशील देशों से उनके व्यापार और निवेश का उदारीकरण क्यों चाहते हैं? क्या आप मानते हैं कि विकासशील देशों को भी बदले में ऐसी माँग करनी चाहिए?
Why do developed countries want liberalisation of investments and their trade from developing countries? Do you feel that the developing countries should also demand the same in return?

उत्तर अक्सर विकसित देश की कम्पनियाँ दूसरे देशों में व्यवसाय के लिये अनुकूल माहौल बनाने के लिए अपनी सरकार पर दबाव डालती हैं। उस दबाव में आकर विकसित देश, विकासशील देशों से उनके व्यापार और निवेश का उदारीकरण चाहते हैं। विकासशील देशों को भी ऐसा ही करना चाहिए।

प्र.7. 'वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है।' इस कथन की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए।
"The impact of globalisation is not even." Explain the statement in your own words.

उत्तर यह बात सही है कि वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है। इससे फायदे और नुकसान दोनों हुए हैं। आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत के लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। लेकिन अमीरों और गरीबों के बीच की खाई और भी चौड़ी हो गई है। आर्थिक उदारीकरण के बाद प्रतिस्पर्द्धा भी बढ़ी है जिसके कारण छोटे व्यवसायियों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है।

प्र.8. व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में कैसे सहायता पहुँचाती है?
How do the liberalisation of trade and investment policies help in the process of globalisation?

उत्तर व्यापार और निवेश नीतियों के उदारीकरण से वैश्विक प्रक्रिया में बहुत मदद मिलती है। इन नीतियों के कारण विदेशी निवेश का रास्ता साफ हो जाता है। इसके साथ ही आयात और निर्यात के रास्ते भी खुल जाते हैं। स्थानीय कम्पनियों और व्यवसायियों को क्वालिटी सुधारने की प्रेरणा मिलती है। कई बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को इस बात का मौका मिल जाता है कि विभिन्न देशों से उत्पादन के विभिन्न चरणों को करवा सकें।

प्र.9. विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार मदद करता है? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए।
How does foreign trade help in the unification of markets in different countries?

उत्तर विदेश व्यापार से विश्व के विभिन्न बाजार आपस में जुड़ जाते हैं जिससे उनका एकीकरण होता है। इसे समझने के लिए कार का उदाहरण लेते हैं। फोर्ड अमेरिकी कम्पनी है और कार बनाती है। उसके किसी कार का इंजन अमेरिका में बनता है तो सीट

TOUCH 'n PASS

बेल्ट भारत में। हेडलाइट चीन में बनता है तो गियर बॉक्स ताइवान में। इस तरह से कार निर्माण के विभिन्न चरण दुनिया के विभिन्न कोनों में होते हैं। उसके बाद तैयार कार कई देशों में बिकती है।

प्र.10. वैश्वीकरण भविष्य में जारी रहेगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज से बीस वर्ष बाद विश्व कैसा होगा? अपने उत्तर का कारण दीजिए।

Globalisation will continue in the future. Can you imagine the world twenty years from now? Give reasons for your answer.

उत्तर आज से बीस साल बाद क्या होगा, इसे समझने के लिए आज की तारीख में तेजी से बढ़ते ई-कॉमर्स को देखने की जरूरत है। आज आप जब अमेजॉन पर कोई चीज खरीदने के लिए ऑर्डर लगाते हैं तो हो सकता है वह वस्तु आपसे तीन हजार किलोमीटर दूर स्थित किसी कारखाने में बन रही हो। उसे आप तक पहुँचने में शायद चार पाँच राज्य पार करने पड़े। इसी का विस्तृत रूप हमें बीस साल बाद देखने को मिलेगा। आप झुमरी तिलैया में बैठकर पेरिस की किसी दुकान से सूट मंगा सकते हैं। इन सबको अंजाम देने में कई टेक्नोलॉजी की भूमिका होगी; जैसे—इंटरनेट, तेज गति के यातायात के साधन, ड्रोन ऑनलाइन पेमेंट आदि।

खण्ड-ब लघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. भारत में युवाओं पर वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक-आर्थिक प्रभावों की चर्चा कीजिए।

Discuss different socio-economic effects of globalisation on the India.

उत्तर

भारत में युवाओं पर वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

(Different Socio-Economic Effects of Globalisation on the Youth in India)

वैश्वीकरण विभिन्न देशों के लोगों, कंपनियों और सरकारों के बीच वार्ता, एकता और परस्पर निर्भरता की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। इसमें राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति शामिल हैं। वैश्वीकरण का समाज पर सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों परिणाम होते हैं।

वैश्वीकरण का प्रभाव अत्यधिक व्यापक है। वैश्वीकरण का प्रभाव युवाओं में तीव्र परिवर्तन एवं अनिश्चितता लाने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार, वैश्वीकरण न केवल युवाओं के बीच आर्थिक अवसर प्रदान करता है, बल्कि सामाजिक परिवर्तनों हेतु भी उत्तरदायी है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के साथ, भारत में युवाओं के पास अब एक विशाल संसाधन है। इसके परिणामस्वरूप, उनमें वैश्विक मनोवैज्ञानिक चेतना का विकास हुआ है।

वैश्वीकरण ने खुले बाजार की अवधारणा के परिणामस्वरूप रोजगार के अधिक अवसर पैदा किये हैं।

वैश्वीकरण युवाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने तथा अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनने के लिये प्रोत्साहन एवं स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसने ग्रामीण भारत से बढ़ते प्रवासन के परिणामस्वरूप शहरी गरीबी को जन्म दिया है। यह समाज में संरचनात्मक असमानताओं को भी जन्म देता है। जाति, वर्ग, लिंग, धर्म और आवास में विभाजन के परिणामस्वरूप युवा लोगों में सुभेद्यता, अस्थिरता और असुरक्षा की भावना बढ़ रही है।

वैश्वीकरण के पश्चात् पश्चिमी मूल्यों और संस्कृति का अंधानुकरण हुआ है और युवाओं ने इसे अपनी भारतीय पहचान में शामिल किया है। जैसा कि न केवल आधिकारिक उद्देश्यों के लिये बल्कि दैनिक जीवन में भी अंग्रेजी भाषा युवाओं के बीच भारतीय भाषाओं पर हावी होती जा रही है।

वैश्वीकरण ने विवाह एवं परिवार की संस्थाओं को भी प्रभावित किया है। आज युवा अपने बुजुर्गों के पास नहीं हैं, जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक सम्बन्धों में अंतराल आए हैं।

वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप ही सामाजिक-आर्थिक अनिश्चितता के बढ़ने से युवाओं में अवसाद तथा आत्महत्या की घटनाओं में वृद्धि हुई है।

वैश्वीकरण ने युवाओं में धार्मिक विश्वास को भी प्रभावित किया है। इस प्रकार अधिकांश धार्मिक गतिविधियाँ युवा वर्ग के लिये अप्रासंगिक होती जा रही हैं।

सुखवाद की संस्कृति ने भारतीयों की पारम्परिक मान्यताओं को पूर्णत: बदल दिया है। नतीजतन, आज युवा आबादी, विशेष रूप से शहरी युवा पश्चिमी नए फैशन के पक्ष में हैं।

TOUCH 'n PASS

युवाओं पर वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए उन्हें शिक्षा, कौशल विकास तथा रोजगार, उद्यमिता, स्वास्थ्य एवं स्वस्थ जीवन शैली आदि में अपनी पूरी क्षमता हासिल करने के लिये सशक्त करना चाहिये। राष्ट्रीय युवा नीति–2014 (एन०वाई०पी०–2014) में उल्लेखित सामाजिक मूल्यों का संवर्द्धन, सामुदायिक सहभागिता, राजनीति एवं शासन में भागीदारी, युवा सहभागिता, समावेश और सामाजिक न्याय जैसे कारकों पर जोर देना चाहिए।

प्र.2. वि-वैश्वीकरण के महत्त्व को संक्षेप मे बताइए।

State briefly the importance of de-globalisation.

उत्तर

वि-वैश्वीकरण का महत्त्व
(Importance of De-globalisation)

वि-वैश्वीकरण का महत्त्व निम्न प्रकार हैं—

1. हम अभी भी एक उच्च वैश्वीकृत दुनिया में रहते हैं और ऐसे संरक्षणवादी कदम उन बुनियादी नियमों के विपरीत है जिनके आधार पर वैश्विक विकास का अनुमान लगाया जाता है तथा विश्व व्यापार संगठन (WTO) जैसे संगठन वैश्विक व्यापार को विनियमित करते हैं।
2. जब बड़े, औद्योगीकृत और समृद्ध राष्ट्र वस्तुओं और सेवाओं के प्रवेश को कठिन बनाने के लिए आगे आते हैं तो इससे उनके कई व्यापारिक भागीदारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
3. वैश्विक आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति और ब्याज दरों की सभी गणनाओं में फिर से गड़बड़ हो सकती है।
4. उदाहरण के लिए, अमेरिकी अर्थव्यवस्था चीन से बहुत सस्ती विनिर्मित वस्तुओं का आयात करती है। यदि टैरिफ युद्ध में अमेरिका में आयात की लागतें बढ़ती हैं, तो घरेलू मुद्रास्फीति में बहुत तेजी से वृद्धि हो सकती है और अमेरिकी ब्याज दरों में तेजी से बढ़ोत्तरी हो सकती है।
5. हाल ही में लिये गए इन टैरिफ निर्णयों का भारत पर ज्यादा प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि अमेरिका, भारत से अपने स्टील और ऐलुमीनियम के कुल आयात का केवल 1% ही प्राप्त करता है।
6. लेकिन सेवाओं और श्रम के संदर्भ में वि–वैश्वीकरण से सेवाओं के निर्यात एवं उच्च शिक्षा तथा नौकरियों के लिए विदेशों में प्रवास करने वाले भारतीय नागरिकों पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है।

प्र.3. कृषीय वैश्वीकरण तथा विकासशील देश पर टिप्पणी कीजिए।

Write a note on agricultural globalisation and developing countries.

उत्तर

कृषि वैश्वीकरण तथा विकासशील देश
(Agricultural Globalisation and Developing Countries)

भिन्न-भिन्न समाजों तथा अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहा जाता है। यह परिघटना उत्पादों, सेवाओं, श्रम, वित्त, सूचना एवं विचारों के राष्ट्रीय सीमाओं के पार प्रवाह को समाहित करता है। सामान्यत: विकासशील देशों की नीतिगत व्यवस्था एवं विशेषकर व्यापार नीतियों में 1980 एवं 1990 के दशक के दौरान महत्त्वपूर्ण खुलापन देखने को मिला, जो कि घरेलू अर्थव्यवस्था के बाह्य अर्थव्यवस्था की ओर एकीकरण की ओर अग्रसारित था।

अधिकांश विकासशील देशों में श्रम के सन्दर्भ में अथवा भूमि उत्पादकता के सन्दर्भ में खाद्य उपभोग का स्तर निम्न तथा कृषि में अल्पविकास था। कृषि का अविकसित होना केवल खाद्य उत्पादों की न्यून पूर्ति से ही व्याख्यायित नहीं किया जा सकता है, बल्कि यह खाद्य पदार्थों की निम्न प्रभावी माँग पर भी निर्भर करता है क्योंकि कुल रोजगार एवं आय का बहुत बड़ा भाग कृषि क्षेत्र से आता है। इन देशों के उपभोक्ताओं के लिए खाद्य सामग्रियों का सापेक्षिक मूल्य खासा महत्त्वपूर्ण होता है। यह आय के वास्तविक वितरण का भी प्रमुख निर्धारक है इनमें किराए में भाग, वास्तविक मजदूरी स्तर तथा सकल लाभ दर एवं इससे प्रभावित मुद्रास्फीति सम्मिलित हैं।

इसीलिए वैश्वीकरण के लाभों में, कई स्थानों पर लाभ में शुद्ध वृद्धि, गरीबी के स्तर में कमी एवं खाद्य सुरक्षा के स्तर में वृद्धि प्राप्त हुई है। वैश्वीकरण ने विकास के वाहक के रूप में कम विकसित देशों में कृषि की भूमिका को बढ़ाया है। जिसके द्वारा उनकी घरेलू माँग में वृद्धि से ज्यादा तीव्र गति से कृषि उत्पादन संभव हो सका है। इससे कृषि क्षमता में वृद्धि के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा में भी वृद्धि हुई है। जिससे लाभों में कई गुणा वृद्धि हुई है तथा श्रम गहनता भी बढ़ी है। इस तरह के लाभों के लिए सहभागिता को सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है, साथ ही गरीबों एवं भूखों को भी गरीबी और भुखमरी से इस प्रक्रिया द्वारा निजात दिलाना है।

TOUCH 'n' PASS

1980 के दशक में अधिकांश विकासशील देशों में आये आर्थिक मंदी तथा ऋण संकट से निपटने के लिए विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा लगाई गई कड़ी शर्तों के कारण इनमें अधिकांश परिवर्तन आये। इन सुधार पैकेजों का मुख्य केन्द्र बिंदु गरीब, विकासशील देशों के कृषि क्षेत्र में आंतरिक एवं बाह्य वैश्वीकरण लाना था। इसी क्रम में उरुग्वे दौर की वार्ता हुई जिसमें बहुपक्षीय तथा संस्थागत कृषीय समझौता हुआ, जिसने कड़ी शर्तों पर आधारित इस समझौते से विकसित देशों को असमान लाभ की क्षमता प्रदान की। इसके अलावा यह कार्य बहुपक्षीय पर्यवेक्षण तथा अनुशासन सम्बन्धी नये नियमों द्वारा हुई, जो देशों की राष्ट्रीय नीतियों पर लागू हुई।

विश्व व्यापार संगठन (WTO) के अधीन हुए इस बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था ने स्वायत्त राष्ट्रीय व्यापार नीतियों की संभावना पर बुरा प्रभाव डाला है। इसमें कृषि भी शामिल है जो पूर्ववर्ती गैट (GATT) के दौरान छोड़ दी गई थी। मूल गैट (GATT) भी कृषि व्यापार पर लागू होते थे परन्तु इसमें कई कमियाँ थी, उदाहरण स्वरूप इसने कुछ देशों को कुछ गैर उचित प्रशुल्क: जैसे—आयात कोता और कृषि व्यापार सब्सिडी आदि के द्वारा बहुत ज्यादा बंध था। इनमें भी मुख्य रूप से आयात सब्सिडी का प्रयोग है जो सामान्यत: औद्योगिक उत्पादों पर लागू नहीं होता है।

उरुग्वे दौर की वार्ता ने कृषि क्षेत्र के संदर्भ में पहली बहुपक्षीय संधि का निर्माण किया। यह स्वच्छ प्रतिस्पर्धा एवं कम विकृत व्यवस्था लाने हेतु प्रथम महत्त्वपूर्ण कदम था। यह लगभग छ: वर्षों की अवधि हेतु लागू किया गया तथा विकासशील देशों के लिए यह अवधि 10 वर्षों की थी जो 1995 से प्रारंभ हुई। उरुग्वे दौर की संधि ने कई वार्ताओं के जरिये सुधारों को जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। यह कृषि संधि की कमी की आवश्यकता की पूर्ति हेतु वर्ष 2000 में प्रारम्भ किये गये थे।

कृषि पर उरुग्वे दौर के समझौते ने जो 1990 के मध्य में हुआ था, जिसने कृषि क्षेत्र में अनेक अनुशासनों को लाया, जिसके फलस्वरूप विकासशील देशों की कृषि नीतियों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आया; जैसे— कृषि सम्बन्धी समझौते में भविष्य में किसी भी प्रकार के बंधन को नहीं लाने की बात कही गई तथा विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं को इसके अनुरूप बनाने पर जोर दिया गया। परन्तु कृषीय समझौता एक मात्र ऐसा समझौता नहीं है जिसने कृषि क्षेत्र में वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया। बहुत-सी विकासशील अर्थव्यवस्थाऐं एक दशक या उसके पहले ही स्थिरता एवं संरचनात्मक समायोजन के एक या उससे अधिक दौर पूर्ण कर चुके थे। इस तरह के अधिकांश मामलों में, जो संस्थागत, राजकोषीय एवं व्यापार नीतियों में संशोधन लाया एवं लागू किया गया, ने कृषि पर बहुत प्रभाव डाला। इन परिवर्तनों के कारण सामान्य एवं विशिष्ट दोनों की दृष्टियों से नीतिगत समायोजन की प्रवृत्ति में उल्लेखनीय समानता देखने को मिली, जिसे उरुग्वे दौर तथा कृषीय समझौते ने अधिक तीव्र गति एवं संस्थागत रूप प्रदान किया।

इन सुधारों का मुख्य कारण कृषीय विरोधी नीतियों में कमी तथा तृतीय विश्व में उदारवादी नीतियों को बढ़ावा देना था। यह आयात प्रतिस्थापन, औद्योगीकरण जैसी आर्थिक रणनीतियों तथा नगरीय एवं अफसरशाही रूचियों का प्रतिनिधित्व करने वाली राजनीतिक व्यवस्था के विपरीत थे। GATT एवं WTO के अधीन कृषि का प्रवेश उरुग्वे दौर के कृषीय समझौते के द्वारा 1990 के मध्य में हुआ।

प्र.4. कृषीय समझौते के अधीन विकासशील देशों के लिए विशेष एवं विभेदक उपचारों का उल्लेख कीजिए।
Explain the special & differential treatment for developing countries under agreement of agriculture.

उत्तर कृषीय समझौते के अधीन विकासशील देशों के लिए विशेष एवं विभेदक उपचार
(Special & Differential Treatment for Developing Countries Under Agreement of Agriculture)

विशेष एवं विभेदक सिद्धांत (S&D) यह बताता है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों का कुछ विशेष आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार विकास होना चाहिए। विश्व व्यापार संगठन (WTO) और विशेष एवं विभेदक (S&D) उपचार के मुख्य दो रूप हैं। प्रथम, बाजार पहुँच की संभावना जिसमें विकासशील देशों की वस्तुओं को विकसित देशों के बाजार में पहुँचाने के लिए वरीयता ही विशेष एवं विभेदक (S&D) उपचार की मुख्य विशेषता हैं। द्वितीय, व्यापार नियमों एवं सिद्धांतों के सापेक्ष में विशेष प्रतिबद्धताओं के अलावा विकासशील देशों को इन बहुपक्षीय समझौतों के कार्यान्वयन हेतु छूट दी जा सकती है। उरुग्वे वार्ता में विशेष एवं विभेदक (S&D) सिद्धांत यह भी प्रावधान करता है कि बहुपक्षीय समझौतों के तहत विकासशील देशों को इन नीतियों के सतत् कार्यान्वयन हेतु हर सम्भव तकनीकी सहायता प्रदान की जाए।

TOUCH 'n' PASS

कृषि पर WTO समझौता यह प्रावधान करता है कि विकासशील देशों को विशेष एवं विभेदक (S&D) सिद्धांत के तहत अनेक रास्ते हैं; जैसे वे वर्तमान सीमा शुल्कों में सुरक्षा और स्वयं निर्धारित सीमा के अधीन अपने प्रशुल्क स्तर को निर्धारित कर सके। इन्हें अपने प्रशुल्कों में कटौती हेतु लम्बी समय सीमा दी गयी; जैसे—निर्यात सब्सिडी कटौती और घरेलू समर्थन कटौती (अल्प विकसित देशों पर लागू नहीं)। इस नीति के कार्यान्वयन हेतु वृहत लचीलेपन का प्रावधान किया गया है; जैसे—निवेश सब्सिडी या निर्यात सब्सिडी। सुधार कार्यक्रम के सम्भावित नकारात्मक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए शुद्ध रूप से खाद्यान्न आयातक विकासशील देशों तथा कम विकसित देशों के लिए विशेष प्रावधान किये गये।

इन कारणों से विकासशील देशों पर WTO के नियम बहुत ही कम बाध्यकारी हैं। उदाहरणस्वरूप, 32 विकासशील देशों द्वारा लगाया जाने वाला प्रशुल्क औसतन 20% है। वे इस प्रशुल्क स्तर को अधिकतम 84% तक कर सकते हैं। कुछ देशों द्वारा व्यापार विकृति हेतु घरेलू समर्थन की अनुमन्य सीमा तक तथा कुछ अन्य देशों जो निर्यात सब्सिडी को जारी रखने में सक्षम है, को भी यह अधिकार प्राप्त है। इस सामान्यीकरण का यह अर्थ नहीं है, कि कृषीय संधि के अधीन उनके द्वारा स्वीकार किये गये प्रतिबद्धताओं को, उस विशिष्ट देश के विशिष्ट उत्पाद को इन प्रतिबद्धताओं से पूरी तरह से छूट मिल जाती है।

परन्तु कुछ विकासशील देश कृषीय संधि में दिये गये लचीलेपन को पर्याप्त नहीं मानते हैं। उनका तर्क है कि उन्हें इस बात का पूर्ण अधिकार होना चाहिए कि वे खाद्यान्न सुरक्षा हेतु घरेलू खाद्यान्न उत्पादन का समर्थन एवं संरक्षण, जीवन-यापन सुरक्षा तथा ग्रामीण विकास के अन्य कारकों के साथ ही उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं को वैश्विक मूल्य अस्थिरता तथा आयात प्रवाह से संरक्षण दे सके। उनका यह भी तर्क है कि वर्तमान संधि असमान है। अनुशासन सम्बन्धी नियम विकासशील देशों पर कठोरता से लागू किये जाते हैं, जबकि विकसित देशों के प्रति इनका रवैया अपेक्षाकृत नरम होता है। उदाहरणस्वरूप, कुछ विकासशील देशों द्वारा अपने किसानों को घरेलू सब्सिडी देने के कारण इस संधि के अधीन व्यापार विकृति के समर्थन ने भविष्य में किये जाने वाले व्यापार को सीमित कर दिया गया है, जबकि दूसरी तरफ विकसित देशों को इसी समझौते के अधीन अपने किसानों को व्यापार विकृति के समर्थन में अत्यन्त कम स्तर का कर लगाया गया है।

जबकि उद्देश्य यह था कि विकासशील देशों के मुकाबले विकसित देशों द्वारा अधिक मात्रा में प्रशुल्कों में कटौती की जायेगी (अल्प विकसित देशों द्वारा किसी प्रकार की कटौती नहीं की जायेगी)। जिस प्रकार से जुलाई 2004 में स्तरीय फार्मूले पर सहमति बनाई गयी जिससे विशेष एवं विभेदक (S&D) उपचार को बढ़ाकर "फ्रेमवर्क संधि" (प्रारूप संधि) द्वारा इसके महत्त्व को और बढ़ाकर लागू किया गया। इनमें सम्मिलित महत्त्वपूर्ण मुद्दों में प्रशुल्क सीमाओं की स्थिति एवं संख्या तथा घटाये जाने वाले गुणकों का आकार महत्त्वपूर्ण है। विकसित और विकासशील दोनों देशों को कुछ संख्या में उत्पादों को संवेदनशील उत्पादों के रूप में वर्गीकरण का अधिकार दिया गया है। यहाँ इस बात को लागू करने के लिए स्तरीय सूत्रों को लागू करना आवश्यक माना गया है।

इसके अलावा विकासशील देश एक अच्छी खासी मात्रा में उत्पादों को विशेष उत्पाद के रूप में चिन्हित कर सकते हैं, जो उनके खाद्यान्न सुरक्षा तथा ग्रामीण विकास की आवश्यकताओं से सम्बन्धित हो। इन उत्पादों के साथ अधिक नरम व्यवहार किया जायेगा, जो आगे होने वाली वार्त्ता के चयन एवं उपचार का आधार बनेंगे।

विशेष सुरक्षा उपाय विकासशील देशों के उत्पादकों के आयात प्रवाह तथा आयात मूल्य में अस्थिरता से बचाने के लिए आवश्यक है, जो कि वैकल्पिक जोखिम प्रबन्धन तथा सुरक्षा उपायों की अनुपस्थिति में और भी महत्त्वपूर्ण हो जाते हैं। यह भी स्वीकार किया जाता है कि विशेष सुरक्षा उपाय व्यवस्था WTO के विकासशील सदस्य देशों के लिए प्रयोग में लाई गयी, परन्तु महत्त्वपूर्ण मापदंड; जैसे—इसमें सम्मिलित होने वाले देश, उत्पाद, खतरनाक स्तर तथा पूर्व परिस्थितियाँ, उपचार के प्रकार एवं अवधि आदि पर निर्णय होना बाकी है।

विकासशील देशों ने यह प्रस्ताव दिया है कि अम्बर बाक्स नीति के साथ अन्य नियमों में भी व्यापक परिवर्तन किया जाना चाहिए, जिससे कि वे अपने उत्पादकों को ज्यादा बेहतर तरीके से बजटीय सहायता प्रदान कर सकें।

प्र.5. वित्तीय वैश्वीकरण पर टिप्पणी लिखिए।

Write a note on financial globalisation.

उत्तर

वित्तीय वैश्वीकरण
(Financial Globalisation)

वित्तीय वैश्वीकरण एक देश के स्थानीय वित्तीय व्यवस्था का अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों एवं संस्थानों के साथ एकीकरण है । यह एकीकरण सरकारों द्वारा घरेलू वित्तीय क्षेत्रों तथा पूँजी खाते को उदार बनाये जाने की आवश्यकता रखता है। यह एकीकरण तब होता है जब उदारीकृत अर्थव्यवस्था में बड़ी मात्रा में सीमापारीय पूँजी प्रवाह के साथ-साथ उस देश के स्थानीय लेनदारों-देनदारों के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय मध्यवर्ती कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लिया जाता है। अभी इस वित्तीय

वैश्वीकरण की प्रक्रिया में विकसित देश जहाँ अधिक सक्रियता से भाग ले रहे हैं, वहीं विकासशील देशों ने भी अधिक सक्रियता से भाग लेना प्रारंभ कर दिया है।

सैद्धांतिक रूप से वित्तीय वैश्वीकरण तथा वित्तीय एकीकरण दो अलग-अलग संकल्पनायें हैं। जहाँ वित्तीय वैश्वीकरण वित्त के सीमापारीय प्रवाह के साथ-साथ इसके बढ़ते वैश्विक जुड़ाव को समाहित करता है, वही वित्तीय एकीकरण किसी देश विशेष के अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी बाजार से जुड़ाव को बताता है। तथापि ये संकल्पनायें आपस में बहुत निकटता से जुड़ी हैं।

वित्तीय वैश्वीकरण ने पिछले 30 वर्षों में कई परिवर्तनों का अनुभव किया है। कई तकनीकी प्रगति, घरेलू वित्तीय क्षेत्रों तथा पूँजी खाते के वैश्वीकरण ने नये विकासों को आगे बढ़ाया है। वित्तीय वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले मुख्य कारकों में सरकारें, निजी निवेशक तथा लेनदार एवं वित्तीय संस्थायें प्रमुख हैं। वित्तीय वैश्वीकरण का वर्तमान प्रवाह, जो कि 1980 के दशक से देखा जा रहा है, जोकि औद्योगीकृत देशों के मध्य पूँजी प्रवाह में तीव्रता तथा विशेष रूप से औद्योगिक एवं विकासशील देशों में देखा जा रहा है।

वित्तीय वैश्वीकरण को कुछ विकसित और विकासशील देशों में पूँजी प्रवाह को उच्च संवृद्धि दर से जोड़ा जाता है, जिनमें से कुछ ने अपने विकास दरों में आवर्ती गिरावट तथा वित्तीय संकटों, जिससे वृहत् आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न हुई, को भी महसूस किया है। परिणामस्वरूप विकासशील देशों के शिक्षाविद् तथा नीति निर्माताओं में वित्तीय एकीकरण के प्रभावों पर गहन चर्चा शुरू हो गई है। परन्तु इनमें से अधिकांश चर्चायें केवल कुछ सीमित आनुभाविक तत्त्वों पर ही आधारित है।

घरेलू अर्थव्यवस्था पर वित्तीय अर्थव्यवस्था के प्रभाव को जानने के लिए किसी को भी निम्न प्रश्नों के उत्तर जानने होंगे—

1. क्या वित्तीय समावेशन ने विकासशील देशों के आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा दिया है?
2. इन देशों में वृहत् स्तरीय आर्थिक अस्थिरता में इनका क्या प्रभाव है? तथा
3. वे कौन-से कारक है जो देशों को वित्तीय वैश्वीकरण के लाभों को लेने में मदद कर सकते है? वित्तीय वैश्वीकरण के लाभों को जानने तथा उन्हें समझने हेतु इन महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर विश्लेषण आवश्यक है।

सैद्धांतिक रूप से, वित्तीय वैश्वीकरण कई माध्यमों से विकासशील देशों के लिए विशेषत: वृद्धि दर बढ़ाने में सहायक है। इनमें से आर्थिक वृद्धि को निर्धारित करने वाले कुछ महत्त्वपूर्ण कारकों द्वारा, जिसमें घरेलू बचत में वृद्धि, पूँजी के मूल्य में कमी, विकसित देशों से विकासशील देशों को तकनीक का हस्तांतरण तथा घरेलू वित्तीय क्षेत्रों का विकास सीधे तौर पर सम्मिलित हैं।

अप्रत्यक्ष माध्यमों, जो कभी-कभी प्रत्यक्ष माध्यमों से ज्यादा महत्त्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। ये उत्पादन विशेषीकरण, बेहतर जोखिम प्रबंधन क्षमता तथा उच्च स्तरीय आर्थिक नीतियों तथा संस्थाओं की उन्नति आदि को सम्मिलित करते हैं, जो वैश्वीकरण की प्रतिस्पर्धी दबाव के फलस्वरूप होती है।

वित्तीय वैश्वीकरण विकासशील देशों को बेहतर निर्गत एवं उपभोग प्रबंधन में भी मदद करता है। सैद्धांतिक रूप से यह माना जाता है कि निर्गत के मुकाबले उपयोग में अस्थिरता की मात्रा आर्थिक एकीकरण में वृद्धि के साथ कम हो जाती है। वैश्विक वित्तीय विविधीकरण का सार तत्त्व यह है कि एक देश अपने कुछ आय जोखिमों को वित्त बाजार की तरफ स्थानांतरित करने में सक्षम है। अधिकांश विकासशील देश, जो अपने निर्गत तथा अन्य सम्बन्धित संरचनात्मक कारकों में विकसित देशों के मुकाबले अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु विशेषीकृत हो सकते हैं, जो अन्तर्राष्ट्रीय उपभोग जोखिम के प्रभावी बँटवारे तथा घरेलू निर्गत का कुछ अंश वैश्विक निर्गम में देने से सम्भव हो सकता है।

संक्षेप में, आर्थिक वैश्वीकरण के लाभों में विकासशील देशों के संवृद्धि को बढ़ाने के अलावा उसकी वृहत् आर्थिकी अस्थिरता विशेष तौर पर निर्गत अस्थिरता से सम्बन्धित उपभोग अस्थिरता में कमी करने में तथा उसके बेहतर प्रबंधन के रूप में है। तथापि व्यावहारिक तथ्य यह बताते हैं कि जिन क्षेत्रों ने प्रारंभिक अवस्था में ही आर्थिक एकीकरण किया है उनमें निर्गत तथा उपभोग दोनों स्तरों पर उच्चतर अस्थिरता का जोखिम होता है। इसलिए वित्तीय वैश्वीकरण की एक मुख्य चुनौती यह है कि आर्थिक एकीकरण के लाभों को प्राप्त किया जाये न कि वित्तीय संकट तथा वृहत् आर्थिक अस्थिरता के परिणामों को देखा जाये। विकासशील देशों के साथ विकसित देशों के वित्तीय एकीकरण से कई प्रकार के सकारात्मक लाभों को प्रयोग में लाया जा सकता है जो एक वृहत् आर्थिक नीतियों का प्रबंधन आसानी से कर सकती है।

प्र.6. वित्तीय वैश्वीकरण में पूँजी नियंत्रण का उल्लेख संक्षेप में दीजिए।
Give a brief explanation of capital control in financial globalisation.

उत्तर

पूँजी नियंत्रण (Capital Control)

पूँजी नियंत्रण, पूँजी के संचालन को विनियमित करने वाले विनियमों के समुच्चय है। ये नियंत्रण पूँजी के अन्त: एवं बाह्य प्रवाह दोनों पर लागू होते हैं। पूँजी नियंत्रण निवेश एवं साख विनियमन, व्यापार प्रतिबंध, विदेशी मुद्रा विनियमन तथा मात्रात्मक एवं कर नीतियों के रूप में हो सकता है। पूँजी नियंत्रण को स्वीकार करने का मुख्य उद्देश्य घरेलू अर्थव्यवस्था को पूँजी के अस्थिर संचलन से बचाने, नीतिगत स्वायत्ता प्राप्त करने, घरेलू पूर्ण रोजगार को बढ़ाने तथा सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने तथा विदेशी मुद्रा को बचाने एवं घरेलू व अन्तर्राष्ट्रीय वित्त को राष्ट्रीय नियंत्रण में रखना है। इसके अलावा पूँजी नियंत्रण के पीछे राजस्व में वृद्धि, अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सुधार तथा संभावित खतरे से निपटने के लिए और समय की चाहत भी है।

विस्तृत अर्थों में, पूँजी नियंत्रण के दो महत्त्वपूर्ण रूप हो सकते हैं। लेन-देन पर प्रशासनिक नियंत्रण तथा कर सम्बन्धी नियंत्रण। अधिकांश प्रशासनिक नियंत्रण को अफसरशाही के द्वारा लागू किया जाता है, इसलिए इन्हें लागू करने और हटाने दोनों में समय की आवश्यकता होती है। कर एवं कर से सम्बन्धी उपाय अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन-देन की लागत को बढ़ाते हैं, जबकि उन्हें प्रतिबन्ध से मुक्ति भी मिल जाती है। इस तरह का महत्त्वपूर्ण परिचित उपाय तथाकथित सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क है, जो छोटे समयावधि वाले भारी निवेश के लेन-देन के प्रत्येक स्तर पर लगाये जाते हैं। इस प्रकार के उपायों में नकारात्मक ब्याज दर, विदेशी बैंकों के लिए विशेष संरक्षित जमा आवश्यकताएँ तथा बैंकों के कुल विदेशी मुद्रा जमा अथवा उनकी विदेशी लेनदारियों के सम्बन्ध में विशेष जमा आवश्यकतायें हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर नियंत्रण छोटी अवधि के प्रवाह को हतोत्साहित करने के लिए, बैंकों पर अनिवासियों से जमा लेने पर प्रतिबंध, कर व्यवस्था के माध्यम से पूँजी की गतिशीलता में कमी कर व्यवस्था के प्रतिस्थापक के रूप में दोहरी विनिमय नीति तथा मात्रात्मक प्रतिबंध जैसे नियंत्रण शामिल हैं। पूँजी नियंत्रण सरकारों के लिए तब लाभकारी होते हैं, जब वे ब्याज दरों तथा नाम मात्र के व्यापार विनिमय दरों को हटा लेते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि केन्द्रीय बैंक स्वतंत्र रूप से नाम मात्र विनिमय दरों तथा घरेलू ब्याज दरों को निर्धारित नहीं कर सकते हैं। अगर नियंत्रणों का समुच्चय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा अन्य दीर्घ अवधि के वित्त को क्षति नहीं पहुँचाती है, तो वे स्वीकार्य हैं।

सामान्यत: जो अन्तर्राष्ट्रीय प्रवाह पर करों के पक्षधर हैं, उनका तर्क है कि इससे उनके राजस्व में वृद्धि, विनिमय दरों की अस्थिरता में कमी तथा नीति-निर्माताओं की स्वतंत्रता में वृद्धि एवं विनिमय दर व्यवस्था की रक्षा कर सकते हैं।

WTO के आगमन के वर्षों में पूँजी-प्रवाह पर नियंत्रण अपेक्षाकृत बढ़ा है, क्योंकि वैश्वीकरण ने पूँजी के प्रवाह को मजबूती से बढ़ाया है। अन्य शब्दों में, कुछ मुद्राओं की उपयोगिता उनके भौगोलिक सीमा को पार कर गई है।

खण्ड-स विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए तथा इसके नकारात्मक प्रभावों का वर्णन कीजिए।
Define globalisation and describe its negative effects on the world.

उत्तर

वैश्वीकरण (Globalisation)

डेल जैसी कम्पनी कम्प्यूटर का निर्माण कर रही है, तो कम्प्यूटर को भारत (एक विकासशील देश) में इकट्ठा किया जा सकता है, हालाँकि कुछ जटिल हिस्सों को चीन (एक उभरता हुआ देश) में बनाया गया था, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में अनुसंधान और विकास किया गया था (एक विकसित देश)। यह सब वैश्वीकरण के कारण सम्भव हुआ है।

देशों के बीच यात्रा, संचार और व्यापार आसान होता जा रहा है और दुनिया के सभी देशों के बीच घनिष्ठ आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सम्बन्धों का विकास होता है। वैश्वीकरण उन देशों पर अलग-अलग प्रभाव डालता है जो उस चरण पर निर्भर करते हैं जहाँ उनकी अर्थव्यवस्थाएँ हैं।

वैश्वीकरण व्यवसाय प्रबंधन को कम्पनी के लिए आसान और कुशल बनाता है।

शोध के आधार पर, वैश्वीकरण दुनिया में व्यापार प्रबंधन को सरल बनाता है। यह प्रौद्योगिकी, परिवहन, संचार, शिक्षा और व्यापार के नियमों की प्रगति के कारण है जो सभी पक्षों के लिए व्यापार निष्पक्ष बनाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संलग्न होने के लिए और अधिक लोगों को आकर्षित करता है।

TOUCH 'n' PASS

उद्योग में उच्च प्रतिस्पर्धा के कारण वैश्विक चुनौतियों का सामना करने वाले प्रबंधकों को अपने ग्राहकों को संतुष्ट करने और बनाए रखने और अपने उत्पादों के लिए अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अच्छे निर्णय लेने होंगे। प्रबंधन में लागत में कमी के कारण कम्पनियाँ व्यापार में पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का आनंद लेती हैं।

यह रिपोर्ट विभिन्न प्रकार के इंटरलिंकिंग प्रश्नों की पड़ताल करती है, जोकि वैश्वीकरण के साथ शुरू होते हैं, विकासशील देशों और विकसित देशों में वैश्वीकरण के प्रभाव क्या हैं, यह सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों के संदर्भ में है। वैश्वीकरण एक ऐसी चीज है जो हम सभी को प्रभावित करती है, चाहे हमारा पेश या रुचि कोई भी हो।

वैश्वीकरण के कारण दुनिया की अर्थव्यवस्थाएँ तेजी से एकीकृत हो रही हैं। उदाहरण के लिए, मोबाइल फोन और इंटरनेट ने लोगों को करीब ला दिया है। दुनिया एक छोटी सी जगह बनती जा रही है। काम को दुनिया के किसी भी हिस्से में आउटसोर्स किया जा सकता है, जिसका इंटरनेट कनेक्शन है क्योंकि ट्रैफिक इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार के कारण व्यक्ति कम समय में किसी एक की मंजिल तक पहुँच सकता है।

वैश्वीकरण को एक चल रही प्रक्रिया के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है, जिसके द्वारा क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं, समाजों और संस्कृतियों को संचार और व्यापार के एक विश्व-व्यापी नेटवर्क के माध्यम से एकीकृत किया गया है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में कई कारक शामिल हैं जो तेजी से प्रौद्योगिकी विकास कर रहे हैं जो वैश्विक संचार को संभव बनाते हैं। ये अतिरिक्त बाजारों के उद्घाटन के साथ कम्पनियों के लिए अधिक विकास के अवसर पैदा करते हैं, साझा सांस्कृतिक मूल्यों में वृद्धि के परिणामस्वरूप अधिक से अधिक ग्राहक सामंजस्य स्थापित करने की अनुमति देते हैं, और अन्य देशों में कम परिचालन लागत और नए कच्चे माल तक पहुँच के साथ एक बेहतर प्रतिस्पर्धी स्थिति प्रदान करते हैं—संसाधन और निवेश के अवसर।

वैश्विक संचार के माध्यम से वैश्वीकरण, वैश्विक बाजारों और वैश्विक उत्पादन ने धन के संबंध में वैश्विक गतिविधि के चौथे क्षेत्र को बढ़ावा और सुविधा प्रदान की है। उदाहरण के लिए, अमेरिकी डॉलर, जापानी येन, यूरो और अन्य प्रमुख राष्ट्रीय मुद्राएँ विश्व स्तर पर प्रसारित होती हैं। वे पृथ्वी पर कहीं भी उपयोग किए जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक रूप से और हवाई परिवहन के माध्यम से कहीं भी प्रभावी ढंग से समय पर नहीं चल रहे हैं। अधिकांश बैंककार्ड दुनिया भर में हजारों स्वचालित टेलर मशीनों (एटीएम) से स्थानीय मुद्रा में नकदी निकाल सकते हैं। साथ ही वीजा, मास्टरकार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस जैसे क्रेडिट कार्ड का उपयोग दुनिया के लगभग हर देश में भुगतान के लिए किया जा सकता है।

लोग एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं, व्यापार प्रतिबंध कम कर रहे हैं, घरेलू बाजार विदेशी निवेश के लिए खुल रहे हैं, दूरसंचार बेहतर तरीके से स्थापित हो रहे हैं और जो देश नवाचारों की अगुवाई कर रहे हैं, वे जरूरतमंद अन्य देशों के लिए अपनी प्रौद्योगिकियों पर गुजर रहे हैं।

नकारात्मक प्रभाव (Negative Effects)

वैश्वीकरण का विकसित राष्ट्रों पर भी इसका दुष्प्रभाव है। इनमें कुछ कारक शामिल हैं— रोजगार असुरक्षा, कीमतों में उतार-चढ़ाव, आतंकवाद, मुद्रा में उतार-चढ़ाव, पूँजी प्रवाह आदि।

नौकरियों की अनिश्चितता (Job Insecurity)

विकसित देशों में लोगों के पास रोजगार की असुरक्षा है। लोग अपनी नौकरी खो रहे हैं। विकसित देशों ने विनिर्माण और सफेद कॉलर नौकरियों को आउटसोर्स किया है। इसका मतलब है कि उनके लोगों के लिए कम नौकरियाँ हैं। इसका कारण यह है कि विनिर्माण कार्य उन देशों के लिए आउटसोर्स किए जाते हैं जहाँ विनिर्माण वस्तुओं और मजदूरी की लागत उनके देशों की तुलना में कम है। उन्होंने चीन और भारत जैसे विकासशील देशों को आउटसोर्स किया है। भारत में आउटसोर्सिंग के कारण एकाउंटेंट, प्रोग्रामर, संपादक और वैज्ञानिक जैसे अधिकांश लोगों की नौकरी चली गई है।

वैश्वीकरण के कारण श्रम का शोषण हुआ है। सस्ते सामान के उत्पादन के लिए सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जाती है। ''व्यवहार में, हालाँकि, लैटिन अमेरिका में हालिया अनुभव यह रहा है कि कई ऐसे खुले हाथों वाले बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने लागत और बाजार के विचारों के कारण, चीन या दक्षिण-पूर्व एशिया में अपने संचालन को स्थानांतरित कर दिया।''

कीमतों में उतार-चढ़ाव (Uses and Downs in Prices)

वैश्वीकरण के कारण मूल्य में उतार-चढ़ाव आया है। प्रतिस्पर्धा में वृद्धि के कारण, विकसित देशों को अपने उत्पादों के लिए अपनी कीमतें कम करने के लिए मजबूर किया जाता है। इसका कारण यह है कि चीन जैसे अन्य देश कम लागत पर माल का

उत्पादन करते हैं जो विकसित देशों में उत्पादित वस्तुओं की तुलना में सस्ता होने के लिए माल बनाता है। इसलिए, विकसित देशों के लिए अपने ग्राहकों को बनाए रखने के लिए उन्हें अपने माल की कीमतें कम करने के लिए मजबूर किया जाता है। यह उनके लिए एक नुकसान है क्योंकि इससे उनके देशों में सामाजिक कल्याण को बनाए रखने की क्षमता कम हो जाती है।

प्र.2. विकसित देशों में वैश्वीकरण के प्रभावों की विवेचना कीजिए।

Explain the effects of globalisation in developing countries.

उत्तर

विकसित देशों में वैश्वीकरण का प्रभाव
(Effects of Globalisation in Developing Countries)

गरीबी उन्मूलन (Poverty Alleviation)

जहाँ तक गरीबी में कमी का सवाल है, भूमंडलीकरण ने विकासशील देशों में गरीबी में कमी लाने में भूमिका निभाई। डीड में अधिकांश विकसित देशों ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अपने अनुपात में गरीबी में कमी का अनुभव किया जिसमें चीन, भारत, वियतनाम जैसे तेजी से विकासशील देश शामिल हैं। जबकि उप-सहारा अफ्रीका जैसे अन्य देशों ने एक विपरीत प्रवृत्ति दर्ज की।

रोजगार की स्थिति (Employment Status)

वैश्वीकरण के माध्यम से, विभिन्न देशों के लोगों को वैश्विक के भीतर रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। इसने आउटसोर्सिंग की अवधारणा तैयार की है। विकसित देश विकासशील देशों को काम प्रदान करना पसंद करते हैं जहाँ लागत सस्ती होती है। भारत जैसे विकासशील देशों को ग्राहक सहायता, सॉफ्टवेयर विकास, लेखा, विपणन और बीमा जैसे कार्य दिए जाते हैं। इसलिए जिस देश को काम दिया जाता है उसे नौकरी मिलती है।

इसने उभरते बाजारों में निवेश करने और वहाँ उपलब्ध प्रतिभाओं को टैप करने का मौका दिया है। विकासशील देशों में, अक्सर पूँजी की कमी होती है जो घरेलू कम्पनियों के विकास में बाधा डालती है। ऐसे मामलों में, व्यवसायों की वैश्विक प्रकृति के कारण, विकासशील देशों के लोग भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं।

प्रौद्योगिकी (Technology)

यह एक शक्तिशाली शक्ति है जो दुनिया को एक परिवर्तित समानता की ओर ले जाती है। इसमें सर्वहारा संचार, परिवहन और यात्रा है। हर जगह अलग-अलग जगहों के लोग प्रौद्योगिकी के माध्यम से उन सभी चीजों को चाहते हैं जो उन्होंने सुनी, देखी या अनुभव की हैं। इसके प्रबंधन के माध्यम से संगठन दुनिया के विभिन्न स्थानों से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जिनका उपयोग संगठन में किया जा सकता है।

टेलीविजन और मीडिया ने अपेक्षाकृत छोटी राष्ट्रीय एकता और वास्तविकता से, वैश्विक बाजार और अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं में, दुनिया की धारणा को प्रभावित करने में बड़ी भूमिका निभाई। चूँकि बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ नए स्थानों में सहायक कम्पनियों की स्थापना करती हैं, वे यह जानती हैं कि अभिभावक से लेकर स्थानीय ऑपरेशन तक कैसे पहुँचते हैं। ज्ञान एक इकाई से दूसरी इकाई के रूप में बहता है पूरे संगठन को विकास गतिविधि से लाभ होता है। ज्ञान हस्तांतरण में संगठनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले तरीकों में से एक कर्मियों का आंदोलन है, जो बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के भीतर होता है। यह विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के साथ विभिन्न स्थितियों में काम करने के बारे में ज्ञान का एक बैंक बनाता है और यह ज्ञान के एक भंडार का प्रतिनिधित्व करता है जिसे विकसित किया जा सकता है और इसका उपयोग संगठन को लाभ पहुँचाने के लिए किया जाता है।

शिक्षा (Education)

दृष्टिकोण से वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव के साथ-साथ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। इसने उच्च शिक्षा की पहुँच बढ़ा दी है और विकासशील देशों में ज्ञान की खाई को कम किया है। इसमें समान रूप से नकारात्मक पहलू हैं जो उन देशों में विश्वविद्यालयों को गम्भीर रूप से खतरे में डाल सकते हैं। इस दृष्टि से यह उच्च शिक्षण संस्थानों तक पहुँच बढ़ाने के माध्यम से विकासशील देशों में अधिक सकारात्मक प्रभाव लाया है। आज आप दुनिया में सबसे अच्छी शैक्षिक सुविधाओं की खोज में आगे बढ़ सकते हैं जिसमें विकासशील देश बिना किसी बाधा के शामिल हैं। यह माध्यमिक विद्यालयों से उत्पादन में वृद्धि, उच्च शिक्षा में महिलाओं की अधिक भागीदारी, स्नातकों के लिए एक बढ़ती निजी क्षेत्र की माँग और विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने की अत्यधिक लागत के कारण है।

TOUCH 'n PASS

बेरोजगारी (Unemployment)

वैश्वीकरण दुनिया की बेरोजगारी की स्थिति के लिए एक दोष है, हालाँकि यह कुछ नौकरियों के अवसरों को लाया। इस तथ्य के बावजूद कि इसने नौकरियों के अवसरों को वैश्विक स्तर पर पहुँचाया लेकिन यह अभी भी मौजूदा स्थिति के लिए एक दोष है। "यह सच है कि वैश्विक आर्थिक एकीकरण और बढ़ी हुई यात्रा के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय और उद्यम स्तरों पर प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई है, उत्पादकों को लागत में कटौती करने, दक्षता में सुधार करने और उत्पादकता बढ़ाने के तरीके खोजने के लिए मजबूर किया गया है।"

"1980-2000 के दौरान रोजगार के स्तर को निर्धारित करने के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण कारक राष्ट्रीय या क्षेत्रीय मैक्रोइकॉनॉमिक नीतियाँ थीं, जिन्हें लागू किया गया और निरंतर किया गया। उदार मैक्रोइकॉनॉमिक सुधार के साथ उन देशों के अलावा, लचीले श्रम बाजारों और रोजगार प्रथाओं को बढ़ावा देने वाली राजनीति, विकेन्द्रीकृत औद्योगिक सम्बन्ध प्रणाली और श्रम के विवेकपूर्ण प्रवर्तन को आगे बढ़ाया। दूसरी ओर, रोजगार कानूनों, विनियमों और नीतियों वाले देशों ने उच्च स्तर के रोजगार का अनुभव किया क्योंकि वे कई रोजगार नौकरियों को आकर्षित करने और बनाए रखने में सक्षम नहीं थे।"

उदाहरण के लिए, इंडोनेशिया ने बेरोजगारी और गरीबी का सामना किया, जो दो दशकों में अनुभव नहीं होने के स्तर तक बढ़ गया, स्वास्थ्य की स्थिति खराब हो गई, और प्राकृतिक वातावरण खराब हो गया।

प्र.3. कृषि से सम्बन्धित विश्व व्यापार संगठन के मानक एवं सुधारों की विवेचना कीजिए।

Describe the norms and reforms of WTO agreement on agriculture.

उत्तर

कृषि से सम्बन्धित विश्व व्यापार संगठन के मानक एवं सुधार
(Norms and Reforms of WTO Agreement on Agriculture)

WTO के अधीन कृषि संधि एक अन्तर्राष्ट्रीय संधि थी, जिस पर GATT की उरुग्वे दौर के दौरान वार्ता हुई थी तथा यह WTO के 1 जनवरी 1995 की स्थापना के साथ प्रभावशाली हो गया था। कृषि समझौते का मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र में व्यापक सुधार तथा अधिक बाजार उन्मुक्त नीतियों का निर्माण है। यह देशों के आयात-निर्यात को बढ़ाने तथा उसकी संभाव्यता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला है। कृषि सम्बन्धी WTO का समझौता अपने प्रावधानों के अधीन कृषि एवं व्यापार नीतियों के तीन प्रमुख वृहद् क्षेत्रों को शामिल करता है जिसमें व्यापार सम्बन्धी आयात बाधाओं को दूर करने वाली बाजार पहुँच, सब्सिडी समेत घरेलू सहायता तथा अन्य कार्यक्रम जिनसे कृषि मूल्य, कृषकों की आय तथा आयात सब्सिडी एवं आयात को कृत्रिम रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने वाली अन्य गतिविधियाँ शामिल हैं।

इस संधि ने सरकारों को उनके ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सहयोग की अनुमति प्रदान की परन्तु ये नीतियाँ व्यापार को कम विकृत करने वाली होनी चाहिए। इसने प्रतिबद्धताओं को लागू करने में कुछ लचीलेपन की भी अनुमति दी। विकासशील देशों को उतनी अधिक मात्रा में अपनी सब्सिडी और प्रशुल्कों में कमी नहीं करनी थी, जितनी विकसित देशों को तथा उन्हें अपनी प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त समय भी प्रदान किया गया। अल्प विकसित देशों को इससे पूर्ण उन्मुक्ति थी। देशों के हितों को विशेषकर अपने खाद्यान्न आपूर्ति को बनाये रखने के लिए आयात एवं अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं की चिन्ताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेष प्रावधान किये गये। कृषि सब्सिडी से सम्बंधित संभावित विवादों एवं चुनौतियों को कम करने के उद्देश्य से नौ वर्ष की अवधि का एक शांति सम्बन्धी का प्रावधान भी शामिल था जो 2003 के अंत तक लागू रहा।

बाजार पहुँच (Market Access)

बाजार पहुँच के नये नियमानुसार कृषि उत्पादों पर केवल प्रशुल्क ही लागू होता है। उरुग्वे दौर के वार्ता के पहले कुछ कृषि आयातों पर कोटा तथा अन्य गैर-प्रशुल्क बाधाओं द्वारा प्रतिबंधित किया जाता था। इन्हें प्रशुल्कों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया जो कमोबेश इसी स्तर की सुरक्षा प्रदान करती है। अगर पूर्व नीतियों के संदर्भ, में घरेलू मूल्यों के वैश्विक कीमतों के मुकाबले 75% की वृद्धि हो जाये तो नये प्रशुल्क 75% के करीब हो सकते हैं। कोटा तथा अन्य प्रकार के कदमों का प्रशुल्कों के रूप में परिवर्तन 'प्रशुल्कीकरण' (tarriffication) कहलाता है।

बाजार पहुँच प्रशुल्कीकरण, प्रशुल्कों में कमी तथा पहुँच के अवसरों को समाहित करता है। प्रशुल्कीकरण का अर्थ सभी गैर प्रशुल्क बाधाओं; जैसे— कोटा, विभिन्न प्रकार की लेवी, न्यूनतम आयात दर, भेदभावपूर्ण लाइसेंसिंग, राज्य के व्यापारिक कदम, स्वैच्छिक प्रतिबन्धात्मक समझौतों को हटाना तथा उन्हें समरूप प्रशुल्कों के रूप में परिवर्तित करना आदि है। विकसित देशों के लिए साधारण प्रशुल्क, प्रशुल्कीकरण के परिणामस्वरूप औसतन 36% से घटकर प्रत्येक प्रशुल्क के मद पर अगले 6 वर्षों में

15% की न्यूनतम दर पर आ गये। विकासशील देशों को 10 वर्षों के अन्दर प्रशुल्कों में 24% की कमी करनी थी। विकासशील देश, जो मात्रात्मक प्रतिबंधों को भुगतान संतुलन की समस्या के कारण जारी रखे थे, को प्रशुल्कीकरण के स्थान पर उच्चतम सीमा बंधन की अनुमति दी गई।

अतिरिक्त करों को लागू करने के लिए विशेष सुरक्षा प्रावधानों के अधीन अनुमति दी गई, जब या तो उनका आयात वृद्धि एक विशेष स्तर से ऊपर चला जाता अथवा 1986–1988 के स्तर की तुलना में आयात मूल्यों में विशेष रूप से कमी आती। यह भी माना गया कि न्यूनतम पहुँच जो 1986–88 में घरेलू उपभोग का 3% थी को लागू करने की अवधि की समाप्ति तक जो वर्ष 1995 थी, को 5% बढ़ाना था।

प्रशुल्कीकरण पैकेज में इसके अलावा भी बहुत कुछ था। इसने यह सुनिश्चित किया कि संधि के लागू होने के पूर्व जो मात्रात्मक निर्यात होता था वह जारी रहेगा और इसने कुछ नये मात्रात्मक गतिविधियों जिन पर कर वसूला जाता था, को प्रतिबंधित न करने की गारंटी दी। यह विशिष्ट मात्राओं; जैसे— प्रशुल्क व्यवस्था, कोटा, न्यून प्रशुल्क दर जो उच्च एवं कभी-कभी कोटे से अधिक होने वाली वस्तुओं पर लागू होती थी, के द्वारा प्राप्त किया गया।

1995 से प्रशुल्कों एवं प्रशुल्क कोटा के सम्बन्ध में नई प्रतिबद्धताऐं, जिनके अधीन सभी कृषिगत् उत्पाद आते थे प्रभावी हुए। जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि उरुग्वे दौर के सहभागियों की सहमति के अनुसार विकसित देशों को अपने उच्चतर कोटे के प्रशुल्कों को औसतन 36% की दर से 6 वर्षों में बराबर-बराबर कम करना था, जबकि विकासशील देशों को 10 वर्षों में 24% की कटौती करनी थी। कुछ विकासशील देशों ने वैसी जगहों पर जहाँ कर बाध्यकारी नहीं थे, उच्चतम प्रशुल्क दरों के विकल्प को अपनाया जो कि उरुग्वे दौर के पहले GATT तथा WTO नियमों के अधीन किये गये थे। न्यून विकसित देशों को अपने प्रशुल्क दरों में कोई कटौती नहीं करनी थी।

वैसे उत्पाद जिनके गैर-प्रशुल्क प्रतिबन्धों को प्रशुल्कों में बदल दिया गया था, के लिए सरकारों को विशेष आपातकालीन कार्यवाहियाँ (विशेष सुरक्षा उपाय) करने का अधिकार दिया गया ताकि तेज गति से गिरते मूल्यों, आयात की बाढ़ से होने वाली हानियों से किसानों को बचाया जा सके। परन्तु संधि के अधीन यह स्पष्ट कर दिया गया कि क्यों और कैसे इन आपातकालीन कार्यवाहियों को लागू किया जाना चाहिए। उदाहरणस्वरूप, इनका प्रयोग प्रशुल्क कोटा के अधीन आने वाले आयातों पर लागू नहीं किया जा सकता था।

इस संदर्भ में चार देशों ने विशेष उपचार प्रावधानों का प्रयोग कार्यान्वयन अवधि के दौरान (विकसित देशों के लिए सन् 2000 तथा विकासशील देशों के लिए 2004) आयातों को प्रतिबंधित करने के लिए, विशेषत: चावल जो संवेदनशील उत्पादों के अधीन आते थे, के लिए किया। परन्तु यह सभी सख्ती से लागू किये गये प्रावधानों के अधीन थे जिनमें विदेशी निर्यातकों के न्यूनतम पहुँच को सुनिश्चित करना शामिल था। ये चार देश थे— चावल के लिए जापान, कोरियाई गणतंत्र तथा फिलीपींस और भेड़ का माँस, दूध, पाउडर तथा अन्य खाद्यान्नों के लिए इजरायल। जापान और इजरायल ने अब उन अधिकारों को छोड़ दिया है परन्तु कोरियाई गणतंत्र तथा फिलीपींस ने चावल के लिए अपने विशेष उपचारों को जारी रखा है। एक नये सदस्य चीनी ताइपेई को अपने सदस्यता के पहले वर्ष 2002 में चावल के लिए विशेष उपचार का अधिकार दिया गया।

घरेलू समर्थन (Domestic Support)

घरेलू समर्थन मूल्य अथवा उत्पादन सब्सिडी के अन्य उपाय सम्बन्धी नीतियों के बारे में प्रमुख शिकायत यह है कि ये अति उत्पादन को प्रोत्साहित करते हैं। जिससे आयात बाधित होता है अथवा निर्यात सब्सिडी के कारण विश्व बाजार में कम मूल्यों पर अधिशेष जमा हो जाता है। कृषि संधि ऐसे समर्थनकारी कार्यक्रमों में विभेद करती है जो उत्पादन को प्रत्यक्ष रूप से और ऐसे उपाय जो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करते हैं।

ऐसी घरेलू नीतियों को समाप्त किया गया जो उत्पादन एवं व्यापार पर सीधा प्रभाव डालती थी। WTO सदस्यों ने कृषि क्षेत्र को प्रतिवर्ष दिये जा रहे इस प्रकार के अधिकांश समर्थन की गणना 1986-88 को आधार वर्ष मानकर, जिसे कुल योग (Total Aggregate) के नाम से जाना जाता है। घरेलू समर्थन नीतियों के लिए, जोकि कमी सम्बन्धी प्रतिबद्धताओं के अधीन थी, तथा 1986-88 के दौरान दिये गये कुल समर्थन की गणना कुल योग समर्थन मापक (AMS) के आधार पर विकासशील देशों को 13.3% तथा विकसित देशों को 20% कमी करने को कहा गया। कमी सम्बन्धी प्रतिबद्धताएँ कोई विशिष्ट उत्पादन न होकर कुल समर्थन के स्तर पर था। ऐसी नीतियों को, जिनके अधीन विशिष्ट उत्पाद तथा गैर-विशिष्ट उत्पाद दोनों के वर्ग आते थे, में घरेलू समर्थन मूल्य विकसित देशों के लिए कुल उत्पादन मूल्य का 5% से कम तथा विकासशील देशों के लिए 10% से कम राशि को किसी प्रकार की प्रतिबद्धता से बाहर रखा गया।

विकासशील सदस्य देशों के लिए विशेष तथा विभेदक उपचार प्रावधान भी उपलब्ध थे। इसमें खाद्य सुरक्षा के लिए प्रशासित मूल्यों पर खरीददारी, जिस हेतु उत्पादकों को सब्सिडी दी जाती थी, की खरीद बिक्री को भी कुल योग समर्थन मापक (AMS) में शामिल किया गया। विकासशील देशों को शहरी एवं ग्रामीण गरीबों को खाद्य सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सब्सिडी को जारी रखने की अनुमति दी गई। इसमें विकासशील देशों की वैसी निवेश सब्सिडी को भी बाहर रखा गया जो सामान्यत: इन देशों के कम आय तथा गरीब किसानों को कृषि एवं कृषि आगत सब्सिडी से सम्बन्धित था।

कृषि सम्बन्धी समझौता घरेलू समर्थन सरंचना (सब्सिडी) को तीन वर्गों अथवा बॉक्स में बाँटता है। ये है ग्रीन बॉक्स, अंबर बॉक्स तथा ब्लू बॉक्स।

कृषि सम्बन्धी समझौता में ऐसी उत्पादन सम्बन्धी नीतियों को जिनका व्यापार को विकृत करने का प्रभाव अत्यंत न्यून अथवा शून्य था उन्हें ग्रीन बॉक्स में शामिल किया गया। दूसरे शब्दों में, ऐसे कदम जिनका व्यापार पर न्यूनतम प्रभाव होता है उन्हें "ग्रीन बॉक्स" में शामिल किया जाता है। सामान्य शब्दों में, ग्रीन बॉक्स के तहत कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली सहायता या सब्सिडी से व्यापार से किसी प्रकार की विकृति नहीं आती है। इसकी सहायता का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्रों में सुधार लाना है। इसके अधीन सरकार द्वारा दी जा रही सेवायें; जैसे—कृषि अनुसंधान, बीमारियों की रोकथाम, अवसंरचना, पौधों का संरक्षण तथा खाद्य सुरक्षा शामिल हैं। इसमें कृषकों को ऐसे सीधे भुगतान सम्बन्धी मदों को भी शामिल किया गया, जिनका उत्पादन बढ़ाने से सीधे सम्बन्ध नहीं है। इसमें कृषकों को कृषि पुर्नसंरचना में सहायता हेतु दिये गये प्रत्यक्ष आय समर्थन तथा पर्यावरण एवं क्षेत्रीय सहायता कार्यक्रमों के अधीन किये गये सीधे भुगतान शामिल हैं। ग्रीन बॉक्स के अधीन पर्यावरणीय कार्यक्रमों के तहत उत्पादकों को किये जाने वाले निश्चित भुगतान भी शामिल हैं जब तक कि ऐसे भुगतानों को वर्तमान उत्पादन स्तर से असम्बन्धित न कर दिया जाये।

इस प्रकार ग्रीन बॉक्स की सूची में छूट प्राप्त नीतियों के अन्तर्गत ऐसी नीतियाँ शामिल हैं जो कृषि को लाभ अथवा सेवा अथवा ग्राम समुदाय, खाद्य सुरक्षा के उद्देश्य से सार्वजनिक सरंक्षण, घरेलू खाद्य सहायता तथा कुछ असम्बन्धित भुगतान, जो उत्पादकों को कतिपय परिस्थितियों में पहुँचने तक उत्पादन सीमितता कार्यक्रम के जरिये सीधे भुगतान से सम्बन्धित हैं, शामिल हैं।

अंबर बॉक्स कृषि क्षेत्र में दी गई वैसी सब्सिडी है जिससे व्यापार प्रक्रिया में विकृति आती है; जैसे-निर्यात सब्सिडी। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए इसे बंद करना चाहिए। अंबर बॉक्स के अधीन ऐसी घरेलू सब्सिडियाँ आती है। जिनको सरकारें कम करने पर सहमत हो गई हैं। लेकिन इन्हें पूर्णत: नहीं हटाया जायेगा। विकसित देश 1995 से शुरू के प्रारंभिक 8 वर्षों के अधीन इस आँकड़े में 20% की कटौती पर सहमत थे। विकासशील देश भी 10 वर्षों की अवधि में 13% की कटौती पर सहमत समर्थन का यह वर्ग अंबर बॉक्स कहलाता है जोकि यातायात स्तंभों के पीले रंग के एक वर्ग से सम्बन्धित है जिसका अर्थ धीमे चलने से है।

ब्लू बॉक्स में ऐसी सब्सिडियाँ शामिल है, जिनमें वृद्धि की कोई सीमा नहीं है तथा जो उत्पादन सीमितता कार्यक्रमों में सीधे भुगतान से सम्बन्धित है। इसके अलावा किसानों को किये गये कुछ अन्य सीधे भुगतान, जो किसानों के उत्पादन आवश्यकताओं से सम्बन्धित है, को भी ब्लू-बॉक्स में शामिल किया गया है, इसमें कृषि को बढ़ावा देने वाले कतिपय सरकारी सहायता कार्यक्रम तथा विकासशील देशों में ग्रामीण विकास से सम्बन्धित एवं अन्य समर्थन जो छोटे पैमाने के किसानों की उत्पादन वृद्धि में सहायता करते हैं, भी सम्मिलित है (विकसित देशों के लिए 5% से कम तथा विकासशील देशों के लिए 10% से कम)।

निर्यात सब्सिडी (Export Subsidies)

यह संधि सदस्य देशों के द्वारा आयात सब्सिडी में कमी का प्रावधान करती है। यह कृषि सम्बन्धी समझौता कृषि उत्पादों पर निर्यात सब्सिडी को प्रतिबंधित करती है, जब तक कि वह सदस्य देश की सब्सिडी प्रतिबद्धता की सूची में शामिल है। इस संधि के अनुसार, WTO के सदस्यों को इस सूची में सूचीबद्ध वस्तुओं पर निर्यात सब्सिडी पर किये जा रहे खर्चों तथा निर्यात सब्सिडी प्राप्त कर रहे वस्तुओं की मात्रा में कमी लाना है। 1986-90 के औसत को आधार मानते हुए विकसित देश 1995 से प्रारंभ हुए छ: वर्षों की अवधि में 36% निर्यात सब्सिडी पर कटौती तथा विकासशील देशों द्वारा 10 वर्षों की अवधि में 24% कटौती करनी है। विकसित देश निर्यात पर दी जा रही मात्रात्मक सब्सिडी में 6 वर्षों के दौरान 21% तथा विकासशील देश 10 वर्षों की अवधि के दौरान 14% कटौती पर सहमत हुए हैं। अल्प विकसित देशों को इस प्रकार की कोई कटौती नहीं करनी है। 6 वर्षों की कार्यान्वयन अवधि के दौरान विकासशील देशों को कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के अधीन सब्सिडी का प्रयोग; जैसे—बाजार मूल्यों में कमी तथा परिवहनीय निर्यात आदि मदों पर करने की अनुमति दी गयी है। यह संधि ऐसे उत्पादों के संदर्भ में जिसका सम्बन्ध निर्यात सब्सिडी से नहीं है, के सम्बन्ध में भविष्य में इन्हें कम करने की प्रतिबद्धता का भी प्रावधान करती है।

TOUCH 'n' PASS

कृषि सम्बन्धी संधि के अधीन अल्प विकसित तथा वैसे देश, जो खाद्यान्न आयात पर निर्भर है, के संदर्भ में विशेष प्रावधान किया गया है। WTO के सदस्यों को अपनी निर्यात सब्सिडी में कमी करनी है, परन्तु कुछ आयातक देशों, जो प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रों से प्राप्त होने वाले सस्ते खाद्यान्न तथा सब्सिडी पर पूर्णत: निर्भर है। इसमें कुछ अत्यंत निर्धन देश तथा उनके कृषि क्षेत्र के लिए उच्च मूल्यों पर आधारित एक गतिशील निर्यात सब्सिडी, जो अल्पकालिक रूप से अनंक कृषि क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है, के सम्बन्ध में विशिष्ट प्रावधान दिये गये हैं। एक विशेष मंत्रीस्तरीय निर्णय ने इस उद्देश्य हेतु कुछ विशिष्ट कदम निर्धारित किये हैं, जो उनके कृषि विकास में सहायता तथा खाद्यान्न सहायता के संदर्भ में प्रावधान करता है। यह IMF तथा विश्व बैंक के द्वारा वित्तीय वाणिज्यिक खाद्यान्न आयात के संदर्भ में सहायता की सम्भावना भी तलाशता है।

प्र.4. वैश्वीकरण की प्रक्रिया में उद्योग एवं सेवाओं का वर्णन कीजिए।

Describe the industry and services in globalisation process.

उत्तर

वैश्वीकरण की प्रक्रिया में उद्योग एवं सेवायें
(Industry and Services in Globalisation Process)

श्रमिकों का प्रवसन तथा आउटसोर्सिंग (Migration of Labour and Outsourcing)

जब से वैश्वीकरण का अर्थ देशों के मध्य व्यापार बाधाओं की समाप्ति तथा वित्तीय प्रवाह, वस्तुओं एवं सेवाओं के माध्यम से देशों की अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण एवं देशों के मध्य निगमीकृत निवेश लिया जाने लगा है तब से, विशेषकर हाल के कुछ वर्षों में तकनीक के क्षेत्र में विशेषकर संचार एवं परिवहन के क्षेत्र में हुई तीव्र वृद्धि के कारण पूरे विश्व में वैश्वीकरण की प्रक्रिया तीव्र हुई है। वैश्वीकरण का उद्योगों पर कई लाभकारी परिणाम हुआ है। जिससे उद्योगों में व्यापार प्रक्रिया का बहिर्स्रोतिकरण मुख्यत: Business process outsourcing (BPO), फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोलियम तथा विनिर्माण क्षेत्र में बड़ी मात्रा में विदेशी निवेश हुआ है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आने के कारण अर्थव्यवस्था में संवृद्धि की गति भी महत्त्वपूर्ण रूप से तीव्र हो जाती है। वैश्वीकरण का एक लाभ यह भी है कि कई विदेशी कम्पनियाँ घरेलू अर्थव्यवस्था में उद्योगों की स्थापना करती है जो देश के लोगों को रोजगार प्रदान करने में भी सहायता प्रदान करता है। इससे देश में गरीबी तथा बेरोजगारी के स्तर में भी कमी आती है। उद्योगों में वैश्वीकरण का एक और लाभ यह है कि विदेशी कम्पनियाँ अपने साथ अत्यंत उच्च तकनीकों को लाती है जो घरेलू उद्योगों की तकनीक को और अधिक उन्नत बनाने में मदद करता है।

सेवायें एक ऐसी आर्थिक प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य आर्थिक इकाई अथवा अन्य आर्थिक इकाई से सम्बन्धित उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि करती है। सेवाओं का एक महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि संस्थान द्वारा सेवा दिये जाने से पहले उत्पादकों और उपभोक्ताओं के मध्य प्रत्यक्ष सम्बन्ध बन जाता है। यह स्थापत्य से लेकर वॉयस मेल (Voice mail) तक, दूरसंचार से लेकर हवाई परिवहन तक सेवायें विकसित तथा विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं में वृहत् एवं अत्यंत गतिशील इकाई के रूप में उपलब्ध कराता है। सेवायें अधिकांश वस्तुओं के उत्पादनों के आगत के रूप में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उरुग्वे दौर की व्यापार वार्ता के दौरान इसे शामिल किये जाने के फलस्वरूप "सेवा व्यापार में सामान्य समझौता" (GATS) संभव हुआ। जनवरी 2000 से यह बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं का विषय बन गया है।

उरुग्वे दौर की वार्ता की एक उल्लेखनीय उपलब्धि, सेवा व्यापार में सामान्य समझौते (GATS) का सृजन है, जो जनवरी 1995 से प्रभावी हुआ। GATS अपने समकक्षी वाणिज्यिक व्यापार (व्यापार एवं प्रशुल्कों पर सामान्य समझौता GATT) के उद्देश्यों से प्रभावित था जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में विश्वसनीय नियमों का सृजन करने, सभी सहभागियों के साथ समान एवं स्वच्छ व्यवहार नियम सुनिश्चित करने (गैर-विभेदकारी नियम), प्रवर्तित बाध्यकारी नियमों के माध्यम से आर्थिक क्रियाकलापों को गति प्रदान करने तथा वृद्धिकारी वैश्वीकरण के माध्यम से व्यापार तथा विकास को बढ़ावा देने से सम्बन्धित है।

वर्तमान में कुल वैश्विक उत्पादन का 60% से अधिक भाग सेवाओं से आता है, जबकि यह कुल व्यापार से उत्पन्न रोजगार का 20% भाग ही रखता है। कई सेवायें जो लम्बे समय तक विशुद्ध रूप से घरेलू क्रियाकलाप मानी जाती थी, अब तीव्र गति से अन्तर्राष्ट्रीय संचरण की सेवायें हो गई है। यह प्रवृत्ति जारी रहने की सम्भावना है जोकि नई स्थानान्तरण तकनीकों का प्रवेश (उदाहरणस्वरूप– ई-बैंकिंग, Tele health सेवायें), कई देशों में चले आ रहे लम्बे एकाधिकार वाले क्षेत्रों को खोलना (जैसे दूरसंचार एवं डाक सेवायें)। उपभोक्ताओं की बदलती प्राथमिकताओं के फलस्वरूप सेवाओं की व्यापारिकता को बढ़ाने के लिए कुछ तकनीकी एवं विनियामक नवाचार शामिल हुए हैं, जिसके फलस्वरूप बहुपक्षीय नियमों के सृजन की आवश्यकता हुई है।

इस प्रकार का समझौता न केवल सप्लाई चेन का फर्म के उत्पादन मूल्य को बढ़ाता है, बल्कि यह अर्थव्यवस्था को भी लाभ पहुँचाता है। मध्यवर्ती बाजार, जो कि विशेषीकृत क्षमता को उपलब्ध कराता है, जिसमें उत्पादों के विविधीकरण की परिस्थितियाँ अधिक बेहतर हो सकती है। वृहद् सूचना मानकों तथा समन्वय एवं सरलीकरण के द्वारा मूल्य कड़ियों में स्पष्ट प्रशासनिक सीमा निर्धारण भी करता है। मध्यवर्ती बाजार का बँटवारा पूरे मूल्य कड़ियों के सरलीकरण तथा सूचनाओं के मानकीकरण, जिसके फलस्वरूप सीमा पार हस्तांतरण गतिविधियाँ आसान हो जाती हैं, से उत्पादन में समन्वय उत्पन्न हो जाता है।

कार्य की व्याख्या में जटिलता के कारण आवश्यकताओं की कोडिंग, मूल्य निर्धारण, विधि नियम एवं शर्तें, ग्राहकों के बहिस्रोंतण सलाहकार द्वारा दी गयी सलाह अथवा बहिस्रोंतण बिचौलिया, प्रदाता को मूल्यांकन तथा निर्णय प्रक्रिया में सहयोग करता है।

''बहिस्रोंत तथा अपने कार्यालय'' दोनों प्रतिमानों में कम्पनियाँ अपने लागत में बहुत बड़ी कटौती, जो 50% से 80% के बीच हो सकती है, विकासशील देशों में आकर कर सकती है। वर्तमान में सेवाओं का बहिस्रोंतण, वैश्वीकरण को अगले चरण में अग्रसारित कर रहा है, जैसा कि किसी भी उभरती हुई प्रवृत्ति में होता है। यहाँ भी नये व्यापार और निवेश की संभावना उभर रही है।

1990 के दशक में बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा विस्तार ने अत्यधिक कुशल श्रमिकों, सेवा कार्यों तथा वैश्विक व्यावहारिक समूहों को सम्मिलित किया है। उद्यमों ने सूचना तकनीकी क्रियाकलापों का 1970 के दशक के प्रारंभ से ही बहिस्रोंतण प्रारंभ कर दिया था, परंतु 1989 में विकसित देशों में कुशल सूचना तकनीकी श्रमिकों की कमी के कारण बहिस्रोंतण का महत्त्वपूर्ण प्रवाह हुआ। इसी समय विभिन्न समय क्षेत्रों में कार्यों के स्थानान्तरण की प्रवृत्ति विश्व के विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों, जिनमें न्यूयॉर्क, हांगकांग तथा लंदन थे, की तरफ वित्तीय उद्योगों के व्यापार के स्थानान्तरण के कारण हुआ।

वैश्वीकरण का एक महत्त्वपूर्ण आयाम लोगों का स्थानान्तरण है। प्रारंभिक व्यापारिक अवधि के दौरान प्रवसन का भाग बहुत अधिक था, जो अब सम्प्रभु राष्ट्रों द्वारा बड़े पैमाने पर चयनात्मक प्रवसन की प्रक्रिया को बढ़ावा देने से कम हुई है। सन् 2000 में तकरीबन 175 मिलियन लोग ऐसे थे, जो अपने जन्म स्थान वाले देश से अलग रह रहे थे। इन्हें तीन वर्गों में बाँटा जा सकता है: 158 मिलियन अन्तर्राष्ट्रीय प्रवासी, 16 मिलियन शरणार्थी तथा नौ लाख शरण माँगने वाले हैं।

भविष्य में विकसित देशों में वृद्धि जनसंख्या में अधिकता के कारण श्रम का विकासशील देशों की ओर संचलन की महत्त्वपूर्ण प्रवृत्ति देखने को मिलेगी। कुल अन्तर्राष्ट्रीय प्रवासी का 45% से 75% प्रवसन परिवारों द्वारा प्रायोजित होता है। जो मुख्यत: विकासशील देशों से यूरोप तथा अमेरिका की ओर होता है।

विधिक प्रवसन को सीमा नियंत्रण प्रक्रिया के अधीन सक्षम अधिकारी तंत्र से पार पाना होता है। विकासशील देशों में प्रवेश के लिए आने वाले आवेदनों की संख्या अनुमति योग्य सीमा से ज्यादा होती है। विस्तृत विधिक प्रक्रिया के कारण कुछ प्रवासी अवैध रूप से प्रवेश कर जाते हैं, जबकि अन्य अवैध प्रवासी अपनी विधिक सीमा खत्म हो जाने के कारण इस श्रेणी में आ जाते हैं।

अमेरिका पर हुए 9/11के हमले के तुरन्त बाद उसके द्वारा उठाये गये कड़े आतंकवादी निरोधक कदमों के कारण प्रवासियों का प्रवाह अमेरिका के मुकाबले अन्य विकसित देशों की ओर आंशिक रूप से मुड़ गया है। बहुत सारे विकसित देश जनसंख्या की बढ़ती उम्र के कारण भविष्य में प्रवासी श्रमिकों के प्रवाह पर अधिक सावधान है और वे मुख्यत: शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, सेवा निवृत्ति लाभों तथा आवास के साथ-साथ व्यापार प्रतिस्पर्धा में अपनी सत्ता को बनाये रखने के लिए आवश्यक श्रमबल की पूर्ति पर ध्यान दे रहे हैं।

सामान्यत: प्रवासी श्रमिक कार्य की खोज में घूमने वाले गतिशील लोग होते हैं जिसमें वे विभिन्न भौगोलिक अवस्थितियों की ओर गमन करते हैं जो वैश्वीकरण से सम्बन्धित एक प्रवृत्ति है। उन्नत कम्प्यूटर तकनीक, उपग्रह दूरसंचार और संरचना इंटरनेट विकास तथा सक्षम परिवहन नेटवर्क एवं कम श्रम लागत, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए पहले के मुकाबले अत्यंत ही सुलभ हो गये हैं।

इंटरनेट तकनीक के कारण देश और काल के संकुचन ने कार्यों को विश्व के विभिन्न भागों में सुनिश्चित किया है। यह पहले के कम लागत क्षेत्रों में उत्पादन से बढ़कर आउटसोर्सिंग और ऑफसोरिंग तक आ गया है। 1960-70 दशक के दौरान बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का प्रवसन विनिर्माण उत्पादन में श्रम लागत में प्रमुख कटौती हेतु कम श्रम लागत वाले क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित हुआ।

सेवा व्यापार में सामान्य समझौता (GATS) सेवाओं की आपूर्ति को चार भागों में विभक्त करता है: सीमा पार व्यापार, सीमा-पार उपभोग, वाणिज्यिक उपस्थिति तथा प्राकृतिक व्यक्ति की उपस्थिति।'' सीमा पार आपूर्ति, किसी क्षेत्र के एक सदस्य से दूसरे सदस्य के क्षेत्र में सेवाओं का प्रवाह (जैसे—बैंकिंग सेवाओं का दूरसंचार अथवा डाक के माध्यम से स्थानान्तरण) है। ''सीमा पार उपभोग'' ऐसी परिस्थिति को बताता है जिसमें सेवा का उपभोक्ता (पर्यटक तथा मरीज), सेवाओं को पाने के लिए दूसरे सदस्य के क्षेत्र में जाता है। ''वाणिज्यिक उपस्थित'' का तात्पर्य एक सदस्य देश के क्षेत्र में उपस्थिति सेवा आपूर्तिकर्त्ता का दूसरे देश के क्षेत्र में स्वामित्व अथवा लीज के माध्यम से सेवा उपलब्ध करवाना है (जैसे—विदेशी बीमा कम्पनियों अथवा होटल शृंखला की

घरेलू अनुषंगी इकाई)। "व्यवसायिक व्यक्तियों की उपस्थिति" से तात्पर्य किसी एक सदस्य देश के व्यक्तियों का सेवाओं की आपूर्ति हेतु अन्य सदस्य देश के क्षेत्र में प्रवेश (एकाउंटेंट, शिक्षक, डॉक्टर आदि) से है। इस व्यावसायिक व्यक्तियों के संचलन में अनेक परिस्थितियाँ होती हैं, तथापि सदस्य देश इन्हें नागरिकता, आवास, स्थायी आधार पर रोजगार, बाजार पहुँच देने के लिए स्वतंत्र है।

बहिस्रोंतिकरण तथा श्रमिकों का प्रवसन
(Outsourcing and Migration of Labours)

बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ तीव्र गति से अपनी सेवा सम्बन्धी क्रियाओं का स्थानान्तरण विकासशील देशों की ओर कर रही है। वाणिज्यिक सेवा उद्योग एक परिवर्तनकारी दौर से गुजर रहे हैं, जिसमें प्रमुख परिवर्तन पश्च-कार्यालयी क्रियाओं का विकासशील देशों की ओर बढ़ता स्थानान्तरण है। 1970 और 1980 के दौरान विनिर्माण आपूर्तिकर्त्ताओं के सम्पूर्ण विश्व में फैलने के पश्चात् वर्तमान में सेवा कम्पनियाँ तथा विनिर्माण उद्योगों के सेवा सम्बन्धी क्रियाकलाप भी वैश्विक हुए हैं। यह विकासशील देशों की अवस्थितियों में बेहतर संचार सुविधाओं, मानकीय तकनीकों तथा समान प्रबंधन प्रक्रियाओं, सूचना तकनीकी विकास का उद्यमों द्वारा हस्तांतरण तथा पश्च-कार्यालयी क्रियाओं के कारण संभव हो सका है। यह तृतीय पक्ष प्रदाता के द्वारा बहिस्रोंतिकरण अथवा अपनी कार्यालयी क्रियाओं का साधारण स्थानान्तरण के माध्यम से संभव हुआ है।

बहिस्रोंतिकरण (आउटसोर्सिंग) सेवाओं का, जैसे उत्पाद रूपरेखा या विनिर्माण का, तृतीय पक्ष कम्पनी के साथ एक उपसंविदा है। किसी भी कार्य को बहिस्रोंतिकरण (आउटसोर्सिंग) द्वारा या स्वयं अपने कार्यालय में करने का निर्णय मुख्य रूप से निम्न उत्पादन लागत, उपलब्ध संसाधनों का बेहतर प्रयोग, व्यवसाय विशेष को प्रतिस्पर्धी बनाने के दृष्टिकोण से अथवा श्रम, पूँजी, सूचना तकनीक तथा भूमि संसाधन के और अधिक दक्षतापूर्ण प्रयोग के आधार पर लिया जाता है। यह अनिवार्य रूप से श्रम का एक वर्गीकरण है।

बहिस्रोंतिकरण (आउटसोर्सिंग) किसी बाह्य सेवा प्रदाता को प्रबंधन का स्थानान्तरण अथवा पूरे व्यावसायिक क्रियाकलापों समेत दिन-प्रतिदिन के कार्यों के स्थानान्तरण को शामिल करता है। इसके अन्तर्गत ग्राहक संगठन एवं सेवा प्रदाता के मध्य स्थानान्तरित सेवाओं को स्पष्ट करने के लिए एक संविदीय समझौता होता है। इस समझौते के अधीन प्रदाता उत्पादन के साधनों, जिसमें लोगों, परिसम्पत्ति तथा अन्य संसाधनों का ग्राहक से स्थानान्तरण है, को प्राप्त करता है। संविदा की शर्तों के अनुरूप ग्राहक प्रदाता द्वारा प्रदान किये गये सेवाओं का मूल्य चुकाता है। बहिस्रोंतिकृत किये जाने वाले व्यवसायों में मुख्यत: सूचना तकनीकी, मानव संसाधन, सुविधाओं, अचल सम्पत्ति का प्रबंधन तथा लेखांकन आदि आते हैं। बहुत-सी कम्पनियाँ अपनी ग्राहक समर्थनकारी तथा कॉल सेंटर क्रियाओं का भी बहिस्रोंतिकरण (आउटसोर्सिंग) करती हैं, जिनमें Telemarketing, ग्राहक सेवायें, बाजार अनुसंधान, विनिर्माण, रूपरेखांकन, नेटवर्क का विकास तथा अभियांत्रिकी शामिल है।

बहिस्रोंतण कई प्रकार के होते हैं, प्रथम अपतटीयकरण (Offshoring), जिसमें क्रेता संगठन किसी अन्य देश का होता है। बहिस्रोंतण तथा ऑफसोरिंग के अर्थों में महत्त्वपूर्ण तकनीकी अंतर होने के बावजूद आम बातचीत में इसे समानार्थी रूप में प्रयोग किया जाता है। बहिस्रोंतिकरण प्रदाता के साथ एक संविदा को शामिल करता है जिसमें ऑफसोरिंग की कुछ मात्रा भी हो सकती है और नहीं भी। ऑफसोरिंग एक संस्थान के क्रियाकलापों का दूसरे देश में स्थानान्तरण है जिसमें बहिस्रोंतण हो सकता है अथवा उसी कम्पनी द्वारा ये काम किया जाता है।

बढ़ते वैश्वीकरण में कम्पनियों के आउटसोर्सिंग में वृद्धि के कारण आने वाले समय में बहिस्रोंतण तथा ऑफसोरिंग के मध्य अंतर करना कठिन हो जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि अमेरिका तथा ब्रिटेन में भारतीय बहिस्रोंतण कम्पनियों की उपस्थिति बढ़ती जा रही है। बहिस्रोंतण कार्यकरण मॉडल ने बढ़ते वैश्वीकरण के फलस्वरूप कई नई पदावलियों को लाया है, जो अवस्थितियों के मिश्रित परिवर्तन को परिलक्षित करती हैं; जैसे—नियर शोरिंग (nearshoring), नो शोरिंग (noshoring) तथा राइट शोरिंग (rightshoring)। यह भारतीय कम्पनियों के द्वारा अमेरिका तथा ब्रिटेन में अपने कार्यालय तथा कार्यकरण केन्द्रों को खोलने में देखा जा सकता है। बहिस्रोंतण के द्वारा एक महत्त्वपूर्ण कार्य लेखांकन तथा कर वापसी की तैयारी है।

द्वितीय मल्टीसोर्सिंग है जो प्रमुख रूप से वृहत् आउटसोर्सिंग समझौते को मुख्यत: सूचना तकनीक के क्षेत्र में सम्मिलित करता है। मल्टीसोर्सिंग एक ऐसा ढाँचा है, जिसमें ग्राहकों के व्यवसाय के विभिन्न भागों के कार्य अलग-अलग प्रदाताओं को दी जाती है। इस हेतु दूरसंचार रणनीति को स्पष्ट रूप से परिभाषित उत्तरदायित्व तथा सभी का एकीकरण के शासन सम्बन्धी मॉडल की आवश्यकता होती है।

तृतीय रणनीतिक बहिर्स्रोतिकरण (आउटसोर्सिंग) है जिसके अधीन कोई कम्पनी बाजार में उपलब्ध कराये जा रहे अपने विशेषीकृत क्षमता को बढ़ाने के लिए किसी दूसरे फर्म की कड़ी से सम्बद्ध हो जाता है।

प्र.5. वैश्वीकरण का विश्व पर सकारात्मक प्रभावों का विवरण दीजिए।

Describe the positive effects on world of globalisation.

उत्तर

वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव

(Positive Effects of Globalisation)

विश्व में बड़े पैमाने पर वैश्वीकरण के कारण सकारात्मकता की सीमा पर चर्चा करना कठिन होगा। लेकिन फिर भी, यहाँ भूमंडलीकरण के सकारात्मक प्रभाव और समाज के इतने जनसांख्यिकीय खंडों पर उनके सकारात्मक प्रभाव हैं।

वैश्विक बाजार (Global Market)

विकसित देशों में अधिकांश सफल उभरते बाजार राज्य के स्वामित्व वाले उद्योगों के निजीकरण का परिणाम हैं। इन उद्योगों के लिए उपभोक्ता माँग बढ़ाने के लिए उनमें से कई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी मूल्य शृंखला का विस्तार और विस्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। व्यवसाय प्रबंधन पर वैश्वीकरण का प्रभाव सीमाओं के पार लेनदेन की संख्या में अचानक वृद्धि से देखा जाता है। पैदावार की रक्षा करने और प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए, व्यवसायों को अपने पदचिह्नों की एक विस्तृत शृंखला विकसित करने के लिए जारी है क्योंकि यह लागत को कम करता है और पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का आनंद लेता है।

बहुराष्ट्रीय निगम वैश्वीकरण का एक परिणाम है। वे वैश्वीकरण की प्रक्रिया के भीतर एक केंद्रीय भूमिका पर कब्जा कर लेते हैं, जैसा कि वैश्विक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह के माध्यम से प्राप्त होता है। पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं में यूरोप के भीतर उनकी सांद्रता ने आकार की बाधाओं को जन्म दिया है, इसलिए नए भौगोलिक क्षेत्रों की आवश्यकता है जिससे वे बाजार में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करेंगे। इसके माध्यम से वे अपने बाजार का विस्तार करेंगे और पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का आनंद लेंगे क्योंकि वैश्वीकरण समय अंतरिक्ष संपीडन की सुविधा देता है। अर्थव्यवस्थाएँ सभी स्तरों पर प्रतिस्पर्धा करती हैं जिसमें निवेशकों को आकर्षित करना शामिल है।

क्रॉस कल्चरल प्रबंधन (Cross-cultural Management)

वैश्वीकरण का अभिजात वर्ग का क्षेत्र है क्योंकि दुनिया के कई हिस्सों में वे एकमात्र ऐसे लोग हैं जो वैश्विक बाजार में उपलब्ध कई उत्पादों को खरीदने के लिए पर्याप्त रूप से समृद्ध हैं। विभिन्न पृष्ठभूमि के उच्च शिक्षित और धनाढ्य लोग पश्चिमी देशों में रहते हैं। पश्चिमी शैली, चूँकि सम्पन्नता और शक्ति का प्रतीक हैं, इसलिए अभिजात वर्ग अक्सर दूसरों को प्रभावित करने के लिए पश्चिमी शैली के उत्पादों और व्यवहार के पैटर्न को अपनाता है। आज पश्चिमी संस्कृति और व्यवहार तथा भाषा के पैटर्न अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका कई अन्य देशों और समाजों पर शक्तिशाली प्रभाव डालता है। दुनिया में आज एक लोकप्रिय सांस्कृतिक शक्ति है। आर्थिक रूप से प्रभावी पश्चिम की लोकप्रिय उपभोक्ता संस्कृति अन्य क्षेत्रों, संस्कृतियों, देशों और समाजों को लगातार और अनिवार्य रूप से रूपांतरित कर रही है। इसके अलावा, इस तरह के परिप्रेक्ष्य का अर्थ है कि तकनीकी परिवर्तन, मास मीडिया, और उपभोक्ता उन्मुख विपणन अभियान अपनी छवि में जो कुछ भी स्पर्श करते हैं, उसका रीमेक बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। यहाँ तक कि समाज, धर्म और प्रौद्योगिकी के बारे में दृष्टिकोण और विचार वैश्वीकरण द्वारा लाए गए सांस्कृतिक प्रसार से बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका में मैकडॉनल्ड्स फास्ट, सस्ते और सुविधाजनक भोजन का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि यह दुनिया भर में समान नहीं है। यह चीन और रूस जैसे अन्य देशों में इसकी उच्च कीमत है जहाँ इसमें सांस्कृतिक अनुभव शामिल हैं।

विदेशी व्यापार (Foreign Trade)

वैश्वीकरण ने दुनिया में विदेशी व्यापार का निर्माण और विस्तार किया है। वे चीजें जो केवल विकसित देशों में पाई जाती थीं, अब वे दुनिया भर के अन्य देशों में पाई जा सकती हैं। लोग अब जो चाहें और किसी भी देश से प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से विकसित देश अपना माल दूसरे देशों को निर्यात कर सकते हैं। देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से व्यापार करते हैं, जिससे वे वैश्विक स्तर पर माल का आयात और निर्यात करते हैं। सामान निर्यात करने वाले इन देशों को तुलनात्मक लाभ मिलता है। दुनिया में देशों की व्यापार गतिविधियों को नियंत्रित करने और विनियमित करने के लिए संगठनों की स्थापना की गई है ताकि निष्पक्ष

व्यापार हो। विश्व व्यापार संगठन एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में उभरे जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों, कॉपीराइट, सब्सिडी, करों और शुल्कों पर नीतियों का पालन करने के लिए व्यक्तिगत सरकारों को प्रभावित करने में सक्षम है। राष्ट्र आर्थिक परिणामों का सामना किए बिना नियमों को नहीं तोड़ सकते।

व्यापार, विदेशी पूँजी और विश्व वित्तीय बाजारों पर निर्भर राष्ट्रों की संख्या बहुत बढ़ गई। विदेशी व्यापार में लगे देशों को तुलनात्मक लाभ मिलता है। पोस्टकार्डियन ट्रेड सिद्धांतों ने भविष्यवाणी की थी कि श्रम और पूँजी गहन वस्तुओं में विशेषज्ञता गरीब और अमीर देशों के बीच भारी वेतन अंतराल को पालेगी, जोकि विकासशील और विकसित देशों में बड़े पैमाने पर श्रमिक आप्रवास से बाद में बख्शा गया है।

विदेशी निवेश (Foreign Investment)

भारत में वैश्वीकरण के सबसे अधिक सकारात्मक प्रभावों में से एक विदेशी पूँजी का प्रवाह है। भारत में उत्पादन इकाइयाँ शुरू करके बहुत सारी कम्पनियों ने सीधे भारत में निवेश किया है, लेकिन हमें जो देखने की जरूरत है वह है विदेशी निवेश की मात्रा जो विकासशील देशों में बहती है। भारतीय कम्पनियाँ, जो भारत में और तटों पर, दोनों में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, विदेशी निवेश को बहुत अधिक आकर्षित करेंगी, और इस प्रकार यह भारत में उपलब्ध विदेशी मुद्रा के भंडार को बढ़ाती है। यह अमेरिका और अन्य विकसित देशों में वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभावों में से एक है क्योंकि विकासशील देश उन्हें एक अच्छा निवेश प्रस्ताव देते हैं।

प्रबंधकों के उद्देश्य कुछ स्थितियों में स्टॉकहोल्डर्स के साथ समान नहीं हो सकते हैं। कॉरपोरेशन जितना अधिक जटिल होगा, शेयरधारकों के लिए प्रबंधन की कार्रवाइयों की निगरानी करना उतना ही मुश्किल होगा, क्योंकि इससे प्रबंधकों को शेयरधारकों की कीमत पर अपने स्वयं के हित में कार्य करने की अधिक स्वतंत्रता मिलती है।

बहुराष्ट्रीय फर्म राष्ट्रीय फर्मों की तुलना में अधिक जटिल हैं। प्रबंधक अंतर्राष्ट्रीय विविधीकरण के पक्ष में हो सकते हैं क्योंकि यह फर्म के विशिष्ट जोखिम को कम करता है या उनकी प्रतिष्ठा में इजाफा करता है। ये लक्ष्य शेयरधारकों के लिए बहुत कम रुचि के हो सकते हैं। शेयरधारकों और प्रबंधकों के बीच हितों का यह विचलन, घरेलू फर्मों के सापेक्ष बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के मूल्य को कम कर सकता है।

प्रतियोगिता (Competition)

वैश्वीकरण के सबसे अधिक दिखाई देने वाले सकारात्मक प्रभावों में से एक है वैश्विक प्रतिस्पर्धा के कारण उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार। ग्राहक सेवा और ग्राहक उत्पादन के लिए राजा का दृष्टिकोण है, जिससे उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। जैसा कि घरेलू कम्पनियों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बाहर रहना पड़ता है, वे बाजार में जीवित रहने के लिए अपने मानकों और ग्राहकों की संतुष्टि के स्तर को बढ़ाने के लिए मजबूर होते हैं।

इसके अलावा, जब एक वैश्विक ब्रांड एक नए देश में प्रवेश करता है, तो यह कुछ सद्भावना की सवारी करने में आता है, जिसे इसे जीना पड़ता है। यह बाजार में प्रतिस्पर्धा और सबसे योग्य स्थिति का अस्तित्व बनाता है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्र.1. निम्नलिखित में से कौन-सा संगठन वैश्वीकरण प्रक्रिया को नहीं संभालता है?

(क) विश्व बैंक (ख) अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष

(ग) विश्व व्यापार संगठन (घ) एशियाई बैंक

उत्तर (घ) एशियाई बैंक

प्र.2. वैश्वीकरण का कारण बना–

(क) माल, पूँजी और सेवाओं की आसान आवाजाही

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि करना

(ग) विभिन्न देशों में कंपनियाँ आसानी से काम कर रही हैं

(घ) उपरोक्त सभी

उत्तर (घ) उपरोक्त सभी

TOUCH 'n' PASS

प्र.3. निम्नलिखित में से किसे निवेश माना जा सकता है?
(क) विभिन्न संपत्तियों पर पैसा खर्च करना, उदाहरण के लिए, जमीन
(ख) स्वास्थ्य पर पैसा खर्च करना
(ग) घरेलू सामानों पर धन खर्च होगा
(घ) किसी सामाजिक कर्मकांड या रीति-रिवाज पर धन खर्च करना

उत्तर (क) विभिन्न संपत्तियों पर पैसा खर्च करना, उदाहरण के लिए, जमीन

प्र.4. एसईजेड का पूर्ण रूप क्या है?
(क) विशेष आर्थिक क्षेत्र (ख) विशेष शिक्षा क्षेत्र
(ग) सामाजिक आर्थिक क्षेत्र (घ) विशेष प्रभावी क्षेत्र

उत्तर (क) विशेष आर्थिक क्षेत्र

प्र.5. अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ खोलना और सुधार करना कहलाता है–
(क) निजीकरण (ख) उदारीकरण (ग) वैश्वीकरण (घ) इनमें से कोई नहीं

उत्तर (ग) वैश्वीकरण

प्र.6. फोर्ड मोटर्स का पहला संयंत्र भारत में कहाँ स्थापित किया गया था?
(क) मुंबई (ख) कोलकाता (ग) दिल्ली (घ) चेन्नई

उत्तर (घ) चेन्नई

प्र.7. भारत सरकार ने विदेशी निवेश और व्यापार प्रतिबंधों को माफ करने का निर्णय कब लिया?
(क) 1990 (ख) 1991 (ग) 1993 (घ) 1992

उत्तर (ख) 1991

प्र.8. वैश्वीकरण के बाद कौन-सा उद्योग विदेशी प्रतिस्पर्धा से प्रभावित हुआ?
(क) चमड़ा उद्योग (ख) डेयरी उत्पादों का (ग) वाहन उद्योग (घ) वस्त्र उद्योग

उत्तर (ख) डेयरी उत्पादों का

प्र.9. क्या कारण है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ विभिन्न देशों में नए कारखाने और कार्यालय स्थापित करती हैं?
(क) उत्पादन लागत कम है और वे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं
(ख) उत्पादन लागत अधिक है और वे उच्च लाभ कमा सकते हैं
(ग) बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ एक महत्त्वपूर्ण उपस्थित बना सकती हैं
(घ) उत्पादन लागत कम है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को नुकसान हो सकता है

उत्तर (क) उत्पादन लागत कम है और वे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं

प्र.10. वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण किस क्षेत्र में सबसे कम लाभ हुआ?
(क) औद्योगिक क्षेत्र (ख) सेवा क्षेत्र (ग) कृषि क्षेत्र (घ) माध्यमिक क्षेत्र

उत्तर (ग) कृषि क्षेत्र

प्र.11. वैश्वीकरण के क्या लाभ हैं?
(क) नवाचार और प्रौद्योगिकी का उपयोग (ख) कम उत्पादन लागत
(ग) विभिन्न नई संस्कृतियों तक पहुँच प्राप्त करें (घ) ये सभी

उत्तर (घ) ये सभी

प्र.12. निम्नलिखित में से कौन वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है?
(क) बाहरी व्यापार (ख) बड़े पैमाने पर व्यापार
(ग) एक छोटे से व्यापार में व्यापार (घ) आंतरिक व्यापार

उत्तर (क) बाहरी व्यापार

TOUCH 'n PASS

प्र.13. भारत में वैश्वीकरण के कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
(क) विदेशी सरकारें (ख) बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ (ग) विश्व बैंक (घ) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (ख) बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ

प्र.14. वैश्वीकरण ने निम्नलिखित में से किसके विकास में काफी हद तक सुधार किया है?
(क) गरीब देश (ख) विकासशील देश (ग) विकसित देशों (घ) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (ग) विकसित देशों

प्र.15. वैश्वीकरण विभिन्न आर्थिक और सामाजिक लाभों को सुनिश्चित करने में मदद करता है–
(क) मजदूरों (ख) उपभोक्ताओं (ग) प्रोड्यूसर्स (घ) ये सभी
उत्तर (घ) ये सभी

प्र.16. इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अनुचित निवेश और सस्ते आयात का कारण बना सकता है–
(क) औद्योगिक क्षेत्र का धीमा विकास (ख) घरेलू प्रस्तुतियों के लिए वैकल्पिक विकल्प ढूँढ़ना
(ग) कृषि क्षेत्र की धीमी वृद्धि (घ) ये सभी
उत्तर (घ) ये सभी

प्र.17. बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वैश्विक बाजार में प्रवेश किया–
(क) यूनेस्को (ख) विश्व व्यापार संगठन (ग) संयुक्त राष्ट्र संघ (घ) ये सभी
उत्तर (ख) विश्व व्यापार संगठन

प्र.18. निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प विदेशी व्यापार के लिए प्रतिबंध हो सकता है?
(क) बिक्री कर (ख) आयात कर (ग) स्थानीय व्यापार कर (घ) गुणवत्ता नियंत्रण
उत्तर (ख) आयात कर

प्र.19. विश्व व्यापार संगठन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को क्या प्रदान करके मदद करता है?
(क) व्यापार और निवेश के लिए कोष (ख) विदेशी श्रम प्रदान करना
(ग) विदेशी सरकारों द्वारा समर्थन (घ) वस्तुएँ और सेवाएँ
उत्तर (क) व्यापार और निवेश के लिए कोष

प्र.20. बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ किसी नए देश में अपना उत्पादन स्थापित करने का निर्णय लेने से पहले हमेशा महत्त्वपूर्ण कारकों पर विचार करती हैं। निम्नलिखित में से सही गुणनखंड क्या है?
(क) सरकारों द्वारा सहायक नीतियाँ (ख) देश में स्थानीय प्रतिस्पर्धियों की उपस्थिति
(ग) अकुशल और सस्ते श्रम की उपलब्धता (घ) बाजार निकटता
उत्तर (ख) देश में स्थानीय प्रतिस्पर्धियों की उपस्थिति

प्र.21. वैश्वीकरण की चुनौतियाँ क्या हैं?
(क) विदेशी श्रमिकों का शोषण (ख) बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विस्तार में कठिनाई
(ग) निर्यात करों में उच्च शुरू (घ) ये सभी
उत्तर (घ) ये सभी

प्र.22. 2006-07 के केंद्रीय बजट में, सीमा शुल्क दर को किस दर तक कम किया गया था?
(क) 10% (ख) 12% (ग) 9% (घ) 20%
उत्तर (क) 10%

प्र.23. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत में अपना संचालन शुरू किया–
(क) अप्रैल 1957 (ख) दिसम्बर 1947
(ग) मार्च 1947 (घ) अगस्त 1957
उत्तर (ग) मार्च 1947

TOUCH 'n PASS

प्र.24. विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है?
(क) आईडीए (ख) आईबीआरडी (ग) आईएफसी (घ) ये सभी
उत्तर (ख) आईबीआरडी

प्र.25. निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान करें–
(क) विश्व बैंक खुदरा कर्जदारों को ऋण देता है।
(ख) विश्व बैंक सदस्य देशों को ऋण देता है।
(ग) विश्व बैंक विदेशों से संस्थागत निवेशकों को ऋण देता है।
(घ) विश्व बैंक उन्हें कर्ज देता है, जिन्हें पैसे की जरूरत होती है।
उत्तर (ख) विश्व बैंक सदस्य देशों को ऋण देता है।

प्र.26. भारतीय बाजार मुख्य रूप से वैश्वीकरण के साथ एक ..... बन गया है।
(क) मोनोप्सनी मार्केट (ख) विक्रेता का बाजार (ग) एकाधिकार बाजार (घ) क्रेता बाजार
उत्तर (घ) क्रेता बाजार

प्र.27. निम्नलिखित में से कौन-सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन विभिन्न राष्ट्रों के बीच व्यापार नियमों से संबंधित है?
(क) ओपेक (ख) विश्व व्यापार संगठन (ग) एसटीसी (घ) संयुक्त राष्ट्र संघ
उत्तर (ख) विश्व व्यापार संगठन

प्र.28. 1995 में व्यापार और शुल्क पर सामान्य समझौते को किस संगठन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था?
(क) विश्व बैंक (ख) ओपेक
(ग) विश्व व्यापार संगठन (घ) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
उत्तर (ग) विश्व व्यापार संगठन

प्र.29. निम्नलिखित में से किस संगठन को सॉफ्ट लेंडिंग आर्म भी कहा जाता है?
(क) आईडीए (ख) आईएमपी (ग) ईडफ (घ) आईएफसी
उत्तर (क) आईडीए

प्र.30. विशेष आहरण अधिकार किस वर्ष जारी किए गए थे?
(क) 2000 (ख) 1969 (ग) 1989 (घ) 1970
उत्तर (ख) 1969

प्र.31. इनमें से कौन-सा एक विशेष आर्थिक क्षेत्र की विशेषता नहीं है?
(क) शीर्ष श्रेणी की सुविधाएँ
(ख) सरकार श्रम कानूनों में लचीलेपन की अनुमति देती है
(ग) एसईजेड को महत्त्वपूर्ण समय के लिए करों का भुगतान नहीं करना पड़ता है
(घ) उन्हें शुरुआत में कुछ टैक्स चुकाने पड़ते हैं
उत्तर (ग) एसईजेड को महत्त्वपूर्ण समय के लिए करों का भुगतान नहीं करना पड़ता है

प्र.32. एसईजेड में कंपनियों को कितने सालों तक करों का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है?
(क) 6 साल (ख) 10 साल (ग) 20 साल (घ) 5 साल
उत्तर (घ) 5 साल

प्र.33. वैश्वीकरण की शुरुआत के बाद, कारगिल फूड्स नामक एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किस भारतीय कंपनी का अधिग्रहण किया गया था?
(क) फन फूड्स लिमिटेड (ख) पारख फूड्स
(ग) अमूल (घ) एग्रो टेक फूड्स लिमिटेड
उत्तर (ख) पारख फूड्स

TOUCH 'n' PASS

प्र.34. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन वैश्वीकरण के लिए सही नहीं है?

(क) श्रमिकों को उनके अधिकारों से वंचित किया गया क्योंकि श्रम कानूनों को लागू नहीं किया गया था।
(ख) इसने सेवा क्षेत्रों में कई नौकरियाँ पैदा करने में मदद की।
(ग) वैश्वीकरण से धन, कौशल और शिक्षा वाले लोगों को कोई लाभ नहीं हुआ।
(घ) वैश्वीकरण के असमान लाभ हैं।

उत्तर (ग) वैश्वीकरण से धन, कौशल और शिक्षा वाले लोगों को कोई लाभ नहीं हुआ।

प्र.35. एक स्थानीय कंपनी के साथ बहुराष्ट्रीय कंपनी के संयुक्त उत्पादन का प्राथमिक लाभ क्या है?

(क) एमएनसी उत्पादन के लिए नवीनतम तकनीक लाने में मदद करती है।
(ख) बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अपने उत्पादों के बीच दर की वृद्धि को आसानी से नियंत्रित कर सकती है।
(ग) बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अपने उत्पाद अपने ब्रांड नाम से बेचती हैं।
(घ) बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ स्थानीय कंपनियों को खरीद सकती है।

उत्तर (ख) बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अपने उत्पादों के बीच दर की वृद्धि को आसानी से नियंत्रित कर सकती है।

प्र.36. 1991 में भारत की नई आर्थिक नीति किसने पेश की?

(क) वल्लभभाई पटेल (ख) पीवी नरसिम्हा राव (ग) डॉ० मनमोहन सिंह (घ) राजीव गांधी

उत्तर (ग) डॉ० मनमोहन सिंह

प्र.37. बाजार एकीकरण का क्या अर्थ है?

(क) प्रतिस्पर्धी मूल्य की पेशकश (ख) माल की एक विशाल विविधता
(ग) विदेशी बाजारों में संचालन (घ) ये सभी

उत्तर (घ) ये सभी

प्र.38. निम्नलिखित में से कौन-सी कंपनी एमएनसी के रूप में उभरी है?

(क) टाटा मोटर्स (ख) मारुति सुजुकी (ग) महिंद्रा एंड महिंद्रा (घ) रेनॉल्ट

उत्तर (क) टाटा मोटर्स

प्र.39. सेवाओं के उत्पादन के विस्तार में किस चीज ने मदद की है?

(क) कॉल सेंटरों (ख) ईमेल (ग) फैक्स (घ) तार

उत्तर (क) कॉल सेंटरों

TOUCH 'n' PASS

यद्यपि इस पुस्तक को यथासम्भव शुद्ध एवं त्रुटिरहित प्रस्तुत करने का भरसक प्रयास किया गया है, तथापि इसमें कोई कमी अथवा त्रुटि अनिच्छाकृत ढंग से रह गई हो तो उससे कारित क्षति अथवा सन्ताप के लिए लेखक, प्रकाशक तथा मुद्रक का कोई दायित्व नहीं होगा। सभी विवादित मामलों का न्यायक्षेत्र मेरठ न्यायालय के अधीन होगा।

इस पुस्तक में समाहित सम्पूर्ण पाठ्य-सामग्री (रेखा व छायाचित्रों सहित) के सर्वाधिकार प्रकाशक के अधीन हैं। अतः कोई भी व्यक्ति इस पुस्तक का नाम, टाइटिल-डिजाइन तथा पाठ्य-सामग्री आदि को आंशिक या पूर्ण रूप से तोड़-मरोड़कर प्रकाशित करने का प्रयास न करें, अन्यथा कानूनी तौर पर हर्जे-खर्चे व हानि के जिम्मेदार होंगे।

इस पुस्तक में रह गई तथ्यात्मक त्रुटियों तथा अन्य किसी भी कमी के लिए विद्वत् पाठकगण से भूल-सुधार/सुझाव एवं टिप्पणियाँ सादर आमन्त्रित हैं। प्राप्त सुझावों अथवा त्रुटियों का समायोजन आगामी संस्करण में कर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार के भूल-सुधार/सुझाव आप info@vidyauniversitypress.com पर भी ई-मेल कर सकते हैं।